संपादकीय

“ सच्चे शिक्षक वे होते हैं, जो हमें खुद के लिए सोचने में मदद करते हैं। -डॉ. एस. राधाकृष्णन

जीएसटी का दूसरा दौर

ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर आशंकाएं मंडरा रही हैं, तब जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी की चार स्लैब वाली संरचना को समाप्त कर दो स्लैब वाली सरल प्रणाली को मंजूरी दिया जाना निश्चित ही स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे आम जनता, मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे व्यवसायियों पर कर का बोझ कम होगा। यह समयानुकूल भी है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के चलते उपभोग में कमी आने के संकेत अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बने हुए थे। लेकिन अब, आम उपभोग की तकरीबन सभी वस्तुओं का सस्ता होना, उपभोक्ताओं में यकीनन खरीद की प्रेरणा को बढ़ाएगा। गौरतलब है कि आठ साल पहले हुई अपनी शुरुआत से जीएसटी व्यवस्था ने सरकार के राजस्व में तो खूब इजाफा किया, लेकिन जटिल दरें और बार-बार होने वाले संशोधन उपभोक्ताओं और कारोबारियों, दोनों के लिए उलझन का कारण बने। ऐसे में, सरकार द्वारा लाए गए ऐतिहासिक सुधार, जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही की थी, निस्संदेह इन उलझनों का समाधान बनेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में जीएसटी की चार दरें-5, 12, 18 और 28 फीसदी लागू हैं, नए सुधारों के तहत जिनके इसी महीने की बाईस तारीख से सिर्फ दो दरों-पांच और 18 फीसदी में तब्दील हो जाने से व्यापारिक गतिविधियों में स्पष्टता आएगी और कर चोरी की गुंजाइश भी कम होगी। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि इससे सरकारी राजस्व को तकरीबन 48 हजार करोड़ रुपये की हानि होगी, पर सरकार का यह कहना उम्मीद जगाता है कि कम दरें उपभोग का स्तर बढ़ाएंगी, कर चोरी को कम करेंगी और कर-आधार को भी विस्तृत करेंगी। इससे दीर्घकाल में राजस्व में वृद्धि ही होगी। हां, सरकार को यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व में तत्कालिक हानि की भरपाई के लिए वह कोई उपाय ढूंढे, ताकि राज्यों व केंद्र के बीच वित्तीय तनाव न बढ़े। किसी भी कर सुधार

की असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होती है। सरकार बड़े दावों से आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित करे कि कटौतियां केवल कॉरपोरेट मुनाफे को ही न बढ़ाएं, बल्कि इनके फायदे आम आदमी तक भी पहुंचें। ये सुधार, अगर सही ढंग से लागू किए जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और गतिशील बनाने में महती भूमिका निभा सकते हैं।

नए युग का सूत्रपात

जीएसटी की दरों में बदलाव और 12 फीसदी टैक्स सीमा को खत्म करना कराधान में एक नए युग का सूत्रपात है। उपभोक्ताओं में खुशी और उम्मीद का माहौल है, क्योंकि स्लैब दर में 50 फीसदी से ज्यादा की कटौती की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन वस्तुओं की कीमतें 50 फीसदी तक गिर जाएंगी।

आठ साल पहले जब जीएसटी को लागू किया गया था, उसी समय से इसे आलोचना और प्रशंसा, दोनों का सामना करना पड़ा है। किसी अन्य कानून का इतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना जीएसटी का पड़ा, क्योंकि इसने एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को जन्म दिया, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी।

पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी परिषद ने केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए 56 बार बैठकें की हैं, यानी औसतन हर साल सात बार। हर गुजरते महीने के साथ जीएसटी संग्रह में वृद्धि एक ऐसी खबर बन गई है, जिस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि करती है, बल्कि औसत भारतीयों द्वारा उपभोग की जाने वाली लगभग हर चीज पर कर चुकाने की कठिनाई को भी उजागर करती है।

नारायण कृष्णमूर्ति
वरिष्ठ पत्रकार

अभी 2-3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब हम चार-स्तरीय दरों- पांच फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के बजाय पांच फीसदी और 18 फीसदी की सरलीकृत दो टैक्स स्लैब की ओर बढ़ रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा कदम है, जिसका मिला-जुला असर होगा, क्योंकि 12 फीसदी दर वाली कुछ वस्तुओं और सेवाओं को 18 फीसदी की उच्चतर स्लैब में डाल दिया गया है, तथा कुछ को पांच फीसदी स्लैब में रखा गया है, जिससे राहत मिलेगी। हमेशा की तरह, तंबाकू जनित उत्पादों और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 फीसदी स्लैब बना हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सिगरेट, प्रीमियम शराब और उच्च श्रेणी की कारों जैसी वस्तुओं को कर में राहत नहीं मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के चलते कर कटौती की उम्मीद तो पहले से ही थी। 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले इस बदलाव से सरकारी राजस्व में 48,000 करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका है।

उपभोक्ताओं में खुशी और उम्मीद का माहौल है, क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई एफएमसीजी वस्तुएं, जैसे साबुन, हेयर ऑयल, शैंपू और अन्य घरेलू सामान, पहले के 12 फीसदी वाले स्लैब से पांच फीसदी वाले स्लैब के दायरे में आ गई हैं। भले ही स्लैब दर में 50 फीसदी से ज्यादा की कटौती की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन वस्तुओं की कीमतें 50 फीसदी तक गिर जाएंगी।

सभी प्रकार की चपाती और परांठे समेत आवश्यक खाद्य पदार्थ कर-मुक्त रहेंगे, जिन पर अब कोई कर नहीं लगेगा, जबकि पहले पांच फीसदी कर लगता था। जीएसटी कर दरों को युक्तिसंगत बनाने की पूरी कवायद घरेलू खपत को बढ़ावा देने और कुछ हद तक व्यवसायों को अमेरिका द्वारा विभिन्न भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करने के लिए की गई है। भावनाएं मजबूत हैं, और यह भावना शेयर बाजारों में आई तेजी से परिलक्षित होती है, क्योंकि जीएसटी दर में कटौती की घोषणा के बाद बाजार में तेजी देखी गई।

लेकिन, दरों में कटौती का जश्न मनाते हुए यह भी सोचना चाहिए कि आखिर कुछ वस्तुओं पर जीएसटी क्यों लगाया गया था। उदाहरण के लिए, नक्शों, चार्ट, पेंसिल और स्टेशनरी पर 12 फीसदी जीएसटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। इसी तरह, जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी उन लोगों पर जुर्माना लगाने जैसा था, जो खुद को वित्तीय जोखिमों से बचा रहे थे। इसी तरह, कृषि उत्पादों, दूध, घी आदि पर जीएसटी शायद टाला जा सकता था, फिर भी ये कर मौजूद हैं। इन दरों का पांच फीसदी स्लैब में आना एक सकारात्मक संकेत है। इन करों का अस्तित्व व्यापक स्तर पर जवाब की मांग करता है।

पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, जो सरकार के राजस्व के लिए अच्छी बात है। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह की खबर सामान्य बात हो गई है, और इसने हर भारतीय को कर के दायरे में ला दिया है। जीएसटी अपने नौवें वर्ष में प्रवेश कर गया है, और यह व्यापार में आसानी, बेहतर अनुपालन और व्यापक आर्थिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार विकसित हो रहा है। चाहे करों में वृद्धि हो या कटौती, उसके असर को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका अन्य कई कारकों पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ता है। वैश्विक तेल की कीमतें, मुद्रा दर, शेयर बाजार की गतिविधि, मांग एवं आपूर्ति, और बदलते रुझान कुछ ऐसे कारक हैं, जो कराधान और उपभोग को प्रभावित करते हैं।

जीएसटी अनुपालन से जुड़ी लागतों से संबंधित मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस धारणा को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जाना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। हमने देखा है कि एफएमसीजी कंपनियां कीमतों में फेरबदल करने के बजाय पैक के आकार के साथ खेल करती हैं, जिसके कारण कई मामलों में कीमतों में प्रत्यक्ष रूप से कोई कमी नहीं दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि इस कदम से बिक्री बढ़े, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे लोगों पर बढ़ती लागत का बोझ सीधे तौर पर कम हो। लोग सिर्फ इसलिए चीजें नहीं खरीदते कि लागत कम हो गई है। कीमत कम होने पर लोग ज्यादा दवाइयां या ज्यादा खाना नहीं खाते।

इसी तरह, जीएसटी के जरिये देश भर में कर संग्रह का एक मजबूत मॉडल तैयार करने के बाद सरकार इसे पूरी तरह से छोड़ने वाली नहीं है। हां, जीएसटी के तहत वस्तुओं पर कर की दर में उतार-चढ़ाव जरूर होगा, लेकिन जीएसटी संग्रह पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। नागरिकों के तौर पर, हमें बदलती कर दरों के साथ तालमेल बिठाना होगा और उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां हम हर बार कर दर में समायोजन के दौरान ज्यादा बचत कर सकते हैं।

फिलहाल, जीएसटी दरों में इस बदलाव को उपभोग को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए, जो बढ़ती लागतों के कारण कम हो रहा था। परिवारों को अपने बजट पर कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि वे वास्तव में कितनी बचत कर सकते हैं और उस बचत का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

प्रकृति

पीर पर्वत की सुननी चाहिए

शीर्ष अदालत का यह कहना, 'यदि हालात ऐसे रहे, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिमाचल नक्शे से ही गायब हो जाएगा।' पहाड़ी राज्यों के विकास मॉडल के लिए गंभीर चेतावनी है।

आसमान से बरसती आफत के बीच दरकते पहाड़ कराह रहे हैं। कई इलाकों के अस्तित्व पर संकट है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से जान-माल की बड़ी क्षति हो रही है। सावन-भादों हर साल आंसुओं के सैलाब लेकर आ रहे हैं। हिमाचल में बीते तीन साल में बादल फटने की सौ से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इस मानसून में करीब 50 जगह बादल फट चुके हैं। वर्ष 1949 के बाद इस बार अगस्त में सर्वाधिक 431 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 68 फीसदी ज्यादा है। बादल फटने, बाढ़-भूस्खलन से 182 लोगों की जान जा चुकी है, 45 लापता हैं।

अब तक 3,525 करोड़ रुपये का नुकसान झेल चुके हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। बीते दिनों शीर्ष अदालत ने पारिस्थितिक असंतुलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यदि हालात ऐसे ही रहे, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिमाचल नक्शे से ही गायब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी आंखें खोलने वाली है। जानकार लंबे अरसे से कह रहे हैं कि पहाड़ों पर बढ़ता मानवीय दखल, अंधाधुंध जल बिजली प्रोजेक्ट, फोरलेन, वन कटान और नदी-नालों के रास्तों में निर्माण आपदाओं की प्रमुख वजहें हैं। अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली भी जरूरी है, लेकिन विकास के ऐसे मॉडल को बदलना होगा, जो आपके अस्तित्व को ही चुनौती देने लगे।

बविंद्र वशिष्ठ

करीब दो माह पहले मंडी के सराज में एक ही रात 17 जगह बादल फटने से भारी तबाही के बाद हिमाचल सरकार के आग्रह पर इसके कारण तलाशने के लिए केंद्र ने टीम भेजी। पहले भी कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्टें फाइलों में दफन हैं। बरसात खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। कभी बादल पर्वतीय क्षेत्रों में फटते थे, लेकिन अब ये आपदाएं मध्य पहाड़ी और आबादी वाले निचले इलाकों में लगातार हो रही हैं। पिघलते ग्लेशियरों से बन रही झीलें और बिजली प्रोजेक्टों के लिए बनाए जा रहे बांधों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद की रिपोर्ट बताती है कि सतलुज बेसिन के ग्लेशियरों में वर्ष 2019 में 562 झीलें थीं, जो 2023 में बढ़कर 1,048 हो गई हैं। आईआईटी, रोपड़ के एक अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल का करीब 45 फीसदी हिस्सा भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं को लेकर संवेदनशील है। ग्लेशियर पिघलने की दर पिछले 25 वर्षों में दोगुनी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल में सतलुज बेसिन पर प्रस्तावित सभी पन बिजली परियोजनाएं यदि धरातल पर उतर गईं, तो खाब से लेकर भाखड़ा डैम तक करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी ही लुप्त हो जाएगी। विकास परियोजनाएं ऐसी कंसल्टेंट एजेंसियों की रिपोर्ट पर बन रही हैं, जिन्हें पहाड़ों के मिजाज का पता ही नहीं है।

विकास की अवधारणा में अर्थशास्त्र के हावी होने से भी कई पहलू नजरअंदाज हो रहे हैं। पहाड़ों की पारिस्थितिकी नाजुक है, लेकिन हमारा विकास मॉडल इसके विपरीत है। पहाड़ महफूज रहेंगे, तभी पर्यटन और कारोबार बढ़ेगा। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने वाले स्थानीय संस्थानों को विकास परियोजनाओं के साथ जोड़ना जरूरी है। पूर्व के अध्ययनों को लिंक कर शोध संस्थान और नीति निर्माता समन्वय के साथ दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएंगे, तो पहाड़ों पर हर साल मच रही यह तबाही रुक सकती है। वैज्ञानिक आकलन के आधार पर संभावित खतरे के मद्देनजर क्षेत्रवार नो कंस्ट्रक्शन जोन को चिह्नित कर नए सिरे से विकास का खाका खींचना समय की जरूरत है।

अपने सभी सुखद पलों को संजोकर रखें, वे बुढ़ापे का अच्छा सहारा बनते हैं। -बूथ टार्किंगटन

बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक होते हैं

बुजुर्ग होना एक अनुभव है, जो आप अपनी पूरी जिंदगी में अर्जित करते हैं। बुजुर्ग होने पर यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना ज्ञान समाज के साथ साझा करें। मानवता के इतिहास में बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक रहे हैं।

हमारे समाज में, जहां युवावस्था और युवा होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, मैं शुरू में अपनी बुजुर्गियत को स्वीकारने से हिचकिचाता था। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाते हैं, तो आप इसे नकार नहीं सकते। मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्ग होना एक अनुभव है, जो आप अपनी पूरी जिंदगी में अर्जित करते हैं।

बुजुर्ग होने पर यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना ज्ञान समाज के साथ साझा करें। मानवता के इतिहास में बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक रहे हैं। आप इस समुदाय के जीवंत इतिहास हैं। मैं अपने साथी बुजुर्गों से आग्रह करता हूं कि वे 'बुजुर्ग' शब्द से परहेज करना बंद करें और समझें कि यह न केवल सम्मान देता है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी लाता है। हम एक अनोखी स्थिति में हैं, हमने एक पूरा जीवन जिया है, हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हैं, और अपने अनुभवों से नई पीढ़ी के लिए सबक दे सकते हैं। अब जब मैं सत्तर के दशक में हूं, मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के आखिरी हिस्से में हूं, मैं इसे 'मृत्यु क्षेत्र' कहता हूं। हर दिन मेरे लिए एक उपहार है, जिसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। आसन्न मृत्यु जीवन पर विचार करने, सफलताओं और असफलताओं, प्यार और नुकसान, खुशियों और त्रासदियों, और उन लोगों, अनुभवों और घटनाओं पर विचार करने की एक शक्तिशाली प्रेरणा है, जिन्होंने मुझे, मेरे मूल्यों और विश्वासों को आकार दिया है। मैं उन चीजों के पीछे भागने से आजाद हो गया हूं, जो लोग जवानी में करते हैं। जवानी में बहुत सारे दबाव होते हैं, जो जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। लेकिन, अब मैं आराम से बैठकर सोच सकता हूं। और मुझे लगता है कि यह वाकई मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली है और बहुत कुछ सीखा है। तो एक बुजुर्ग के तौर पर, शरीर की गति धीमी हो सकती है। मेरा दिमाग अब भी काम कर रहा है, और मुझे काम करना है। अच्छी तरह से बुढ़ापा बिताने का मतलब है कुछ ऐसा करते रहना, जो आपको उत्साहित करे।

डेविड सुजुकी

मुड़-मुड़ के देख

मथुरा के 70 वर्षीय रामप्रसाद रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उम्र के साथ मेडिकल खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में वह अपना घर बेचने के बारे में सोच रहे हैं। पर वह उलझन में हैं। विशेषज्ञों ने उन्हें वे सभी विकल्प सुझाए, जिनसे वह सही निर्णय लेकर घर को कमाई का जरिया बना सकें।

घर चलाने के लिए घर बेचना जरूरी नहीं

रिवर्स मॉर्गेज ऐसी सुविधा है, जो बुजुर्गों को नियमित कमाई का सहारा दे सकती है।

मथुरा की संकरी गलियों में सुबह की पहली किरणें यमुना नदी के किनारे धीरे-धीरे फैल रही थीं। यमुना का शांत जल, इस शहर को एक अनोखा आध्यात्मिक आकर्षण देता है। यहां के एक पुराने मोहल्ले में रामप्रसाद जी का मकान है। लाल पत्थरों से बना यह घर अब एक बड़े सवाल का केंद्र बन चुका था। रामप्रसाद, उनकी पत्नी सरला और बेटा अनिल घर के भविष्य को लेकर उलझन में हैं। क्या वे इसे बेच दें? रिवर्स मॉर्गेज लोन लें? या किराये पर दे दें?

रामप्रसाद 70 साल के हैं और सरला 65 कीं। रामप्रसाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन से उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं। बेटा अनिल दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। रामप्रसाद और सरला को चिंता थी कि उनकी बचत और पेंशन उनके भविष्य के लिए काफी नहीं होगी। अनिल भी चाहता है कि उसके माता-पिता की जिंदगी आरामदायक हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि वे जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लें। इसलिए सभी विकल्पों को परखना जरूरी था। इसके लिए उसने वित्तीय

सलाहकार राकेश से परामर्श लेने की सोची, जिन्होंने उसे सारे आयामों के बारे में बारीकी से समझाया।

विकल्प 1 : घर बेचना

वित्तीय सलाहकार-मान लीजिए, घर 50 लाख में बिकता है। इन पैसों से जरूरत के हिसाब से आप छोटा घर खरीद सकते हैं या किराये पर रह सकते हैं। बाकी पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं। घर बेचना तभी सही है, जब आप नए घर में खुशी से रह सकें। क्योंकि, जिस घर में आपका जन्म और शादी हुई, बच्चे बड़े हुए हों, उससे भावनात्मक रिश्ता होता है। घर बेचने के बाद आप भावनात्मक लगाव खो देते हैं और रकम को सही जगह निवेश न करना दूसरा बड़ा नुकसान है। तीसरा-अगर आप किराये पर रहते हैं, तो हर साल किराये का बोझ बढ़ेगा।

किराया बढ़ने की रफ्तार : प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के अनुसार, देश के सात शीर्ष शहरों के प्रमुख इलाकों में पिछले तीन साल में किराये में 76 फीसदी तक वृद्धि दर्ज की गई। बंगलूरू के सरजापुर रोड में घरों का औसत किराया सबसे ज्यादा 76 फीसदी बढ़ा है। 2021 के आखिर में 1000 वर्गफुट के 2 बीएचके घर का किराया 21,000 रुपये से बढ़कर 2024 के आखिर में 36,900 रुपये महीना हो गया। इसी तरह, एनसीआर के नोएडा सेक्टर 150 में किराया 66 फीसदी बढ़कर 16,000 रुपये से 26,600 रुपये हो गया। इस दौरान, पुणे के वाघोली में किराया 65 फीसदी बढ़ा है। बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में किराया बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है।

विकल्प 2 : घर किराये पर देना

राकेश ने दूसरा रास्ता बताया कि आप घर का एक हिस्सा किराये पर दे दें और खुद दूसरे हिस्से में रहें। मान लीजिए, आप दो कमरे किराये पर देते हैं, तो आपको 10-12 हजार रुपये महीने के मिल सकते हैं। इससे आय बढ़ेगी और घर भी आपके पास रहेगा।

विकल्प 3: रिवर्स मॉर्गेज

रिवर्स मॉर्गेज एक तरह का लोन है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मकान मालिकों को मिलता है। रिवर्स मॉर्गेज में आप अपना घर छोड़े बिना उसकी कीमत का कुछ हिस्सा बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं। बैंक आपको हर महीने एक निश्चित रकम या एकमुश्त राशि देगा और बदले में घर उनके नाम पर गिरवी रहेगा। आप जब तक जीवित हैं, घर में रह सकते हैं। आपके बाद, बैंक घर बेचकर अपना लोन वसूल करेगा।

रिवर्स मॉर्गेज लोन की शर्तें

- उम्र कम से कम 60 साल हो। अगर पति-पत्नी मिलकर आवेदन करते हैं, तो पत्नी की उम्र कम से कम 55 साल होनी चाहिए।
- लोन की अवधि 10 से 15 साल तक होती है। जिसे कुछ शर्तों के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ आवासीय संपत्ति पर लोन लिया जा सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इसके लिए पात्र नहीं है।
- लोन की रकम बैंक की तरफ से आवासीय संपत्ति के लिए तय बाजार मूल्य, उधार लेने वाले की उम्र और ब्याज दर पर निर्भर करेगी। एसबीआई की अधिकतम लोन सीमा दो करोड़ रुपये, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीमा एक करोड़ रुपये रखी है।
- गिरवी रखी जाने वाली आवासीय संपत्ति पर कोई बकाया लोन या अन्य वित्तीय देनदारी नहीं होनी चाहिए।

रिवर्स मॉर्गेज के फायदे

- कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति के निधन के बाद बैंक प्रॉपर्टी बेचकर पैसे वसूल कर लेगा। चाहें तो लोन चुकाकर बैंक से घर छुड़वा सकते हैं। कोई अतिरिक्त चार्ज या पेनल्टी नहीं लगती।
- रिवर्स मॉर्गेज से मिलने वाली रकम का उपयोग रोजमर्रा के खर्चों या मेडिकल बिलों के लिए किया जा सकता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(43) के तहत रिवर्स मॉर्गेज से मिली रकम को आय नहीं माना जाता। टैक्स नहीं देना पड़ता।

अपनी जरूरत के हिसाब से लें फैसले

फिनकार्ट के फाउंडर तनवीर आलम बताते हैं कि हर व्यक्ति की वित्तीय जरूरतें अलग-अलग हैं। अपनी वित्तीय जरूरतों के आधार पर फैसला करें। अगर आपके पास नियमित आय का कोई जरिया नहीं है। साथ ही सिर्फ अपने जीने तक घर में रहना चाहते हैं, तो रिवर्स मॉर्गेज बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन ब्याज दरों और शर्तों की जांच करें। अगर आपके पास नियमित आय का साधन है और एकमुश्त बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, तो घर किराये पर चढ़ाना अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें घर आपके पास ही रहेगा और अतिरिक्त आय से आप इलाज के खर्च मैनेज कर पाएंगे। यदि आपको तुरंत बड़ी रकम चाहिए, तो घर बेचना ठीक हो सकता है, लेकिन रकम को सावधानी से निवेश करें।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 102 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊंचाई पर सेवा क्षेत्र

एक निजी सर्वेक्षण के मुताबिक, मजबूत मांग के कारण अगस्त में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी, जिससे कीमतों में भी एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे तेज वृद्धि हुई. यह मांग में पर्याप्त सुधार के बीच नये ऑर्डर एवं उत्पादन में तेज वृद्धि से प्रेरित रही. सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती को प्रतिबिंबित करता है, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बावजूद अगस्त में तेज गति से बढ़ा. नये ऑर्डर में बढ़ोतरी के कारण एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआइ जुलाई के 60.5 अंक से बढ़कर अगस्त में 62.9 पर पहुंच गया, जो जून, 2010 के बाद सबसे अधिक है, जबकि समग्र पीएमआइ 63.2 रहा, जो 17 साल में सबसे तेज विस्तार है. पीएमआइ-यानी क्रय प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर के अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार और 50 से कम का आशय संकुचन होता है. लगातार तीसरे महीने में सूचकांक 60 से ऊपर रहा, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में लचीली मांग को दर्शाता है. गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ही मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धि दर का आंकड़ा जारी हुआ, जो 7.8 फीसदी है, और जो पिछली पांच तिमाहियों में सर्वाधिक है. नया कारोबार, जो मांग का एक प्रमुख पैमाना है, जून, 2010 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ा. इसे मजबूत होती अंतरराष्ट्रीय मांग से समर्थन मिला तथा निर्यात ऑर्डरों में 14 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गयी. मजबूत मांग ने कंपनियों की बढ़ती लागत का बोझ ग्राहकों पर ज्यादा आक्रामक तरीके से डाला. तथ्य बताते हैं कि इनपुट लागत सबसे तेज गति से बढ़ी. कीमतों के मोर्चे पर मुद्रास्फीति की दर नौ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी, तो इस बीच मांग में उछाल ने जुलाई, 2012 के बाद से उत्पादन शुल्क में सबसे तेज वृद्धि को संभव बनाया. कीमतों पर बढ़ते दबाव का मतलब यह भी है कि जो मुद्रास्फीति जुलाई में आठ साल के निम्नतम स्तर पर चली गयी थी, आने वाले दिनों में उसमें तेजी आ सकती है. अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाये जाने के कारण अगली तिमाहियों में वृद्धि दर में कमी आने की आशंका तो है ही. इसके अलावा मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका के कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर असर पड़ सकता है.

सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 15 साल की ऊंचाई पर पहुंच गयी. सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती को प्रतिबिंबित करता है, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बावजूद अगस्त में तेज गति से बढ़ा. है.

जीएसटी सुधार से आम आदमी को राहत

मधुरेन्द्र सिन्हा
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ
madhurendra.sinha6@gmail.com

आयकर में भारी छूट के बाद जीएसटी में बड़ी राहत न केवल महंगाई को नियंत्रित करेगी, बल्कि मध्यवर्ग की खपत की क्षमता को बढ़ावा देगी. अब रोजमर्रा के सामान, खाने-पीने की वस्तुओं, कारों, ट्रकों, सीमेंट जैसी चीजों पर टैक्स या तो खत्म कर दिया गया है या घटा दिया गया है. इससे ग्राहकों खासकर मध्यवर्ग को काफी फायदा होने वाला है. इस समय अर्थव्यवस्था को एक एक बूस्टर की जरूरत थी, जो उसे मिल गया है.

आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा कर ही दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में जनता को आश्वस्त किया था कि जीएसटी की दरें घटायी जायेंगी, जो उनके लिए दिवाली का उपहार होगा. वह अपनी बात पर खरे उतरे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी बात मानते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दर में भारी कटौती की घोषणा कर दी. यह आसान काम नहीं था और न ही पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में था, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं. उनमें से कई इस तरह की कटौतियों का विरोध कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि इससे उनके राजस्व पर बुरा असर पड़ेगा. इसलिए उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन भाजपा तथा एनडीए के मुख्यमंत्रियों के समर्थन से यह संभव हो गया. विपक्ष के वित्त मंत्री अब भी इस फैसले के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तो कहा कि इससे 47,700 करोड़ रुपये का धक्का लगेगा. वैसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीमा पर टैक्स हटाने का स्वागत किया और इसे अपनी पार्टी की नैतिक जीत बताया. दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा की तरह हमलावर रही तथा उसने इस घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठाये. उसकी तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस आठ साल से टैक्स घटाने की मांग कर रही थी. उन्होंने पूछा कि क्या जीएसटी की दरों में कटौती सुस्त बिकास को लेकर की गई है? या फिर बढ़ते हुए घरेलू कर्ज को लेकर? या घरेलू बचत में गिरावट के कारण? जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि जीएसटी सुधार का ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि हम इस पर डेढ़ साल से काम कर रहे थे. इस पर चूंकि काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब राजनीति की गुंजाइश नहीं है.

जाहिर है, जीएसटी की दरों में कटौती अब सच्चाई है. जीएसटी काउंसिल ने व्यापक सुधारों के तहत पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय टैक्स संरचना को मंजूरी दे दी. यह व्यवस्था आगामी 22 सितंबर से लागू होगी. परिषद के फैसलों के अनुसार अब रोजमर्रा के सामान, खाने-पीने की वस्तुओं, कारों, ट्रकों, सीमेंट जैसी चीजों पर टैक्स या तो खत्म कर दिया गया है या घटा दिया गया है. इससे ग्राहकों खासकर मध्यवर्ग को काफी फायदा होने वाला है.

कम टैक्स देने से वे कहीं ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे. सीमेंट पर टैक्स घटने से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आयेगी. इससे सर्विस सेक्टर को भी सहारा मिलेगा, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटाकर जीएसटी परिषद ने बड़ा कदम उठाया है. इसी तरह स्वास्थ्य बीमा पर 18 फीसदी के भारी-भरकम टैक्स को शून्य पर ले जाने से जनता को तो फायदा होगा ही, बीमा क्षेत्र को भी लाभ होगा. इससे इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी क्योंकि भारत में अब भी 30 फीसदी लोगों के पास ही बीमा है. शेष लोग किसी भी तरह के सुरक्षा कवच से वंचित हैं. ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ऐसे क्षेत्र हैं, जो बड़ी तादाद में रोजगार देते हैं और इन पर टैक्स घटाकर इन्हें प्रोत्साहित किया गया है. इससे पर्यटन और बढ़ेगा तथा सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी वृद्धि होगी. प्रीपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं पर टैक्स की दर घटने से कम आय वाले लोगों को राहत मिलेगी, तो इंटरनेट और डीटीएच की दरें घटने से युवा वर्ग को राहत होगी. यानी समाज के हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गयी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से मुद्रास्फीति की दर में 1.1 फीसदी की कमी आयेगी. जीएसटी की दरों में कटौती के फैसले का स्वागत शेयर बाजार ने किया. निवेशक भी इस फैसले से खुश हैं. दरअसल बाजार में मांग की कमी दिख रही थी और यह देखते हुए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है, यह कदम उत्साहवर्धक है. दरअसल इस समय अर्थव्यवस्था को एक एक बूस्टर की जरूरत थी, जो उसे मिल गया है. इससे खरीदारी बढ़ेगी और उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा, जो अंततः रोजगार बढ़ायेगा. इससे अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और जीडीपी विकास की दर ऊंची रहेगी, जो इस समय कुलांचे भर रही है, लेकिन जिस पर ट्रंप के टैरिफ का खतरा मडरा रहा है. आयकर में भारी छूट के बाद जीएसटी में बड़ी राहत न केवल महंगाई को नियंत्रित करेगी, बल्कि मध्यवर्ग की खपत की क्षमता को बढ़ावा देगी. लोकतंत्र में टैक्स वसूली ही सब कुछ नहीं है, टैक्स में सुधार करना और उसे जनता के मनमाफिक बनाना भी जरूरी है. जीएसटी काउंसिल ने यह बड़ा कदम उठाकर आर्थिक सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी है.

पिछले कुछ समय से जीएसटी में सुधार की बहुत मांग की जा रही थी और पक्ष तथा विपक्ष के सांसद भी मुखर हो रहे थे. दरअसल कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरों में विसंगति थी, तो कुछ में अधिकता थी. जैसे, दो तरह के जो सामान मिलकर एक उत्पाद होते हैं, उन पर अलग-अलग टैक्स दरें हैं, जो कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण है. जैसे, रेस्तरां में रोटी पर कम टैक्स है, तो परांठे पर ज्यादा. बिना एसी वाले रेस्तरां के लिए अलग दर है, तो एसी वाले के लिए अलग. खुले सामान पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पैकेट में आते ही उस पर टैक्स लगेगा. ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जो जीएसटी की विसंगतियों के बारे में बताते हैं. लेकिन अब नयी घोषणा के बाद सभी तरह की विसंगतियां खत्म हो गयी हैं. जीएसटी के जरिये कर संग्रह का जो लक्ष्य रखा गया था, वह काफी हद तक पूरा हो गया है. पिछले पांच साल में जीएसटी वसूली दोगुनी हो चुकी है. वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी वसूली 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गयी है, जो 9.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. यह भी एक कारण है कि सरकार टैक्स में कमी करने को तैयार हो गयी. अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियां, कारोबारी, दुकानदार, रेस्तरां मालिक टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचायें. पिछली बार यह देखा गया था कि इसका फायदा खुद कारोबारी अपने सामान या सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर हड़प लेते हैं. उम्मीद करनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

बच्चों में हिंसक भावनाओं का बढ़ना चिंताजनक

डॉ. ऋतु सारस्वत
समाजशास्त्री
drritusarswat ajm@gmail.com

माता-पिता अथवा परिवार के सदस्यों से प्राप्त स्नेह बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. जिन बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और हिंसक व्यवहार होता है, वे अक्सर हिंसक हो जाते हैं. जिन बच्चों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें अक्सर रिश्ते बनाने तथा दूसरों की परवाह करने में कठिनाई होती है.

हाल ही में अहमदाबाद के खोखरा-मणिनगर में स्थित सेवेंथ डे स्कूल में दसवीं कक्षा के छात्र की पेपर कटर से हत्या उसके सहपाठी द्वारा किये जाने का मामला सामने आया है. ठीक इसी तरह गाजीपुर जिले में स्कूल कैंपस के अंदर छात्र पर हमले की घटना सामने आई है. दस साल पहले 31 दिसंबर, 2015 को भी ऐसी ही सनसनीखेज वारदात हुई थी, जब आठवीं कक्षा के छात्र ने सहपाठी को गोली मार दी थी. निरंतर बढ़ती ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं. बच्चों का यह आक्रामक एवं हिंसक व्यवहार एकाएक उत्पन्न नहीं हो रहा है.

एक बच्चा माता-पिता के मार्गदर्शन में समाज और रिश्तों के बारे में सीखता है. जिन घरों में वयस्कों का व्यवहार भ्रमित करने वाला और भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है और जहां अभिव्यक्ति और संचार की स्थिति खराब होती है, वहां अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में समस्याएं होती हैं. घर में हिंसक व्यवहार और मीडिया व मनोरंजन में हिंसा को सहन करना बच्चे के इस विश्वास को बढ़ावा दे सकता है कि रोमांच की तलाश और हिंसा समस्याओं को हल करने के तरीके हैं. भावनात्मक आघात बच्चे की भावनात्मक शैली पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो उनके रिश्तों और दुनिया को देखने के उनके तरीके को गहराई से प्रभावित करता है. शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक शोषण बच्चे की सुरक्षा की बुनियादी भावना को नष्ट कर देते हैं. जिन बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और हिंसक व्यवहार होता है, वे अक्सर हिंसक हो जाते हैं. जिन बच्चों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें अक्सर रिश्ते बनाने और दूसरों की परवाह करने में कठिनाई होती है. छोटे बच्चों द्वारा की जाने वाली ज्यादातर हत्याएं योजनाबद्ध नहीं होतीं; बल्कि, वे क्रोध, हताशा या पारस्परिक संघर्ष के कारण होती हैं. किसी भी बच्चे के सकारात्मक विकास के लिए संवेदनशील और प्यार भरे माहौल की आवश्यकता होती है, जहां उसे सुरक्षित होने का भाव प्राप्त हो. और जब बच्चे स्वस्थ विकास के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण आधार स्नेह और सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं, तब वे भावनात्मक, व्यावहारिक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं की शृंखला खड़ी कर देते हैं. ऐसे बच्चे अक्सर आक्रामक, अनियंत्रित और विकृत व्यवहार करते हैं, जो असामाजिक व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है.

किशोरावस्था से पहले ही ये बच्चे विवेक की कमी, दूसरों की कीमत पर आत्म-संतुष्टि, जिम्मेदारी की कमी, बेईमानी तथा परिवार व समाज के नियमों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करते हैं. जिन किशोरों ने जीवन के शुरुआती दिनों में लगाव संबंधी कठिनाइयों का अनुभव किया है, उनके हिंसक अपराध करने की आशंका तीन गुना अधिक होती है. जीवन के महत्वपूर्ण शुरुआती तीन वर्षों के दौरान लगाव में खलल पड़ने से 'स्नेहहीन मनोरोग' हो सकता है, जिससे सार्थक, भावनात्मक संबंध बनाने में असमर्थता, लगातार क्रोध, आवेगों पर नियंत्रण की कमी और पश्चाताप की कमी जैसे विकार स्वाभाविक रूप से बच्चों के जीवन में स्थान बना लेते हैं. इन विचलित करने वाले विकारों ने आज के युवाओं द्वारा किये जा रहे अपराधों को और अधिक हिंसक तथा 'हृदयहीन' बना दिया है. दरअसल माता-पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्यों से प्राप्त सुरक्षित लगाव बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. आज जब जीवन की आपाधापी में बच्चों की भावनाओं, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो वे किशोरावस्था तक पहुंचते-पहुंचते भावना शून्य हो जाते हैं. दुनिया भर के शोध यह स्थापित करते हैं कि बालपन में मिली स्नेह और सुरक्षा की भावना बच्चों को गंभीर समस्याओं से बचाती है. इसके विपरीत जो बच्चे परिवार और समाज के स्नेह से वंचित रह जाते हैं, उनमें संवेदनशीलता और सहानुभूति का अभाव होता है. एक और महत्वपूर्ण बात जो पिछले दशकों में समाज में हर ओर व्याप्त है, वह है जीतने की प्रबल भावना. येन- केन-प्रकारेण यह भाव सही और गलत के भाव से परे सिर्फ प्रभुत्व और जीत के भाव के साथ धीरे-धीरे इतना प्रबल होता चला जाता है कि हिंसक व्यवहार सामान्य-सा प्रतीत होने लगता है. गलत और सही के अंतर का बोध कराना सर्वप्रथम माता-पिता का दायित्व है.

इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल उन माता-पिता का वीडियो है, जहां वे अपने छोटे बच्चों को सहपाठी को मारने पर न केवल समझाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि ऐसा करना गलत है. वे यह भी समझाते हैं कि किसी को चोट पहुंचाना अच्छा बच्चा होने की निशानी नहीं है. माता-पिता का यह प्रयास उस बच्चे के भीतर आक्रामकता के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न करेगा. हिंसक प्रवृत्ति जिस क्षण जन्म लेती है, उसी पल उसका कृत्य किसी न किसी रूप में सामने आता है. ठीक उसी समय अगर उसे रोक दिया जाये, तो भविष्य में अहमदाबाद, नोएडा, मणिनगर और देश के दूसरे क्षेत्रों में बच्चों द्वारा सहपाठियों व दोस्तों के साथ किये गये घोर हिंसक व्यवहार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से प्रभावित हो सकता है बच्चों का विकास

काफी रिसर्च और अध्ययन के बावजूद अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बच्चों के लिए कितनी स्क्रीन टाइम सुरक्षित है. इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मानक भी नहीं है. जैसे हर बच्चा अलग होता है, वैसे ही उनकी जरूरतें भी अलग होती हैं. जब तक विज्ञान सही राय देने के लिए पर्याप्त डाटा जुटाता है, तब तक तकनीक और समाज कई कदम आगे बढ़ चुका होता है. ऐसे में डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, नशा विशेषज्ञ और मीडिया शिक्षा से जुड़े लोग कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सहमत हैं. यह सिद्धांत बच्चों की उम्र और उनके विकास के चरणों से जुड़ा है तथा 'दुर्घटना से सावधानी बेहतर है' वाले नियम पर चलता है. जर्मनी में बच्चों के लिए एक ही नारा है, 'तीन साल तक स्क्रीन से दूरी है जरूरी.' बच्चों के लिए मीडिया गाइड लाइन बनाने वाली बाल रोग विशेषज्ञ, उलरीके गैसर कहती हैं कि इस उम्र में बच्चों को स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं होती है. विशेषज्ञों की चिंता यह है कि स्क्रीन पर बिताया गया समय बच्चों के असली विकास का समय छीन लेता है, यानी वह समय जिसमें उन्हें अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना चाहिए, लोगों से मिलना-जुलना और सामाजिक अनुभव लेना चाहिए था. हाल में हुए शोध बताते हैं कि स्क्रीन के सामने बिताये गये हर एक मिनट में बच्चे अपने माता-पिता के मुकाबले औसतन छह शब्द कम सुनते हैं. लंबे समय में यह बड़ी कमी पैदा कर देती है. बच्चे जितना ज्यादा समय स्क्रीन के सामने अकेले बैठेंगे, उनका भाषा कौशल बाद में उतना ही कमजोर हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करने से बच्चों की भाषा, ध्यान, सामाजिक व्यवहार और हाथ-पैरों की बारीक गतिविधियों में सुधार देखा जा सकता है. बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते, तब तक उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने आसपास की दुनिया को देखें, चीजों को महसूस करें, जगह को समझें और दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ाएं.

–आना कार्टहाउज

Deutsche Welle

शिक्षक दिवस पर विशेष

शिक्षक की पहचान को सबसे ऊपर रखते थे डॉ राधाकृष्णन

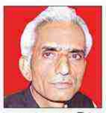

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

वर्ष 1888 में पांच सितंबर को यानी आज के ही दिन जन्मे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सुविदित है कि उनको अपने शिक्षक होने का इतना स्वाभिमान था कि वह उससे जुड़ी अपनी पहचान को राष्ट्रपति, दार्शनिक और राजनयिक समेत दूसरी सारी पहचानों से ऊपर रखते थे. इसीलिए उनके राष्ट्रपति रहते उनके शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि वे उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनायें. तभी से हर पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा. आज भी इस दिन शिक्षकों की समस्याओं के निवारण पर विचार-विमर्श और उनके योगदानों का स्मरण किया जाता है.

राधाकृष्णन ने 21 वर्ष की अल्पायु में ही दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली थी. तदुपरांत मैसूर प्रेसीडेंसी कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं. शिक्षक के रूप में उनकी मान्यता थी कि आनंद और खुशी का जीवन ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के आधार पर ही संभव है और तभी, जब मानवता को उसकी उन नैतिक जड़ों की ओर वापस ले जाया जाये, जहां से व्यवस्था और स्वतंत्रता, दोनों उत्पन्न होती हैं.

लेकिन वह शिक्षकीय पृष्ठभूमि से आये इकलौते राष्ट्रपति नहीं थे. उनसे पहले और उनके बाद राष्ट्रपति का पद संभालने वाली कई विभूतियां अपने वक्त में शिक्षक थीं. पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद भी पहले शिक्षक रहे थे. उनकी मेधा तो ऐसी थी कि एक परीक्षा में उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले ने उस पर टिप्पणी लिख दी थी कि 'एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर'. अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित करने के बाद उन्होंने बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर और बाद में प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं. जब वह कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तब कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने शिक्षण कार्य किया था.

डॉ राधाकृष्णन के बाद पदासीन हुए तीसरे राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन भी शिक्षाविद् और शिक्षक थे. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में तो कार्य किया ही था, उन दिनों राष्ट्रवाद के प्रमुख केंद्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापकों में भी वह एक थे, जो आजादी की लड़ाई के दौरान संकीर्ण धार्मिक/सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकारों के निशाने पर रहता था. वहां के कुलपति रहते हुए उन्होंने छात्रों को साफ-सफाई व अनुशासन की सीख देने के अभिनव प्रयोगों की कई मिसालें बनायी थीं. एक बार जब उनके कई बार के आदेश के बावजूद छात्रों ने अनुशासित रहने और साफ-सुथरे कपड़े व चमकते हुए जूते पहनकर परिसर व कक्षाओं में आने में कोताही बरती, तो वह खुद गेट पर ब्रश व पॉलिश लेकर बैठ गये तथा उधर से गुजरने वाले छात्रों के जूते पॉलिश करने लगे. लज्जित छात्रों ने न सिर्फ उनसे माफी मांगी, बल्कि उनके आदेश पर अमल करना भी आरंभ कर दिया.

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(05 सितंबर, 1888 – 17 अप्रैल, 1975)

नवें राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा भी राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने से पहले अकादमिक क्षेत्र में सक्रिय थे और राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले भोपाल विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर हुआ करते थे. उनके बाद राष्ट्रपति बने केआर नारायणन ने भी राष्ट्रपति और राजनयिक बनने से पहले कई वर्षों तक शिक्षण किया था. स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने कई वर्ष इस क्षेत्र को दिये थे. उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि भी उनके करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा थी. मिसाइलमैन कहलाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भी एक समय प्रोफेसर रहे थे. वर्ष 2001 में वह चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन के प्रोफेसर हुआ करते थे. राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद वह फिर शिक्षण व लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हो गये थे. उन्होंने कई संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर, मानद फेलो और अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था. यही नहीं, उन्होंने युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु 'व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट' भी शुरू किया था. वह युवाओं को बताते थे कि सपने वे नहीं होते, जो हम सोते हुए देखते हैं. सपने दरअसल वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते.

जबकि चुनौतियां ऐसी चीज नहीं हैं, जिनसे लड़ा जाये. वे ईंटों की तरह हैं, जो हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं तथा सफल क्षणों को और मधुर बनाती हैं. उनके अनुसार मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सफलता का आनंद लेने के लिए आवश्यक हैं. वह कहते थे कि यदि आप अपना लक्ष्य बनाकर मेहनत करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी. तेरहवें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शिक्षक के रूप में ही अपना करियर आरंभ किया था. कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्रियां हासिल करने के बाद वह कलकत्ते के ही एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे.

आपके पत्र

निर्वाचन आयोग पर उठ रहे सवाल

निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. देश में निष्पक्ष चुनाव कराना इसका दायित्व है. अब तक के इतिहास में चुनाव आयोग की कार्यशैली निष्पक्ष व ईमानदार की रही है. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग के कार्यों पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं. इनमें सबसे बड़ा मामला वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का है. इसको लेकर चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे आम वोटरों में विश्वास बना रहे कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. वोट चोरी के सवाल पर भी आयोग को डाटा को सार्वजनिक कर देना चाहिए.

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

दूर हो आर्थिक विकास की असमानता

भारत में श्रमबल की भागीदारी लगभग 46 प्रतिशत है, जो देश के लिए चिंता का विषय है. भारत में आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई है. उद्योगों से लाभ भी बढ़ा है. लेकिन रोजगार के अवसर में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है. यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है, जिससे रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई हैं. इसका कारण विशाल जनसंख्या है. इससे रोजगार सृजन में परेशानी हो रही है. इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कौशल विकास पर जोर देना होगा. इससे आर्थिक असमानता कम होगी.

प्रसिद्ध यादव, पटना

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हर खबर पर पैनी नजर
नई सोच एक्सप्रेस
(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

अतिरिक्त टैरिफ भारतीय निर्यात प्रभावित

भारत पर अतिरिक्त 25 फीसद अमेरिकी शुल्क बुधवार को लागू हो गया। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है, और इसी के साथ भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ कर 50 फीसद हो गया। माना जा रहा है कि 48 अरब डॉलर से ज्यादा का अमेरिका को किया जाने वाला भारतीय निर्यात इससे प्रभावित होगा। भारत के वस्त्र, परिधान, रत्न-आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते-चप्पल, पशु उत्पाद, रसायन, विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी उद्योग पर सर्वाधिक असर पड़ेगा। भारत के अलावा ब्राजील एकमात्र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार है, जिसे 50 फीसद आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली और कमजोर वैश्विक रुझान से निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ी है। सर्राफा बाजार में भी तेजी का रुझान बन गया है। दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश चाहता है, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को बहाना बना कर यह अतिरिक्त शुल्क थोपा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त शुल्क थोप कर भारत पर कूटनीतिक और व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि कृषि और डेयरी क्षेत्र में भारत कोई समझौता नहीं करेगा क्योंकि हमारे लिए किसानों के हित सवरेपरि हैं। भारत, अमेरिका को 79 अरब डॉलर का कुल निर्यात करता है, इसमें से 45 अरब डॉलर के भारतीय उत्पाद अमेरिकी शुल्क के दायर में आ जाएंगे यानी अमेरिका को लगभग 45 फीसद भारतीय निर्यात अमेरिकी टैरिफ के दायर से बाहर होगा, लेकिन 55 फीसद भारतीय निर्यात प्रभावित होना तय है। दवा क्षेत्र को अमेरिका ने अभी नहीं छुआ है, लेकिन धमकी जरूर दे दी है कि भारतीय दवाओं पर भी 150 फीसद शुल्क लगाया जा सकता है। बेशक, अमेरिका से निर्यात मोर्चे पर बड़ी चुनौती दरपेश है, लेकिन भारत के सामने तमाम विकल्प हैं। भारत को अमेरिका से बाहर नये बाजार तलाशने होंगे। जरूरी है कि रूस के साथ वह नई रणनीति के साथ बढ़े। भारत पलटवार की भी सोच सकता है। चुनिंदा वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने की स्थिति में है। अपने प्रभावित क्षेत्रों को घरेलू स्तर पर सब्सिडी देकर प्रोत्साहन देकर मजबूत स्थिति में बनाए रख सकता है।

शिक्षक का ध्येय : मूल्य और आदर्शों से संपन्न पीढ़ी

आरती कुमारी

शिक्षक ही सभ्यता और संस्कृति के असली शिल्पी होते हैं। विज्ञान, तकनीक और राजनीति चाहे जितनी प्रगति कर लें, यदि शिक्षा और शिक्षक दिशा न दें तो मानवता दिशाहीन हो जाती है। इसी कारण 5 सितम्बर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा आरंभ हुई। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को होता है, जो भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज में शिक्षक के महत्व, उनके योगदान और मार्गदर्शक भूमिका को सम्मान देना है। यह अवसर विद्यार्थियों और समाज को याद दिलाता है कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं बल्कि आदर्श, प्रेरक और चरित्र-निर्माता भी होते हैं। आज जबकि नया भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत निर्मित हो रहा है, तब शिक्षकों की भूमिका अधिक प्रासंगिक हो गयी है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितम्बर 1888 को आंध्र प्रदेश के तिरुत्तनी में हुआ था। वे एक महान दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दर्शनशास्त्र पढ़ाया। उनकी पुस्तकें 'इंडियन फिलोशॉफी' 'दी हिन्दू व्यूह ऑफ लाइफ' और 'दी आइडलिस्ट ऑफ लाइफ' विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुईं। वे 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उन्होंने विनम्रता से कहा कि यदि आप लोग मेरे जन्मदिन को विशेष रूप से मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से ही 5 सितम्बर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉ. राधाकृष्णन का संदेश यही था कि शिक्षक समाज की रीढ़ हैं और उनका सम्मान करना ही वास्तविक राष्ट्र निर्माण है। निश्चित ही शिक्षकों का यह सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य का घोषणापत्र है। यह दिवस राष्ट्र को शिक्षा, विज्ञान, शांति एवं प्रगति का सन्देश देने के लिए कृत संकल्पित है। भारत का इतिहास शिक्षा की गौरवमयी परंपरा से जुड़ा है। प्राचीन समय से भारत शिक्षा का बड़ा केन्द्र रहा है और उसने संसार में जगतगुरु की भूमिका निभाई है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत को जगतगुरु का दर्जा दिलाया। महान् दार्शनिक आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा था-"व्यक्तित्व-निर्माण का कार्य अत्यन्त कठिन है और यह केवल निःस्वार्थी एवं जागरूक शिक्षक ही कर सकता है।" यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। प्राचीन भारतीय दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य 'सा विद्या या विमुक्तये' रहा है, अर्थात् शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह 'सा विद्या या नियुक्तये' बन गई है अर्थात् शिक्षा वही है जो नौकरी दिलाए। यही कारण है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने के बावजूद समाज में अपराध और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है-"एक स्कूल खुलेगा तो सौ जेलें बंद होंगी।" परन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया है। इसमें केवल क्या पढ़ना है पर ही नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है, इस पर भी जोर दिया गया है। आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, उद्यमशीलता और नैतिकता को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है। लेकिन इन सभी का केन्द्रबिंदु शिक्षक ही है। यदि शिक्षक प्रेरणाहीन, निरुत्साहित या असंवेदनशील होंगे तो कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। शिक्षा केवल किताबों और पाठ्यक्रम से नहीं, बल्कि शिक्षक की जीवंत उपस्थिति से सार्थक होती है। पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था-"अगर कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त है और सुंदर दिमागों का राष्ट्र बन गया है, तो उसके लिए तीन प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार होंगे-पिता, माता और शिक्षक।" यह कथन शिक्षक के महत्व को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करता है। भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हमारे शिक्षक नई पीढ़ी को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि चरित्रवान भी बनाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। नेल्सन मंडेला ने कहा था-"शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया बदली जा सकती है।" युद्ध और आतंक के बीज मानव मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, इसलिए बचपन से ही शांति और सह-अस्तित्व के बीज बोने होंगे। बच्चों को अपने देश से प्रेम के साथ विश्व-प्रेम यानी मानवता का पाठ सिखाना होगा, तभी दुनिया से युद्ध, हिंसा, आतंक का खात्मा होगा। भारतीय संस्कृति का "वसुधैव कुटुम्बकम्" मूल मंत्र इसमें सहायक बन सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का स्वरूप धीरे-धीरे मिशन से व्यवसाय की ओर झुकता जा रहा है। ज्ञान की बोली लग रही है, शिक्षक और छात्र के संबंधों में अविश्वास और हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने और उसे मानवीय मूल्यों से जोड़ने की जिम्मेदारी सबसे पहले शिक्षकों पर ही आती है। आज आवश्यकता केवल शिक्षा क्रांति की नहीं, बल्कि शिक्षक क्रांति की भी है। अच्छे पाठ्यक्रम, नई तकनीक और आधुनिक संस्थानों की व्यवस्था तभी सार्थक है जब उनके केंद्र में ऐसे शिक्षक हों, जो छात्रों को प्रेरणा दें, जो उनके सर्वांगीण विकास का माध्यम बनें। खेत, बीज और उपकरण के रहते हुए किसान न हो तो सब बेकार है। उसी प्रकार, विद्यालय, पाठ्यक्रम और तकनीक के रहते हुए यदि शिक्षक नहीं हैं तो सब निरर्थक है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था-"सर्वांगीण विकास का अर्थ है हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान।" शिक्षक ही ऐसे व्यक्तित्व गढ़ते हैं। शिक्षा के बदलते अर्थ ने समाज की मानसिकता को बदल दिया है। यही कारण है कि आज समाज में लोग केवल शिक्षित होना चाहते हैं, सुशिक्षित यानी गुण-सम्पन्न नहीं बनना चाहते। मानो उनका लक्ष्य केवल बौद्धिक विकास ही है। इन स्थितियों से शिक्षकों को बाहर निकलने में नई शिक्षा नीति से बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को केवल साक्षर बनाना नहीं, बल्कि उनमें सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास करना है। 2030 तक स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य इसी दृष्टि से रखा गया है। किंतु संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और बदलते सामाजिक परिवेश की चुनौतियां इस दिशा में बड़ी बाधाएं हैं। इसके बावजूद भारत में शिक्षा की परंपरा इतनी प्राचीन और समृद्ध रही है कि विदेशी विद्वान भी इसकी प्रशंसा करते आए हैं। एफ. डब्ल्यू. टॉमस ने लिखा है-"भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो।" वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका भले ही बदली हो, लेकिन उनका महत्व एवं व्यक्तित्व-निर्माण की जिम्मेदारी अधिक प्रासंगिक हुई है। क्योंकि सर्वतोमुखी योग्यता की अभिवृद्धि के बिना युग के साथ चलना और अपने आपको टिकाए रखना अत्यंत कठिन होता है। फौलाद-सा संकल्प और सब कुछ करने का सामर्थ्य ही व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। शिक्षक ही ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं। आर्थिक आपाधापी, आतंक, युद्ध एवं हिंसा के आधुनिक युग में शिक्षकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे छात्रों को न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि उन्हें जीवन में जरूरी कौशल भी सिखाते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सहयोग करते हुए उन्हें नैतिक मूल्यों एवं शांतिपूर्ण जीवन के बारे में भी समझाते हैं जो एक अच्छे नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षक को ऐसे छात्र तैयार करने होंगे जो वैज्ञानिक-आध्यात्मिक हो, जिनमें बौद्धिकता एवं भावनात्मकता के साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास हो। शिक्षक दिवस 2025 का वास्तविक संदेश यही होना चाहिए कि शिक्षक केवल पेशेवर नहीं, बल्कि समाज की आत्मा के निर्माता हैं। भारत यदि पुनः विश्वगुरु बनना चाहता है तो उसे केवल नई शिक्षा नीति ही नहीं, बल्कि निष्ठावान और दूरदर्शी शिक्षकों की फौज तैयार करनी होगी।

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' - बिहार की बदलती राजनीति की दस्तक

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

बिहार की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद तथा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद। कांग्रेस दशकों से हाशिए पर पड़ी थी और चुनावी समीकरण में उसकी भूमिका सीमित होकर रह गयी थी। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' ने न केवल कांग्रेस को फिर से प्रासंगिक बनाया है, बल्कि विपक्षी राजनीति को भी नई दिशा दी है। यह यात्रा जनता से सीधा संवाद बनाकर उभरी है और बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों की गवाही दे रही है। बिहार का राजनीतिक इतिहास सामाजिक न्याय, जातीय समीकरण और गठबंधनों के उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। लालू प्रसाद ने 90 के दशक में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति को केंद्र में रखा। नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास का नारा देकर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की। भाजपा ने अपने संगठन और कैडर के दम पर बिहार में स्थायी उपस्थिति दर्ज की। कांग्रेस, जो कभी राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी, धीरे-धीरे सिमटती चली गयी। लंबे समय से समीकरण यही था कि भाजपा-जदयू गठबंधन बनाम राजद। लेकिन इस बार समीकरण में तीसरा ध्रुव तेजी से उभर रहा है – कांग्रेस और राहुल गांधी की सक्रियता। राहुल गांधी की यह यात्रा केवल राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जनता से संवाद का एक अनोखा प्रयास है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और पलायन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। गांव और कस्बों की गलियों में पहुंचकर जनता की आवाज सुनना इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है। कार्यकर्ता स्तर पर कांग्रेस को ऊर्जा और मजबूती मिल रही है। जनता महसूस कर रही है कि कोई नेता उनकी आवाज को केवल चुनावी नारे तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि उसे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना रहा है। यह सवाल अब बार-बार उठ रहा है कि बिहार में विपक्ष का चेहरा कौन है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के भीतर बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाए। उनके भाषण धारदार होते हैं, लेकिन सीमित दायरे तक। राहुल गांधी ने मैदान में उतरकर मुद्दों को आंदोलन का रूप दिया। जनता से सीधे संवाद, पदयात्रा और सभाओं के माध्यम से उन्होंने विपक्ष को नई ऊर्जा दी। यानि तेजस्वी यादव की राजनीति कथनी तक सीमित है, जबकि राहुल गांधी की राजनीति करनी और आंदोलन तक पहुंच रही है। कांग्रेस का बिहार में लंबा इतिहास है। लेकिन 90 के दशक के बाद वह लगातार सिमटती चली गयी। सीटों का ग्राफ गिरता गया। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता गया। जनता ने कांग्रेस को विकल्प मानना छोड़ दिया। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने इस स्थिति को बदल दिया है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में सक्रियता लौट रही है। जनता से सीधा संवाद ने कांग्रेस को नई पहचान दी है। पार्टी केवल राजद की सहयोगी न रहकर, वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभर रही है। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है मुद्दों और अधिकारों की

राजनीति। राहुल गांधी ने चुनावी नारों की बजाय बुनियादी सवालों को केंद्र में रखा है, रोजगार और पलायन, किसानों की बदहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य, महंगाई और भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी। यानि राहुल गांधी की रणनीति है लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को असली मुद्दा बनाना। गांवों और कस्बों में सभाओं के दौरान जिस तरह युवाओं, महिलाओं और किसानों की भागीदारी बढ़ी है, वह संकेत देता है कि जनता पारंपरिक राजनीति से हटकर नए विकल्प की तलाश में है। लोग महसूस करने लगे हैं कि राहुल गांधी केवल नेता नहीं हैं, बल्कि जनता की आवाज को आंदोलन का रूप देने वाले नेता हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने दोहरा असर डाला है। एनडीए सरकार को सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। राजद को यह अहसास कराया कि विपक्ष का नेतृत्व केवल उनके हाथों में नहीं है। यह स्थिति राजद के लिए चुनौती है। कांग्रेस के उभार से विपक्ष की राजनीति में नई शक्ति संतुलन बन रहा है। जनता विपक्ष से केवल सत्ता पक्ष की आलोचना नहीं, बल्कि सड़क पर आंदोलन और ठोस पहल की उम्मीद करती है। इस कसौटी पर तेजस्वी यादव कमजोर पड़ते हैं। राहुल गांधी का तरीका जनता को ज्यादा आकर्षित करता है। राहुल की शैली अलग है, वे सुनते हैं, नोट करते हैं और फिर उन्हें राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाते हैं। यही उनकी ताकत है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस की सक्रियता वोट शेयर में बढ़ोतरी कर सकती है। राजद और जदयू-भाजपा गठबंधन दोनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। राहुल गांधी का चेहरा विपक्ष को नया भरोसा देता है। अगर यह रफ्तार जारी रही, तो कांग्रेस बिहार की राजनीति में फिर से मजबूत दावेदार बन सकती है। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसने उन्हें जनता से जोड़ने का काम किया। अब वोटर अधिकार यात्रा ने यह संदेश और मजबूत कर दिया है कि राहुल केवल संसद में बोलने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर संघर्ष करने वाले नेता हैं। आज की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस फिर से प्रासंगिक बन रही है। राहुल गांधी ने विपक्षी राजनीति को नया चेहरा दिया है। जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। यह यात्रा केवल कांग्रेस की वापसी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास है।

https://t.me/AllNewsPaper

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आप किसी काम को अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर लेंगें , जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आज आप जीवनसाथी के साथ घर के मुद्दों को लेकर कुछ बात कर सकते हैं , जिससे उसका समाधान निकलेगा। आज आप किसी भी फैसले को करने से पहले बड़ो की राय अवश्य जान लें।

वृष राशि - आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आपको व्यापार में बड़े लाभ की संभावना बन रही है। आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे आप योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पायेंगें। आज आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनेंगें और आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था व विश्वास मजबूत होगा।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा, इस बार आप कड़ी मेहनत से उसको सफल बनायेंगें। इस राशि की महिलाओं के लिए दिन अच्छा रहेगा, आज आप खुद के लिए समय निकालर अपनी सहेलियों के साथ इंजॉय करेंगी। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है, आप इसे हांथ से जाने न दें।

कर्क राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपकी सैलरी में इजाफा होगा, जिससे आर्थिक समस्या दूर होगी। आज किसी की मदद से आपके सरकारी काम बनते नजर आयेंगें। आज आप भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें, सोच - समझकर और बहुत जिम्मेदारी से काम करें। इस राशि के इंजिनियर आज किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर सकतें हैं।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक रहने वाला है। आज आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकतें हैं। आज आपको पूर्व में किये कार्यों का बढ़िया लाभ मिलेगा। आज आप किसी अच्छी कम्पनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकतें हैं, आपको जल्द ही ऑफर लेटर प्राप्त होगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और परिवार में खुशहाली आएगी।

कन्या राशि- आज का दिन आपके लिए बेहद खुशहाल रहने वाला है। आज आप अपने ऑफिसियल काम पूरे करने के लिए किसी मित्र की सहायता ले सकतें हैं। आपकी मुलाकात बचपन के किसी दोस्त से होगी, आपकी पुरानी यादें ताजा होंगी। आज आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगें, जिसमें आपको पारिवारिक सहयोग की प्राप्ति होगी।

तुला राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारिक लाभ होने के साथ - साथ आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगें तो इससे बच जायेंगें। जिन बातों में आपकी ज्यादा रुचि है, उन पर ध्यान देंगे तो आपको ख़ुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो भविष्य में आपके काम आएगा।

वृश्चिक राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक बना रहेगा। आज इस राशि के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति को धन लाभ कमाने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आज आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करें अन्यथा विरोधी इसका लाभ उठा सकतें हैं। आज आप माता - पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकतें हैं , जहाँ आपके मन को शांति प्राप्त होगी।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए मिला - जुला रहने वाला है। आज आपको पैतृक सम्पति का लाभ मिलने से ख़ुशी होगी। आज भाई के साथ किसी काम को लेकर आप बात कर सकतें हैं, जिसमें वो आपका पूरा सहयोग करेंगें। आज किसी काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें।

मकर राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप फैमली फंक्शन में शामिल होंगें, आपको देखकर सभी सदस्य खुश हो जायेंगें। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे 7 आज आपकी रूचि सामाजिक कार्यों में बनी रहेगी, आपके द्वारा किये गए कार्य दूसरों के जीवन में अच्छा बदलाव लेकर आयेंगें।

कुम्भ राशि- आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस राशि के विद्यार्थी अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही किसी एग्जाम को क्रैक कर लेंगें। नये काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिल सकता है, लेकिन मौके को हाथ से न जाने दें।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगें जो भविष्य में आपका लाभ करायेंगें। आज आप व्यर्थ की बातों से दूर रहें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

चिंताजनक - रोजाना पांच सौ लोग सड़क दुर्घटनाओं में गंवा रहे हैं जान!

मनोज कुमार अग्रवाल

देश में प्रतिदिन 474 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 'सड़क हादसे 2023' की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं।2024 और 2025 के आंकड़े और अधिक भयावह होने के आसार हैं। भारत में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर घंटे लगभग 55 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं जिनमें 20 लोगों की जान जाती है। 2023 में लगभग 4.80 लाख सड़क हादसे हुए जिनमें 1.72 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने युवाओं की मौतों पर चिंता व्यक्त की है जिनमें 18-45 वर्ष के 66.4% युवा शामिल हैं। भारत में जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या और गति बढ़ रही है उससे भी अधिक स्पीड से दुर्घटनाओं में अकाल मरने वालों की तादाद बढ़ी है। इससे देश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में कोई दिन ऐसा नहीं है जब देश की सड़कों पर दुर्घटनाओं में खून न बहा हो। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में कभी नहीं आई है, बल्कि साल दर साल इसमें इजाफा हो रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटनाएं, 2023 शीर्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर घंटे 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों ने वर्ष 2023 के दौरान कुल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाओं की सूचना दी है, जिनमें 1,72,890 लोगों की जान गई और 4,62,825 लोग घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में लगातार चौथे वर्ष तक सड़क दुर्घटना के शिकार ज्यादातर युवा थे। 18-45 पर्ष आयु वर्ग के चुना वयस्कों की संख्या 66.4 प्रतिशत है। राजस्थान की बात करे तो इस अवधि में 24 हजार 694 सड़क हादसों में 11 हजार 400 लोगों की भौतें हुई। भारत में सड़कों और हाईवे के साथ हादसों की रफ्तार भी धमने का नाम नहीं ले रही। देश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो नहीं जाता जब देश के किसी भाग में सड़क हादसा न होता हो। सड़क पर ट्रक पार्क करना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण हैं और लोग यातायात अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सड़के आतंकी हो गई है और हादसे थमने के नाम नहीं ले रहे है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 1,72,890 मौतों में से 40% से अधिक मौतें हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करने और नशे में वाहन चलाने के कारण हुई हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में मारे गए 54,568 दोपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिनमें 39,160 चालक और 15,408 यात्री शामिल थे. यह 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 31.6% था. इसी तरह, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन सवारों में 16,025 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें 8,441 चालक और 7,584 यात्री शामिल थे, जो वर्ष के दौरान दर्ज कुल मौतों का 9.3% हैं। देश में मोटर वाहन कानून 2019 लागू होने के बाद भले ही सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई हो मगर दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। सख्त कानून का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सड़क हादसों के शिकार 30 प्रतिशत लोगों की मौत जीवन रक्षक उपचार नहीं मिल पाने के कारण होती है। 2023 में सबसे ज्यादा सड़क हादसों में मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं. यहां 23,652 लोगों की सड़क हादसे में जान गई है, जो 2022 (22,595) और 2021 (21, 227) से अधिक है. सबसे कम मौतें अंडमान और निकोबार में दर्ज की गईं. यहां सिर्फ 24 लोगों की जान गई है. 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दिल्ली (1457), बेंगलुरु (915) और जयपुर (849) में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, जबकि अमृतसर, चंडीगढ़ और श्रीनगर में सबसे कम लोगों की जान गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दर्ज कुल 1,72,890 लोगों की मौत में से 63,112 (36.5 प्रतिशत) राष्ट्रीय राजमागों पर, 39,439 (22.5 प्रतिशत) राज्य राजमार्गों पर और 70,339 (40.7 प्रतिशत) अन्य सड़कों पर हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण है। यह अक्सर मानवीय भूल, सड़क के वातावरण और वाहनों को स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। वर्ष 2023 में, यातायात नियम उल्लंघन की श्रेणी में, तेज गति से गाड़ी चलाना एक प्रमुख दुर्घटना का कारण था, जिसमें मारे गए लोगों का 68.1 प्रतिशत हिस्सा था। सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहन श्रेणियों में, लगातार तीसरे वर्ष, वर्ष 2023 के दौरान कुल दुर्घटनाओं और मौतों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। कार, जीप और टैक्सियों सहित हल्के वाहन दूसरे स्थान पर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सड़क हादसों के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे देश में लोग जान हथेली पर लेकर चलते है। देश में सड़कों और हाईवे की संख्या बहुत तेजी से पड़ी है। इसी के साथ हादसों की रफ्तार भी थमने का नाम नहीं ले रही। सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है। इन सभी दुर्घटनाओं के पीछे शराब मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में जरुरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना और थकान आदि होना है। ऐसी स्थिति में हादसों में घायल होने वाले पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत पूरे भारत में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को कैशलेस इलाज करवाने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ित के सात दिन तक इलाज पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सुचित कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार पीड़ित के इलाज का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही सरकार ने हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट में आए मौतों के आंकड़े चिंतित करते हैं. भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन जमीन पर वास्तविक बदलाव लाने के लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है. हादसे के पीछे की एक वजह नियम को सही तरीके से पालन नहीं कराना भी है. उन्होंने कहा कि हमारे यहां नियमों को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है लेकिन उसको पालन कराने पर जोर नहीं दिया जा रहा. दूसरा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी कई हादसे हो रहे हैं. सड़कों पर लेन मार्किंग साफ नजर नहीं आती हैं, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, कई हाईवे पर मीडियन में गैप है, शार्प टर्न्स पर बोर्ड नहीं है, कई सारे एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट है जिस पर टकराकर लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य इस्तेमाल और जन जागरूकता अभियान चलाने पर भविष्य में स्थिति में सुधार हो सकता है।

टेक क्रांति की तरफ बढ़ते कदम

भारत ने टेक क्रांति की तरफ बढ़ते हुए पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित कर लिया है। इसरो की सेमीकंडक्टर लैब इस कामयाबी की साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट से शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है। उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है। आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। यहां तक कि छोटा-सा देश ताइवान दुनिया के लगभग साठ फीसदी से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर रहा है। जिसमें करीब नब्बे फीसदी उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। कोविड संकट के बाद आधुनिक तकनीक व उन्नत उपकरणों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर होड़ पैदा हो गई है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पचास फीसदी पूंजीगत सहायता दे रही है। वहीं राज्य सरकारें कुल परियोजना लागत का बीस फीसदी प्रोत्साहन दे रही हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है। साधारण शब्दों में कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरों का संजाल है। जो कंप्यूट करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है। उम्मीद है कि भारत का स्वेदशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पर तो होगा ही, नये रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा।

डिजिटल युग में शिक्षक की बदलती भूमिका

गणेश दत्त पाठक
(वरिष्ठ स्तंभकार)

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर विशेष

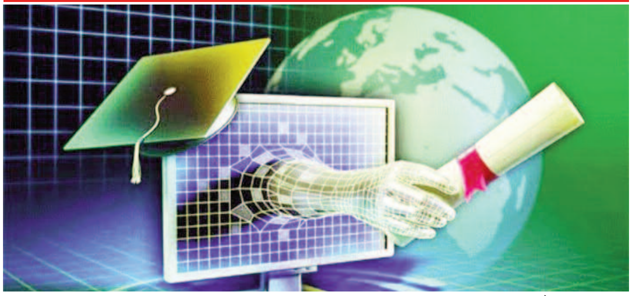

समय के साथ आ रहा तकनीकी बदलाव शिक्षक की बदलती भूमिका को भी कर रहा है रेखांकित, शिक्षक अब सिर्फ ज्ञान प्रदाता और चरित्र निमार्ता ही नहीं अपितु मार्गदर्शक, प्रेरक के तौर पर बढ़ी भूमिका, अभी की अनिवार्यता शिक्षकगण के नवाचारी बनने और छात्रों की सृजनात्मकता को बृहद स्तर पर प्रेरित करने की है।

समाज में सकारात्मकता का संचार करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान, नैतिक मूल्यों और कौशलों के साथ तैयार करते हैं, जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक और हितकारी रहता है। आज के डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में शिक्षक की भूमिका में और भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब शिक्षक का दायित्व महज परम्परागत तरीके से ज्ञान प्रदान और उन्हें चरित्रवान बनाना ही नहीं रहा अपितु आज के डिजिटल दौर के शिक्षक को प्रेरक, मार्गदर्शक के तौर पर भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है। आज के शिक्षकों को डिजिटल टूल्स और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर छात्रों को 21 वीं सदी के कौशलों के साथ तैयार करने की आवश्यकता भी है। डिजिटल युग में छात्रों के भटकाव और भ्रम के लिए तमाम अवसर आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आती है। आवश्यकता इस बात की भी है कि शिक्षक समय के साथ अपने को अपडेट करें और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को सहजता से अंगीकार भी करें। अभी की अनिवार्यता शिक्षक के नवाचारी बनने और छात्रों की सृजनात्मकता को बृहद स्तर पर प्रेरित करने की है।

भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो या अन्य सभ्यताओं की। शिक्षक को जीवन में रौशनी का संचार करने वाला माना जाता रहा है। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है, जो स्वयं जल कर अपने प्रकाश से शिष्यों के जीवन को आलोकित करता है। शिक्षकों का प्रारंभिक दायित्व ज्ञान और संस्कृतियों को पीढ़ियों तक पहुंचाना और छात्रों को नैतिक और बौद्धिक तौर पर विकसित करना होता है। वैसे शिक्षक का मुख्य दायित्व ज्ञान का प्रसार करना ही रहा है, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों में महारत हासिल हो सके। नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण और पुरातन संस्कृति का संरक्षण भी शिक्षक के ही दायित्व रहे हैं। शिक्षक परम्परागत तौर से छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखते रहे हैं ताकि छात्र अपनी पूरी क्षमता से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में वैसे भी कई प्रश्न उठते रहे हैं? आज के डिजिटल युग में तो शिक्षक की बदलती भूमिका को समझना एक अनिवार्य तथ्य हो चला है।

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आज के डिजिटल युग में छात्र स्वयं के स्तर पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। डिजिटल ओवरलोड और एडिक्शन, बढ़ता स्क्रीन टाइम, पर्याप्त डिजिटल बुनियादी संरचना का अभाव आदि चुनौतियां छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है। साथ ही साइबर अपराध मसलन फिशिंग, हैकिंग, मैलवेयर आदि डाटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर आतंकवाद जैसे खतरे भी छात्रों के समक्ष बड़ी चुनौतियों के तौर पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में उनके नैतिक विचलन, सांस्कृतिक पतन और कैरियर निर्माण से भटकाव की आशंकाएं ज्यादा उत्पन्न हो रही है। जब इन तथ्यों पर गौर करते हैं तो यह विदित होता है कि परिवार के साथ अभी शिक्षकों की भूमिका ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है। जहां गूगल पर तो भरपूर ज्ञान उपलब्ध है लेकिन उसको कैसे उपयोग करें, कितना उपयोग करें? आदि सवाल उठते दिखाई देते हैं। अभी शिक्षक को केवल ज्ञान प्रदाता से अलग छात्रों के लिए प्रेरक, मित्र और मार्गदर्शक बनने की आवश्यकता ज्यादा रेखांकित होती है।

डिजिटल युग में शिक्षकों की भूमिका में बदलाव को हर स्तर पर महसूस किया जा रहा है। इस दौर में शिक्षकों की भूमिका मार्गदर्शक और सुविधाप्रदाता की दिख रही है जो छात्रों को सीखने के संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हैं। शिक्षकों द्वारा छात्रों में डिजिटल साक्षरता के विकास के लिए प्रयास और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जिसमें शिक्षक परम्परागत ज्ञान के साथ ऑनलाइन सुरक्षा, सूचना साक्षरता के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए यह भी आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि वे नवीनतम तकनीकों और डिजिटल टूल्स का उपयोग करके शिक्षण पद्धतियों को और आकर्षक और आसान बनाएं। जरूरत इस बात की भी है कि शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण पद्धतियों को उनके अनुकूल बनाए। डिजिटल उपकरणों के सावधानीपूर्वक उपयोग के संदर्भ में भी शिक्षकों का सहयोग अब एक अनिवार्य तथ्य है।

ऐसे में जब डिजिटल युग में शिक्षकों की भूमिका में बदलाव के तथ्य को समझा जा रहा है तो शिक्षकों को भी अपने में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्हें डिजिटल टूल्स और प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति सक्षमता को प्राप्त करने और नई नई तकनीकों को सीखने पर फोकस बढ़ाना चाहिए। उन्हें नवीनतम तकनीकों और डिजिटल टूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों अभिभावकों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद और समन्वय की भूमिका के निर्वहन की आवश्यकता भी है ताकि वे छात्रों को सही मार्गदर्शन देने में सक्षम हो पाएं। आज के डिजिटल युग में शिक्षकों द्वारा निरंतर सीखने और अपने कौशलों को अद्यतन रखने की इच्छा को रखना बेहद जरूरी है।

डिजिटल युग में शिक्षकों के लिए अगर बड़ी चुनौती मौजूद है तो कई अवसर भी उपलब्ध है। आज के शिक्षकों को नवीनतम तकनीक और डिजिटल्स टूल्स का उपयोग करके शिक्षण पद्धतियों को आकर्षक और प्रभावी बनाने के अवसर भी उपलब्ध है। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म एक बड़ा अवसर है जो उन्हें अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाने और छात्रों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना भी एक बड़ा अवसर है, जो उन्हें अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है। वर्तमान डिजिटल युग में शिक्षकों के पास वैश्विक स्तर तक पहुंच का अवसर उपलब्ध है, जो उन्हें दुनियाभर के छात्रों के साथ जुड़ने और अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। डिजिटल दौर में शिक्षकों के पास निरंतर सीखने और स्वयं को अद्यतन करने का अवसर भी उपलब्ध है। शिक्षकों के पास यह अवसर उपलब्ध है कि वे छात्रों से आसानी से जुड़ सकें और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सके। वर्तमान डिजिटल युग में यह अवसर भी उपलब्ध है कि शिक्षक नवाचार करें और अपने छात्रों को सृजनात्मक कार्य के प्रति प्रेरक बन सकें। निश्चित तौर पर डिजिटल दौर में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें डिजिटल साक्षर, ऑनलाइन शिक्षण और संचार कौशल से युक्त होने की आवश्यकता अवश्य है। शिक्षकों को व्यक्तिगत स्तर पर सीखने के अनुभव बनाने, डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और छात्रों को महत्वपूर्ण सोच और विश्वसनीय स्त्रोतों का मूल्यांकन करना सिखाने के लिए अपनी भूमिकाओं और दक्षताओं को निरंतर बढ़ाना होगा। उन्हें छात्रों के साथ मानवीय जुड़ाव बनाए रखना होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन जैसे कौशल विकसित करने में मदद करनी होती है, और निश्चित तौर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होता है।

कई शिक्षक अभी भी नवीनतम डिजिटल टूल्स के उपयोग में सक्षम नहीं है। शिक्षकों को उस स्तर का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है जिसकी आवश्यकता है। कई स्कूलों में अभी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता है। ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बड़ी है।

शिक्षकों की भूमिका में बदलाव समय की मांग है। परंपरागत शिक्षण पद्धति के शिक्षक की तुलना में आज के शिक्षक को कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभानी है। आज के शिक्षक सिर्फ ज्ञान प्रदाता और चरित्र निमार्ता ही नहीं अपितु मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक के तौर पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।

उम्मीदों की चिप से हौसलों की उड़ान भरता भारत

ललित गर्ग
(पत्रकार, स्तंभकार)

भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया इतिहास रचते हुए अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर तैयार कर एक तकनीकी क्रांति को आकार दिया है। यह उपलब्धि न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। भारत ने इस तकनीकी क्रांति की तरफ कदम बढ़ते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी तकनीकी प्रगति को नये आयाम दिये हैं। पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये इसरो की सेमीकंडक्टर लैब साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट से शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं, अब भारत को इस तरह की तकनीक के लिये विदेशों के पराधीन नहीं होना होगा। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है, निश्चित ही इससे भारत की ताकत बढेगी और तकनीक के साथ-साथ यह आर्थिक विकास को तीव्र गति देगा। फिलहाल आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। विशेषतः भारत की यह जादूई उपलब्धि अमेरिका को आइना दिखाने वाली है, ट्रंप को यह एक बड़ा झटका है।

सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है, जिससे भारत अनेक मोर्चें पर सफलता के परचम फहरायेगा। इस स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अर्धचालक प्रयोगशाला ने अभिकल्पित किया है और इसे 'विक्रम' नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष-मानक माइक्रोप्रोसेसर है, जो मुख्यतः अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेट प्रणालियों में प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) चंडीगढ़ के साथ मिलकर दो स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। यह माइक्रोप्रोसेसर प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में मदद करेंगे। विक्रम 3201 पूरी तरह भारत में बना पहला 32-बिट प्रोसेसर है। इस कदम से इसरो को विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिससे अंतरिक्ष में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। निश्चित ही इससे भारत ने महाशक्ति बनने की ओर अपनी गति को तीव्रता दी है, जिससे अमेरिका हिला और दुनिया भारत की ताकत से रू-ब-रू हो रही है।

अब तक भारत को अनेक जटिल अंतरिक्ष अभियानों के संचालन हेतु विदेशी सूक्ष्म-प्रक्रमकों और अर्धचालक पट्टिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यह विदेशी निर्भरता न केवल आर्थिक दृष्टि से बोझिल थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण थी। 'विक्रम' माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण से भारत ने इस निर्भरता की बेड़ियों को तोड़ा है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाया है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिये निरन्तर प्रयासरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिये मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं भारत को ऐसे ही विकास के नये शिखरों पर आरोहण कराने का सशक्त माध्यम बन रही है।

निश्चित रूप से मोदी सरकार के प्रयासों से भारत चिप उत्पादन के वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल, डिजिटल डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों की कार्यकुशलता उन्नत चिप की ताकत पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरों का संजाल है। जो कंप्यूट करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है। उम्मीद है कि भारत का स्वेदशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपोलिटिक्स पर तो होगा ही, नये रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा, भारत तकनीकी विकास के नये आयाम उद्घाटित करते हुए विश्व को अचंभित भी करेगा। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति शृंखला को मजबूत बना सकते हैं।

सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है, जिससे भारत अनेक मोर्चें पर सफलता के परचम फहरायेगा। इस स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अर्धचालक प्रयोगशाला ने अभिकल्पित किया है और इसे 'विक्रम' नाम दिया गया है।

32-बिट क्षमता का अर्थ है कि यह माइक्रोप्रोसेसर अधिक व्यापक स्मृति का उपयोग कर सकता है और जटिल संगणकीय कार्यों को तीव्र गति से संपन्न कर सकता है। अंतरिक्ष अभियानों में जहाँ प्रत्येक क्षण और प्रत्येक संकेत का महत्व होता है, वहाँ इस प्रकार की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। यह केवल गति और कार्यकुशलता नहीं देता बल्कि विकिरण-सहनशीलता और दीर्घकालीन स्थिरता जैसे गुण भी समाहित करता है। अंतरिक्ष में प्रबल विकिरण, तापमान का उतार-चढ़ाव और कठोर परिस्थितियाँ होती हैं, जिनका सामना सामान्य माइक्रोप्रोसेसर नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार का अंतरिक्ष-योग्य माइक्रोप्रोसेसर ही मिशनों की सफलता का आधार बन सकता है। इस उपलब्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए आवश्यक रूपांकन, निर्माण और परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया भारत में ही सम्पन्न की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका सर्जक भी है। सूक्ष्म-संगणक की यह अभिकल्पना केवल एक चिप का निर्माण नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, उसकी दूरदृष्टि और आत्मविश्वास का परिचायक है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं के लिये केंद्र व राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में परियोजना की कुल लागत का सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान पहले ही 'शक्ति' और 'वेगा' जैसे स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर पर काम कर चुके हैं। इन प्रयासों ने आधारभूमि तैयार की और आज 'विक्रम' के रूप में वह प्रयास मूर्त रूप में सामने आया है। यह न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र बल्कि रक्षा, चिकित्सा उपकरणों और संचार प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। निश्चित ही चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन, उपकरण-समूह की उपलब्धता, संगणक-कार्यक्रमों का विकास, अनुप्रयोग-तंत्र का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन जैसी प्रक्रियाएँ अभी पूरी करनी होंगी। किंतु भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस दिशा में पहला कदम रखा है, वह आश्वस्त करता है कि भविष्य में हम और भी उन्नत सूक्ष्म-प्रक्रमक तैयार करने में सक्षम होंगे। 'विक्रम' केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की स्वाभिमानी यात्रा का घोष है। यह घोषणा है कि अब भारत केवल विज्ञान का अनुयायी नहीं बल्कि विज्ञान का निमार्ता और मार्गदर्शक बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना अब शब्दों में नहीं, ठोस उपलब्धियों में आकार ले रही है।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 05-09-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP10 User: kamlesh.mestry Time: 09-04-2025 22:42 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 5 सितंबर 2025

बदरूप होता टकराव

पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जो कुछ हुआ वह सदन की गरिमा और मर्यादा को तार-तार करने वाला है। TMC और BJP के बीच की तल्खी विशेष सत्र के आखिरी दिन सतह पर आ गई। दोनों दलों में तगड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और मतभेद हैं। फिर भी सदन का इस्तेमाल सार्थक वाद-विवाद के लिए किया जा सकता था।

चर्चा के बजाय हंगामा । सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC का आरोप है कि BJP शासित राज्यों में रहने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सदन में इसी पर चर्चा होनी थी, लेकिन जब विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंच कर हंगामा किया तो स्पीकर ने BJP के चीफ व्हिप शंकर घोष को सस्पेंड कर दिया। उनको बाहर निकालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। इस दौरान वह बेहोश हो गए।

विधानसभा में हंगामा

बांग्ला भाषियों का मुद्दा । प्रवासी बांग्ला भाषियों का मुद्दा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC के लिए बेहद संवेदनशील है। वह इसे बांग्ला अस्मिता व पहचान से जोड़कर आगे बढ़ रही हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने यहां तक कह दिया था कि दूसरे राज्यों में गए बंगाल के लोग लौट आएं, सरकार उनका ख्याल रखेगी। तीन दिन पहले जब कोलकाता में लगे तृणमूल कांग्रेस के अस्थायी मंच को सेना ने हटा दिया था, तब भी काफी बवेला मचा था। तब सेना की तरफ से बताया गया था कि पार्टी ने परमिशन खत्म होने के बाद भी मंच नहीं हटाया था, इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी।

गवर्नर से विरोध । पश्चिम बंगाल एक लंबे अरसे से केंद्र और राज्य के बीच टकराव का मैदान बना हुआ है। राज्यपाल के अनधिकृत दखल से लेकर SIR तक - विवाद के कई बिंदु हैं। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और जगदीप धनखड़ व मौजूदा गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ राज्य के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। केशरीनाथ ने जाते-जाते ममता पर तुष्टिकरण का आरोप लगा दिया था, तो धनखड़ ने कहा था कि बंगाल में लोकतांत्रिक हालात सही नहीं हैं। वहीं, ममता का आरोप है कि राजभवन के जरिये केंद्र उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है।

सीमाओं का ध्यान । विपक्ष शासित किसी और सूबे की तुलना में बंगाल में केंद्र-राज्य संघर्ष ज्यादा आक्रामक है। इसकी वजह है वहां की सियासत। पिछले विधानसभा चुनाव में BJP पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। तब से वह अपना स्पेस लगातार बढ़ाने की कोशिश में है, जबकि TMC के सामने चुनौती है अपनी जगह बचाए रखने की। राज्य में अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। यानी टकराव और गहरा होगा। लेकिन, इसमें दोनों पक्षों को राजनीतिक मर्यादा और सीमाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

रोज़-ब-रोज़

AI से बात

शैलेंद्र पांडेय

ChatGPT में जल्द ही ऐसे फीचर जोड़े जाएंगे, जिनसे पैरंट्स अपने बच्चों के अकाउंट पर ज्यादा निगरानी रख सकेंगे। अगर उन्हें लगता है कि कुछ फीचर्स उनके बच्चों के लिए सही नहीं हैं, तो वे उसे बंद कर सकेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि ChatGPT आत्महत्या के लिए भी उकसा रहा है। कैलिफोर्निया के एक परिवार ने तो OpenAI और उसके को-फाउंडर व सीईओ सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा भी ठोक दिया है कि उनके बेटे ने ChatGPT पर आत्महत्या के तरीकों के बारे में बात की और फिर अपनी जान दे दी। आरोपों के मुताबिक, AI ने उस बच्चे को सुझाव दिया कि वह खुदकुशी का जो तरीका अपनाना चाहता है, वह काम करेगा या नहीं! AI से जुड़ी यह नई चिंता है। मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स अभी तक इसी बात से परेशान थे कि कहीं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर हद से ज्यादा निर्भरता Cognitive Atrophy - यानी दिमाग की कोशिकाओं और न्यूरल कनेक्शन का धीरे-धीरे सिकुड़ना या कमजोर होना - की वजह न बन जाए। लेकिन, अब चिंता की वजह ज्यादा बड़ी है।

क्या मशीन किसी को बरगला सकती है? इस घटना से पहले ऑल्टमैन ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ChatGPT को लेकर कुछ आशंकाएं भी जताई थीं, 'अगर कोई यूजर मानसिक रूप से कमजोर स्थिति में है, उसे भ्रम होता है, तो हम नहीं चाहते कि AI उस भ्रम को और मजबूत करे...। अगर कोई ChatGPT से बात करके अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन हकीकत में लंबे समय के लिए वह अपना बुरा कर रहा है, तो यह गलत है...। यह भी गलत है कि कोई चाहकर भी ChatGPT का उपयोग कम नहीं कर पा रहा...।' बातचीत जब लंबी चले, तो कई बार कुछ ऐसा भी मुंह से निकल जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए। यही खतरा है AI के साथ भी। कंपनी ने माना है कि सामान्य और छोटी बातचीत में सेफ्टी फीचर्स ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। बात जैसे-जैसे लंबी होती जाती है, सुरक्षा कमजोर पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है और तब जवाब ऐसे हो सकते हैं, जो घातक हों। तो बातें कीजिए, पर याद रखिए - अति का भला न बोलना...।

एकदा

एवरेस्ट से वादा

न्यूजीलैंड के एक छोटे-से गांव में रहने वाले दुबले-पतले और शांत स्वभाव के उस लड़के को बचपन से ही पहाड़ों से लगाव था। उसका नाम था एडमंड हिलेरी और उसका सपना था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। 1951 और 1952 में उसने दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। पहली बार खराब मौसम ने रास्ता रोका और दूसरी बार मार्ग ही बंद हो गया। थका और निराश हिलेरी लौट तो आया, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। कुछ समय बाद, न्यूजीलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर उसके सम्मान में एवरेस्ट की बड़ी तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर उसके मन में सोई हुई ज्वाला को फिर से जगा गई। भाषण खत्म कर जब वह जाने लगा तो अचानक मुड़ा और तस्वीर को देखते हुए बोला, 'एवरेस्ट, पहली बार तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हराऊंगा।' ये शब्द सुनकर पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह आवाज एक पर्वतारोही की थी या किसी योद्धा की। और सचमुच, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी ने अपने शेरपा साथी तेनजिंग नोर्गे के साथ एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। वह पहले इंसान बने जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया और दुनिया को दिखा दिया कि मजबूत इच्छाशक्ति व अडिग संकल्प से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है।

Subrata Dhar

संकलन : **रिंकल शर्मा**

GST की दरों में सरकार ने जो ताज़ा बदलाव किए हैं, उनका क्या असर होगा

NBT आमने-सामने

खपत बढ़ेगी, विकास को मिलेगी तेज़ गति

नीलांजन घोष

GST काउंसिल ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। काउंसिल ने GST ढांचे को मुनासिब बनाते हुए 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए हैं, और पूरी प्रक्रिया को आसान करके दो रेट वाले सिस्टम में बदल दिया है। एक हद तक यह सुधार जरूरी सामान और सेवाओं पर लोगों को राहत पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम लग्जरी गुड्स की बात करते हैं, तो उन पर टैक्स काफी बढ़ा दिया गया है- सीधा 40% तक। फिर भी यह देश के लिए सही है, क्योंकि यहां तरक्की ज्यादातर खपत पर आधारित है।

जरूरी थे सुधार । जरूरी चीजों पर टैक्स काफी घटा दिया गया है - ज्यादातर मामलों में 18% या 12% से घटाकर 5% पर। खास तौर पर कुछ चीजों, जैसे ऊंचे तापमान पर तैयार किया गया दूध, पनीर वगैरह पर GST अब जीरो कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कई जरूरी और जिंदगी बचाने वाली दवाओं पर से टैक्स हटा लिया गया है। कुल 33 दवाएं, जिनमें कैंसर और दूसरी लाइलाज या पुरानी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं- उन पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

सरकार का फोकस
- मिडल और लोअर मिडल क्लास पर ध्यान
- देश में निजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास
- टैक्स सिस्टम आसान होने से कारोबार बढ़ेगा

दवाओं में राहत । यह कदम निश्चित रूप से उपयोगी होगा। ज्यादातर मामलों में दवाओं की गिनती उन वस्तुओं में की जाती है, जिनकी मांग पर दाम का कोई असर नहीं पड़ता। यानी कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए, अगर जान बचानी है तो खर्च करना ही पड़ेगा। इसीलिए, अगर दाम बढ़ते हैं तो भी यह जरूरी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में विशेषकर बुजुर्गों के लिए लागत काफी बढ़ जाती है। इसी वजह से दवाओं को टैक्स फ्री करने का फैसला स्वागत योग्य है। बल्कि, सच कहूं तो मेरा मानना है कि Amoxicillin जैसी कुछ और दवाओं पर भी GST खत्म कर देना चाहिए।

बीमा को बढ़ावा । एक और महत्वपूर्ण बात इस सुधार में बीमा उत्पादों को लेकर है। कुछ बीमा उत्पादों, खासकर बीमा प्रीमियम के मामले में, बीमा नीतियों को और सस्ता बनाया गया है। यह हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सामाजिक सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, साथ ही पुनर्बीमा, जीवन बीमा- इन सबको पूरी तरह GST से मुक्त कर दिया गया है। पहले इन पर 18% तक टैक्स लगता था। इसका एक अच्छा असर यह देखने को मिल सकता है कि अब आम लोग भी बीमा पॉलिसी अपेक्षाकृत आसानी से ले पाएंगे।

रिफॉर्म का मकसद । Macro-economic स्तर पर देखें तो इसके दो पहलू हैं, जिनके बारे में मेरा मानना है कि वित्त मंत्री प्रतिबद्ध हैं। पहला, पिछले कुछ बजटों में हमने पूंजीगत खर्च बढ़ते हुए देखा है। दूसरा, वित्त मंत्री लगातार कोशिश कर रही हैं कि खपत को बढ़ावा दिया जाए। पिछले तीन दशकों में यह साफ रहा है कि भारत ने हमेशा खपत-आधारित विकास को ही आगे बढ़ाया है। यह GST सुधार उसी दिशा में एक प्रोत्साहन है। अगर भारत को अपनी तरक्की की गति बनाए रखनी है, तो जरूरी है कि खपत को विकास का अहम चालक बनाए रखा जाए। यह GST सुधार यही सुनिश्चित करता है।

गरीबी घटाने में मदद । दूसरा पहलू यह है कि तरक्की सिर्फ ऐशो-आराम के सामान की खपत से नहीं आती। असल खपत तो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास की वजह से बढ़ती है। वजह कि इन तबकों की खर्च करने की प्रवृत्ति अमीर तबके से ज्यादा होती है। GST घटाने से मध्य और उच्च मध्य वर्ग की खपत बढ़ेगी। वो ज्यादा खर्च करेंगे, और खपत हिंदुस्तान जैसी अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ तरक्की बल्कि गरीबी घटाने में भी मदद करेगी। गरीबी की परिभाषा भी यहां खपत से जुड़ी हुई है, और गरीबी घटने की एक बड़ी वजह खपत का बढ़ना ही रहा है।

Adobe Stock

सुधरेगा कारोबार । GST का यह सुधार निजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी अच्छा कदम है, क्योंकि इससे कारोबार की कार्यकुशलता बढ़ती है और कारोबारी माहौल सुधरता है। GST की बहुस्तरीय दरों का पालन अलग-अलग वस्तुओं पर कई तरह की उलझन पैदा करता था। मेरा मानना है कि ज्यादातर देशों में या तो एक दर होती है या अधिकतम दो-तीन दरें। हमारे यहां पहले कई दरें थीं, जिन्हें अब घटाकर तीन कर दिया गया है।

तर्कसंगत कदम । कुल मिलाकर GST सुधार अच्छा कदम है। यह एक ओर टैक्स सिस्टम को बेहतर तर्कसंगत बनाता है, दूसरी ओर tax compliance को आसान करता है। यह सुधार सेवा देने वालों, वस्तुएं बनाने वालों और टैक्स ऑफिसर्स- सभी के लिए लाभकारी है। इससे अनुपालन की लागत घटती है और जब किसी अर्थव्यवस्था में अनुपालन की लागत घटती है, तो उसकी कारोबारी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। यह GST सुधार उस दिशा में एक बहुत अहम कदम है।

(लेखक ORF में डिवेलपमेंट स्टडीज के VP हैं)

बदलाव पर कुछ राज्यों को आपत्ति

अभिजीत मुखोपाध्याय

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर (GST) काउंसिल ने बुधवार को इसकी दरों में बदलाव किए, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। इन बदलावों का बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं की टैक्स दरों पर असर पड़ेगा। इस रिफॉर्म का मकसद ज्यादातर वस्तु और सेवा को 5% और 18% के टैक्स स्लैब में लाना है।

तार्किक बदलाव । पनीर, रोटी और पराठा जैसे खाने की चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैंसर की दवाओं, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को भी GST से मुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ, तंबाकू-पान मसाला जैसे 'sin goods' और 350cc इंजन से अधिक क्षमता वाले मोटरसाइकल पर 40% GST देना होगा। AC और सभी साइज के टेलीविजन जैसे कंस्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स पर एक समान टैक्स लगाया गया है और इनकी टैक्स दरों में भी कटौती की गई है।

पॉजिटिव कदम । GST में इस रिफॉर्म का लंबे समय से इंतजार था। बहुत अधिक स्लैब होने और एक ही कैटिगरी की चीजों पर अलग-अलग दरों से काफी उलझन होती थी और इससे टैक्स कंप्लायंस में भी दिक्कत पेश आती थी।

खपत को बढ़ावा । आज भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में घरेलू खपत को बढ़ावा देना जरूरी है। तभी आर्थिक विकास दर यानी GDP ग्रोथ को तेज बनाए रख पाना मुमकिन होगा। फिर भी इस सुधार का पूरा असर कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है।

कई गुना का फायदा । पहली बात तो यह है कि सरकार ने GST की दरों में जो कटौती की है, उसका फायदा ग्राहकों को मिले। अगर कंपनियां ऐसा करती हैं तो आने वाले फेस्टिव सीजन में ही इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे कंपनियां प्रॉडक्शन बढ़ाएंगी और उनके ऐसा करने से रोजगार के अवसर भी अधिक बनेंगे। रोजगार बढ़ने से लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। GST की दरों में इन बदलावों से वित्त वर्ष 2025-26 देश की GDP में 0.2-0.3% की बढ़ोतरी हो सकती है।

मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण । ऊपर मैंने इस ओर ध्यान दिलाया है कि मौजूदा व्यवस्था में एक ही कैटिगरी की चीजों पर अलग-अलग टैक्स देना होता है। इससे उलझन होती थी और यह इस बात का भी संकेत था कि टैक्स मनमाने ढंग से तय किया गया है। ग्राहकों को प्रॉसेस्ड या पैकेज्ड चीजों पर अधिक टैक्स देना पड़ता था, जबकि वे उन्हीं चीजों के अनप्रॉसेस्ड वर्जन से थोड़े ही अलग होते थे। अभी वाली व्यवस्था में जरूरी हाइजीन प्रॉडक्ट्स, जैसे- महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन या छोटे बच्चों की नैपीज पर 12% GST लगता है, जबकि सैनिटरी नैपकिन के लिए जिन कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, उन पर इंडिविजुअल बेसिस पर इससे अधिक टैक्स लिया जाता है। इससे फाइनल प्रॉडक्ट कहीं महंगे हो जाते हैं।

पॉजिटिव असर
- घरेलू खपत को मिल सकता है बढ़ावा
- अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद
- टैक्स चोरी में कमी आने के आसार

टैक्स चोरी घटेगी । GST को जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसे लाने का मकसद टैक्स दरों में कमी लाना, कंप्लायंस और प्रॉसेस को सहूलियत भरा बनाना था। इसे लागू करने के बाद वर्षों में इस व्यवस्था से राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मासिक राजस्व में धीमी ही सही निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन यह भी सच है कि इस व्यवस्था में कई खामियां बनी हुई थीं। कंप्लायंस में कारोबारियों को दिक्कत होती थी। टैक्स रिफंड में देरी का भी उन्हें सामना करना पड़ता था। इसलिए टैक्स चोरी के मामले भी आम थे।

कुछ राज्यों को आपत्ति । वित्त मंत्री का अनुमान है कि दरों में बदलाव से सरकार को करीब 48,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन इन सुधारों की वजह से अगर GST कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है तो इसकी भरपाई जल्द ही हो जाएगी। हालांकि, टैक्स की दरों में इन बदलावों की वजह से कुछ राज्य सरकारें मुआवजे की भी मांग कर रही हैं। दरअसल, इन राज्यों ने साल की शुरुआत में जो बजट अनुमान तय किए थे, GST की दरों में बदलाव के कारण उन्हें हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इससे उनका खर्च भी प्रभावित होगा। ऐसे में केंद्र और विपक्षी शासित राज्यों के बीच मतभेद से इनकार नहीं किया जा सकता।

मध्य वर्ग का फायदा । वहीं, इस सुधार से मध्य वर्ग को फायदा होने की उम्मीद है। इससे जरूरी चीजों के दाम में कमी आएगी। कृषि क्षेत्र और MSMEs के लिए भी यह फायदेमंद है और इससे कारोबारी सुगमता भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ, लग्जरी और sin goods और महंगे होंगे और इस वजह से आखिरकार सरकारी राजस्व पर दबाव भी बन सकता है। कुल मिलाकर, यह ग्रोथ, ग्राहकों के हित में है और इससे अर्थव्यवस्था अधिक समावेशी बनेगी।

(वरिष्ठ अर्थशास्त्री, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन)

संविधान में ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिस पर सवाल नहीं हो सकता

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। विपक्षी खेमे I.N.D.I.A. ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस **बी. सुदर्शन रेड्डी** को प्रत्याशी बनाया है। मौजूदा चुनाव को लेकर **मंजरी चतुर्वेदी** ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंशः

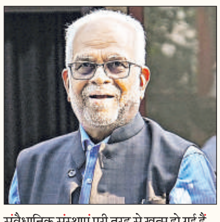

■ कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, आपने अपने प्रतिद्वंद्वी पर न सिर्फ गायब होने का आरोप लगाया बल्कि यह भी कहा कि वह मीडिया में बोलते नहीं हैं, इन आरोपों के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं?

मैंने जो कहा, वह आरोप नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि अगर वह कुछ बोलते हैं तो एक चर्चा हो सकती है, एक संवाद हो सकता है। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में गायब होने की बात तो बोल ही नहीं सकता।

■ NDA के पास संख्या बल है। ऐसे में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? I.N.D.I.A. के समर्थन के अलावा वह कौन सी चीज है, जो आपको जीत के प्रति आश्वस्त करती है?

इस चुनाव में राज्यों के दल तो वोट करेंगे नहीं। इसमें वोट देने वाले सदन के सदस्य हैं। उन सभी सदस्यों को मैं अपने समर्थन के बाबत चिट्ठी लिख चुका हूं। दूसरा, इसमें व्हिप जारी नहीं होता। तीसरा, इसमें चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। तभी इसके निर्माताओं का मानना था कि सदस्य सोच-समझ कर अपना मतदान करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर।

■ विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या संवैधानिक चुनौती नजर आती है?

मैं इतना ही कह सकता हूं कि विपक्षी नेता और विपक्षी दलों की अपनी अपनी सोच और नैरेटिव है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि देश में संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा जरूर लगता है कि हमारी संस्थाओं को जिस तरह से संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मुझे उनके काम में कमी लगती है।

■ आप खुद जुडिशरी में रहे हैं, पिछले कुछ सालों में देश की जुडिशरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या होना चाहिए कि जनता का एक बार फिर से जुडिशरी में भरोसा बने?

मैं नहीं समझता कि जुडिशरी को लेकर आम आदमी का भरोसा टूटा है। एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, लोगों की अपेक्षा लगातार बढ़ती है। अगर जुडिशरी का रेस्पॉन्स, नोट, कमेंट, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता तो कभी लग सकता है कि भरोसा डगमगा रहा है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि जुडिशरी काम नहीं कर रही, या काम नहीं करती। सवालों की बात पर मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में ऐसा कोई विभाग या अंग नहीं है, जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल करने का अधिकार संविधान ने दिया है। हर कोई सवाल उठा सकता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई, जो खुद के लिए काम करे। व्यवस्थाएं इस तरह से बनाई गईं कि सब मिलकर नागरिकों के लिए काम करें। इसलिए जब लोग कोई कमी महसूस करते हैं तो सवाल उठाते हैं। इसमें गलत बात क्या है? लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए।

■ पिछले दिनों आपने कहा कि उपराष्ट्रपति का यह चुनाव भारत के हालिया इतिहास में सभी चुनावों से अलग होगा। आपका आशय?

आज देश में हालत यह है कि लोग सार्वजनिक तौर पर रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बारे में इन पदों के चुनावों के दौरान कम से कम वैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने देश के लोगों के सामने एक वादा किया था कि चुनाव के दौरान भाषा को पूरी तरह से शालीन रखूंगा। मैं सोच-समझकर बोलता हूं। किसी पर आरोप नहीं लगाता, ना किसी को हर्ट करता हूं। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया और आइंदा भी नहीं करूंगा।

■ आपने कहा कि आप सभी दलों से संपर्क साध रहे हैं, तो क्या आप NDA के घटक दलों से भी समर्थन मांगेंगे? खासकर, आपकी मातृभाषा बोलने वाले दोनों राज्य तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों जैसे TDP, YSRCP और पवन कल्याण की पार्टी से?

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जहां मैं पैदा हुआ, वहां सभी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं और सब लोगों को जानता हूं, वे मुझे जानते हैं। मेरा मानना है कि यहां बात राज्यों की नहीं, उपराष्ट्रपति पद की है। उपराष्ट्रपति देश का होता है तो देश के लिए सबसे समर्थन मांगूंगा, NDA के दलों से भी मांग रहा हूं। मैंने सबको चिट्ठी लिखी है। मेरा मानना है कि मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं और ना ही मेरी इच्छा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की है।

■ अगर आप उपराष्ट्रपति बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी?

राज्यसभा को ठीक तरीके से चलाने की, सभी दलों को बराबरी से मौका देने की कोशिश रहेगी। हाउस ऑर्डर में चलाने की कोशिश करना और संविधान की रक्षा करना ही मेरी प्राथमिकता होगी।

डिप्रेशन से बचना है, तो समय को जान लीजिए

सलिल पाण्डेय

हर इंसान के जीवन में दिन, महीने और घंटे तय होते हैं। इन्हीं समय के टुकड़ों में कोई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, कोई असफलता में फंसा रह जाता है। सवाल यह है कि बराबरी के दो लोगों में से एक सफल क्यों हो जाता है और दूसरा क्यों विफल रह जाता है? जवाब है, समय का सही उपयोग। सफल व्यक्ति आज का काम आज ही पूरा करता है, असफल व्यक्ति आलस्य और टालमटोल में उलझा रहता है।

असफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने समय की कीमत नहीं समझी। वे हर काम को अगले दिन पर टालते गए। धीरे-धीरे काम इतने बढ़ गए कि समझ नहीं आया कहां से शुरू करें। जब तक कदम उठाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय केवल पछतावा ही हाथ लगा। अक्सर ऐसे लोग कहते मिलते हैं कि पहले उनके पास अच्छे मौके थे, वे बहुत सक्षम थे, चाहते तो बड़ी सफलता पा सकते थे। बीते समय को याद करके वे निराशा में डूब जाते हैं। यही निराशा धीरे-धीरे अवसाद में बदल जाती है। महाभारत के समय अर्जुन भी ऐसे ही अवसाद में डूब गए थे। युद्ध के मैदान में वह शस्त्र उठाने से हिचकने लगे। यहां शस्त्र का मतलब केवल लड़ाई नहीं, बल्कि कर्म भी है। हमारा मन, दिमाग और हाथ-पांव ही हमारे असली शस्त्र हैं। अर्जुन की स्थिति देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में जागरूक और कर्मशील बनने के लिए है।

इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गया, वह कभी वापस नहीं आएगा। अतीत की गलतियों को याद करके समय बर्बाद करना मूर्खता है। समय ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने समय की कद्र की, वह कभी पीछे नहीं रह सकता। लेकिन जो बीते कल को कोसते रहते हैं, उनके जीवन में अंधकार और ग्लानि ही रह जाती है। यही ग्लानि इंसान को इतना कमजोर बना देती है कि वह खुद को परिवार और समाज के लिए बेकार समझने लगता है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

इससे बचने का केवल एक रास्ता है – यह मान लेना कि बीता हुआ कल अब लौटने वाला नहीं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आने वाला समय व्यर्थ न जाए। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोग जीवन के उत्तरार्ध में भी बड़ी सफलता पाए हैं - 'जब जागो तभी सवेरा' कहावत इसी सत्य को बताती है। जब इंसान जागरूक होकर परिश्रम करता है तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। तभी मान भी बढ़ता है। यहां तक कि असफलता के दिनों में जो लोग उपेक्षा करते थे, वही फिर उसके आस-पास दिखाई देने लगते हैं।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

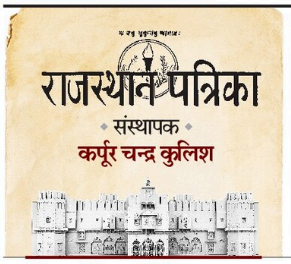

जीएसटी से जुड़े फैसले कई मायनों में अहम

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में किया गया बड़ा बदलाव नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक बेहतर कदम है। वैसे तो नई कर प्रणाली यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब में वर्ष 2017 में इसके लागू होने के बाद से कई परिवर्तन किए गए हैं लेकिन, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने बुधवार को जो फैसले किए, वे कई मायनों में अहम कहे जाएंगे। अमरीका में डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वैश्विक व्यापार में बड़ी उथल-पुथल चल रही है। ट्रंप ने खासतौर पर भारत को निशाना बनाया है, जिसके कारण कारोबारी तनाव में हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए टैक्स स्लैब में सुधार काफी जरूरी थे। वैसे भी चार तरह के टैक्स स्लैब के कारण जीएसटी प्रणाली का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में छूट से घरेलू खपत बढ़ेगी जिससे 'ट्रंप टैरिफ' से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

सरकार ने जीएसटी प्रणाली में सुधार करते हुए अब सिर्फ दो तरह के स्लैब बरकरार रखे हैं, जिसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने आवश्यक वस्तुओं को करमुक्त करने के साथ कई वस्तुओं पर टैक्स घटाकर घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे कारोबारियों को काफी राहत दी है। पहले चार तरह के टैक्स स्लैब थे- 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी वाला ही प्रभावी रहेगा। पहले जिन वस्तुओं पर 12 फीसदी और 28 फीसदी का टैक्स लगता था उसे अब कम स्लैब के दायरे में लाया गया है जो आप उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली बात है। खाने-पीने की चीजों और जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का एक स्पेशल टैक्स स्लैब जरूर बनाया गया है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 27 अगस्त से लागू 50 फीसदी 'ट्रंप टैरिफ' के कारण भारत के 60.2 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ा है। यह अमरीका भेजे जाने वाले माल का 55 फीसदी और भारत के कुल निर्यात का 18 फीसदी है। सबसे ज्यादा असर कपड़ा, सी-फूड, रत्न व आभूषण और चमड़ा क्षेत्र पर पड़ा है। लघु और मध्यम श्रेणी के ये उद्योग-व्यापार श्रम पर अधिक निर्भर हैं। इन क्षेत्रों के तनाव में आने का असर गरीब परिवारों पर पड़ने की आशंका है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी में 0.4 फीसदी से 0.6 फीसदी तक कमी हो सकती है। त्योहारी सीजन और बिहार चुनाव से ठीक पहले यह फैसला न सिर्फ कारोबारी बल्कि, दूसरे कारणों से भी अनुकूल माना जाएगा। घरेलू मांग मजबूत होने से संबंधित उद्योगों को बाहरी झटकों से बचाया जा सकेगा।

जीएसटी कटौती : खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत आधारित है

उपभोक्ता को शक्ति तथा बाजार को मिलेगी गति

मधुरेन्द्र सिन्हा
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

इस समय अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर की जरूरत थी जो उसे मिल गया है। इससे खरीदारी बढ़ेगी और उसका असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा जो अंततः रोजगार बढ़ाएगा। इससे अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। मुद्रास्फीति की दर में भी 1.1 फीसदी की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

एक जीवंत लोकतंत्र में तरह-तरह के सुधार उसे गतिमान बनाए रखते हैं और यह बात आर्थिक सुधारों पर भी लागू होती है। सरकार का लक्ष्य टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरना नहीं होना चाहिए बल्कि जनता को राहत देना भी होना चाहिए। इस बजट सत्र में केन्द्र सरकार ने जहां इनकम टैक्स की दरें काफी घटाकर टैक्स देने वाली जनता को काफी राहत पहुंचाई वहीं अब जीएसटी में कटौती की घोषणा करके उसकी क्रय शक्ति में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी का कदम उठाया है। इस टैक्स व्यवस्था से आम जनता को काफी फायदा होगा क्योंकि अप्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स के विपरीत सभी पर लागू होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इस कटौती के बारे में संकेत दिया था और कहा था कि देश की जनता को यह दिवाली का उपहार होगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की दरों में अच्छी खासी कटौती करके जनता को नवरात्रि पर ही उपहार दे दिया। इस कटौती से सरकारों को 47,700 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा लेकिन टैक्स की दरें कम होने से अधिक खरीदारी होगी जिससे अंततः राजस्व में बढ़ोतरी ही होगी। खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत आधारित है न कि निर्यात आधारित। हमारे जीडीपी की दर पिछली तिमाही में 7 फीसदी से भी ज्यादा रही जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए एक सबक है। अब इस गति को बनाए रखने में टैक्स कटौती का यह अभूतपूर्व कदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रोजमर्रा के सामान, खाने-पीने की वस्तुओं, कारों, ट्रकों, सीमेंट वगैरह जैसी चीजों पर टैक्स या तो खत्म कर दिया गया है या घटा दिया गया है। इससे ग्राहकों खासकर मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। कम टैक्स देने से वे कहीं ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे। सीमेंट पर टैक्स घटने से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। सर्विस सेक्टर जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे भी सहारा मिलेगा। जीवन रक्षक दवाइयों पर टैक्स हटाकर काउंसिल ने बड़ा कदम बढ़ाया है।

इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत के भारी भरकम टैक्स को शून्य पर ले जाने से जनता को तो फायदा होगा ही, बीमा क्षेत्र को भी लाभ होगा। वहां रोजगार की संभावना बढ़ेगी क्योंकि भारत में अभी भी 30 फीसदी लोगों के पास ही बीमा है। शेष जनता किसी भी तरह के सुरक्षा कवच से वंचित है। बीमा पर जीएसटी में कटौती बहुत बड़ी राहत साबित होगा। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़ी तादाद में रोजगार देते हैं और इन पर टैक्स घटाकर इन्हें प्रोत्साहित किया गया है। इससे टूरिज्म और बढ़ेगा तथा सरकार को मिलने वाला टैक्स भी। प्री पेड तथा पोस्ट पेड मोबाइल सेवाओं पर टैक्स की दर घटने से कम आय के लोगों को राहत मिलेगी। इंटरनेट और डीटीएच की दरें घटने से युवा वर्ग को बहुत राहत होगी। यानी समाज के हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से मुद्रास्फीति की दर में 1.1 फीसदी की कमी आएगी। निवेशक इस बड़े फैसले से खुश हैं। दरअसल बाजार में मांग की कमी दिख रही थी और यह देखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है, यह कदम उत्साहवर्धक है। इस समय अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर की जरूरत थी जो उसे मिल गया है। इससे खरीदारी बढ़ेगी और उसका असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा जो अंततः रोजगार बढ़ाएगा। इससे अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से जीएसटी में सुधार की मांग जोर-शोर से की जा रही थी और पक्ष-विपक्ष के सांसद भी मुखर हो रहे थे। दरअसल कुछ वस्तुओं पर अभी टैक्स की दरों में विसंगति है तो कुछ में अधिकता है। मसलन दो तरह के सामान जो मिलकर एक उत्पाद होते हैं, उन पर अलग-अलग टैक्स दरें हैं। यह कारोबारी के लिए एक परेशानी है। अगर हम स्नैक बन मस्का को देखें तो पाएंगे कि बन पर टैक्स की दर अलग है और मस्का यानी मक्खन पर अलग। अब व्यापारी किस दर से टैक्स लेगा? रेस्तरां में रोटी पर कम टैक्स है तो परांठे पर ज्यादा। बिना एसी वाले रेस्तरां के लिए अलग दर है तो एसी वाले के लिए अलग। खुले सामान पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन पैकेट में आते ही उस पर टैक्स लगेगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो जीएसटी की विसंगतियां बताती हैं। लेकिन अब नई घोषणा के बाद सभी तरह की विसंगतियां खत्म हो गई हैं। सरकार ने जीएसटी के जरिये कर संग्रह का जो लक्ष्य रखा था वह काफी हद तक पूरा हो गया है। पिछले पांच वर्षों में जीएसटी वसूली दोगुनी हो चुकी है। 2024-25 में कुल जीएसटी वसूली 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है जो 9.4 फीसदी की दर से बढ़ी है। यह भी एक कारण है कि सरकार टैक्स में कटौती करने को तैयार हो गई है।

अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियां, कारोबारी, दुकानदार, रेस्तरां मालिक टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाएं। पिछली बार यह देखा गया था कि इसका फायदा कई कारोबारी और कंपनियां खुद अपने सामानों या सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर हड़प लेती हैं। अब यह नहीं होना चाहिए।

बुक इनसाइट

नो मिनिस्टर

भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने पिछले छह वर्षों में सात किताबें लिखी हैं। 'नो मिनिस्टर-नेविगेटिंग पावर, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद ए स्टीली रिसॉल्व' इनकी नवीनतम कृति है। 424 पेज की इस किताब में लेखक ने सरकार के साथ काम करने के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों के साथ ही लेखक ने कुछ ऐसे किस्से भी इस पुस्तक में शामिल किए हैं, जो राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से लेकर राजस्थान, दिल्ली और वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक तक की अपनी सेवा यात्रा को समाहित करते हुए लेखक ने पूर्व मुख्यमंत्रियों भैरोंसिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के साथ के कुछ संस्मरण भी साझा किए हैं। इनके अलावा अरुण जेटली, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण के साथ के अनुभव भी उन्होंने इसमें लिखे हैं। वित्तीय मामलों पर गर्ग ने प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश भी इस पुस्तक के जरिये पाठकों के साथ साझा किए हैं। एक तरह से यह किताब प्रशासनिक सेवा के तौर तरीकों और नजरिये को सरल रूप में प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज है।

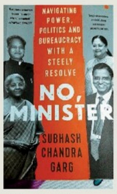

- धर्मेंद्र भंडारी, पूर्व ओएसडी, आरबीआइ

शिक्षक दिवस विशेष | डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों का स्थान बहुत ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं

ज्ञान के दीपक और भविष्य के शिल्पकार हमारे शिक्षक

प्रो. अशोक कुमार
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय
@patrika.com

हर वर्ष 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ एक छुट्टी या उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उन महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का एक अवसर है जो हमें शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक समाज के निर्माण में शिक्षकों का योगदान कितना महत्त्वपूर्ण है। डॉ. राधाकृष्णन न केवल एक उच्च-कोटि के राजनेता थे, बल्कि वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि समाज में शिक्षकों का स्थान बहुत ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। जब उनके कुछ शिष्यों और मित्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि उनके जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय, अगर इस दिन को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाए, तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। उनका यह विचार उनकी शिक्षा और शिक्षकों के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है। यह एक ऐसा कदम था जिसने शिक्षकों के सम्मान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।

शिक्षा वह नींव है जिस पर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। एक बच्चे के जीवन में माता-पिता के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि वे अपने छात्रों को जीवन के मूल्यों, नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ भी सिखाते हैं। वे छात्रों को उनकी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। एक शिक्षक का प्रभाव केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह छात्रों के जीवन भर के निर्णयों और सोच को प्रभावित करता है। वे एक मूर्तिकार की तरह होते हैं जो कच्चे पत्थर को तराश कर एक सुंदर और मूल्यवान कलाकृति में बदल देते हैं। आधुनिक युग में, शिक्षकों की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। आज उन्हें केवल पारंपरिक ज्ञान देने के बजाय छात्रों को आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और रचनात्मकता जैसे 21वीं सदी के कौशल सिखाने होते हैं। तकनीकी प्रगति के इस दौर में शिक्षक छात्रों को इंटरनेट और सूचना के इस महासागर में सही और गलत की पहचान करने में भी मदद कर रहे हैं।

शिक्षक दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करें। यह एक ऐसा दिन है जब हम रुककर उन सभी गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, चाहे वे स्कूल के शिक्षक हों, कॉलेज के प्रोफेसर हों या जीवन के किसी भी पड़ाव पर हमें कुछ सिखाने वाले व्यक्ति हों। इस दिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम शिक्षकों के महत्त्व को कैसे बढ़ा सकते हैं। सरकार, समाज और अभिभावकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों को उचित सम्मान, बेहतर सुविधाएं और एक ऐसा वातावरण मिले जहां वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। एक समृद्ध और शिक्षित समाज के निर्माण के लिए शिक्षकों का सशक्तीकरण अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिज्ञा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि एक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है और इस शिक्षा की बागडोर हमारे शिक्षकों के हाथों में है। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षक दिवस तीनों एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, जो समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन तीनों को समझना हमें यह बताता है कि ज्ञान और नैतिकता का प्रसार किस तरह से होता है। शिक्षक वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल से दूसरों को शिक्षित करता है। शिक्षक का काम सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं होता, बल्कि वे छात्रों को जीवन के मूल्यों, अनुशासन और नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताते हैं। वे मूर्तिकार की तरह होते हैं जो बच्चों के कच्चे मन को तराशकर आदर्श नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका योगदान किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव होता है, क्योंकि वे ही भविष्य के नेताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों और नागरिकों का निर्माण करते हैं।

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। यह सिर्फ किताबें पढ़ने या परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास का एक व्यापक हिस्सा है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। एक शिक्षित समाज ही अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए, शिक्षा को किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ माना जाता है। आइए, हम सब मिलकर इस दिन को न केवल मनाएं, बल्कि अपने जीवन में शिक्षकों के महत्त्व को समझें और उन्हें वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। क्योंकि शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान का एक पुंज होता है जो न जाने कितने ही जीवन को आलोकित करता है।

गुरु महत्त्व घटने से कमजोर होते हैं समाज और राष्ट्र

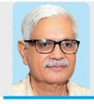

गिरीश्वर मिश्र
पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
@patrika.com

मानव मूल्यों की स्थापना और संवर्धन के लिए जरूरी मानते हुए सभ्य समाजों में शिक्षा को संस्थागत रूप दिया गया, विद्यालय और विश्वविद्यालय बने और विद्यालय जाकर कुछ वर्षों तक शिक्षा पाना सामान्य जीवन का अनिवार्य अंग बन गया। सभ्यता का यह हस्तक्षेप ज्ञान के सतत प्रवाह को बनाए रखने में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इस संस्था की मुख्य धुरी के रूप में गुरु या अध्यापक की भूमिका सुनिश्चित की गई। गुरु को शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विषय-वस्तु तथा उसके उपादान आदि सब को निर्धारित करने का दायित्व मिला। गुरु की संस्था में समाज का भरोसा विकसित हो गया और उसे नैतिक आदर्श के मॉडल के रूप में पहचान मिली। भारत में गुरुकुलों और गुरुओं की लंबी श्रृंखला रही है, जिन्होंने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुरु-परम्परा(घराना) की अमिट छाप छोड़ी है। हर तरह के ज्ञान को साधने में गुरु ही सहायक होता है। आज भी गुरु, उस्ताद, कोच, मेंटर, मास्टर की भूमिकाएं महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं। लोग अपने गुरु पर बड़ा भरोसा करते हैं और गुरु से ज्ञान, आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए श्रद्धा के साथ तत्पर रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने वाले सभी लोगों ने जीवन-यात्रा में गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

गौरतलब है कि 'गुरु' शब्द के जो भी अर्थ किए जाते हैं वे हमारा ध्यान गांभीर्य और श्रेष्ठता जैसे उदात्त भावों की ओर ले जाते हैं। गुरु वह होता है, जो ज्ञान के अंजन से शिष्य की आंख खोल देता है। वह अंधकार दूर कर प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु को एक ग्रह (जूपिटर) के रूप में सौर मंडल में भी स्थान मिला हुआ है। वह संभवतः सबसे बड़ा ग्रह है और भारतीय परम्परा में गुरु ग्रह के देवता देवगुरु बृहस्पति कहे गए हैं।

ज्योतिष की मानें तो व्यक्ति के जातक में गुरु की स्थिति ज्ञान, वैभव, सुख, पद और समृद्धि के साथ जुड़ी होती है। संगीत में वर्ण भी लघु और गुरु होते हैं। 'गुरु' शब्द और शिक्षक के रूप में सर्वस्वीकृत हैं। इसी अर्थ में यह अंग्रेजी के शब्दकोश में भी अब शामिल हो चुका है। गुरु और शिष्य के बीच अटूट संबंध को बताते हुए उपनिषद में गुरु को पूर्व-पक्ष और शिष्य को उत्तर-पक्ष के रूप में पहचाना गया है। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु और गुरु से दीक्षा की बड़ी महिमा बखानी गई है। सद्गुरु ही शिष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यवहार के स्तर पर शील और आचरण पर बड़ा जोर दिया गया है। आधुनिक युग में ज्ञान की व्यवस्था में विविधता आई है और शिक्षा पाने की प्रक्रिया तकनीकी प्रगति की कृपा से अधिकाधिक विमानवीकृत होती जा रही है। कई जगह यंत्र-शिक्षक (रोबोट) भी कक्षा में दाखिल हो रहा है। शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इंटरनेट की बदौलत ऑनलाइन सीखने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। अब मोबाइल और लैपटॉप संचार, संवाद, लेखन, परीक्षा आदि को नया आयाम दे रहे हैं। कक्षा में स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं जो कम्प्यूटर-स्क्रीन सरीखे काम कर रहे हैं।

जीवनोपयोगी ज्ञान के लिए गुरु के सान्निध्य में प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। धीरे-धीरे गुरु की स्थिति अन्य व्यवसायों जैसी होती जा रही है। गुरुओं के भी जाति और वर्ग बनते गए। उनके आचरण में भी दुर्बलताएं आती गईं। शिक्षा संस्थाओं के भी आज कई स्तर हैं और अध्यापकों के वेतन और अन्य सुविधाओं में भी बड़ा फर्क है। कार्य की संस्कृति में भी भिन्नता है। आइआइटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा आइआइएम आदि चुनिंदा संस्थाओं को स्वायत्त ढंग से काम करने अवसर है। फलतः वहां पर गुणवत्ता का स्तर बना हुआ है जबकि अन्य शिक्षा संस्थान प्रश्नांकित हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि शिक्षकों और सुविधाओं अनदेखी करते हुए शिक्षा संस्थाएं खुल रही हैं, हालांकि उनकी संख्या अब भी नाकाफी है।

निजी क्षेत्र में भी शिक्षा के लिए द्वार खुले हैं पर सुविधा, स्वायत्तता और गुणवत्ता की दृष्टि से वहां की स्थिति असंतोषजनक है। साथ ही वे बड़े मंहगे भी हैं। इनके साथ ही कोचिंग और ट्यूशन की संस्थाओं का जाल भी पसरता जा रहा है और आज उनकी वैसाखी पर प्रतियोगिता में सफलता का दारोमदार है। उनकी स्थिति कितनी खतरनाक है यह विगत दिनों हुए हादसों से अनुमान लगाया जा सकता है।

शिक्षा संस्थाओं में औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था चिंताजनक हो रही है। शिक्षक-प्रशिक्षण के नाम पर अभी हम लोग प्रभावी कदम नहीं उठा सके हैं। इन सबके पीछे ज्ञान के अतिरिक्त राजनीति, भ्रष्टाचार और अवांछित हस्तक्षेप प्रमुख कारण हैं। आज सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की लगातार गिरावट चिंता का विषय है। इन सबके मूल में शिक्षकों की समुचित भागीदारी की कमी है चाहे वह योग्यता और कौशल की कमी के कारण हो या फिर उनके मन में पल रहे असंतोष के चलते हो। समाज के भविष्य को गढ़ते तराशते इन शिक्षकों का कई तरह से शोषण हो रहा है। उनकी स्थिति को सुधारने पर सरकारों को वरीयता से विचार करना होगा। यदि विकसित भारत का स्वप्न साकार करना है तो गुरु संस्था को सशक्त बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

प्रसंगवश

कोचिंग को लेकर कानून बनाना ही काफी नहीं, सतत निगरानी की जरूरत

बच्चों को अवसादग्रस्त होने से बचाना सबकी प्राथमिकता में हो शामिल

कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण को लेकर राजस्थान विधानसभा ने प्रवर समिति से आए विधेयक को पारित कर कानून का रूप दे दिया है। कोचिंग संस्थानों, अभिभावकों और सरकार तीनों से जुड़े इस अहम कानून की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कोई भी कानून बने उससे सभी पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट हों ऐसा संभव भी नहीं होता। इसकी बड़ी वजह संबंधित पक्षों के अलग-अलग हित जुड़े होना है। राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 की कहानी भी कमोबेश ऐसी ही थी इसीलिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। अभिभावकों की सदैव यह उम्मीद रहती है कि कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाया जाए, पढ़ाई का माहौल रहे और बच्चों पर अनावश्यक मानसिक दबाव भी न हो। विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में भी बेहतर माहौल और सुरक्षित प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। कोचिंग संस्थान संचालक अपने व्यवसाय के लाभ पर जोर देते रहे हैं।

कोचिंग छात्र-छात्राओं के आत्महत्या करने के बढ़ते मामलों को लेकर अदालतों ने भी समय-समय पर सरकारों का ध्यान दिलाया है। सरकार की मंशा भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की रही है। हालांकि सदन में चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष की यही शिकायत रही कि विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए विधेयक में अभिभावकों के सुझावों को नजरअंदाज किया गया है। बहरहाल, कानून की सफलता भविष्य के गर्भ में है। आत्महत्या जैसी समस्याएं, सामाजिक दबाव और कोचिंग संस्थाओं की ओर से वसूले जाने वाले छिपे हुए शुल्क जैसे मुद्दे अभी अधूरे से ही हैं। यह कानून लाने की मूल भावना कोचिंग संस्थानों द्वारा अभिभावकों का शोषण रोकने व बच्चों को अवसादग्रस्त होने से बचाने की है। छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग उद्योग से जुड़े इस अहम कानून के प्रावधान लागू हो रहे हैं अथवा नहीं, इसकी सतत निगरानी करना ज्यादा जरूरी है। अभी से ही ऐसा मानना जल्दबाजी होगा कि अब सब-कुछ ठीक ही होगा।

- महेन्द्र सिंह शेखावत
Mahendra.shekhawat@in.patrika.com

शिक्षक पढ़ाते ही नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं

वासुदेव देवनानी
विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान
@patrika.com

शिक्षक दिवस ज्ञान, संस्कार, राष्ट्र निर्माण और आत्म निरीक्षण का पर्व है और इस दिवस का सही संदेश सही अर्थों में शिक्षकों का सम्मान करना है। यह केवल एक दिन की औपचारिकता न होकर जीवनभर की कृतज्ञता होनी चाहिए। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जगाते हैं, प्रश्न पूछने और सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। समाज उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे आने वाली पीढ़ी को सिर्फ नौकरी पाने योग्य ही न बनाएं, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और सृजनशील नागरिक भी बनाएं।

मैं स्वयं एक शिक्षक रहा हूं इसलिए शिक्षा के महत्त्व और इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी भलीभांति समझता हूं। मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि शिक्षा में स्थानीय और राष्ट्रीय नायकों को उचित स्थान मिलना चाहिए। इस भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने शिक्षा मंत्री कार्यकाल के दौरान राजस्थान में लगभग 200 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विभूतियों को शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ा था, ताकि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण केवल विदेशी विचारकों तक सीमित न रहकर भारतीय महापुरुषों से भी समृद्ध हो।

भारत में शिक्षा को सदैव राष्ट्र निर्माण का मूल आधार माना गया है। समय-समय पर शिक्षा की नीतियों में बदलाव होते रहे हैं, किंतु नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी-2020) ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। यह नीति केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और भविष्य निर्माण पर केंद्रित है। इस नीति को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की है। यदि शिक्षक नीति की आत्मा को समझकर उसे व्यवहार में लाएंगे, तभी इसका वास्तविक लाभ विद्यार्थियों और समाज तक पहुंच सकेगा। इसलिए आज के संदर्भ में शिक्षक से अपेक्षाएं और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाना है। इससे अपेक्षा है कि शिक्षक केवल विषय-ज्ञान देने तक सीमित न रहें, बल्कि कला, विज्ञान, खेल, कौशल और नैतिक शिक्षा को जोड़कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें। नई शिक्षा नीति ने छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करने पर बल दिया है। शिक्षक से अपेक्षा है कि वे छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें सोचने, तर्क करने और नवीन प्रयोग करने की दिशा दें। इस प्रकार छात्र जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनेंगे।

नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर जोर दिया गया है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपनी स्थानीय भाषा और संस्कृति को शिक्षा का आधार बनाएं, ताकि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। साथ ही, वे उन्हें वैश्विक भाषाओं और ज्ञान से भी परिचित कराएं। डिजिटल शिक्षा आज के समय की आवश्यकता है। शिक्षकों से यह अपेक्षा भी है कि वे स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन माध्यम, वर्चुअल लैब और ई-लर्निंग संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें। वे स्वयं तकनीकी रूप से दक्ष हों और छात्रों को भी बदलते तकनीकी वातावरण के अनुरूप तैयार करें। नई शिक्षा नीति अनुसंधान और नवाचार आधारित शिक्षा की पैरवी करती है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक न बांधकर उन्हें प्रयोग, प्रोजेक्ट और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें।

नई नीति में शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर भी बल दिया गया है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे समय के साथ स्वयं भी सीखते रहें। जो शिक्षक नए ज्ञान और तकनीक को आत्मसात नहीं करेगा, वह विद्यार्थियों को तैयार नहीं कर पाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक की भूमिका और अधिक व्यापक हो गई है। अब वे केवल अध्यापक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत, नवाचारक और मूल्यनिष्ठ राष्ट्र निर्माता हैं। भारत के भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे शिक्षक कितने समर्पित, प्रशिक्षित और दूरदर्शी हैं। वास्तव में, यदि शिक्षक नई शिक्षा नीति की भावना को अपनाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में पुनः विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

आपकी बात

बहुआयामी स्तर पर होंगे बदलाव

सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण से दैनिक जीवन की वस्तुओं से लेकर शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुआयामी स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह भारत की डिजिटल संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करेगी। **- दिनेश चौधरी**, सिरोही

तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी

सेमीकंडक्टर चिप बनने के बाद तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रक्षा और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। **- दीक्षिता साहू**, धमतरी

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, सेमीकंडक्टर चिप देश में ही बनने के बाद तकनीकी क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन होने की उम्मीद है?' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/8cBtV

आज का सवाल

जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 5 सितम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

मैं एक ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो अपने द्वारा सृजन किए गए लोगों को पुरस्कृत करे और सजा दे, यह बस मनुष्य के दोष का प्रतिबिंब है।
-अल्बर्ट आइंस्टाइन

बढ़ती छटपटाहट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि भारत टैरिफ लगा कर हमें मार रहा है। एक रेडियो शो में उन्होंने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील अपने ऊंचे टैरिफ से अमेरिका को मार रहे हैं। ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को जंग सुलझाने वाले हथियार बता रहे हैं, परंतु बातचीत को बेहतरीन ताकत कहा। साथ ही, दावा किया उन्होंने सात जंगें रोकी हैं। अमेरिका को दुनिया की रीढ़ बताते हुए बाइडेन प्रशासन की टैरिफ नीति की आलोचना भी की। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा कर इसे कुल 50% कर दिया था, जिसे कम करने के संकेत बार-बार दिए जा रहे हैं। परंतु ट्रंप के मंत्रियों का कहना है कि रूस से तेल खरीद बंद करने के बाद अतिरिक्त टैरिफ खत्म किया

जाएगा। जिस हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल की बात ट्रंप कर रहे हैं, उस पर अपने पिछले कार्यकाल में वह खुद काफी सख्त रवैया दिखा चुके हैं। फोर्ब्स के अनुसार इस कंपनी का मार्केट कैप इस वर्ष पौने तीन अरब डॉलर था। चूंकि यह विशिष्ट और समृद्ध लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बाइक है, इसलिए भारत सरकार ने इस पर लगाए गए टैरिफ को कम करने पर कभी विचार ही नहीं किया। हालांकि अमेरिकी अदालत द्वारा अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए अक्टूबर तक की मोहलत दी है। इसलिए घबराने या अफरा-तफरी की जरूरत नहीं। भारत दुनिया भर के लिए बड़ा बाजार है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए हर बड़ी कंपनी को यहां कारोबारी विस्तार में रुचि है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई से लेकर यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ समझौते हो चुके हैं, या बात आगे बढ़ रही है। बेशक, अमेरिका के साथ इस टैरिफ वॉर का देश के निर्यात और आर्थिक प्रगति पर असर पड़ने की आशंकाएं हैं क्योंकि सात लाख करोड़ रुपये का सामान भारत द्वारा वहां निर्यात किया जा रहा था, जो 50% टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद को शंति दूत बताने का ट्रंप का दांव स्वात:सुखाय ज्यादा लगता है। जिन युद्धों को रोकने में वे मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहे हैं, उसे लेकर दुनिया कायल नहीं नजर आती। शांति का नोबेल झटकने की उनकी रणनीति में भारत ही नहीं, चीन और रूस भी रोड़ा लग रहे हैं। इसलिए उनकी खीज स्वाभाविक कही जा सकती है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है।

कुदरत का कहर

पिछले कुछ दिनों से देश के अधिकांश हिस्सों, विशेषकर उत्तरी भारत में लगातार बारिश ने एक तरह से आफत की बरसात कर रखी है। जम्मू-कश्मीर में मूसलाधार बारिश जारी है, वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बुधवार को फिर भूस्खलन हुआ, पंजाब में बुधवार को एक बार फिर से भारी बारिश होने से बाढ़, जो राज्य में 1988 के बाद से सर्वाधिक भीषण है, और भी भयावह हो गई, लगातार बारिश से राजस्थान के कई हिस्से जलमग्न हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ में एकाएक आई बाढ़ से चार लोगों की मृत्यु हो गई और तीन अन्य लापता हो गए। तीन लोग घायल भी हुए। दिल्ली-एनसीआर में भी बीते कई दिनों ने रुक-रुक कर बारिश होने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। दिल्ली

में यमुना नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर है, और हथिनीकुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़े जाने से स्थिति और भी भयावह हो सकती है। यमुना का जल स्तर निकासी निशान को पार करने के बाद पुराने रेल पुल पर वाहनों के साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया है, और 44 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित ज्यादातर राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में जनजीवन को पटरी से उतार दिया है, और फसले बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं, और रेल, सड़क, और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोगों को परामर्श दिया गया है कि संवेदनशील स्थानों से दूर रहें और आपात स्थिति में हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ के जवान बचाव और राहत कार्यों में प्राणपण से जुटे हैं। यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं है कि इंसानी गलतियों के चलते मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं। विकास के नाम पहाड़ी इलाकों में नदियों के प्रवाह बाधित किए गए तो सड़क बिछाने के नाम पर जमीन खोखली कर दी गई। शहरों में जल निकासी के मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए जिसके चलते हर शहर-कस्बे में कुछ घंटों की बारिश ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देती है। इसी प्रकार नहरों के रखरखाव पूरे साल उपेक्षित रहते हैं, और मानसून के दिनों में वे समुद्र जैसी दिखलाई पड़ने लगती हैं। जरूरी है कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए हम तत्परता दिखाएं। एकजुट तत्परता के आगे कुदरती मुसीबत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी।

शिक्षक दिवस/प्रो. आर.के. जैन

गुरु का बदलता स्वरूप

शिक्षक दिवस, जिसे भारत में हर साल 5 सितम्बर को उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है, केवल औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और जीवन मूल्यों का जीवंत महोत्सव है। यह दिन हमें डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षाविद् की याद दिलाता है, जिन्होंने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। आज यह दिन न केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित रह गया है, बल्कि हमें हर उस व्यक्ति को सम्मानित करने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को नये अर्थ, दिशा और संभावनाओं से समृद्ध करता है। परंपरागत रूप से, शिक्षक वह गुरु था जो ज्ञान का दीप जलाता था, और शिष्य उसकी रोशनी में जीवन पथ पर आगे बढ़ता था, लेकिन आधुनिक युग में शिक्षक की परिभाषा और अधिक व्यापक हो गई है।

आज शिक्षक वह नहीं जो केवल किताबी ज्ञान दे, बल्कि वह है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने, चुनौतियों का सामना करने और मूल्यों को अपनाने की कला सिखाता है। यह माता-पिता हो सकते हैं, जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, दोस्त जो कठिन समय में हौसला देते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति जिसकी सलाह हमारे जीवन को नया मोड़ देती है। शिक्षक दिवस को नये दृष्टिकोण से देखना यही है कि हम इसे केवल एक व्यक्ति या पेशे तक सीमित न करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज का हर वह व्यक्ति है, जो हमें कुछ सिखाता है। एक बच्चा अपनी मासूम जिज्ञासा से नया दृष्टिकोण देता है, एक सहकर्मी सहयोग और नेतृत्व की कला सिखाता है, और हमारी असफलताएं भी हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती हैं। इस तरह शिक्षक दिवस एक दिन का उत्सव भर नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की प्रक्रिया का सम्मान है, जो हमें हर पल बेहतर बनाती है। यह हमें अहसास कराती है कि ज्ञान का कोई एक स्रोत नहीं है-बल्कि यह जीवन के हर अनुभव, हर रिश्ते और हर क्षण में बिखरा हुआ है। शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ऐसा मूर्तिकार है, जो संवेदनशीलता, मानवीयता और नैतिकता को आकार देता है। आज के युग में, जब तकनीकी प्रगति दुनिया को तेजी से बदल रही है, शिक्षक हमें सिखाता है कि असली प्रगति मशीनों या व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सामूहिक कल्याण में निहित है। सच्चा शिक्षक वही है, जो हमें बदलते समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है।

दंभ ज्यादा, 'ट्रंप' कम

अमेरिकी टैरिफ

प्रेम प्रकाश

हाल में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन ने बहुचर्चित विक्ट्री डे परेड मनाया। इस मौके पर चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दुनिया को दिखाईं। यही नहीं, परेड की सलामी लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग माओ जैसी पोशाक में पहुंचे। जिनपिंग ने बेलाग लहजे में कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है।

गौरतलब है कि इस तरह की तमाम छवियां और घोषणाएं दिखा रही हैं कि अमेरिका के सैन्य और आर्थिक सामर्थ्य के साथ विश्व के शीर्ष राष्ट्र होने के उसके दावे को चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि जिंनपिंग के रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की एक साथ चहलकदमी जब कैमरे में कैद हुई सबसे ज्यादा हैरान जो देश हुआ, वह था अमेरिका। यह दुनिया में बड़े परिवर्तन के गाढ़े संकेत हैं। निश्चित रूप से भविष्य की दुनिया में चौधराहट की भाषा बोलने का लाइसेंस किसी एक देश के पास नहीं होगा। इस स्थिति को थोड़े ठहराव के साथ देखें-समझें तो पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद न सिर्फ अमेरिका की, बल्कि इसने पूरी दुनिया की स्थिति और संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। आम तौर पर नई सरकार बनने के बाद हर देश में स्थिति बदलती है, नये सिरे से नीतिगत प्राथमिकताएं तय होती हैं। भारत खुद इस स्थिति को बीते दशक से देख रहा है। रही बात अमेरिका की तो ट्रंप ने सत्ता में दोबारा वापसी करके अपना सियासी दमखम दिखाया है।

राष्ट्रपति बनने के बाद से वे लगातार अपनी नीति और बयानों से दुनिया को हतप्रभ किए हुए हैं। अलबत्ता, विमर्श की दुनिया में ट्रंप की मानसिकता और प्राथमिकताओं को कहीं से भी न तो सुविचारित ठहराया जा रहा है, न ही इससे अमेरिकी हितों को लेकर कोई दूरदर्शी विजन मान रहा है। ट्रंप नीति के जिन दो सिरों को लेकर लगातार चर्चा है, वे हैं उनकी व्यापार और हथियारों को लेकर दुनिया के देशों से करार। बड़ी बात यह है कि अब तक ऐसा कोई आकलन सामने नहीं आया है, जिसमें इन दोनों मुद्दों पर ट्रंप के विवेक और निर्णय को अमेरिका सहित पूरे विश्व के लिए शुभ माना गया हो। हाल में इस लिहाज से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के साथ इस्राइल के संघर्ष के बीच अमेरिका के अचानक कूद जाने के फैसले से उसके 25 फीसद जरूरी हथियार खत्म हो चुके हैं। यह हैरान करने वाली स्थिति है। ईरान-इस्राइल युद्ध में अमेरिका ने थाड मिसाइल इंटरसेप्टर्स का 25 फीसद स्टॉक इस्तेमाल किया जबकि वहां इसका उत्पादन बेहद धीमा है। यह खुलासा सीएनएन की एक रिपोर्ट में हुआ है। इस

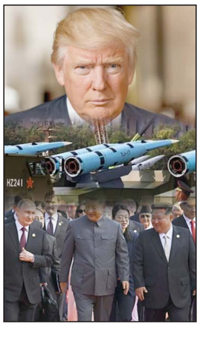

रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें 2024 में 11 और अगले वर्ष तक अमेरिका 37 इंटरसेप्टर्स ही बना सकेगा। गौरतलब है कि थाड मिसाइल, जिसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा जाता है, अमेरिका की ताकतवर एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है।

इसका मुख्य काम छोटी और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में रोकना और नष्ट करना है। दुनिया में युद्ध की मौजूदा सूरत में इस तरह की उच्च तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल अमेरिका की बड़ी ताकत तो है ही, इसका लोहा दुनिया के बाकी देश भी मानते हैं। रक्षा विषयों पर नजर रखने वाले भूले नहीं है कि थाड को 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराक द्वारा दागे गए स्कड मिसाइलों के जवाब में विकसित किया गया था। आज की तारीख में अमेरिका ने इसे संयुक्त अरब अमीरात, इस्राइल, रोमानिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में बने सैन्य अड्डों पर तैनात कर रखा है। जिस थाड की ताकत पर अमेरिका ने ईरानी हमलों से अपना बचाव किया, उसकी एक और बैटरी हाल में उसने इस्राइल को भी भेजी है, जो ईरान से बढ़ते तनाव के बीच एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। अमेरिकी दावे कुछ भी हों पर इस तथ्य को छिपाना मुश्किल है कि ईरान और इस्राइल के बीच चले 12 दिनों के हालिया युद्ध ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान अमेरिका ने बचाव के लिए खास तौर पर थाड इंटरसेप्टर्स को ही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किए थे। सीएनएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान पर 100 से 150 के करीब थाड इंटरसेप्टर दागे। ऐसे में इस मिसाइल की बची हुई उपलब्धता अमेरिका के लिए एक बड़े संकट की तरह है।

अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो न तो अमेरिका खुद की और न ही साथी मुल्क की थाड के जरिए अपेक्षित तरीके से सुरक्षा कर पाएगा। इस बात से इनकार नहीं है कि पेंटागन का 2025-26 के बजट में मिसाइल सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर खासा जोर है। उसने अपने बजट में 1.3 अरब डॉलर आपूर्ति श्रृंखला सुधार और 2.5 अरब डॉलर मिसाइल उत्पादन पर खर्च करने का फैसला किया है। यह कदम खास तौर पर ईरान और रूस के जंगी रुख के कारण उठाया गया है। इन दोनों मुल्कों के आक्रामक तेवर ने अमेरिका को यह सोचने पर विवश किया कि उसकी मौजूदा एयर डिफेंस प्रणाली मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका के साथ ईरान ने हालिया संघर्ष में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। थाड के जोर पर अमेरिका इनमें 86 फीसद को ही इंटरसेप्ट कर पाया था। यह भी एक विरोधाभास ही है कि एक ऐसे दौर में जब अमेरिकी समाज में गन कल्चर हावी हो रही है, यह देश खुद सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई तरह की चिंता से घिरा है।

अगर सब कुछ समय से सामान्य नहीं हुआ तो कल का इतिहास इस बात को हिकारत के साथ कहेगा कि जिस डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के गौरव को वापस लाने के नाम पर सत्ता में वापसी की, उनके दौर में अमेरिकी समाज का ताना-बाना तो तांबे और पीतल की गोलियों से छिन्न-भिन्न हो ही रहा था, यह देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर भी सबसे खतरनाक और नाजुक दौर से गुजर रहा था। यह देखने वाली बात होगी कि ट्रंप शासन की आक्रामक व्यापार नीति उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मददगार होगी कि नुकसानदेह। अगर इस बारे में कोई कयास ही लगाना हो ते हम कह सकते हैं कि बड़बोले ट्रंप ने अमेरिका के लिए जोखिम और खतरों को ही अब तक ज्यादा बढ़ाया है, उसके आगे अवसर और लाभ की जमीन लगातार कम पड़ती जा रही है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> सब कुछ समय से सामान्य नहीं हुआ तो कल का इतिहास हिकारत के साथ कहेगा कि जिस ट्रंप ने अमेरिका के गौरव को वापस लाने के नाम पर सत्ता में वापसी की, उनके दौर में अमेरिकी समाज का ताना-बाना तो तांबे और पीतल की गोलियों से छिन्न-भिन्न हो ही रहा था, यह देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर भी सबसे खतरनाक और नाजुक दौर से गुजर रहा था। देखने वाली बात होगी कि ट्रंप शासन की आक्रामक व्यापार नीति उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मददगार होगी कि नुकसानदेह

ग्रीन-टी

वजन कम करने से लेकर दिल की सेहत तक, सबमें असरदार है

■ बदलती दिनचर्या और बढ़ते तनाव के बीच आज लोग पहले से कहीं ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए हैं। इसी सेहतमंद बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बनी है 'ग्रीन-टी', जो अब भारतीय रसोई में भी अपनी जगह बना चुकी है

■ माना जाता है कि ग्रीन-टी के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं, और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ग्रीन-टी को वैज्ञानिक भाषा में कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है। इसमें दूध या चीनी नहीं डाली जाती और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए यह काफी फायदेमंद मानी जाती है

(मीडिया इनपुट्स)

भारत पर ट्रंप का टैरिफ निराशाजनक घटनाक्रम है, लेकिन यह भारतीय नेताओं के उनके प्रति अपनापे, जिसमें उनकी चुनावी जीत के लिए अभियान चलाना भी शामिल है, का ही खमियाजा है। अच्छा लगा देख कर कि भारत गुटनिरपेक्षता और तमाम देशों के साथ आर्थिक सहयोग संबंधी नेहरू की नीति की तरफ लौटता दिखलाई पड़ रहा है।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

जलभराव का जिम्मेदार कौन

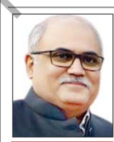

गुरुग्राम **रजनीश कपूर**

आज का गुरुग्राम, जिसे 'मिलेनियम सिटी' और 'साइबर सिटी' जैसे गौरवशाली नामों से नवाजा जाता है, हर साल मानसून के आगमन के साथ जल में डूबे नरक में तब्दील हो जाता है। महज दो घंटे की बारिश शहर को घुटनों तक पानी में डुबो देती है। सड़कों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। करोड़ों रुपये की कीमत वाले आलीशान घरों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त हो उठते हैं। यह विडंबना है कि एक ओर गुरुग्राम भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में से एक है, जहां लोग भारी-भरकम टैक्स और किराए चुकाते हैं, वहीं सरकारी विभागों की लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी के कारण यह शहर हर बारिश में डूब जाता है।

हाल में प्रसिद्ध लेखक और उद्यमी सुहेल सेठ ने एक सार्वजनिक मंच पर हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने गुरु ग्राम की स्थिति को 'शर्मनाक' करार देते हुए कहा, ''गुरुग्राम खत्म हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। बीजेपी को गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। वे 11 साल से इस राज्य को चला रहे हैं, अब नेहरू को दोष नहीं दे सकते।'

सुहेल सेठ ने अपनी एक अन्य टिप्पणी में कहा, 'क्या नालों की सफाई के लिए रॉकेट साइंस चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।' इस शहर का बुनियादी ढांचे के मामले में इतना पिछड़ा होना न केवल शर्मनाक है, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता को भी दर्शाता है। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर मानसून के दौरान शहर की सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, और प्रमुख मार्ग जैसे गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, और दिल्ली-जयपुर हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहता है। एक सितम्बर, 2025 को महज चार घंटे की बारिश में 100 मिमी. से अधिक वर्षा दर्ज की गई जिसने शहर को पूरी तरह ठप कर दिया। नेशनल हाईवे-48 पर 7 किमी. लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सोशल मीडिया पर निवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा किए जिनमें गोल्फ कोर्स रोड जैसे पॉश इलाकों में गहरे पानी में डूबी गाड़ियां और फंसे हुए लोग दिखाई दिए।

गुरुग्राम में जन्मे और वहीं पर बसे सफल उद्यमी और समाजसेवी शरद गोयल ने हाल में एक चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा, 'इस संकट का मूल कारण है शहर का अनियोजित शहरीकरण और सरकारी विभागों में आपसी तालमेल का अभाव। आज गुरुग्राम अनियंत्रित निर्माण और बुनियादी ढांचे की कमी का शिकार है। गुरु ग्राम की पुरानी भौगोलिक संरचना में कई प्राकृतिक जलाशय और नाले थे, जो बारिश के पानी को संचित करते थे। लेकिन तेजी से हुए निर्माण ने इन जल निकायों को नष्ट कर दिया।' वे आगे कहते हैं, 'जनता बारिश और जल भराव से त्रस्त होती है लेकिन जनप्रतिनिधि कभी भी ऐसे मौकों पर सड़क पर दिखाई नहीं देते। नेताओं को छोड़िए निगम के अधिकारी भी ईद का चांद बने हुए हैं, जो केवल अनियमितताओं के चलते ही हरकत में आते हैं। अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कभी भी जनता के बीच नहीं दिखाई देते। सरकारी विभागों के बीच जवाबदेही का अभाव समस्या को और गंभीर बनाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम (एमसीजी), हरियाणा अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) जैसे विभिन्न निकाय एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं करता। गुरुग्राम हो या देश अन्य कोई शहर, सभी को इंदौर से सबक लेना चाहिए जहां के अधिकारी और जनता सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां पूर्णतः निभाते हैं, और सुखी रहते हैं।'

समाधान के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ शहरी नियोजन की जरूरत है। प्राकृतिक जल निकायों के पुनर्जनन, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुओं का निर्माण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। हर वो अधिकारी जो गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में तैनाती पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाता है वो यहां आते ही काम करने से क्यों बचता है? यदि उस पर काम न करने पर तबादले की तलवार लटका दी जाए या कुछ आलसी अधिकारियों का तबादला कर दिया जाए तो इससे बाकी अधिकारियों के बीच सही संदेश जाएगा। गुरुग्राम को 'मिलेनियम सिटी' का दर्जा बनाए रखने के लिए आलीशान इमारतें और कॉरपोरेट कार्यालय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसे ऐसा शहर बनाना होगा जो अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर सके। जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते, तब तक गुरुग्राम हर मानसून में डूबता रहेगा और निवासियों की निराशा बढ़ती रहेगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

परेशानियां **श्री राम शर्मा आचार्य**

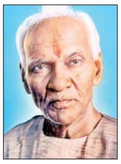

मनुष्य अपनी तमाम परेशानियों से छूटने का उपाय कर रहा है। वस्तुतः उसका सारा उद्योग, परिश्रम और पुरुषार्थ है ही केवल परेशानियां कम करने और कष्टों से छूटने के लिए। किंतु उसके कष्टों में कमी के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। मनुष्य अंधकार में हाथ-पांव मारता हुआ सुख की दिशा की बजाय भ्रम की वीथियों में भटकता फिर रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य अपनी खुशियों का कारीगर होता है बशर्ते अपने सुखों के लिए ईमानदारी से प्रयास करे। लेकिन वह सुख-सुविधाएं जुटाने के फेर में उचित-अनुचित का भेद नहीं रख पाता और परिणामस्वरूप तमाम परेशानियों से दो-चार होने को अभिशप्त हो जाता है। सुख के प्रयास में दुःख ही पाता चला जा रहा है। निस्संदेह मनुष्य की यह दुर्दशा दया की ही पात्र है। संसार में अशक्य अथवा असाध्य कुछ भी नहीं है। उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ, दृढ़ निष्ठा, उपयुक्त दृष्टिकोण, मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा की आवश्यकता है। तृष्णा भयानक अजगर के समान है। जब यह किसी मनुष्य में अनियंत्रित हो जाती है तो संपूर्ण संसार को निगल जाने की इच्छा किया करती है। अपनी इस अनुचित इच्छा से प्रेरित होकर जब मनुष्य अग्रसर होता है, तब भयानक संघर्ष, विरोध एवं बैर में फंस कर चोट खाता और तड़पता है। स्वार्थ से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि मानसिक विकृतियों का जन्म होता है, जो स्वयं ही किसी अन्य साधन के बिना मनुष्य को जला कर भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त होती हैं। दृष्टिकोण की अव्यापकता भयानक बंदीगृह है, जिसमें बंदी बना मनुष्य एकाकीपन और सूनेपन से घिर कर तड़पता-कलपता रहता है। संकीर्ण दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपनी मान्यताओं, विश्वासों अथवा भावनाओं से भिन्न किसी भावना, विश्वास अथवा मान्यता को सहन नहीं कर पाता। किसी दूसरी सभ्यता अथवा संस्कृति को फूटी आंख भी फलते-फूलते नहीं देख सकता। जो उससे संबंधित है, वही सत्य है, शिव है, और सुंदर है, अन्य सब कुछ अमंगल एवं अशुभ है। विविधताओं, विभिन्नताओं एवं अन्यताओं से भरे इस संसार में भला इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति किस प्रकार सुखी रह सकता है? उससे भिन्न मान्यताएं उठेंगी, विविधताएं व्यग्र करेंगी और भ्रांतियां उत्पन्न होंगी।

रीडर्स मेल

बसपा के चुनावी फैसले

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दनादन फैसले लेते हुए 22 राज्यों के अध्यक्षों को नियुक्त किया है और चुनाव के हिसाब से देश को छह क्षेत्र में बांट कर रणनीति तैयार की है। संभवत यह पहली बार है कि इस तरह से व्यापक स्तर पर नियुक्ति की गई है और बाकायदा प्रेस में इसकी जानकारी दी गई है। एक बार फिर आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। इसी के साथ नवम्बर में होने वाले बिहार के चुनाव की कमान भी आकाश आनंद को सौंप दी गई है। बसपा का सारा दमदार 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिका हुआ है लेकिन बिहार के चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं। इस बार बसपा ने बिहार में अकेले लड़ने का फैसला किया है। देखना यह भी महत्त्वपूर्ण होगा कि बिहार चुनाव को चौकोणीय बनाने में कितना कामयाब होगी। बिहार में एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक नंबर तीसरा कोण है जनसुराज पार्टी का और बसपा बिहार के चुनाव को चोकोणीय बनाने में लगी है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

जीएसटी संबंधी फैसला राहतकारी

जीएसटी परिषद का यह फैसला जनता के लिए निश्चित रूप से राहत भरा है। लंबे समय से लोग टैक्स ढांचे की जटिलता से परेशान थे। अब केवल दो मुख्य स्लैब होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और कर चुकाने की प्रक्रिया आसान होगी। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाना मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा सहारा है। तंबाकू और शराब जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाकर सरकार ने सकारात्मक संदेश दिया है कि विलासिता और हानिकारक वस्तुएं महंगी होंगी जबकि जरूरी वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। यह निर्णय न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी है, बल्कि इससे कर चोरी पर अंकुश लगेगा। सरकार को चाहिए कि इस नये ढांचे को सख्ती और पारदर्शिता से लागू करे ताकि इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। लंबे समय से जटिल टैक्स ढांचे की शिकायत की जा रही थी। अब केवल दो दरें होने से प्रणाली आसान होगी और कर चोरी पर रोक लगेगी। तंबाकू और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर भारी टैक्स लगना समाज के लिए भी लाभकारी है।

आराध्या सिंह, आजमगढ़

व्हाइट हाउस को झटका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से देश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपना आदेश जारी कर रहे थे, उन सब पर एक एक-करके रोक लगना शुरू हो गया है। यह तो होना ही था। गलत को आखिर, कब तक आप सही ठहरा सकते हैं? न्यायाधीशों ने टैरिफ के लिए ट्रंप के औचित्य को खारिज कर दिया, उसके बाद लॉस एंजेल्स में संघीय सैनकों की अवैध तैनाती को खारिज कर दिया गया, जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार को खत्म करने वाला आदेश अदालत ने अवैध घोषित कर दिया, मेरीलैंड के न्यायधीशों पर ट्रंप द्वारा चलाये जा रहे मुकदमे को भी अदालतों ने गंभीरता से लिया है। 3 सितम्बर को एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संघीय अनुसंधान निधि को रोक कर संविधान का उल्लंघन किया है। इससे व्हाइट हाउस को तेज झटका लगा है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 22
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011- 23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ऐसे शिक्षक... जो शिक्षा को घर-घर ले जा रहे हैं

पढ़ाई के अपने अलग तरीकों से देशभर में अपनी पहचान बनाने वाले शिक्षकों से आज सीखिए जीवन को सफल बनाने के गुर। साथ ही पढ़िए दुनियाभर की महान हस्तियों द्वारा अपने शिक्षकों के बारे में लिखी गई बातें, शिक्षा की इनोवेटिव एप्रोच और गुरु मंत्र...

सफलता का एक ही मंत्र रोज खुद का आकलन हो

नितिन विजय
मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक

मानसिक स्वास्थ्य आज की बड़ी समस्या है। टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को सिखाएं कि मानसिक स्वास्थ्य की आने वाली समस्याओं से कैसे लड़ें।

नंबर और रिजल्ट सिर्फ कॉम्पीटिशन के लिए जरूरी हैं। आप जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे ये किसी एग्जाम के मार्क्स या रिजल्ट तय नहीं करेंगे। पहले मैं भी बच्चों को क्लास के दौरान कहता था कि कॉम्पीटिशन जंग है। लेकिन अब कहता हूं कि ये जंग नहीं है, केवल जीवन का पड़ाव है, जिसमें हमें अपना बेस्ट देना है। कॉम्पीटिशन कई रूप में जीवनभर चलता है। ऐसे में जीवन में सफल होने के लिए कॉम्पीटिशन की आदत डालना जरूरी है। संघर्ष की प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है।

बच्चों को समझना चाहिए कि पढ़ने का मतलब अकेले पढ़ना नहीं है। 12 घंटे या 8 घंटे पढ़कर ही सफलता मिलेगी, ऐसा नियम नहीं है। अगर अकेलापन लगता है तो दोस्तों के साथ पढ़िए। डिप्रेशन और हैप्पीनेस ये माइंडसेट हैं। हम डिप्रेशन में तब आते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं और हम फेल तब होते हैं, जब टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमेशा टारगेट अपनी स्किल और काबिलियत के अनुसार सेट करें।

टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि समझें कि बच्चे ने जो ट्रैक चुना है वे उसकी इच्छा और काबिलियत को मैच करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो उसे मना कर देना चाहिए। अगर करता है तो उसे सही दिशा और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

आज पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट हैं। कहीं से भी कोई पढ़ सकता है। 20-25 साल पहले कंटेंट की समस्या थी। आज कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन कौन-सा सही कौन-सा नहीं, ये समस्या है। 10 साल बाद समाधान खोजना समस्या नहीं होगी, आप जो पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा। लेकिन बच्चों को उसके लिए तैयार करना होगा। ताकि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और सही सवाल पूछ पाएं। हर बच्चे की काबिलियत अलग होती है। पहले गुरुकुल प्रणाली में हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। एआई से अफॉर्डेबल कस्टमाइज प्रणाली बना सकते हैं।

एआई... चुनौती, अवसर और सतर्कता जरूरी

1. एआई चुनौती नहीं अवसर है। इससे नए सवाल बना सकते हैं, नई थ्योरी बना सकते हैं, नया कंटेंट बना सकते हैं, उसे शॉर्ट कर सकते हैं। चुनौती उनके लिए हो सकती है, जो इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं।
2. सफलता का एक ही मंत्र यह है कि आपकी खुद से ही रेस होना जरूरी है। हर दिन खुद से आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुझमें क्या कमी है। और उसे कैसे सुधारना है।
3. खुद से पूछें कि मोबाइल आपका उपयोग कर रहा है या आप मोबाइल का। पढ़ाई के दौरान 2-3 घंटे के लिए मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर उसे दूर रखें।

बच्चों की रुचि समझकर उनकी काउंसलिंग जरूरी

अवध ओझा
शिक्षाविद् और मोटिवेशनल स्पीकर

जब तक शिक्षा केवल अंक और नौकरी के दायरे में कैद रहेगी, तब तक न व्यक्ति स्वतंत्र सोच पाएगा, न समाज मजबूत बनेगा और न ही देश आगे बढ़ सकेगा।

भारत की शिक्षा व्यवस्था पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। समस्या बच्चे के नर्सरी में दाखिले से ही शुरू हो जाती है। मां-बाप उस पर टॉप करने का दबाव बनाने लगते हैं, जबकि आठवीं तक पढ़ाई का उद्देश्य बच्चों पर दबाव कम करना होना चाहिए, ताकि वे सहजता से सीख सकें। नौवीं से बारहवीं तक पढ़ाई के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास पर भी जोर होना चाहिए। यही वह उम्र है जब बोलने, समझने और विचार करने की कला सिखाई जानी चाहिए। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को जानना उतना ही जरूरी है जितना गणित या विज्ञान को। अगर ग्यारहवीं और बारहवीं में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो यह सबसे बड़ा सुधार होगा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो पाया कि नब्बे फीसदी शिक्षक केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जबकि व्यक्तित्व का विकास बेहद जरूरी है। मैंने कॉन्सेप्ट को कहानियों से जोड़ना शुरू किया, जैसा भारतीय दर्शन करता है। ध्यान सिखाना हो तो हनुमान जी का चरित्र सामने लाता। यह तरीका मैंने आचार्य रजनीश से सीखा। नतीजा यह हुआ कि कुछ छात्र कॉन्सेप्ट से जुड़े, कुछ कहानी से और दोनों का मेल कई बार पंद्रह-बीस छात्रों के चयन का कारण बन गया। तकनीक ने इस कमी को और गहरा कर दिया है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति को समझदार, विवेकशील और साहसी बनाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत है, जो व्यक्ति को जीवन जीना सिखाए, उसे समाज और देश से जोड़कर रखे और इतना सक्षम बनाए कि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। यही बदलाव भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम होगा। जब तक शिक्षा केवल अंक और नौकरी के दायरे में कैद रहेगी, तब तक न व्यक्ति स्वतंत्र सोच पाएगा, न समाज मजबूत बनेगा और न ही देश आगे बढ़ सकेगा। असली सुधार तब होगा, जब शिक्षा जीवन का मार्गदर्शन बने, न कि केवल परीक्षा पास करने का जरिया।

एआई ने हमारी चिंतन परंपरा को कमजोर किया है

1. एआई के कारण सोचने की क्षमता कम हो रही है। शोध और चिंतन की परंपरा कमजोर पड़ रही है। नई चीजों को जानने की भूख घट रही है। यही चलता रहा तो मशीनें ज्यादा समझदार और इंसान उन पर ज्यादा निर्भर होता जाएगा।
2. जो शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान देंगे, उनका महत्व खत्म हो जाएगा। पढ़ने के बाद चिंतन, बहस और नोट्स लिखना समग्र अध्ययन है। जो छात्र यह करेगा, वही आगे बढ़ पाएगा।
3. हमारे यहां काउंसलिंग की संस्कृति अब तक नहीं है। अगर सही समय पर बच्चों की प्रवृत्ति समझें और विशेषज्ञ से सलाह लें, तो बड़ी त्रासदियों से बचा जा सकता है।

किताबों से आगे; शिक्षा वही जो बच्चों को नए सपने दे

अलख पांडे
फिजिक्सवाला के संस्थापक, शिक्षक

एआई टूल्स ने क्लास को और आकर्षक बना दिया है। लेकिन बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि एआई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि सीखने में सहायक है।

आठवीं क्लास में पहली बार मैंने अपने स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। उस वक्त घर की हालत मजबूत नहीं थी, इसलिए पढ़ाना मेरे लिए सिर्फ पैशन नहीं, सहारा भी था। धीरे-धीरे यही मेरी पहचान बन गया। कॉलेज तक पहुंचते-पहुंचते मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने लगा और बच्चों से जुड़ना मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गई। मेरी टीचिंग जर्नी का सबसे भावुक पल तब आया जब एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने क्लास जॉइन करने के लिए अपने घर की बकरी बेच दी। मैंने उससे पूछा कि अगर सिलेक्ट नहीं होते तो? उसने मुस्कराकर कहा, 'सर, तब बकरी भी जाती और सपना भी।' उस दिन समझ आया कि बच्चों के सपनों की कीमत कितनी बड़ी होती है और उन्हें सही दिशा देना कितना जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। एआई टूल्स ने क्लास को और आकर्षक बना दिया है। यह बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग और टीचर्स को समय बचाने में मदद करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि असली चुनौती यही है कि बच्चों को समझाया जाए कि एआई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सीखने में सहायक है। अगर शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात हो तो मैं चाहूंगा कि यह सिर्फ मार्क्स और एग्जाम तक सीमित न रहे। क्लास 6 से ही बच्चों को नए करिअर और स्किल्स- जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी सिखाए जाएं। डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं, डिजाइनर, उद्यमी, क्लाइमेट साइंटिस्ट या फिल्ममेकर बनना भी उतना ही जरूरी है। असली शिक्षा वही है जो बच्चों को नए सपने दे और उन्हें पूरा करने की तैयारी स्कूल से ही शुरू कराए। आने वाले 10 सालों में शिक्षा पूरी तरह टेक-इनेबल्ड होने वाली है। एआई हर क्लासरूम का हिस्सा होगा। करिअर के रास्ते लगातार बदल रहे हैं और भविष्य का विजेता वही होगा जो पढ़ाई के साथ-साथ सीखने का सही तरीका भी अपनाएगा।

हर रोज खुद में सुधार लाना ही असल सफलता है!

1. असली सफलता है ईमानदारी से लगातार मेहनत करना और हर दिन अपने भीतर सुधार लाना। अगर रोज शाम को आप खुद से पूछ पाएं कि आज मैंने कल से बेहतर क्या सीखा... तो यही असली प्रगति है।
2. शिक्षा सिर्फ पढ़ाई या फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। टीचर वही है जिसके पास बच्चा सवालों के साथ अपने सपनों और परेशानियों को भी लेकर आ सके।
3. बच्चों के सपनों को नई उड़ान देना और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिंदगी का असली उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है।

शिक्षकों के नाम, हस्तियों के संदेश

अल्बेयर कामू- नोबेल विजेता

आपकी शिक्षा के बिना मुझे नोबेल संभव नहीं था

प्रिय मिस्टर जर्मेन,

इन दिनों मेरे चारों ओर जो हलचल है (नोबेल मिलने की) मैंने उसे थोड़ा शांत होने दिया, ताकि मैं आपसे दिल की गहराइयों से बात कर सकूं। मुझे अभी-अभी एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। इतना बड़ा कि न तो मैंने इसे चाहा था और न ही इसके लिए कभी प्रयास किया था। जब मैंने नोबेल मिलने की खबर सुनी, तो अपनी मां के बाद मैंने किसी के बारे में विचार किया तो वो आप ही थे। आपकी शिक्षा और स्नेहिल हाथों के बिना यह कभी भी संभव नहीं हो पाता। वैसे तो मैं इस तरह के सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। लेकिन कम से कम इसने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको बता सकूं कि आप मेरे लिए क्या रहे हो और अब क्या हो। साथ ही मैं आपको यह आश्वासन दे सकूं कि आपकी मेहनत, आपका काम और आपका उदार हृदय अब भी आपके एक छोटे से छात्र में जीवित हैं।

बिल गेट्स- माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक

लाइब्रेरी टीचर की बातों से बढ़ती गई पढ़ने में दिलचस्पी

मैं चौथी कक्षा का एक शर्मीला लड़का था, जब मेरी मुलाकात श्रीमति ब्लांश कैफियर से हुई। वह सिएटल के व्यू रिज एलिमेंट्री स्कूल की पुस्तकालयाध्यक्ष थीं। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी की नजर मुझ पर न पड़े, क्योंकि मुझमें कुछ कमजोरियां थीं- जैसे खराब लिखावट और बेतरतीब डेस्क। मैं यह भी छुपाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे पढ़ना पसंद है, क्योंकि उस समय पढ़ने का शौक लड़कियों के लिए कूल माना जाता था, लड़कों के लिए नहीं। लेकिन कैफियर मैम ने मुझे एहसास दिलाया कि किताबें पढ़ने वाला, बिखरा-सा, पढ़ाकू लड़का होना बिल्कुल ठीक है। वह मुझसे सवाल पूछतीं- तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं? फिर मुझे बहुत-सी किताबें सुझातीं। जब मैं उन्हें पढ़ लेता, तो वह पूछती तुमने क्या सीखा? कैफियर मैम के साथ बिताया समय ही वह चिंगारी था, जिसने मुझे पुस्तकालयों व पुस्तकों के प्रति आकर्षित किया और हर बच्चे को अच्छे शिक्षकों का लाभ दिलाने की मेरी कोशिशों की नींव रखी। शिक्षकों ने ही सिखाया है कई बार बिना मार्गदर्शन के क्रिएटिव होना पड़ता है।

बराक ओबामा- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति

मेरी शिक्षक ने मुझे अहसास कराया कि मैं खास हूं

मैं अपनी शिक्षा का श्रेय किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान की तरह ही मिस मेबल हेफ्टी को भी देता हूं। जब मैं 1971 में उनकी पांचवीं कक्षा में शामिल हुआ, तब मेरा अजीब सा नाम था। और तो और नए स्कूल में खुद को थोड़ा असमंजस में भी महसूस कर रहा बच्चा था। जब मिस हेफ्टी ने मुझे पहली बार बुलाया तो मैं सोच में पड़ गया था। मेरा दिल चाहता था कि काश उन्होंने ऐसा न किया होता। मैं सच में चाहता था कि मैं उस डेस्क पर नहीं होता, किसी और जगह बैठा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन उस पूरे साल मिस हेफ्टी ने मुझे सिखाया कि मेरी विभिन्नताओं के कारण ही मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। उन्होंने उस कक्षा के हर एक विद्यार्थी को खास महसूस करवाया। उन्होंने सहानुभूति के उन मूल्यों को भी दोहराया, जो मेरी मां और दादा-दादी ने मुझे सिखाए थे। ये ऐसे मूल्य हैं, जिन्हें मैं राष्ट्रपति बनकर भी हर दिन अपने साथ रखता हूं। यही है एक अच्छे शिक्षक की सरल लेकिन निर्विवाद शक्ति। वे शिक्षक ही हैं, जो हमारे बच्चों को सही आकार और मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।

अब्दुल कलाम- भारत के पूर्व राष्ट्रपति

धैर्य, अनुशासन व जीवन के मूल्य शिक्षकों ने ही सिखाए

इदुराई सोलोमन हमारे एक महान शिक्षक थे। उन्होंने हम सबको अपनी कीमत समझाई। उन्होंने हमें एहसास कराया कि अगर आपको खुद में भरोसा है तो आप किस्मत को बदल सकते हैं। वे कहते थे अगर आपमें तीन चीजें- कुछ करने की इच्छा, विश्वास और उम्मीद है तो आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। उनका मानना था कि एक अच्छा स्टूडेंट, बुरे टीचर से भी बहुत कुछ सीख सकता है, वहीं एक बुरा स्टूडेंट एक खूब स्किल्ड शिक्षक से उतना नहीं सीख सकता। शिक्षकों ने मुझे केवल किताबों से पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि उन्होंने जीवन से जुड़ी कई बातें सिखाई हैं। जीवन के असल मूल्य, अनुशासन और धैर्य भी शिक्षकों ने हमें सिखाए। मेरे स्कूल के शिक्षक जीवन के मार्गदर्शक थे। उन्होंने न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया बल्कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का पाठ भी पढ़ाया।

देश के पहले प्राइवेट स्कूल से रिपोर्ट

चेन्नई में 310 साल पुराना स्कूल, लाइब्रेरी में 300 साल पुरानी किताबें, एक लाख से ज्यादा छात्रों को किया शिक्षित

राम कुमार | चेन्नई

बामुश्किल सुबह के साढ़े आठ-पौने नौ बज रहे होंगे। मैं चेन्नई के शेनॉय नगर स्थित सेंट जॉर्ज एंग्लो-इंडियन हायर सेकंडरी स्कूल पहुंचता हूं। जैसे ही स्कूल में घंटी बजती है, बच्चे इसके लाल ईंटों से बने ऐतिहासिक कॉरिडोर में दौड़ मारते नजर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर स्कूल में अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन यह कोई आम स्कूल नहीं है, बल्कि ये तो देश का सबसे पुराना या कहें कि एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। साल 1715 में शुरू हुआ यह स्कूल 300 वर्षों उपरांत आज भी शिक्षा दान का अपना काम मजबूती के साथ कर रहा है। लाल ईंटों से बनीं स्कूल की दीवारों ने कई पीढ़ियों के छात्रों को देखा है। स्कूल से 1 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ले चुके हैं। स्कूल में हम सबसे पुरानी टीचर इसाबेल मनोहरन से मिले। इसाबेल 1974 से स्कूल से जुड़ी हैं। उन्होंने हमें बताया कि पहले यह स्कूल सिर्फ अंग्रेज बच्चों के लिए ही था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, यहां सिर्फ 40 ही एंग्लो-इंडियन बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में कुल 600 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से अधिकांश गरीब तबके से आते हैं। अपनी जॉइनिंग के दिनों को याद करते हुए इसाबेल कहती हैं कि एक समय था जब हमारे इस स्कूल में करीबन 300 एंग्लो इंडियन बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल के हेडमास्टर वेस्ली हडसन बताते हैं कि ब्रिटिश स्कूल के रूप में शुरू हुआ सेंट जॉर्ज अब गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करता है। सरकार मिड-डे मिल और एंग्लो-इंडियन छात्रों की फीस भरने के लिए हमें पैसे देती है। हम अपनी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन समय के साथ हम बदल भी रहे हैं।

ब्रिटिश स्कूल से भारतीय संस्थान तक

सेंट जॉर्ज स्कूल की शुरुआत रेव. विलियम स्टीवेंसन ने की थी। इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेंट मेरीज चर्च की मदद से चलाया जाता था। इसकी शुरुआत एक चैरिटी स्कूल के रूप में की गई थी। शुरू में यहां केवल 30 ब्रिटिश बच्चे और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। भारतीय छात्रों को यहां पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सालों में, स्कूल कई बार बदला। यह उन अनाथालयों के साथ जुड़ गया, जो ब्रिटिश सैनिकों के बच्चों की देखभाल करते थे। तीन बार स्कूल अलग-अलग इमारतों में शिफ्ट हुआ। पहली बार वहां, जहां आज एग्मोर रेलवे स्टेशन है और 1954 में अपने वर्तमान घर शेनॉय नगर में आ गया।

21 एकड़ में फैला स्कूल इतिहास को समेटे हुए है

यह स्कूल 21 एकड़ में फैला हुआ है। स्कूल का कैंपस अपने आप में जीती-जागती इतिहास की किताब है। यहां स्थित चैपल बिल्कुल वैसा नजर आता है, जैसे 1884 में था, बिल्कुल इंग्लिश गांव के छोटे चर्च की तरह। स्कूल की लाइब्रेरी भी बेहद खास है। इसमें आज भी 300 साल पुरानी किताबें रखी हुई हैं। वहीं यहां स्थित आरफेनेज बिल्डिंग भी आज भी पहले की ही तरह हरे रंग से रंगी हुई है। स्कूल की हॉकी टीम भी बहुत पॉपुलर है। इसे शहर की बेस्ट हॉकी टीम का दर्जा मिला हुआ है।

हेडमास्टर वेस्ली हडसन

टीचिंग की सबसे इनोवेटिव एप्रोच

प्रकृति में पढ़ाई से एडवांस तकनीक सीखने के तरीके

फ्लिप्ड क्लासरूम : कक्षा में चर्चा और घर पर पढ़ाई

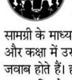

फ्लिप्ड क्लासरूम पद्धति में पारंपरिक शिक्षण की प्रक्रिया के उलट छात्र घर पर वीडियो, लेख या अन्य सामग्री के माध्यम से नया विषय सीखते हैं। और कक्षा में उस पर चर्चा व सवाल-जवाब होते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भी इस पद्धति को अपनाया है।

ग्रीन स्कूल : प्रकृति के बीच जीवन सीखते हैं बच्चे

ग्रीन स्कूल शिक्षा को प्रकृति व जीवन कौशल से जोड़ता है। बांस से बनी दीवार-मुक्त कक्षाओं में छात्र पर्यावरण, जैविक खेती, सौर ऊर्जा जैसे विषयों को सीखते हैं। रटने की जगह स्कूल सोचने, करने और समाज में बदलाव लाने पर जोर देता है। ये स्कूल बाली, न्यूजीलैंड आदि जगह मौजूद हैं।

होल इन द वॉल : बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा देने की पहल

यह अनूठी पहल भारत में हो रही है। इसमें देशभर की झुग्गियों और छोटे स्कूलों में सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर कम्प्यूटर लगाए जाते हैं। ताकि वंचित वर्ग के बच्चों को भी कम्प्यूटर की शिक्षा मिल सके। इसे होल इन द वॉल कहा गया है। इसकी मदद से अब तक 25 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा ले चुके हैं।

स्माइल : तरीका बदलने वाला मोबाइल लर्निंग मॉडल

स्टैनफोर्ड द्वारा निर्मित SMILE (स्टैनफोर्ड मोबाइल इनक्वायरी बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट) मोबाइल-आधारित शिक्षण मॉडल है, जिसमें छात्र खुद प्रश्न तैयार करते हैं, उन्हें साझा करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक गाइड या कोच का काम करते हैं।

गुरु मंत्र, जीवन बदलने वाले सबक

सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है

शिक्षकों के ये वो शब्द हैं, जो किताबों से नहीं, दिल से निकलते हैं और आत्मा को छू जाते हैं। ये सबक बनकर जीवनभर साथ चलते हैं...

गलती करने से मत डरो, गलती करने से सीख मिलती है। शिक्षक की इस बात ने जीवन में **आत्मविश्वास** की नींव रखी।

हर सवाल का जवाब किताब में नहीं होता, कुछ जवाब जीवन में खोजने पड़ते हैं। इसने मुझे नया करने के लिए **प्रेरित** किया।

अच्छे अंक के लिए कोशिश करो। असफल रहो तो प्रयास बढ़ाओ। शिक्षक की इस बात ने **मेहनती** और हार न मानने का सबक दिया।

डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई दोस्त नहीं। शिक्षक की इस बात ने **निडरता** का बीज मन में रोपा।

परीक्षा से मत डरो। असफलता मंजिल का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मौका है। इसने मुझे **धैर्यशील** बनाया और गिरने के बाद भी फिर उठ खड़े होने की ताक़त दी।'

जो पूछना है खुलकर पूछो। सवाल पूछने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। इसने मुझे **जिज्ञासा** का महत्व बताया।

शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। इसने मुझे **संस्कार** के महत्व के बारे में बताया।

कभी-कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा ही होता है। इसने मुझे विश्वास और **उम्मीद** की ताकत दी।

नई कला और हुनर सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही मंजिल तक पहुंचाती है। इसने मुझे **सच्चे प्रयास** की राह दिखाई।

'शाबाश... देखो कल तुमसे यह सवाल हल नहीं हो रहा था, लेकिन तुमने कोशिश की तो आज हो गया।' इस बात ने मुझमें लगन पैदा की और यकीन दिलाया कि **मेहनत** बेकार नहीं जाती।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

05 hindi nd-06_page 02.qxd 9/4/2025 8:18 PM Page 1

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 सितंबर 2025

मानसून का कहर
मुसीबत में अनेक शहर

यह एक और मानसून का मौसम है जब हर कोई बारिश को कोस रहा है, इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा कि हमारी परेशानियों के लिए प्रकृति नहीं, बल्कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हम बरसात के मौसम में बारिश का रोना रोते हैं और जैसे ही मानसून लौटता है, हम उसे भूल जाते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर जयपुर तक, मानसून जलभराव, बाढ़ और बीमारियों के प्रकोप का एक बुरा सपना लेकर आता है। हालांकि, इस साल स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी में, यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचले इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इस हफ़्ते नदी का जलस्तर 206.4 मीटर दर्ज किया गया, और पूवार्नुमानों के अनुसार यह 207 मीटर को पार कर सकता है। दीर्घकालिक समाधानों के बजाय, दिल्ली अभी भी आखिरी समय में निकासी और अस्थायी आश्रयों पर निर्भर है।

मुंबई में, मानसून अराजकता का पर्याय बन गया है। 2005 की विनाशकारी बाढ़ के बाद जल निकासी व्यवस्था में करोड़ों खर्च किए जाने के बावजूद, शहर हर भारी बारिश के साथ डूब जाता है। सड़कें धंस जाती हैं, ट्रेनें धीमी हो जाती हैं और उड़ानें देरी से होती हैं। विशेषज्ञ अनियंत्रित निर्माण, सिकुड़ते आर्द्रभूमि और अपर्याप्त जल निकासी को दोषी ठहराते हैं। मीठी नदी, जो कभी बाढ़ के खिलाफ प्राकृतिक बफर

थी, कचरे और अतिक्रमणों से भर गई है।

इस मानसून की सबसे चौंकाने वाली विडंबनाओं में से एक जयपुर है, जो अपने शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, व्यापक बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी वर्षा ने इसके नाजुक जल निकासी ढांचे को तबाह कर दिया, जिससे इसकी विरासत वाली सड़कें नदियों में बदल गईं। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे रेगिस्तानी शहर बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, जिन्हें कभी झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इस साल, मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर चेन्नई के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया।

कुख्यात 2015 की बाढ़, राहत शिविर, निकासी और आपातकालीन परामर्श ही प्रतिक्रिया का केंद्र बिंदु हैं, जबकि दीर्घकालिक समाधान सरकारी फाइलों में धूल फांक रहे हैं। भारत में भीषण जल प्रलय को वार्षिक त्रासदी बनने से रोकने के लिए, भारत को अपनी शहरी नियोजन और बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। नदियों, आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों को संरक्षित और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। ये प्राकृतिक स्पंज अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और बाढ़ को कम करते हैं। भारतीय शहर औपनिवेशिक काल के जल निकासी डिजाइनों पर निर्भर हैं जो पूरी तरह से पुराने हो चुके हैं।

वर्षा जल निकासी नालियों का विस्तार, गाद निकालने और आधुनिक शहरी बुनियादी ढाँचे के साथ एकीकरण आवश्यक है। बाढ़ के मैदानों और आर्द्रभूमि पर निर्माण पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर भारतीय शहरों को अगली सदी तक जीवित रहना है, तो आत्मसंतुष्टि की जगह लचीलापन अपनाना होगा।

स्थायी आपदा राहत कानून की जरूरत

भारत दुनिया के सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहां 4 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि बाढ़ के खतरे में है और एक लंबा तटीय क्षेत्र चक्रवातों के संपर्क में है। जलवायु परिवर्तन ने इन खतरों को और बढ़ा दिया है, जिससे बाढ़ और भी तीव्र हो गई है।

दिनेश सूद
लेखक, स्तम्भकार हैं।

जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो वे न केवल हमारे भूभाग की कमजोरियों को उजागर करती हैं, बल्कि हमारे शासन की कमियों को भी उजागर करती हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में जारी तबाही, जिसे इतिहास की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बताया जा रहा है, ने एक बार फिर बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ राहत से निपटने के लिए एक अधिक संरचित, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे की मांग को जन्म दिया है।

केंद्र द्वारा 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित धनराशि के उपयोग को अनिवार्य करने वाला आपदा राहत कानून बनाने का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है, जो दशकों से विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में सालाना 15-20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसमें बैंकों और डाकघरों में जमा 78,213 करोड़ रुपये, ईपीएफओ खातों में 27,000 करोड़ रुपये, बीमा में 22,000 करोड़ रुपये, स्टॉक और लाभांश (आईईपीएफ) में 90,093 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में 2,600 करोड़ रुपये शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक केंद्रीय लावारिस संपत्ति प्राधिकरण (सीयूपीए) की स्थापना की सिफारिश की है। यह एक एकल सरकारी निकाय होगा जो लावारिस धन पर नजर रखेगा और उसका प्रबंधन करेगा। एक कानून बनाकर इस धन का सदुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह अब देश का धन है, जो वर्षों से बेकार पड़ा है।

इसके सदुपयोग के लिए प्राकृतिक आपदा राहत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, जो समयोचित और अत्यावश्यक दोनों है। यदि केंद्र के पास 2 लाख करोड़ रुपये लावारिस और बेकार पड़े हैं, तो क्या इसे तबाह हो चुके जीवन, बुनियादी ढाँचे और आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?

यह अपील केवल हिमाचल और पंजाब के बारे में नहीं है, यह पूरे देश में गूंजती है। साल दर साल, राज्य बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप से जूझ रहे हैं। मानवीय और आर्थिक नुकसान का पैमाना केंद्र और राज्यों द्वारा हर आपदा के बाद घोषित किए जाने वाले तदर्थ राहत पैकेजों से कहीं ज्यादा है। 1980 और 2024 के बीच, अकेले पंजाब में बाढ़ आई जिससे लगभग 1.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 4.64 लाख हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ कृषि भूमि जलमग्न हो गई, 8 लाख से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए, 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और लगभग 18,000 पशुधन की हानि हुई, और वर्तमान में 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में चालू मानसून सीजन के दौरान पहले ही 2,348 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। ये मामूली आँकड़े नहीं हैं; ये जीवन और आजीविका की रक्षा करने में व्यवस्थागत विफलता को दशार्ते हैं।

भारत में आपदा राहत प्रयास वर्तमान में प्रतिक्रियात्मक हैं, और मुआवजे की घोषणाएँ तभी की जाती हैं जब काफी नुकसान हो चुका हो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष मौजूद तो हैं, लेकिन उनका आवंटन लगातार अपर्याप्त है। इससे भी गंभीर बात यह है कि केंद्र सरकार के लिए तुरंत या अनुमानित क्षति के अनुपात में धनराशि जारी करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह स्थिति राज्यों को लंबी बातचीत और राजनीतिक दांव-पेंच के लिए असुरक्षित बना देती है।

भारत दुनिया के सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहां 4 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि बाढ़ के खतरे में है और एक लंबा तटीय क्षेत्र चक्रवातों के संपर्क में है। जलवायु परिवर्तन ने इन खतरों को और बढ़ा दिया है, जिससे बाढ़ और भी तीव्र हो गई है और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस वास्तविकता को देखते हुए, वर्तमान राहत मॉडल, जो बार-बार आने वाली आपदाओं के लिए डिजाइन किया गया है, पूरी तरह से अपर्याप्त है। हमें उन प्रणालीगत मुद्दों का सामना करना होगा और उनका समाधान करना होगा जो प्रभावी आपदा राहत में बाधा डालते हैं।

एक स्थायी आपदा राहत कानून स्थापित करना वैकल्पिक नहीं है; यह अनिवार्य है। इस कानून में आपदा-पश्चात सौदेबाजी के बजाय वैज्ञानिक जोखिम आकलन के आधार पर पूर्व-आवंटित धनराशि को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महीनों तक चलने वाले विलंब के बजाय, कुछ ही दिनों में राहत राशि का स्वतः वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

इसके अलावा, इस कानून में केवल आपातकालीन प्रावधानों के बजाय, आवास, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें देरी और कुप्रबंधन के लिए जवाबदेही को भी संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हाल की आपदाएँ हिमालयी राज्यों के सामने मौजूद जटिल जोखिमों को उजागर करती हैं। ये क्षेत्र नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों से जूझ रहे हैं जो भूस्खलन, भारी वर्षा के कारण अचानक बाढ़, और बढ़ते मानवीय अतिक्रमण से ग्रस्त हैं जो प्राकृतिक आपदाओं को और बढ़ा देते हैं। पंजाब की स्थिति मौजूदा व्यवस्था की एक और गंभीर विफलता को उजागर करती है; बार-बार आने वाली बाढ़ दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन समाधानों में निवेश की तत्काल आवश्यकता को दशार्ती है।

लाखों लोगों के प्रभावित होने और साल-दर-साल भारी नुकसान होने के बावजूद, पंजाब बाढ़ प्रबंधन में आवश्यक दीर्घकालिक निवेश करने में विफल रहा है जिससे नुकसान कम हो सके। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते; स्थायी बाढ़ प्रबंधन उपायों में निवेश को प्राथमिकता देना अपरिहार्य है। खराब जल निकासी व्यवस्था, अनियमित रेत खनन और निवारक योजना का अभाव भारी बारिश के प्रभावों को बढ़ा देता है। ये दोनों मामले स्पष्ट रूप से दशार्ते हैं कि टुकड़ों में किए जाने वाले राहत प्रयास अपर्याप्त हैं। कानूनी रूप से गारंटीकृत ढाँचे के बिना, राज्य असुरक्षित बने रहेंगे, नागरिक अनिश्चित रहेंगे, और पुनर्निर्माण के प्रयास अधूरे रहेंगे। हमें एक मजबूत आपदा राहत प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना होगा जो हमारे समुदायों की रक्षा करे और शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित करे।

भारत में आपदा राहत वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी आपदा-पश्चात घोषणा पैकेजों पर निर्भर है, जो नुकसान की पूरी सीमा का खुलासा होने के बाद ही जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष मौजूद तो हैं, लेकिन वे बार-बार अपर्याप्त निधियों, वितरण में देरी और आवश्यक बड़े पैमाने पर पुनर्वास के लिए अत्यंत अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, इन निधियों का जारी होना अक्सर एक स्पष्ट, बाध्यकारी ढाँचे का पालन करने के बजाय बातचीत, अत्यधिक लालफीताशाही और राजनीतिक तिकड़मों में उलझा रहता है।

इस तदर्थ दृष्टिकोण को त्यागना होगा। आपदाएँ अब छिटपुट घटनाएँ नहीं हैं; वे स्थायी वास्तविकताएँ हैं जिनका हम सामना करते हैं। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को बिगाड़ रहा है, जिससे अधिक भयंकर बाढ़ और लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। राहत प्रयासों को विवेकाधीन घोषणाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए; उन्हें गारंटीकृत, समय पर और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए।

हमारी संकट प्रतिक्रिया को बदलने के लिए एक स्थायी आपदा राहत कानून आवश्यक है। इस कानून में प्रत्येक राज्य के लिए पूर्व-आवंटित धनराशि को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो वैज्ञानिक जोखिम आकलन द्वारा निर्धारित हो। यह अस्वीकार्य है कि राहत में महीनों लगें; प्रभावित परिवारों को कुछ ही दिनों में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि स्वचालित रूप से वितरित की जानी चाहिए। इसके अलावा, इसमें दीर्घकालिक पुनर्वास प्रयास भी शामिल होने चाहिए, जिनमें घरों का पुनर्वास, आजीविका की बहाली, स्वास्थ्य सेवा प्रावधान और बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण शामिल है। हमें सरकारों को आपदा प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा और अपेक्षित परिणाम प्रकाशित करने के लिए बाध्य करके उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। यह मुद्दा अटूट है और राजनीतिक विवादों से परे है। नेताओं को, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के, आपदाओं की अंधाधुंध प्रकृति को पहचानना होगा; वे किसी भी क्षेत्र या विचारधारा को नहीं छोड़ते। संकट के समय में स्वचालित निधि आवंटन की गारंटी देने वाला कानून भारत की लचीलापन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा और राज्य की अपने नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा।

हम ऐसे कानून की मांग को राजनीतिक शोरगुल में दबने नहीं दे सकते। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को इस महत्वपूर्ण बदलाव की मांग करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाएँ अपरिहार्य हैं, लेकिन संस्थागत उपेक्षा से उत्पन्न होने वाली पीड़ा पूरी तरह से रोकी जा सकती है। तदर्थ वादों का युग समाप्त हो गया है; अब समय आ गया है कि हम एक स्थायी आपदा राहत कानून स्थापित करें।

संसद को आपदा राहत को कानून में शामिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ढांचा न केवल प्रभावित नागरिकों को निश्चितता प्रदान करने के लिए, बल्कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की आपदा तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। राहत को एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक उदारता की सनक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

ट्रंप का सपना नोबल विजेता बनने का

भारत आज ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की ओर झुक रहा है, पश्चिम को पूरी तरह से खारिज करने के लिए नहीं, बल्कि स्वायत्तता और संतुलन स्थापित करने के लिए। ट्रंप को नामांकित करने से इनकार करके, भारत ने एक संदेश दिया।

संतोष मैथ्यू
लेखक, पांडिचेरी विवि में प्रोफेसर हैं।

इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, यह झुकता है, मुड़ता है और स्वयं का खंडन करता है, अक्सर हमें सच्चाई से भी ज्यादा तीखी विडंबनाएं देता है। इसने समय के साथ नेताओं, राष्ट्रों और संस्थानों को परिभाषित किया है। लोगों को न केवल उनके आदर्शों के लिए, बल्कि उनके द्वारा धारण किए गए विभिन्न विरोधाभासों के लिए भी याद किया जाता है।

तथ्य इन विरोधाभासों को निर्मम स्पष्टता के साथ उजागर करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि महत्वाकांक्षा - व्यक्तिगत या राजनीतिक, नैतिक स्थिरता से कहीं अधिक निहित स्वार्थों को पोषित करती है। वैश्विक मान्यता के मंच से बेहतर इसे कुछ ही क्षेत्र दशार्ते हैं, जहां ऊंचे पुरस्कार राजनीति से जुड़ते हैं, और जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प की नोबेल आकांक्षाएँ भारत के विकल्पों से टकराती हैं।

पुलित्जर पुरस्कार पर विचार करें, जो पत्रकारिता का शिखर है। इसके संस्थापक, जोसेफ पुलित्जर, खोजी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। फिर भी उन्होंने सनसनीखेज पीत पत्रकारिता३ का भी बीड़ा उठाया, अपने अखबारों को घोटाले से प्रेरित सुर्खियों से भर दिया। पत्रकारिता को ऊंचा उठाने के लिए प्रशंसित एक व्यक्ति ने इसे नष्ट कर दिया। नोबेल शांति पुरस्कार में भी यही विडंबना है। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया, ने डायनामाइट और हथियारों के जरिए अपना भाग्य बनाया। मौत का सौदागर शांति का संरक्षक संत बन गया।

यह विरोधाभास नेताओं के जीवन में भी दिखाई देता है। इथियोपिया के अबी अहमद ने 2019 में इरिट्रिया के साथ शत्रुता समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके देश को एक खूनी गृहयुद्ध में धकेल दिया।

आंग सान सू की, जिन्हें कभी म्यांमार में लोकतंत्र की प्रतीक माना जाता था, ने बाद में रोहिंग्याओं पर अत्याचारों का बचाव किया। माइक्रोफाइनेंस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मुहम्मद यूनुस को अपने देश में ही विरोध का सामना करना पड़ा। नोबेल का इतिहास ऐसे ही अपरिपक्व निर्णयों से भरा पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रम्प की नोबेल शांति पुरस्कार की महत्वाकांक्षाएं प्रकट होती हैं। तेजतर्रार और अप्रत्याशित ट्रम्प ने बार-बार दावा किया कि उनसे ज्यादा नोबेल का हकदार कोई नहीं है, उत्तर कोरिया के साथ अपनी बातचीत या मध्य पूर्व की पहल का हवाला देते हुए।

एक आश्चर्यजनक मोड़ में, पाकिस्तान ने उन्हें नामांकित किया। हालांकि, भारत ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी का इनकार ट्रम्प के व्यक्तिगत हितों से कम और सिद्धांत से ज्यादा जुड़ा था: भारत अल्पकालिक नाटकीयता के लिए दीर्घकालिक हितों का सौदा नहीं करेगा।

ऊपर से, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान लाभ। ट्रंप ने टैरिफ में ढील की पेशकश की, जबकि भारत को भारी बढ़ोतरी और गिरते रुपये का सामना करना पड़ा। लेकिन तात्कालिक लागतों के पीछे एक गहरा हिसाब-किताब छिपा है। नोबेल की प्रतिष्ठा संदेहास्पद है; सू की और अबी जैसे लोग दिखाते हैं कि कितनी जल्दी प्रशंसा शर्मिंदगी में बदल सकती है। यहाँ तक कि गांधी को भी - जो यकीनन इतिहास में शांति के सबसे बड़े पैरोकार थे, कभी सम्मानित नहीं किया गया। अगर गांधी को नकारा जा सकता है, तो भारत ट्रंप के लिए पैरवी क्यों करे, जो अमेरिका फर्स्ट के एकतरफापन से परिभाषित व्यक्ति हैं?

भारत का फैसला दूरदर्शिता भरा था। वैश्विक राजनीति नैतिकता के बारे में नहीं, बल्कि स्थायी हितों के बारे में है। जैसा कि पुरानी कहावत है: कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं।

भारत आज ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की ओर झुक रहा है, पश्चिम को पूरी तरह से खारिज करने के लिए नहीं, बल्कि स्वायत्तता और संतुलन स्थापित करने के लिए। ट्रंप को नामांकित करने से इनकार करके, भारत ने एक संदेश दिया: वह किसी अन्य नेता के प्रदर्शन में गौण भूमिका नहीं निभाएगा।

नोबेल के लिए ट्रंप की लालसा अपने आप में विरोधाभासी है। यहाँ एक ऐसा नेता है जिसने संयुक्त राष्ट्र का मजाक उड़ाया, नाटो की निंदा की, टैरिफ लगाए सहयोगियों के साथ, और बहुपक्षवाद को खारिज कर दिया–फिर भी दुनिया की सबसे प्रतीकात्मक बहुपक्षीय संस्थाओं में से एक से मान्यता की लालसा की। शांति की मान्यता के लिए उनकी खोज निरंतरता से कम और विडंबना अधिक थी।

भारत ने ट्रंप की नाराजगी की अल्पकालिक कीमत चुकाई, लेकिन दीर्घकालिक विश्वसनीयता बनाए रखी। पाकिस्तान ने अनुग्रह पाने के लिए प्रतीकात्मक इशारे किए। इसके विपरीत, भारत ने संप्रभुता और बहुध्रुवीय संतुलन को प्राथमिकता दी।

अगर उसने ट्रंप के नामांकन का समर्थन किया होता, तो वह नोबेल की विरासत को नुकसान पहुँचाने वाले समय से पहले किए गए समर्थनों की लंबी सूची में शामिल हो सकता था। इसके बजाय, उसने संयम को चुना।

शांति पुरस्कार स्वयं विरोधाभास का दर्पण बन गया है। इसने गांधी की अनदेखी की है, नेताओं को बहुत जल्दी पुरस्कृत किया है, और कभी-कभी उन शांतिदूतों को ताज पहनाया है जिन्होंने बाद में हिंसा फैलाई। यह मानव इतिहास के विरोधाभासों का प्रतीक है। इस प्रकाश में, ट्रंप को शामिल करने से भारत का इनकार कमजोरी नहीं बल्कि स्पष्टता थी–एक ऐसा निर्णय जिसे इतिहास बुद्धिमानी भरा मान सकता है।

पुलित्जर की पत्रकारिता से लेकर नोबेल के डायनामाइट तक, जेफरसन की स्वतंत्रता से लेकर जिन्ना की धर्मनिरपेक्षता तक, गांधी की शांति से लेकर बोस के राष्ट्रवाद तक, इतिहास हमें सिखाता है कि नेताओं की पहचान शुद्धता से कम, विरोधाभास से ज्यादा होती है। ट्रम्प की नोबेल की खोज विडंबनाओं की इस किताब में एक और कड़ी है। 'नहीं' कहकर, भारत ने एक शाश्वत सिद्धांत की पुष्टि की: दीर्घकालिक ज्ञान के लिए अल्पकालिक प्रलोभनों का विरोध करने का साहस।

विरोधाभास असफलताएं नहीं हैं; वे इतिहास के निशान हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे ऊँचे पुरस्कार, सबसे महान आदर्श, और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली नेता भी विडंबना से बंधे होते हैं। कभी-कभी, सबसे सच्ची ताकत मान्यता पाने की चाहत में नहीं, बल्कि उसे अस्वीकार करने में निहित होती है।

आप की बात

जीएसटी दरों में कटौती

मोदी सरकार ने देशवासियों को दिवाली से पहले एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती की है। इस कदम को न केवल कर प्रणाली की जटिलता को सरल बनाने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है, बल्कि ३एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार३ के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में भी एक ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है।सरकार द्वारा की गई दरों की पुनर्रचना से अब अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी 5% और 18% के दायरे में सीमित रहेगा, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे उल्लेखनीय निर्णय मेडिक्लेम बीमा को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त करना है। इससे आम जनता को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और देश में स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ेगी। डिजिटल इनवॉइसिंग और ई-वे बिल जैसे तकनीकी उपायों ने कर प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। हालांकि, छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विशेष नीति प्रयासों की आवश्यकता है। जीएसटी परिषद की सक्रियता संघीय सहयोग का प्रतीक है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से नीति निर्माण और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। यह सुधार केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है।

– **भगवानदास छारिया**, इंदौर

शिक्षक दिवस का महत्व

5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, वे विद्वान होने के साथ-साथ दार्शनिक भी थे। उन्होंने शिक्षक की महत्ता व उसकी क्षमता को समझते हुए अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की पहल की, ताकि इस दिन शिक्षकों का सम्मान कर प्रोत्साहित किया जा सके।आज भी ऐसे शिक्षकों की कतई कमी नहीं है, जो अपनी क्षमता के अनुरूप श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन गम की बात है कि अपवाद स्वरूप शिक्षकों के कारण शिक्षक पद की जो गरिमा है,उस पर चोट पहुंच रही है। शिक्षा के परिसर में उनके द्वारा जिस तरह से बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे अनैतिक कांडों की खबरें आती है, जो निंदनीय होने के साथ-साथ शिक्षक जैसे नेक कर्म पर लांछन लगाती हैं। जो शिक्षक पद पर आरूढ़ है, या जो शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं, उन्हें इस दिन दृढ़ संकल्प लेना होगा की वे न केवल श्रेष्ठ व नेक बनकर अपने बच्चों को भगवान स्वरूप मानकर शिक्षा देंगे बल्कि नैतिक रूप से भी शिक्षक पद की गरिमा का मान-सम्मान बनाए रखेंगे। सादा भोजन, उच्च विचार के साथ-साथ, शिक्षक बच्चों को बिना किसी भेदभाव, जाति-पाति, प्रताड़ना के शिक्षा दे। ऐसा कोई कदम न उठाए जो उपहास व निंदा का कारण बने।राष्ट्र की मजबूती शिक्षा व शिक्षक पर निर्भर होती है। शिक्षक पद की गरिमा को बनाए रखना, स्वयं शिक्षक के हाथों में है।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, अक्षत खाचरोद, उज्जैन

गब्बर सिंह टैक्स पर लगाम

नवरात्र के पहले दिन ही जयभवानी (निर्मला सीतारमण) के हाथों से गब्बर सिंह (टैक्स जीएसटी) जो आम ईमानदार लोगों को ८ सितम्बर २०१६ से बुरी तरह परेशान कर रहा था वो अब २२ सितम्बर २०२५ को बुरी तरह घायल अवस्था में आ जाएगा. याने लगभग मरा ही समझो. रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कहीं शून्य तक हो जाएगा तो कहीं १८ या १२ से ५% और कहीं २८% से १८% तक उसका पारा गिर जाएगा। हां विलासिता की वस्तुओं और नशीले पदार्थ पर जरूर जीएसटी के तेवर २८% से ४०% पर पहुंच गए हैं। जहां रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम दर से आम लोगों को वस्तुएं सस्ती मिलेगी जिससे उन्हें राहत भी महसूस होगी. वहीं विलासिता की वस्तुओं पर अधिक दर जहाँ सक्षम लोगों के लिए अफोर्डेबल होगी वहीं नशीली वस्तुओं पर बढ़ी दर के उपयोग को कम करने में सहायक भी होगी. आम लोगों को और अधिक राहत दिलानी है तो सरकार को एमआरपी पर भी नियंत्रण करना और सही कीमतें प्रोडक्ट्स पर प्रिंट करने हेतु विशेष कदम उठाने चाहिए. क्योंकि कुछ विक्रेताओं को छोड़कर अधिकांश विक्रेता खरीददारों से "एमआरपी" पर ही कीमत वसूलते हैं। फिर चाहे रोजमर्रा की वस्तुएं हों या आरामदायक अथवा विलासिता की वस्तुएं. बहुत ही मजेदार बात यह है कि कुछ व्यापारी "एमआरपी" कम करके वस्तुएं देने पर जैसे एहसान जताते हैं।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

साहसी कदम

उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी देकर एक अहम और संवेदनशील मुद्दे पर कड़ा कदम उठाया है। इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकना है ताकि समाज में सामंजस्य और शांति बनी रहे। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन जब यह अधिकार प्रलोभन, दबाव या छल से प्रभावित होता है, तो वह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि देश के पंथनिरपेक्ष ढांचे के लिए भी चुनौती बन जाता है। संशोधित विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि नौकरी, धन, उपहार, मुफ्त शिक्षा या बेहतर जीवन का वादा कर-के किसी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना जबरन धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा। इस तरह के मामलों में तीन से दस साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि सामूहिक धर्मांतरण या विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण कराया जाता है, तो दोषियों को सात से चौदह साल तक की सख्त सजा हो सकती है। साथ ही महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति या दिव्यांग व्यक्ति के जबरन धर्मांतरण पर और कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है। विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें ३प्रलोभन३ की विस्तृत परिभाषा दी गई है, जिसमें नकद या वस्तु के रूप में लाभ, नौकरी, संपत्ति, या दैवीय नाराजगी का भय दिखाना भी शामिल है।

– **विभुक्ति बुपक्या**, उज्जैन

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 171

नया जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बुधवार को आयोजित 56वीं बैठक में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में अहम सुधारों की घोषणा की गई। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और अनुपालन में सुधार होगा। जीएसटी में बदलाव करके उसे मोटे तौर पर 5 और 18 फीसदी की दो दरों वाला तुलनात्मक रूप से सरल ढांचा बना दिया गया है। चुनिंदा नुकसानदेह वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40 फीसदी की दर रखी गई है। यह भी कहा जा सकता है कि जीएसटी अभी भी पूरी तरह एकल दर वाले कर ढांचे के विचार के करीब नहीं है लेकिन ताजा बदलाव कई विसंगतियों और व्यवस्था की ढांचागत कमियों को दूर करने वाले साबित होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि इस माह के अंत से पहले वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय पंचाट का परिचालन शुरू किया जाएगा ताकि अपील स्वीकार की जा सकें। जीएसटी के ढांचे में इस व्यवस्था की कमी महसूस की जा रही थी। नया कर ढांचा 22 सितंबर से प्रभावी होगा।

अब 12 और 28 फीसदी की दरों को समाप्त कर दिया गया है और इनमें आने वाली वस्तुओं को 5 और 18 फीसदी की दर में समाहित कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी। उदाहरण के लिए खाद्य वस्तुओं की बात करें तो उन्हें 5 फीसदी के स्लैब में डाल दिया गया है। एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़े टेलीविजनों पर अब 28 फीसदी के बजाय 18 फीसदी कर लगेगा। छोटी कारों और मोटरसाइकल पर भी 28 फीसदी के स्थान पर 18 फीसदी कर लगेगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बीमा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे वे किफायती बनी रहेंगी और उनकी पहुंच बढ़ेगी। इनवर्टेड कर ढांचे से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी सुधार किया गया है। उदाहरण के लिए मानव निर्मित कपड़े और उर्वरक क्षेत्र में। कृषि उपकरणों मसलन ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनरी पर भी जीएसटी कम किया गया है। क्षतिपूर्ति उपकर जिसका संग्रह राज्यों को महामारी के दौरान हुई राजस्व हानि की भरपाई की खातिर लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए किया जाता है, उसका भी अंत हो जाएगा। केवल चुनिंदा नुकसानदेह वस्तुओं पर ही वह लागू रहेगा।

सामान्य स्तर पर, जीएसटी दरों में कटौती से मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। एक अनुमान के अनुसार, यह आने वाली कुछ तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में लगभग एक फीसदी का योगदान कर सकता है और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है। हालांकि, वास्तविक परिणामों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। केवल त्योहारों के कारण और दरों में कटौती की उम्मीद से रुकी हुई मांग से आगे बढ़कर। फिर भी, समग्र रूप से कम जीएसटी दरों का मुद्रास्फीति पर नरमी लाने वाला प्रभाव अवश्य पड़ेगा। सबसे कठिन होगा इसके राजकोषीय प्रभाव का आकलन। यानी सरकार के राजस्व और व्यय पर इसका असर जानना।

सरकार ने कहा है कि दरों को तर्कसंगत बनाने से राजस्व पर करीब 48,000 करोड़ रुपये का असर होगा। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग किस तरह प्रतिक्रिया देती है। नीतिगत नजरिये से देखें तो औसत जीएसटी दर 11.6 फीसदी से कम हो जाएगी जो पहले ही एकदम आरंभ के 14.4 फीसदी से कम है। परिषद शायद 5 फीसदी की निचली दर को कुछ हद तक बढ़ाने की संभावना पर विचार कर सकती थी ताकि राजस्व संग्रह को बढ़ाया जा सके। इससे उपभोक्ता को समग्र स्तर पर लाभ मिलता ही, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुछ हद तक राजस्व की सुरक्षा भी कर पातीं। इसके अलावा, यह भविष्य में एक समान दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता। यह संरचना को और अधिक सरल बनाने का अवसर भी देता, जिससे जूते-चप्पल, परिधान और वाहन जैसे उत्पादों पर एक ही दर से कर लगाया जा सकता। फिर भी, किए गए बदलाव समग्र रूप से सकारात्मक हैं और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को कहीं अधिक सरल बनाएंगे।

कॉरपोरेट जगत को नहीं बनाना चाहिए निशाना

भारतीय व्यापारिक घरानों और उनकी तथाकथित व्यापारी मानसिकता पर किए जा रहे हमले एकदम अनुचित हैं। विस्तार से बता रहे हैं आर जगन्नाथन

भारतीय कारोबारी जगत ने कई नाकामियों का सामना किया है, इसके बावजूद एक बात जो नहीं होनी चाहिए वह है राजनीतिक दलों या बुद्धिजीवियों द्वारा उन पर कीचड़ उछालना या उन्हें गलत ठहराना। जब बड़े राजनेता उन पर हमला करते हैं (इस समय राहुल गांधी और अतीत में अरविंद केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं) तो इससे देश का कोई भला नहीं होता। भले ही उद्योग जगत ने गलतियां की हों लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अदाणी और अंबानी के बारे में अंतहीन प्रलाप करना और फिर उन्हीं कारोबारी घरानों से यह उम्मीद करना कि वे निवेश करेंगे और भारत को वैश्विक छवि प्रदान करेंगे, यह मूर्खतापूर्ण है। एकाधिकार को रोकना एक बात है और यह मानना एकदम दूसरी बात है कि भारत को दिग्गज कारोबारी समूहों की आवश्यकता नहीं है।

बड़े कारोबारी घरानों की आलोचना विदेशी ताकतों को प्रेरित करेगी कि वे भी भारत के हितों को सीमित करने के लिए ऐसा ही करें। यह महज संयोग नहीं है कि अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग और हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अदाणी को निशाना बनाया जबकि उनके कदमों से किसी अमेरिकी नागरिक के अधिकार प्रभावित नहीं हुए थे। हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा दिया गया बयान भी इसी श्रेणी में आता है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत (यानी रिलायंस) सस्ते रूसी तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों को निर्यात करता है और इससे मुनाफा कमा रहा है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इससे भी आगे बढ़ते हुए भारत को रूस का लॉन्ड्रोमैट यानी धुलाई केंद्र कह दिया। उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए।

अगर यूक्रेन युद्ध से किसी को लाभ हुआ है तो वह अमेरिका के सैन्य-औद्योगिक गठजोड़ को क्योंकि यूरोप और यूक्रेन दोनों ने उससे अधिक रक्षा साजोसामान खरीदे। अगर कोई अर्थव्यवस्था वाकई धुलाई केंद्र है तो वह अमेरिका है। दुनिया का कोई भी ऐसा मादक पदार्थ गठजोड़ या अवैध कारोबार नहीं है जो अमेरिकी डॉलर की मदद से काला धन सफेद नहीं करता हो। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई के 2022 के एक शोध पत्र के मुताबिक 1.1 लाख करोड़ डॉलर की अमेरिकी नकदी में 100 डॉलर के नोटों का दो तिहाई विदेश में केंद्रीय बैंकों से परे रखा हुआ है। क्रिप्टो के आगमन के बाद इसमें बदलाव आ रहा है लेकिन डॉनल्ड ट्रंप अब क्रिप्टो कारोबार में भी नजर आ रहे हैं।

अंबानी की आलोचना करने वाले एक महत्त्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। वह यह कि निजी कंपनियां सस्ते रूसी तेल के उपलब्ध होने से पहले ही कच्चा तेल आयात कर परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करती रही हैं। भारत की सरकारी तेल कंपनियां मूल्य निर्धारण के नियमों से बंधी होती हैं, जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है। इसका परिणाम यह है कि निजी रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए उपयोग होता है। यदि तेल की कीमतें वास्तव में मुक्त हों, तो अधिक परिष्कृत उत्पाद भारत में ही बेचे जा सकते हैं।

इससे भी अधिक नुकसानदेह है कई बुद्धिजीवियों मसलन प्रताप भानु मेहता जैसे लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपने स्तंभ में लिखा कि भारतीय पूंजीवाद का उदय मुख्य रूप से कारोबारियों से हुआ जो मूल्य में अंतर से तो खूब लाभ कमाते हैं लेकिन वे निर्माण और सृजन में सक्षम नहीं रहे। शोध में कम निवेश करने और केवल मुनाफे पर काम करने के लिए भारतीय कंपनियों की आलोचना करना उचित है लेकिन यह मोटे तौर पर लाइसेंस परमिट राज का परिणाम है। अब वही नियामकों के राज में हो रहा है। राजनेता और अफसरशाह दोनों ही उद्योग जगत पर भरोसा नहीं करते। अगर यह बदलता है तो कारोबार अधिक भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्लेटफॉर्म, उत्पादों का निर्माण करेंगे और आर्थिक ताकतों को मजबूत करेंगे।

व्यापारिक मानसिकता के लिए केवल भारतीय कारोबारों को दोष देना सही नहीं। अमेरिका और यूरोप का पूरा खुदरा क्षेत्र इसी मॉडल पर काम कर रहा है। यानी सस्ते चीनी उत्पाद खरीदकर उनको देश में बेचना। कारोबार के लिए व्यापार और निर्माण दोनों आवश्यक हैं। जब आप प्रतिस्पर्धी नहीं रहते तो आप व्यापार से पैसे कमाते हैं। वह आपको अपना ग्राहक वर्ग बनाने का अवसर देता है ताकि आप अपना उत्पाद तैयार कर सकें। बात केवल अंबानी, अदाणी, बिरला या टाटा की नहीं है। ध्यान दीजिए कि मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं में क्या हो रहा है। एक दशक पहले भारतीय ब्रांड मसलन माइक्रोमैक्स और कार्बन आदि बाजार में काफी हिस्सेदारी रखते थे और ये चीन से आयातित कलपुर्जों से बनते थे। परंतु वे चीन की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाए। अब वीवो और श्याओमी जैसी चीनी कंपनियां उस बाजार पर काबिज हैं।

देश की आईटी कंपनियां भी कारोबार में हैं। वे सस्ते भारतीय कोडरों की मदद से अमेरिका और यूरोप के उच्च मार्जिन वाले बाजारों में काम करती हैं। वे भी व्यापारियों से अलग नहीं हैं। जब व्यापार करना लाभकारी होता है, तो अधिकांश व्यवसाय उसे अपनाते हैं। लेकिन जब व्यापार में लाभ नहीं दिखता, तो वे निर्माण की ओर रुख कर सकते हैं। जब सरकार और व्यवसाय का समीकरण भरोसे में बदल जाएगा, तो भारत की कंपनियां पीछे नहीं रहेंगी।

अब ऐसा ही हो रहा है। रक्षा से लेकर निजी क्षेत्र अब सैन्य साजोसामान बना भी रहा है और निर्यात भी कर रहा है। जोमैटो के संस्थापक अपने दो करोड़ डॉलर निवेश करके गैस टर्बाइन इंजन बना रहे हैं जो छोटी जगह से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम विमान और मानवरहित विमान बनाने में इस्तेमाल होंगे। टाटा और महिंद्रा ने भारत के साथ वैश्विक बाजारों के लिए कार प्लेटफॉर्म बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी अखबार के मुताबिक कुछ दोपहिया वाहन कंपनियों ने शोध एंव विकास पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आरंभ कर दिया है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी सोलर और हाइड्रोजन तकनीक में भारी निवेश की योजना घोषित की है जबकि अदाणी अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही करेंगे। लार्सन ऐंड टुब्रो, गोदरेज, टाटा, बिड़ला और कई छोटे स्टार्टअप्स भी एरोस्पेस, रक्षा उपकरणों और ड्रोन में निवेश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप और फैब्स तो हैं ही।

नियमन के अलावा, उन कंपनियों के लिए जो गहन तकनीक, उत्पादों और प्लेटफार्म में निवेश करने की क्षमता रखती हैं, शेयर बाजार ध्यान भटकाने वाला तत्व बन गया है। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों के पास भारी नकदी है जिसे आसानी से भारत के मालिकाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकार के विकास में लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बजाय वे इसका उपयोग अपने अंशधारकों को प्रसन्न करने में लगाती हैं। या तो इन कंपनियों को लाभांश भुगतान कम करना चाहिए और उस बचत को बौद्धिक संपदा अधिकार के निर्माण में लगाना चाहिए, या फिर उनके संस्थापकों को अपनी संपत्ति का उपयोग करके बड़े प्लेटफार्म और उत्पाद बनाने चाहिए।

अगर जोमैटो के दीपिंदर गोयल अपनी निजी संपत्ति से शोध एवं विकास में निवेश कर सकते हैं, तो बाकी अरबपति क्यों नहीं कर सकते? कुछ सूचीबद्ध कंपनियां सूचीबद्धता समाप्त करने पर विचार कर सकती हैं ताकि वे दीर्घकालिक बौद्धिक संपदा परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकें।

भारत की कंपनियों में विश्वास बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अविश्वास और व्यापारिक मानसिकता के आरोपों से कोई मदद नहीं मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एमेजॉन जैसी वैश्विक ताकतों का मुकाबला अगर कोई कर सकता है, तो वे हैं अदाणी, अंबानी, बिड़ला और टाटा जैसे भारतीय उद्योगपति। हमारे बड़े व्यवसायों को उनकी खामियों के बावजूद संरक्षण देना चाहिए। अगर वे कोई गलती करते हैं, तो हमें उसे यहीं सुलझाना चाहिए। विदेशियों को उन्हें कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मौद्रिक नीति प्रसार का अलग तरीका

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले सभी बॉन्ड (सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋण और कॉरपोरेट बॉन्ड) पर यील्ड बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ, सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल एवं कॉरपोरेट बॉन्ड के बीच यील्ड का अंतर (स्प्रेड) भी बढ़ता जा रहा है।

खबरों के अनुसार पिछले सप्ताह कम से कम दो कंपनियों आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) और बजाज फाइनैंस लिमिटेड ने बाजार से रकम जुटाने की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी क्योंकि यील्ड उनके हिसाब से काफी अधिक हो गई थीं। बॉन्ड बाजार के मौजूदा हालात पर विचार करने से पहले हम यह समझ लेते हैं ऐसे हालात आखिर क्यों बने हैं।

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 1.55 फीसदी बढ़ी जो पिछले 8 वर्षों की सबसे सुस्त बढ़ोतरी थी। खुदरा मुद्रास्फीति लगातार पांचवें महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य 4 फीसदी (2 प्रतिशत घट-बढ़) से नीचे रही। वर्ष 2019 के बाद यह पहला अवसर था जब खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य से नीचे ही सिमट कर रह गई। आरबीआई ने फरवरी और जून के बीच रीपो दर 6.5 फीसदी से घटाकर 5.5 फीसदी कर दी। केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षी अनुपात में 1 फीसदी कटौती का फैसला 6 सितंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े में प्रभावी हो जाएगा। इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये आ जाएंगे। आदर्श रूप में इस तरह की पृष्ठभूमि में बॉन्ड यील्ड में कमी आनी चाहिए जिससे ट्रेजरी प्रबंधकों को खुश होना चाहिए। मगर ट्रेजरी कार्यालयों में बॉन्ड डीलरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वे सभी अपने नुकसान की भरपाई करने में जुटे हैं।

गत 26 अगस्त को 10 साल की अवधि के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड कारोबार के दौरान 6.65 फीसदी तक पहुंच गई और बाद में 6.60 फीसदी पर बंद हुई। चालू वित्त वर्ष में यह यील्ड सबसे अधिक है। इससे पहले 26 मार्च को यील्ड 6.60 फीसदी पर पहुंची थीं। उस समय यह 6.645 फीसदी तक पहुंच गई थी मगर 6.60 फीसदी पर बंद हुई।

उल्लेखनीय है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में नीतिगत दर 6.25 फीसदी थी और वित्तीय प्रणाली में नकदी की कमी लगभग 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। फिलहाल नीतिगत दर 5.5 फीसदी है और 26 अगस्त को वित्तीय प्रणाली में 1.78 लाख करोड़ रुपये अधिशेष नकदी थी।

आरबीआई ने फरवरी में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू किया था और अप्रैल और जून में भी यह जारी रहा और फिर अगस्त में थम गया। पहले दो अवसरों पर केंद्रीय बैंक ने 25 आधार अंक और जून में 50 आधार अंक की कटौती की थी। कुछ दूसरे आंकडे भी हैं। 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड पर यील्ड बढ़ रही है मगर अल्प अवधि के ट्रेजरी बिल (बॉन्ड) पर इसमें कमी आ रही है। अब 26 मार्च और 26 अगस्त के रुझान पर विचार करते हैं। 26 मार्च को 91 दिन और 180 दिन के ट्रेजरी बिल पर यील्ड 6.52 फीसदी थी जबकि 364 दिन के ट्रेजरी बिल पर यील्ड 6.47 फीसदी थी। 26 अगस्त को 91 दिन की अवधि के ट्रेजरी बिल पर यील्ड कम होकर 5.484 फीसदी, 180 दिन के बिल पर 5.575 फीसदी और 364 दिन के बिल पर 5.60 फीसदी रह गईं। ओवरनाइट इंटरबैंक कॉल मनी रेट कम होकर 26 अगस्त को 5.49 फीसदी रह गई जो 26 मार्च को 6 31 फीसदी थी।

दूसरे शब्दों में कहें तो नीतिगत दर में कटौती का प्रभाव अल्प अवधि में महसूस किया जाता है मगर दीर्घ अवधि के बॉन्ड पर यह नहीं दिखता है। बॉन्ड कारोबार में इसे बीयर स्टीपनिंग कहते हैं। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें दीर्घ अवधि की ब्याज दरें अल्प अवधि की ब्याज दरों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं जिससे यील्ड कर्व अधिक हो जाता है। यील्ड कर्व बॉन्ड पर यील्ड या ब्याज को दर्शाता है जिनकी क्रेडिट गुणवत्ता समान होती है लेकिन परिपक्वता तिथियां अलग-अलग होती हैं।

6 जून को नीतिगत दर में कमी के बाद 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड की कीमत 101.64 रुपये पहुंच गई थी मगर बाद में 100.67 पर बंद हुई। 26 अगस्त को इसकी कीमत कम होकर 97.77 रुपये रह गई। यील्ड और बॉन्ड की कीमत एक दूसरी के विपरीत चलती है। अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड डीलर क्यों मायूस दिख रहे हैं।

दीर्घ अवधि के बॉन्ड पर यील्ड में बढ़ोतरी एक दूसरी कहानी है। एक दूसरी अहम बात सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल एवं कॉरपोरेट बॉन्ड पर यील्ड में बढ़ता अंतर है। 29 अगस्त को कारोबार बंद होने पर सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल एवं कॉरपोरेट बॉन्ड पर स्प्रेड 68 आधार अंक था। दरों में कटौती के मौजूदा दौर में 6 फरवरी को हुई पहली कटौती के दिन सरकारी प्रतिभूतियों एवं एसडीएल के बीच स्प्रेड 40 आधार अंक था। सरकारी प्रतिभूतियों एवं कॉरपोरेट बॉन्ड का स्प्रेड 55 आधार अंक था। 6 जून को दरों में हुई आखिरी कटौती के दिन सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल के बीच स्प्रेड 42 आधार अंक और सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड के बीच 66 आधार अंक था।

ये आंकड़े मांग-आपूर्ति में असंतुलन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाजार में बिक्री के लिए अधिक बॉन्ड मौजूद हैं मगर इनकी मांग सुस्त पड़ती जा रही है। बैंकों को यील्ड बढ़ने के बीच बॉन्ड खरीदने में कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। बाजार को भी लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला समाप्त हो गया है। 29 अगस्त तक केंद्र सरकार की सकल उधारी 6,38,000 करोड़ रुपये थी जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6,00,607 करोड़ रुपये रही थी। जहां तक एसडीएल की बात है तो इनके जरिये इस साल अब तक 3,79,310 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 3,03,394 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। शुद्ध उधारी में भी यह रुझान दिख रहा है। यह ऐसा समय है जब बड़े पेंशन फंड बॉन्ड बाजार से दूर रह रहे हैं और शेयरों पर दांव खेल रहे हैं। अब उन्हें शेयरों में अपने कोष के 15 फीसदी के बजाय 25 फीसदी तक निवेश करने की अनुमति मिल गई है।

एक आंकड़ा मोटे तौर पर सरकारी बॉन्ड में बैंकों की दिलचस्पी कम होने का इशारा कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में 8 अगस्त तक बैंकिंग प्रणाली ने जमा के रूप में 8,93,287 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस अवधि के दौरान बैंकों ने 3,62,069 करोड़ रुपये ऋण आवंटित किए हैं। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में मात्र 51,536 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह निवेश 2,22,255 करोड़ रुपये था।

अंत में बड़ा सवाल यह है कि ये आंकड़े आखिर क्या संकेत दे रहे हैं? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ब्याज दरों में 1 फीसदी अंक कटौती का लाभ नहीं मिला है। बाजार से रकम जुटाने वाली कंपनियों को भी कोई खास फायदा नहीं मिला है। उनके लिए उधारी पर लागत बढ़ गई है। हां, यह जरूर है कि बैंकों से ऋण लेने वाली कंपनियों को लाभ हुआ है क्योंकि ऐसे ऋणों पर ब्याज बाहरी मानक जैसे रीपो दर या एक साल के ट्रेजरी बिल से जुड़े हैं। इन पर ब्याज में कमी आई है। कई बैंकों ने अपनी कोष आधारित उधारी की सीमांत लागत दर घटा दी है।

मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि केंद्रीय बैंक के पास मौद्रिक प्रसार यानी उसका लाभ ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाने और सरकार के उधारी कार्यक्रमों को सफल बनाने की योजना मौजूद है। बेशक, जून तिमाही में रियल जीडीपी में 7.8 फीसदी वृद्धि आगे ब्याज दरों में कमी की उम्मीद पर पानी फेर चुकी है। बाजार जून में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में रुख में हुए बदलाव पर अब नाखुशी का इजहार भी नहीं कर सकता।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं।)

आपका पक्ष

सेमीकॉन इंडिया: एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया-2025 का उद्घाटन करते हुए भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की महाशक्ति बनाने का आह्वान किया। यह आयोजन अपने पैमाने और महत्त्व में अभूतपूर्व है क्योंकि इसमें 33 देशों की 350 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 'डिजाइन इन इंडिया' का विचार रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह केवल 'मेक इन इंडिया' का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का अगला कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। यह संदेश अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की टैरिफ नीतियों की ओर इशारा था। वैश्विक परिदृश्य में जब महाशक्तियां अपने हित साधन में लगी हैं, भारत को अपनी तकनीकी ताकत स्वयं खड़ी करनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों भारत अभी भी चीनी वस्तुओं पर इतना निर्भर है। ऐसी कई वस्तुएं जिनका उत्पादन देश में सहजता से हो सकता है उनका बड़े पैमाने पर चीन से आयात हो रहा है। कभी जो चीजें भारत में बनती थीं वह आज विदेश से मंगाई जाती हैं। यह स्थिति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के विपरीत है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे और मझोले उद्योग भी इस अभियान का हिस्सा बनें। असली आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब देश का पूरा उद्योग जगत अनुसंधान, उत्पादन और नवाचार में योगदान दे। अगर सही नीति, निवेश और उद्यमशीलता का संगम हुआ, तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में नेतृत्वकारी भूमिका भी निभा सकेगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया -2025 प्रदर्शनी का अवलोकन किया

प्रदूषण नियंत्रण के लिए कारगर नीति की दरकार

प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को लेकर सतत निगरानी कर सख्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है। असल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचाव के तरीकों के बारे में बच्चे प्राथमिक कक्षाओं से कॉलेज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन उन पर अमल के लिए उतने सटीक, व्यावहारिक व ईमानदार प्रयास अभी तक नहीं हो पाए हैं। प्रदूषण जैसी विशाल समस्या की गंभीरता को देखते हुए कई कानून व संगठन बनाए गए हैं, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन अधिनियम आदि। लेकिन कुल मिलाकर वही ढाक के तीन पात। सार्थक कोशिश की पहल के अभाव में देश इन दिनों प्रदूषण की गहरी मार झेल रहा है। इस दिशा में सुधार के लिए समग्र समझ, चौतरफा उपायों व व्यापक अभियानों की आवश्यकता है। एक तरफ महानगरों में तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या पर विधिवत अंकुश लगाने के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा व फसल अवशेष जलाने को हतोत्साहित कर, वैकल्पिक उपाय बेहद जरूरी है। हर नागरिक की इस प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी व भूमिका सुनिश्चित होनी ही चाहिए। चाहे इसके लिए कोई नीति बनानी पड़े या चाहे कोई कड़ा कानून।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

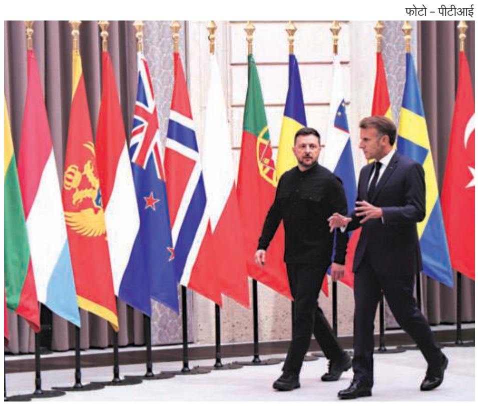

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की पेरिस में गुरुवार को यूक्रेन पर आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुए। यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इस बैठक की मेजबानी की।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

नेक्सट जेन जीएसटी सुधार

लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव लाने की जो घोषणा की थी उसे पूरा कर दिया गया है। वर्ष 2017 से लागू की गई वस्तु एवं कर सेवा को आसान बनाने की प्रक्रिया के तहत जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब में से 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे तथा 5 और 18 प्रतिशत वाले स्लैब ही रहेंगे। नुक्सानदेह और विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी की दर से शुल्क लगाने का फैसला किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं इस टू टियर टैक्स स्ट्रक्चर से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को व्यापार करने में बहुत आसानी होगी। आम आदमी ने तो सस्ती और महंगे होने वाले उत्पादों के बारे में तो जानकारी ले ही ली होगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हर कोई जेब के मुताबिक बाजार में जाकर खरीदारी करेगा। भारत निर्यात उन्मुखी देश नहीं है। हम जो पैदा करते हैं उसी को अपने ही बाजार में बेचते हैं। अगर बाजार में चीजें सस्ती होती हैं तो निश्चय ही इससे आम आदमी को राहत मिलती है। बाजार तभी गुलजार होंगे जब उपभोक्ता की जेब में पैसा होगा। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ही हर साल सरकार की कमाई में जोरदार इजाफा होता आया है। इस साल 2025 में तो जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। शुरूआती साल में इसके जरिए सरकारी खजाने में 7.41 लाख करोड़ रुपये (जुलाई से मार्च तक) आए थे, तो वहीं अगले साल 2018-19 में जीएसटी से कमाई का आंकड़ा 11.77 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं इसकी शुरुआत से अब तक कलेक्शन में तीन गुना से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है और 2021-22 से लेकर 2024-25 तक सिर्फ पांच साल में ही जीएसटी से सरकार की कमाई दोगुनी हो चुकी है और ये 11.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि स्लैब कम होने से घरेलू मांग में जबरदस्त इजाफा होगा और इससे राजस्व बढ़ेगा। अगर राजस्व संग्रह बेहतर होता है तो फिर राज्यों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कर सुधारों से उद्योग जगत को भी फायदा होगा। कपड़ा, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल उद्योग को इस फैसले से लाभ होगा क्योंकि कर घटने से उनकी बिक्री बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, 1,200 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मध्यमवर्गीय खरीदारों के लिए सकारात्मक रहेगा और इससे ऑटोमोबाइल सैक्टर की बिक्री में उछाल आ सकता है।

इस साल 2025 में जीएसटी क्लैक्शन ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े और सरकार को ताबड़तोड़ कमाई कराई। अप्रैल महीने में अब तक सबसे बड़ा मासिक जीएसटी क्लैक्शन हुआ जो 2.37 लाख करोड़ का रहा। जीएसटी दरों में बदलाव के चलते सरकार ने करीब 40 हजार करोड़ के सालाना राजस्व नुक्सान की आशंका जताई है। इसका मतलब यह है कि कर सुधारों से कमाई पर असर पड़ेगा। विपक्ष शासित राज्य सरकारें राजस्व की भरपाई की मांग कर रही हैं। राज्यों का कहना है कि अगर वर्ष 24-25 के आधार वर्ष होने के कारण वृद्धि 14 फीसदी से कम रहती है तो उनके राजस्व को होने वाले नुक्सान की भरपाई की जानी चाहिए। विशेषज्ञ लम्बे समय से यह कहते रहे हैं कि अलग-अलग स्लैब होने से जीएसटी प्रणाली का कामकाज और प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्हें युक्ति संगत बनाने की कवायद काफी समय से लम्बित थी। जीएसटी के शुरूआती पांच साल तक राज्यों की क्षतिपूर्ति उपकर के जरिये की गई। कोरोना महामारी के दौरान जब उपकर संग्रह कम हो गया तो उसकी भरपाई उधारी से की गई। फिर उधारी को चुकाने के लिए उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई गई लेकिन यह व्यवस्था हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। राज्यों को राजस्व की हानि न हो। इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि स्लैब कम होने से घरेलू मांग में जबरदस्त इजाफा होगा और इससे राजस्व बढ़ेगा। अगर राजस्व संग्रह बेहतर होता है तो फिर राज्यों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कर सुधारों से उद्योग जगत को भी फायदा होगा। कपड़ा, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल उद्योग को इस फैसले से लाभ होगा क्योंकि कर घटने से उनकी बिक्री बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, 1,200 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मध्यमवर्गीय खरीदारों के लिए सकारात्मक रहेगा और इससे ऑटोमोबाइल सैक्टर की बिक्री में उछाल आ सकता है। वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें घटने से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर लग्जरी गाड़ियां और महंगे इलैक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को नुक्सान हो सकता है क्योंकि 40 प्रतिशत कर से उनकी बिक्री घट सकती है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए किए गए सुधार भी महत्वपूर्ण हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर देना और निर्यातकों को ऑटोमैटिक रिफंड की सुविधा देना व्यापार की आसानी को बढ़ाएगा। इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों की नकदी प्रवाह में सुधार होगा और वे अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा पाएंगे। ऑटोमैटिक रिटर्न फाइलिंग का नया प्रस्ताव जीएसटी अनुपालन को सरल बनाएगा और करदाताओं को झंझट से बचाएगा। यह सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में एक अहम कदम माना जाएगा। जीएसटी परिषद ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इससे आर्थिक विकास होगा तथा अमरीकी टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

इन कर सुधारों को नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार कहा गया है। उम्मीद की जाती है कि इन बदलावों से भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य राजस्व के लिए जीएसटी पर ही निर्भर हैं। राज्यों के साथ राजस्व साझा करने के मामले पर केन्द्र को उदार हृदय से काम लेना होगा।

वह हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान...

कभी प्यार तो कभी सख्त मिजाज से समझाते हैं,
एक गुरु ही तो है इस संसार में जो हमें खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं,
वह हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में ले आते हैं,
सच्चे गुरु ही तो जौहरी की तरह हम सभी को तराश कर हीरा बनाते हैं...!!

गीता पाढा

भारतीय विद्यार्थी का दर्द...

कलम-दवात
कुमकुम चड्ढा

जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने छात्र वीज़ा पर सख्ती लागू की तो व्यापक असंतोष फैल गया। अनेक मामलों में वीज़ा आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों में प्रतीक्षा अवधि दस महीने से भी अधिक खिंच गई। कुछ पीएचडी प्रस्ताव तो इस अंतहीन प्रतीक्षा के कारण स्वत: समाप्त हो गए। सरकार का तर्क है कि इस कदम का उद्देश्य उन छात्रों को चिन्हित करना है जो वास्तविक पढ़ाई के बजाय वीज़ा का उपयोग काम और स्थायी निवास पाने के साधन के रूप में करते हैं किंतु इस प्रक्रिया में ईमानदार और गंभीर छात्रों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है।

सरकार ने एक श्रृंखलाबद्ध सुधारों की घोषणा की है, जिनमें वीज़ा की कठोर शर्तें, अधिक कठिन अंग्रेज़ी भाषा परीक्षण और विदेशी छात्रों को लाने वाले शिक्षा एजेंटों के लिए कड़े नियम शामिल हैं। इन शर्तों ने संस्थानों की नीतियों को भी प्रभावित किया है और कुछ ने तो भारतीय छात्रों पर संपूर्ण प्रतिबंध तक लगा दिए हैं। सरकार यह स्वीकार करती है कि परिवर्तन कठिन होता है किंतु उनका कहना है कि वर्तमान में प्रवासन का स्तर अत्यधिक है और इसे 'संतुलित स्तर' पर लाना आवश्यक है।

इन परिस्थितियों ने भारतीय छात्रों के बीच गहरी चिंता उत्पन्न कर दी है। भारत परंपरागत रूप से ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय रहा है। छात्रों का मानना है कि जिस नीति ने कभी खुले द्वारों से उनका स्वागत किया था, वही अब अचानक उनके लिए दरवाज़े बंद कर रही है। अनिश्चितता और अप्रत्याशितता के कारण कई आवेदकों ने अपने वीज़ा आवेदन वापस ले लिए हैं। हालांकि आव्रजन की पारदर्शिता और गंभीरता को लेकर सरकार की चिंताएं उचित कही जा सकती हैं परंतु यह कदम दोनों देशों के बीच बनी आपसी सद्भावना को कमज़ोर कर सकता है।

स्थिति को स्पष्ट करते हुए भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फ़िलिप ग्रीन ने कहा कि वीज़ा अस्वीकृतियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। उनके शब्दों में, यह सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के वीज़ा अनुमोदनों का दर लगातार बढ़ रहा है। भारतीय छात्रों के ऑस्ट्रेलिया जाने का एक लंबा इतिहास रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा, पर यह केवल एकतरफ़ा रास्ता नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूं कि वास्तव में हो क्या रहा है। भारतीय सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां शाखा कैंपस खोलने का अवसर दिया है और भविष्य इसी दिशा में है। फिर भी बहुत से भारतीय उच्च गुणवत्ता वाली ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा चाहते रहेंगे और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी जाते रहेंगे लेकिन इन कैंपसों की वजह से भारतीय परिवारों को कम लागत पर भारत में ही वही शिक्षा पाने का विकल्प उपलब्ध होगा।

कूटनीति की दृष्टि से यह शायद सबसे संतुलित बयान हो सकता था। फिर भी, क्या ये मीठे शब्द वस्तुत: एक 'अदृश्य प्रतिबंध' नहीं हैं, क्योंकि शाखा कैंपस भारत में खोले जा रहे हैं? इस पर ग्रीन ने कहा- 'नहीं' यह केवल विकल्प देने की बात है। भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का अवसर बना रहेगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि छात्रों की संख्या को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच रहा है। उनके अनुसार यह वास्तविकता है और यह भी सच है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत से आने वाले छात्र उच्च गुणवत्ता के स्तर पर हों। इसके बावजूद हम भारतीय छात्रों का स्वागत करते रहेंगे और वे ऑस्ट्रेलिया आते रहेंगे। साथ ही, यह दूसरा रास्ता भी खुला रहेगा जिसके ज़रिये कुछ छात्र भारत में ही इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा पाएंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी दृष्टिकोण पर ग्रीन ने कहा-भारत विकासशील देश है। यह तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां गहन ऊर्जा और जीवंतता है और आने वाले दशकों में यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर और भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत को गहराई से समझे और उससे निकटतर सहयोग बनाए। इस प्रश्न पर कि 'नए भारत' की अवधारणा क्या हाल की है या वर्षों से विकसित हो रही है, फ़िलिप ग्रीन ने कहा- पिछले पांच वर्षों में इसकी रफ्तार तेज़ हुई है। मैंने देखा है कि भारत का वैश्विक प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले पांच वर्षों में तीसरे स्थान पर होगा। यह इस बात का संकेत है कि हाल के वर्षों में प्रगति कितनी तीव्र रही है।

द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए ग्रीन ने क्रिकेट और व्यापार को एक ही सांस में जोड़ा। उनके अनुसार, हमारे बीच आधुनिक और समकालीन संबंध हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और हमारे पास यह मानवीय सेतु है, लगभग दस लाख भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यह सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रवासी आबादी है। क्रिकेट भी हमें जोड़ता है, पर हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं और उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहते हैं जो हमें भविष्य की ओर ले जाएंगे। क्रिकेट के लिए आइए और व्यापार के लिए रुकिए यह वाक्यांश इसी भावना से है कि भारतीय क्रिकेट का आनंद लें और साथ ही कुछ समय व्यापारियों के साथ बिताकर ऑस्ट्रेलिया में अपना व्यवसाय बढ़ाएं। मैं आधुनिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, पर क्रिकेट की अहमियत को भी नज़रअंदाज़ नहीं करुंगा।

ग्रीन तब चर्चा में आए जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स को दिल्ली के मालचा मार्ग पर चाय पिलाने ले गए। उन्होंने बताया - हम ऑटो से गए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है और क्यों लेकिन वे बेहद प्रसन्न हुए। हम एक प्राचीन वृक्ष के नीचे खड़े थे, वहीं पास में एक छोटा सा मंदिर था और दशकों से वहां मौजूद चाय वाला हमें अपनी मशहूर चाय परोस रहा था। उनके लिए यह अनोखा अनुभव था। भारतीय संस्कृति की एक झलक। यह कहते हुए वे अपने लुटियंस दिल्ली स्थित भव्य आवास पर चाय की चुस्की लेते हैं, वह घर जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार जोसेफ़ स्टीन ने बनाया था और जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

अंत में सकारात्मक संदेश देते हुए ग्रीन ने कहा-यह समाज विकास की दिशा में बड़े परिवर्तन से गुज़र रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरी तरह सही प्रतीत होता है। कुछ देश आर्थिक रूप से मजबूत और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनने के बाद दुनिया से अपने संबंधों में आक्रामक हो जाते हैं। मेरी आशा है कि भारत गांधी की भावना से प्रेरणा लेकर एक वैश्विक शक्ति बनेगा जो शेष विश्व के साथ तालमेल और समन्वय के साथ आगे बढ़े।

दलितों के केस में सीजेआई ने खींची लक्ष्मण रेखा, हाई कोर्ट का फैसला पलटा

● एससी, एसटी एक्ट में आरोपी को जमानत तभी मिल सकती है जब प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनता हो

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न से जुड़े मामले यानी एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है, जब स्पष्ट रूप से यह साबित हो कि आरोपी के खिलाफ प्रथम द्रष्टया कोई मामला न बनता हो। यानी पहली नजर में ही यह तथ्य साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के प्रति कोई हिंसा नहीं की है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को कमजोर वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था और यह आरोपी को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने पर रोक लगाता है। इसके साथ ही पीठ ने जातिगत अत्याचार के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 (अग्रिम जमानत देने संबंधी) को लागू नहीं करने के बारे में है और इसे धारा के तहत दायर आवेदनों को सुनवाई से बाहर करने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धारा 18 आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है।

हालांकि, पीठ ने ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने के लिए स्पष्ट रेखा खींचते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत अगर प्रथम द्रष्टया यह साबित होता है कि आरोपी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है तो अदालत आरोपी को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर आवेदनों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत देने का विवेकाधिकार रखता है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा 18 स्पष्ट भाषा के साथ सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर आवेदनों को खारिज करती है और एससी/एसटी समुदाय के लोगों के प्रति अपराध करने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है।" पीठ ने कहा कि ऐसे आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ''यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।'

भारत-चीन सीमा पर बसे गांव के बच्चों का सैनिक स्कूल में प्रवेश का सपना साकार

अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती जनजातीय गांव सरली की एक 12 वर्षीय बच्ची 'मिली याबी' ने अपनी लगन और भारतीय सेना के मार्गदर्शन के बल पर सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में प्रवेश प्राप्त कर एक प्रेरणादायी मिसाल कायम की है।सेना को उम्मीद है कि यह छात्रा एक दिन एनडीए में प्रवेश लेकर सैन्य अधिकारी के तौर पर राष्ट्र की सेवा करेगी।दरअसल, सरली देश का सीमावर्ती गांव है, जो भारत-चीन सीमा के समीप बसा है। इस गांव की आबादी लगभग 1,500 है और यह ईटानगर से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

ऐसे में यहां संसाधनों की कमी और कई भौगोलिक कठिनाइयां मौजूद हैं। इसके बावजूद यहां के बच्चे भारतीय सेना से प्रेरणा लेकर सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देखते हैं। इसी भावना को साकार करने के लिए भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स ने मई 2024 में एक विशेष मेंटरशिप पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ सीमावर्ती गांवों के बच्चों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना था। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 5 और 8 के 33 बच्चों का चयन किया गया। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक चले प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को 88 क्लास, 18 मॉक टेस्ट और विस्तृत परामर्श सत्र कराए गए। बच्चों को इंटीग्रेशन एवं मोटिवेशनल टूर पर भी ले जाया गया, जहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण किया।

सेना ने इस दौरान न सिर्फ बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन में मदद की, बल्कि प्रवेश परीक्षा के लिए ईटानगर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी उठाई। इस अथक प्रयास का अभूतपूर्व परिणाम सामने आया और 33 में से 32 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की। फिलहाल चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच, मिली याबी ने पहली चयनित उम्मीदवार बनकर सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में प्रवेश प्राप्त किया।

सेना को उम्मीद है कि आगामी काउंसलिंग दौर में कम से कम 4 से 6 अन्य बच्चों का चयन सैनिक स्कूल में होगा। भारतीय सेना ने मिली याबी की उपलब्धि को सीमा क्षेत्र के बच्चों की आकांक्षाओं और अरुणाचल के युवाओं की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक बताया है। सेना का मानना है कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर सरली जैसे दुर्गम गांव भी भविष्य में सशस्त्र बलों के अधिकारी तैयार कर सकते हैं। संभव है कि एक दिन मिली याबी एनडीए, खड़कवासला में प्रवेश लेकर राष्ट्र की सेवा वर्दी में कर सके।

एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे अवार्ड

आकाश चोपड़ा

भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सफीना हुसैन के एनजीओ यानी नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन 'एजुकेट गर्ल्स' को 2025 का रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिलेगा। यह पहला इंडियन ऑर्गनाइजेशन है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय गैर-सरकारी संस्था है। यह संस्था दूरदराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ती है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है।

साल 2007 में सफीना हुसैन ने इसकी शुरुआत की थी। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 'एजुकेट गर्ल्स' मैग्सेसे सम्मान पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ है। सफीना हुसैन का जन्म 1971 में दिल्ली में हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। गरीबी, घरेलू हिंसा और मुश्किल हालातों ने उनके रास्ते में कई रुकावटें खड़ी कीं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। परिवार चाहता था कि उनकी जल्दी शादी कर दी जाए लेकिन एक रिश्तेदार आंटी ने उनका साथ दिया। उन्हें अपने घर में जगह दी और पढ़ाई दोबारा शुरू करने में मदद की। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सफीना ने 1987 से 1989 तक दिल्ली के डीपीएस स्कूल आरके पुरम से पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद सफीना ने पारंपरिक रास्ता अपनाया। उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि, ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला और मात्र 9 महीने में नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने कम्युनिटी-बेस्ड ग्लोबल डेवलपमेंट सैक्टर में अपना करियर शुरू किया। इसके चलते उन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की यात्राएं कीं। सफीना ने दो साल तक गर्ल्स एजुकेशन की समस्या का अध्ययन किया और उसके बाद साल 2007 में 'एजुकेट गर्ल्स' नाम के एनजीओ की शुरुआत की। यह एनजीओ ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में 5 से 14 साल की उम्र की लड़कियों की पहचान करता है और उन्हें स्कूलों में भर्ती करवाता है।

जब उन्होंने 50 स्कूलों से अपने काम की शुरुआत की तब उन्हें कोई फंड कहीं से नहीं मिला। उन्होंने अपने खर्चे से काम शुरू किया लेकिन जब रिजल्ट्स दिखने लगे तो राजस्थान सरकार ने 500 स्कूलों में काम करने की परमिशन दी और 5 प्रतिशत का सपोर्ट दिया। फिर जब सरकार ने एक पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने की परमिशन दी तो 17 प्रतिशत का सपोर्ट दिया। यानी जैसे-जैसे गवर्नमेंट का भरोसा बढ़ता गया उनका सपोर्ट भी बढ़ता गया। एजुकेट गर्ल्स को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इस संस्था ने उन परंपरागत सोच और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी जिनकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई पर रोक लगाई जाती थी। संस्था ने हजारों बच्चियों को निरक्षरता से बाहर निकाल कर शिक्षा, हिम्मत, हुनर और आत्मनिर्भरता की ताकत दी।

इस अवॉर्ड के साथ एजुकेट गर्ल्स अब उन महान हस्तियों की पंक्ति में शामिल हो गई है जिनमें सत्यजीत रे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी, विनोबा भावे, दलाई लामा, मदर टेरेसा और हायाओ मियाजाकी जैसे नाम आते हैं। "हमारे लिए शिक्षा सिर्फ प्रगति का रास्ता नहीं बल्कि हर लड़की का बुनियादी अधिकार है। यह सम्मान साबित करता है कि अगर सरकार, कॉरपोरेट और समाज साथ आएं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को बदला जा सकता है। हम भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मिशन को मजबूत बनाया।" यह बात सच है कि आज के आधुनिक दौर में भी हमारे समाज में ऐसी रूढ़िवादी सोच पल रही है जो लड़कियों की शिक्षा को तवज्जो देने से रोकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस धारणा की बेड़ियों को तोड़कर लड़कियों को निरक्षरता के अंधेरे से बाहर निकालने और उनका शिक्षा के उजाले से साक्षात्कार कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। 'एजुकेट गर्ल्स' संस्था ने इस तरह के सफल प्रयासों की एक नई मिसाल पेश की है। इस संस्था ने राजस्थान से शुरूआत करते हुए देशभर में सबसे जरूरतमंद समुदायों की पहचान की, स्कूल न जाने वाली लाखों लड़कियों को कक्षा में पहुंचाया और उन्हें उच्च शिक्षा एवं रोजगार पाने के लिए सक्षम बनाया। एजुकेट गर्ल्स ने अब तक 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाया है। एजुकेट गर्ल्स की इस पहल से 1.55 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। खास बात यह है कि वे सिर्फ स्कूल में दाखिला कराने तक नहीं रुकते। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चियां स्कूल में टिकें और पढ़ाई में बेहतर करें। इसके लिए वे टीम बालिका नाम से 55,000 वॉलेंटियर्स की टीम के साथ काम करते हैं। ये वॉलेंटियर्स गांव-गांव जाकर उन परिवारों को समझाते हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में हिचकते हैं। संगठन ने प्रगति नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किया जिसके तहत 15 से 29 साल की 31,500 युवतियों को ओपन स्कूलिंग के जरिए पढ़ाई पूरी करने में मदद की जाती है। इसके अलावा 2015 में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड शुरू किया गया जिसने राजस्थान में दाखिला और पढ़ाई के नतीजों को बेहतर किया। सफीना की शादी मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता से हुई है जो सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं। उनके पिता यूसुफ हुसैन बॉलीवुड अभिनेता थे, जिनका 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। सफीना की कहानी और उनका काम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वह कहती हैं कि एक लड़की को पढ़ाने का असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को बदल देता है। उनका लक्ष्य है कि 2035 तक 1 करोड़ बच्चों तक उनकी पहुंच हो और उनका मॉडल दुनियाभर में अपनाया जाए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

सच्चे शिक्षक वे होते हैं, जो हमें खुद के लिए सोचने में मदद करते हैं। -डॉ. एस. राधाकृष्णन

जीएसटी का दूसरा दौर

ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर आशंकाएं मंडरा रही हैं, तब जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी की चार स्लैब वाली संरचना को समाप्त कर दो स्लैब वाली सरल प्रणाली को मंजूरी दिया जाना निश्चित ही स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे आम जनता, मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे व्यवसायियों पर कर का बोझ कम होगा। यह समयानुकूल भी है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के चलते उपभोग में कमी आने के संकेत अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बने हुए थे। लेकिन अब, आम उपभोग की तकरीबन सभी वस्तुओं का सस्ता होना, उपभोक्ताओं में यकीनन खरीद की प्रेरणा को बढ़ाएगा। गौरतलब है कि आठ साल पहले हुई अपनी शुरुआत से जीएसटी व्यवस्था ने सरकार के राजस्व में तो खूब इजाफा किया, लेकिन जटिल दरें और बार-बार होने वाले संशोधन उपभोक्ताओं और कारोबारियों, दोनों के लिए उलझन का कारण बने। ऐसे में, सरकार द्वारा लाए गए ऐतिहासिक सुधार, जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही की थी, निस्संदेह इन उलझनों का समाधान बनेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में जीएसटी की चार दरें-5, 12, 18 और 28 फीसदी लागू हैं, नए सुधारों के तहत जिनके इसी महीने की बाईस तारीख से सिर्फ दो दरों-पांच और 18 फीसदी में तब्दील हो जाने से व्यापारिक गतिविधियों में स्पष्टता आएगी और कर चोरी की गुंजाइश भी कम होगी। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि इससे सरकारी राजस्व को तकरीबन 48 हजार करोड़ रुपये की हानि होगी, पर सरकार का यह कहना उम्मीद जगाता है कि कम दरें उपभोग का स्तर बढ़ाएंगी, कर चोरी को कम करेंगी और कर-आधार को भी विस्तृत करेंगी। इससे दीर्घकाल में राजस्व में वृद्धि ही होगी। हां, सरकार को यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व में तत्कालिक हानि की भरपाई के लिए वह कोई उपाय ढूंढे, ताकि राज्यों व केंद्र के बीच वित्तीय तनाव न बढ़े। किसी भी कर सुधार की असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होती है। सरकार बड़े दावों से आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित करे कि कटौतियां केवल कॉरपोरेट मुनाफे को ही न बढ़ाएं, बल्कि इनके फायदे आम आदमी तक भी पहुंचें। ये सुधार, अगर सही ढंग से लागू किए जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और गतिशील बनाने में महती भूमिका निभा सकते हैं।

नए युग का सूत्रपात

जीएसटी की दरों में बदलाव और 12 फीसदी टैक्स सीमा को खत्म करना कराधान में एक नए युग का सूत्रपात है। उपभोक्ताओं में खुशी और उम्मीद का माहौल है, क्योंकि स्लैब दर में 50 फीसदी से ज्यादा की कटौती की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन वस्तुओं की कीमतें 50 फीसदी तक गिर जाएंगी।

आठ साल पहले जब जीएसटी को लागू किया गया था, उसी समय से इसे आलोचना और प्रशंसा, दोनों का सामना करना पड़ा है। किसी अन्य कानून का इतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना जीएसटी का पड़ा, क्योंकि इसने एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को जन्म दिया, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी।

पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी परिषद ने केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए 56 बार बैठकें की हैं, यानी औसतन हर साल सात बार। हर गुजरते महीने के साथ जीएसटी संग्रह में वृद्धि एक ऐसी खबर बन गई है, जिस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि करती है, बल्कि औसत भारतीयों द्वारा उपभोग की जाने वाली लगभग हर चीज पर कर चुकाने की कठिनाई को भी उजागर करती है।

नारायण कृष्णमूर्ति
वरिष्ठ पत्रकार

अभी 2-3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब हम चार-स्तरीय दरों- पांच फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के बजाय पांच फीसदी और 18 फीसदी की सरलीकृत दो टैक्स स्लैब की ओर बढ़ रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा कदम है, जिसका मिला-जुला असर होगा, क्योंकि 12 फीसदी दर वाली कुछ वस्तुओं और सेवाओं को 18 फीसदी की उच्चतर स्लैब में डाल दिया गया है, तथा कुछ को पांच फीसदी स्लैब में रखा गया है, जिससे राहत मिलेगी। हमेशा की तरह, तंबाकू जनित उत्पादों और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 फीसदी स्लैब बना हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सिगरेट, प्रीमियम शराब और उच्च श्रेणी की कारों जैसी वस्तुओं को कर में राहत नहीं मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के चलते कर कटौती की उम्मीद तो पहले से ही थी। 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले इस बदलाव से सरकारी राजस्व में 48,000 करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका है।

उपभोक्ताओं में खुशी और उम्मीद का माहौल है, क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई एफएमसीजी वस्तुएं, जैसे साबुन, हेयर ऑयल, शैंपू और अन्य घरेलू सामान, पहले के 12 फीसदी वाले स्लैब से पांच फीसदी वाले स्लैब के दायरे में आ गई हैं। भले ही स्लैब दर में 50 फीसदी से ज्यादा की कटौती की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन वस्तुओं की कीमतें 50 फीसदी तक गिर जाएंगी।

सभी प्रकार की चपाती और परांठे समेत आवश्यक खाद्य पदार्थ कर-मुक्त रहेंगे, जिन पर अब कोई कर नहीं लगेगा, जबकि पहले पांच फीसदी कर लगता था। जीएसटी कर दरों को युक्तिसंगत बनाने की पूरी कवायद घरेलू खपत को बढ़ावा देने और कुछ हद तक व्यवसायों को अमेरिका द्वारा विभिन्न भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करने के लिए की गई है। भावनाएं मजबूत हैं, और यह भावना शेयर बाजारों में आई तेजी से परिलक्षित होती है, क्योंकि जीएसटी दर में कटौती की घोषणा के बाद बाजार में तेजी देखी गई।

लेकिन, दरों में कटौती का जश्न मनाते हुए यह भी सोचना चाहिए कि आखिर कुछ वस्तुओं पर जीएसटी क्यों लगाया गया था। उदाहरण के लिए, नक्शों, चार्ट, पेंसिल और स्टेशनरी पर 12 फीसदी जीएसटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। इसी तरह, जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी उन लोगों पर जुर्माना लगाने जैसा था, जो खुद को वित्तीय जोखिमों से बचा रहे थे। इसी तरह, कृषि उत्पादों, दूध, घी आदि पर जीएसटी शायद टाला जा सकता था, फिर भी ये कर मौजूद हैं। इन दरों का पांच फीसदी स्लैब में आना एक सकारात्मक संकेत है। इन करों का अस्तित्व व्यापक स्तर पर जवाब की मांग करता है।

पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, जो सरकार के राजस्व के लिए अच्छी बात है। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह की खबर सामान्य बात हो गई है, और इसने हर भारतीय को कर के दायरे में ला दिया है। जीएसटी अपने नौवें वर्ष में प्रवेश कर गया है, और यह व्यापार में आसानी, बेहतर अनुपालन और व्यापक आर्थिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार विकसित हो रहा है। चाहे करों में वृद्धि हो या कटौती, उसके असर को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका अन्य कई कारकों पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ता है। वैश्विक तेल की कीमतें, मुद्रा दर, शेयर बाजार की गतिविधि, मांग एवं आपूर्ति, और बदलते रुझान कुछ ऐसे कारक हैं, जो कराधान और उपभोग को प्रभावित करते हैं।

जीएसटी अनुपालन से जुड़ी लागतों से संबंधित मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस धारणा को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जाना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। हमने देखा है कि एफएमसीजी कंपनियां कीमतों में फेरबदल करने के बजाय पैक के आकार के साथ खेल करती हैं, जिसके कारण कई मामलों में कीमतों में प्रत्यक्ष रूप से कोई कमी नहीं दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि इस कदम से बिक्री बढ़े, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे लोगों पर बढ़ती लागत का बोझ सीधे तौर पर कम हो। लोग सिर्फ इसलिए चीजें नहीं खरीदते कि लागत कम हो गई है। कीमत कम होने पर लोग ज्यादा दवाइयां या ज्यादा खाना नहीं खाते।

इसी तरह, जीएसटी के जरिये देश भर में कर संग्रह का एक मजबूत मॉडल तैयार करने के बाद सरकार इसे पूरी तरह से छोड़ने वाली नहीं है। हां, जीएसटी के तहत वस्तुओं पर कर की दर में उतार-चढ़ाव जरूर होगा, लेकिन जीएसटी संग्रह पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। नागरिकों के तौर पर, हमें बदलती कर दरों के साथ तालमेल बिठाना होगा और उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां हम हर बार कर दर में समायोजन के दौरान ज्यादा बचत कर सकते हैं। फिलहाल, जीएसटी दरों में इस बदलाव को उपभोग को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए, जो बढ़ती लागतों के कारण कम हो रहा था। परिवारों को अपने बजट पर कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि वे वास्तव में कितनी बचत कर सकते हैं और उस बचत का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

edit@amarujala.com

प्रकृति

पीर पर्वत की सुननी चाहिए

शीर्ष अदालत का यह कहना, 'यदि हालात ऐसे रहे, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिमाचल नक्शे से ही गायब हो जाएगा।' पहाड़ी राज्यों के विकास मॉडल के लिए गंभीर चेतावनी है।

आसमान से बरसती आफत के बीच दरकते पहाड़ कराह रहे हैं। कई इलाकों के अस्तित्व पर संकट है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से जान-माल की बड़ी क्षति हो रही है। सावन-भादों हर साल आंसुओं के सैलाब लेकर आ रहे हैं। हिमाचल में बीते तीन साल में बादल फटने की सौ से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इस मानसून में करीब 50 जगह बादल फट चुके हैं। वर्ष 1949 के बाद इस बार अगस्त में सर्वाधिक 431 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 68 फीसदी ज्यादा है। बादल फटने, बाढ़-भूस्खलन से 182 लोगों की जान जा चुकी है, 45 लापता हैं।

अब तक 3,525 करोड़ रुपये का नुकसान झेल चुके हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। बीते दिनों शीर्ष अदालत ने पारिस्थितिक असंतुलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यदि हालात ऐसे ही रहे, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिमाचल नक्शे से ही गायब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी आंखें खोलने वाली है। जानकार लंबे अरसे से कह रहे हैं कि पहाड़ों पर बढ़ता मानवीय दखल, अंधाधुंध जल बिजली प्रोजेक्ट, फोरलेन, वन कटान और नदी-नालों के रास्तों में निर्माण आपदाओं की प्रमुख वजहें हैं। अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली भी जरूरी है, लेकिन विकास के ऐसे मॉडल को बदलना होगा, जो आपके अस्तित्व को ही चुनौती देने लगे।

बविंद्र वशिष्ठ

करीब दो माह पहले मंडी के सराज में एक ही रात 17 जगह बादल फटने से भारी तबाही के बाद हिमाचल सरकार के आग्रह पर इसके कारण तलाशने के लिए केंद्र ने टीम भेजी। पहले भी कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्टें फाइलों में दफन हैं। बरसात खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। कभी बादल पर्वतीय क्षेत्रों में फटते थे, लेकिन अब ये आपदाएं मध्य पहाड़ी और आबादी वाले निचले इलाकों में लगातार हो रही हैं। पिघलते ग्लेशियरों से बन रही झीलें और बिजली प्रोजेक्टों के लिए बनाए जा रहे बांधों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद की रिपोर्ट बताती है कि सतलुज बेसिन के ग्लेशियरों में वर्ष 2019 में 562 झीलें थीं, जो 2023 में बढ़कर 1,048 हो गई हैं। आईआईटी, रोपड़ के एक अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल का करीब 45 फीसदी हिस्सा भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं को लेकर संवेदनशील है। ग्लेशियर पिघलने की दर पिछले 25 वर्षों में दोगुनी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल में सतलुज बेसिन पर प्रस्तावित सभी पन बिजली परियोजनाएं यदि धरातल पर उतर गईं, तो खाब से लेकर भाखड़ा डैम तक करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी ही लुप्त हो जाएगी। विकास परियोजनाएं ऐसी कंसल्टेंट एजेंसियों की रिपोर्ट पर बन रही हैं, जिन्हें पहाड़ों के मिजाज का पता ही नहीं है।

विकास की अवधारणा में अर्थशास्त्र के हावी होने से भी कई पहलू नजरअंदाज हो रहे हैं। पहाड़ों की पारिस्थितिकी नाजुक है, लेकिन हमारा विकास मॉडल इसके विपरीत है। पहाड़ महफूज रहेंगे, तभी पर्यटन और कारोबार बढ़ेगा। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने वाले स्थानीय संस्थानों को विकास परियोजनाओं के साथ जोड़ना जरूरी है। पूर्व के अध्ययनों को लिंक कर शोध संस्थान और नीति निर्माता समन्वय के साथ दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएंगे, तो पहाड़ों पर हर साल मच रही यह तबाही रुक सकती है। वैज्ञानिक आकलन के आधार पर संभावित खतरे के मद्देनजर क्षेत्रवार नो कंस्ट्रक्शन जोन को चिह्नित कर नए सिरे से विकास का खाका खींचना समय की जरूरत है।

बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक होते हैं

बुजुर्ग होना एक अनुभव है, जो आप अपनी पूरी जिंदगी में अर्जित करते हैं। बुजुर्ग होने पर यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना ज्ञान समाज के साथ साझा करें। मानवता के इतिहास में बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक रहे हैं।

हमारे समाज में, जहां युवावस्था और युवा होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, मैं शुरू में अपनी बुजुर्गियत को स्वीकारने से हिचकिचाता था।

लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाते हैं, तो आप इसे नकार नहीं सकते। मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्ग होना एक अनुभव है, जो आप अपनी पूरी जिंदगी में अर्जित करते हैं।

डेविड सुजुकी

बुजुर्ग होने पर यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना ज्ञान समाज के साथ साझा करें। मानवता के इतिहास में बुजुर्ग ही समाज के शिक्षक रहे हैं। आप इस समुदाय के जीवंत इतिहास हैं। मैं अपने साथी बुजुर्गों से आग्रह करता हूं कि वे 'बुजुर्ग' शब्द से परहेज करना बंद करें और समझें कि यह न केवल सम्मान देता है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी लाता है। हम एक अनोखी स्थिति में हैं, हमने एक पूरा जीवन जिया है, हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हैं, और अपने अनुभवों से नई पीढ़ी के लिए सबक दे सकते हैं। अब जब मैं सत्तर के दशक में हूं, मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के आखिरी हिस्से में हूं, मैं इसे 'मृत्यु क्षेत्र' कहता हूं। हर दिन मेरे लिए एक उपहार है, जिसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। आसन्न मृत्यु जीवन पर विचार करने, सफलताओं और असफलताओं, प्यार और

मुड़-मुड़ के देख

नुकसान, खुशियों और त्रासदियों, और उन लोगों, अनुभवों और घटनाओं पर विचार करने की एक शक्तिशाली प्रेरणा है, जिन्होंने मुझे, मेरे मूल्यों और विश्वासों को आकार दिया है। मैं उन चीजों के पीछे भागने से आजाद हो गया हूं, जो लोग जवानी में करते हैं। जवानी में बहुत सारे दबाव होते हैं, जो जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। लेकिन, अब मैं आराम से बैठकर सोच सकता हूं। और मुझे लगता है कि यह वाकई मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली है और बहुत कुछ सीखा है। तो एक बुजुर्ग के तौर पर, शरीर की गति धीमी हो सकती है। मेरा दिमाग अब भी काम कर रहा है, और मुझे काम करना है। अच्छी तरह से बुढ़ापा बिताने का मतलब है कुछ ऐसा करते रहना, जो आपको उत्साहित करे।

घर चलाने के लिए घर बेचना जरूरी नहीं

रिवर्स मॉर्गेज ऐसी सुविधा है, जो बुजुर्गों को नियमित कमाई का सहारा दे सकती है।

मथुरा के 70 वर्षीय रामप्रसाद रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उम्र के साथ मेडिकल खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में वह अपना घर बेचने के बारे में सोच रहे हैं। पर वह उलझन में हैं। विशेषज्ञों ने उन्हें वे सभी विकल्प सुझाए, जिनसे वह सही निर्णय लेकर घर को कमाई का जरिया बना सकें।

मथुरा की संकरी गलियों में सुबह की पहली किरणें यमुना नदी के किनारे धीरे-धीरे फैल रही थीं। यमुना का शांत जल, इस शहर को एक अनोखा आध्यात्मिक आकर्षण देता है। यहां के एक पुराने मोहल्ले में रामप्रसाद जी का मकान है। लाल पत्थरों से बना यह घर अब एक बड़े सवाल का केंद्र बन चुका था। रामप्रसाद, उनकी पत्नी सरला और बेटा अनिल घर के भविष्य को लेकर उलझन में हैं। क्या वे इसे बेच दें? रिवर्स मॉर्गेज लोन लें? या किराये पर दे दें?

रामप्रसाद 70 साल के हैं और सरला 65 कीं। रामप्रसाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन से उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं। बेटा अनिल दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। रामप्रसाद और सरला को चिंता थी कि उनकी बचत और पेंशन उनके भविष्य के लिए काफी नहीं होगी। अनिल भी चाहता है कि उसके माता-पिता की जिंदगी आरामदायक हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि वे जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लें। इसलिए सभी विकल्पों को परखना जरूरी था। इसके लिए उसने वित्तीय सलाहकार राकेश से परामर्श लेने की सोची, जिन्होंने उसे सारे आयामों के बारे में बारीकी से समझाया।

विकल्प 1 : घर बेचना

वित्तीय सलाहकार-मान लीजिए, घर 50 लाख में बिकता है। इन पैसों से जरूरत के हिसाब से आप छोटा घर खरीद सकते हैं या किराये पर रह सकते हैं। बाकी पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं। घर बेचना तभी सही है, जब आप नए घर में खुशी से रह सकें। क्योंकि, जिस घर में आपका

जन्म और शादी हुई, बच्चे बड़े हुए हों, उससे भावनात्मक रिश्ता होता है। घर बेचने के बाद आप भावनात्मक लगाव खो देते हैं और रकम को सही जगह निवेश न करना दूसरा बड़ा नुकसान है। तीसरा-अगर आप किराये पर रहते हैं, तो हर साल किराये का बोझ बढ़ेगा।

किराया बढ़ने की रफ्तार : प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के अनुसार, देश के सात शीर्ष शहरों के प्रमुख इलाकों में पिछले तीन साल में किराये में 76 फीसदी तक वृद्धि दर्ज की गई। बंगलूरू के सरजापुर रोड में घरों का औसत किराया सबसे ज्यादा 76 फीसदी बढ़ा है। 2021 के आखिर में 1000 वर्गफुट के 2 बीएचके घर का किराया 21,000 रुपये से बढ़कर 2024 के आखिर में 36,900 रुपये महीना हो गया। इसी तरह, एनसीआर के नोएडा सेक्टर 150 में किराया 66 फीसदी बढ़कर 16,000 रुपये से 26,600 रुपये हो गया। इस दौरान, पुणे के वाघोली में किराया 65 फीसदी बढ़ा है। बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में किराया बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है।

विकल्प 2 : घर किराये पर देना

राकेश ने दूसरा रास्ता बताया कि आप घर का एक हिस्सा किराये पर दे दें और खुद दूसरे हिस्से में रहें। मान लीजिए, आप दो कमरे किराये पर देते हैं, तो आपको 10-12 हजार रुपये महीने के मिल सकते हैं। इससे आय बढ़ेगी और घर भी आपके पास रहेगा। हालांकि, किरायेदार चुनते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। रेंट एग्रीमेंट बनवाकर पुलिस वैरिफिकेशन भी करवाएं। **-पवन पांडेय, *द बोनस***

विकल्प 3: रिवर्स मॉर्गेज

रिवर्स मॉर्गेज एक तरह का लोन है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मकान मालिकों को मिलता है। रिवर्स मॉर्गेज में आप अपना घर छोड़े बिना उसकी कीमत का कुछ हिस्सा बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं। बैंक आपको हर महीने एक निश्चित रकम या एकमुश्त राशि देगा और बदले में घर उनके नाम पर गिरवी रहेगा। आप जब तक जीवित हैं, घर में रह सकते हैं। आपके बाद, बैंक घर बेचकर अपना लोन वसूल करेगा।

रिवर्स मॉर्गेज लोन की शर्तें

- उम्र कम से कम 60 साल हो। अगर पति-पत्नी मिलकर आवेदन करते हैं, तो पत्नी की उम्र कम से कम 55 साल होनी चाहिए।
- लोन की अवधि 10 से 15 साल तक होती है। जिसे कुछ शर्तों के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ आवासीय संपत्ति पर लोन लिया जा सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इसके लिए पात्र नहीं है।
- लोन की रकम बैंक की तरफ से आवासीय संपत्ति के लिए तय बाजार मूल्य, उधार लेने वाले की उम्र और ब्याज दर पर निर्भर करेगी। एसबीआई की अधिकतम लोन सीमा दो करोड़ रुपये, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीमा एक करोड़ रुपये रखी है।
- गिरवी रखी जाने वाली आवासीय संपत्ति पर कोई बकाया लोन या अन्य वित्तीय देनदारी नहीं होनी चाहिए।

रिवर्स मॉर्गेज के फायदे

- कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति के निधन के बाद बैंक प्रॉपर्टी बेचकर पैसे वसूल कर लेगा। चाहें तो लोन चुकाकर बैंक से घर छुड़वा सकते हैं। कोई अतिरिक्त चार्ज या पेनल्टी नहीं लगती।
- रिवर्स मॉर्गेज से मिलने वाली रकम का उपयोग रोजमर्रा के खर्चों या मेडिकल बिलों के लिए किया जा सकता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(43) के तहत रिवर्स मॉर्गेज से मिली रकम को आय नहीं माना जाता। टैक्स नहीं देना पड़ता।

अपनी जरूरत के हिसाब से लें फैसले

फिनकार्ट के फाउंडर तनवीर आलम बताते हैं कि हर व्यक्ति की वित्तीय जरूरतें अलग-अलग हैं। अपनी वित्तीय जरूरतों के आधार पर फैसला करें। अगर आपके पास नियमित आय का कोई जरिया नहीं है। साथ ही सिर्फ अपने जीने तक घर में रहना चाहते हैं, तो रिवर्स मॉर्गेज बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन ब्याज दरों और शर्तों की जांच करें। अगर आपके पास नियमित आय का साधन है और एकमुश्त बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, तो घर किराये पर चढ़ाना अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें घर आपके पास ही रहेगा और अतिरिक्त आय से आप इलाज के खर्च मैनेज कर पाएंगे। यदि आपको तुरंत बड़ी रकम चाहिए, तो घर बेचना ठीक हो सकता है, लेकिन रकम को सावधानी से निवेश करें।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बंगाल में विद्वेष

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ा तनाव दुखद व दुर्भाग्यजनक है। ऐसे कम ही अवसर आते हैं, जब सदन में झड़प या हिंसा की नौबत आती है, पर जब ऐसा होता है, तब पूरे देश को चिंता होती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे के लिए दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। देश में बंगाली प्रवासियों के साथ अत्याचार से संबंधित सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया, पर घोष ने सदन से बाहर जाने से मना कर दिया, तब मार्शल ने उन्हें बाहर किया। कुछ अन्य भाजपा विधायकों को भी सदन से बाहर निकाला गया। कुछ विधायकों को चिकित्सा सेवा की भी जरूरत पड़ गई। विपक्षी विधायकों ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष की ओर से उन पर पानी की बोतलें फेंकी गई हैं।

खैर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में परस्पर कितनी कटुता है, इसका अंदाजा ममता बनर्जी के भाषण से सहज ही लग जाता है। देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई चल रही है, पर पश्चिम बंगाल में यह मामला अलग ही राजनीतिक रूप ले चुका है। किसी जमाने में ममता बनर्जी को भी घुसपैठियों को लेकर बड़ी चिंता हुआ करती थी, पर अब उन्हें केवल बांग्लाभाषियों की चिंता है। उन्होंने इसे राजनीतिक औजार बना लिया है और इस कथित अत्याचार को वह बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं। नेताओं को क्षेत्रीयता की ऐसी संकीर्ण राजनीति से बचना चाहिए। अगर किसी एक राज्य में ऐसी राजनीति होगी, तो इसका असर तमाम राज्यों पर पड़ेगा। मिसाल के लिए, गुरुवार को हुए बिहार बंद के जवाब में गुजराती बनाम बिहारी की राजनीति कतई प्रशंसनीय नहीं है। बंगाली प्रवासियों के प्रति देश में कतई खराब माहौल नहीं है। देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां इस भाषा के आधार पर किसी को निशाना बनाया जा रहा हो।

बिहार हो या बंगाल या मणिपुर, देश के वरिष्ठ नेताओं को संकीर्ण राजनीति से बचना होगा, तभी हम समस्याओं का यथोचित समाधान निकाल पाएंगे।

कहीं भी अगर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है, तो उसमें लगभग सभी राज्यों के गरीब प्रभावित होते हैं, लेकिन केवल बंगाली प्रवासियों के प्रति चिंता जताने की राजनीति निंदनीय है। कितना अच्छा होता, अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के तमाम प्रवासियों के अधिकारों और सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनातीं।

आज घुसपैठ की समस्या वाकई बहुत बड़ी है, इसके इलाज के प्रति अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां ईमानदार नहीं हुईं, तो इससे देश को बहुत नुकसान होगा। भारत शायद ऐसा अकेला देश है, जहां घुसपैठियों का भी मनोबल बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। तभी तो घुसपैठ की बीमारी का अंत नहीं हो रहा है। गौर कीजिए, ममता बनर्जी ने विदेशी अधिनियम पर केंद्र के आदेश को एक चुनावी हथकंडा बताया और लगे हाथ यह भी दावा किया कि इससे मतदाता प्रभावित नहीं होंगे। हमें संभलना होगा। बिहार हो या बंगाल, देश के वरिष्ठ नेताओं को संकीर्ण राजनीति से बचना होगा। संकीर्ण राजनीति से बचकर ही हम समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। मिसाल के लिए, मणिपुर में कुकी-जो समूहों के साथ जो ताजा समझौता हुआ है, वह मणिपुर को एक जरूरी राहत की ओर ले जाता है। जब हम शांति से बैठकर बात करेंगे, तब समाधान निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम छोटे मामलों में भी राजनीति को हावी होने देंगे, तो यकीन मानिए एक परेशान और अशांत समाज बनाएंगे। अब राजनीति हो, तो विकास की हो, विद्वेष की नहीं।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 04 सितम्बर, 1950

भयंकर युद्ध

कोरिया में इस समय कैसा भयंकर युद्ध हो रहा है, उसके बारे में दो विशेष संवाददाताओं ने मोर्चे से आंखो देखा वर्णन किया है। मसान से लायोनेल क्रेन ने सामुद्रिक तार में लिखा है कि साम्यवादियों ने 13वीं अमरीकी सेना पर सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों से हमला बोल दिया। नाकटोंग क्षेत्र से जान शा ने तार भेजा है कि 50 मील के मोर्चे पर उत्तर कोरियाई सेना ने तीन डिवीजन झोंक दिये।

लायोनेल क्रेन ने मसान से युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया हैः सुबह जीप और फिर तीन घंटे तक विमान द्वारा यात्रा करने के बाद मुझे लड़ाई का विस्तृत चित्र ज्ञात हो गया। भूमि पर मैं तेरहवीं रेजीमेंट के कमांडर कर्नल हेनरी फिशर से मिला। वह अपनी कमान की चौकी में दीवार के सहारे आधे सोये से पड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने कहाः 'उन्हें जो कुछ मिला उससे उन्होंने हम पर हमला बोल दिया। हमारे कुछ अग्रिम दस्तों के पीछे लाल सेना की चार कम्पनियां हैं और उनके साथ तोपें तथा टैंक भी हैं। लेकिन वे अधिक से अधिक कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह हमने देख लिया है। हम यहां डटे रहेंगे-वे हमें यहां से नहीं खदेड़ सकते।' मोर्चे के मध्य तक सारे रास्ते में हमने तोपों को ले जाते हुए काफिले देखे और आसपास की पहाड़ियों से मशीनगनें आग उगल रही थीं। शाम को जब हमने आकाश से युद्ध की स्थिति का निरीक्षण किया, तो हमें मालूम हुआ कि हवाई कार्रवाई भी आश्चर्यजनक है। पूरे तीन घंटों तक हम विमानों से घिरे रहे।

लड़ाकू तथा बमवर्षक विमान निरन्तर शत्रु के ठिकानों पर बमवर्षा कर रहे थे। जब हम हमान शहर के ऊपर से उड़े, जहां कि भीपण युद्ध हुआ है, तो जेट विमान तीन मील पश्चिम में दूसरे शहर पर बम गिराने के लिये उड़े। उन्होंने गोला-बारूद के जखीरों पर सीधे प्रहार किये। उनकी बमबारी के दो घंटे बाद भी जखीरे में विस्फोट होता रहा और आग की लपटें ऊंची उठती रहीं। कारसेयर बमवर्षकों ने हमान के पश्चिम में निचली पहाड़ियों पर भारी बम गिराये, जहां कि शत्रु-सेनाएं नगर पर और आक्रमण के लिये रुकी हुई थीं। हमारे विमान चालक ने लड़ाकू विमानों को फौजों के एक और जमाव पर हमला करने या रेल के किनारे पड़ी हुई शत्रु की रसद को तहस-नहस करने को कहा।

जनता को राहत देगा जीएसटी सुधार

गौरव वल्लभ | अर्थशास्त्री व भाजपा नेता

यहां स्कैन करें

जीएसटी में किए गए हालिया सुधारों के बाद हर परिवार के पास ज्यादा खर्च करने लायक आमदनी बचेगी और लोग अन्य वस्तुओं व सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे।

जीएसटी सुधार की नई पहल देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक प्रभावशाली बदलाव है। इसमें दर-संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित करके उसे दो श्रेणी में बांटा गया है और दर कम रखे गए हैं, जिससे घरेलू मांग बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, अमेरिकी टैरिफ के दुष्प्रभाव को कुंद करने और तमाम क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, इससे चालू वित्त वर्ष में खपत में 1.98 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे परिवार, बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए यह सुधार 'गेमचेंजर' साबित होगा।

बीते 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने न सिर्फ चार दरों के जटिल कर-ढांचे की इस व्यवस्था को दो सरल दरों (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) में श्रेणीबद्ध किया, बल्कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी की दर को मंजूरी दे दी। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और बुनियादी जरूरी संसाधनों को अब निचली दो कर श्रेणी में रखा किया गया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। ये तमाम बदलाव आगामी 22 सितंबर से त्योहारों के मौसम के साथ लागू होंगे।

नई दरों के मुताबिक, बाल में लगाए जाने वाले तेल, साबुन, मक्खन, घी, नमकीन, चॉकलेट, कॉफी जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर अब सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले की दरों (12 से 18 फीसदी) से काफी कम है। अब न सिर्फ जीवन रक्षक दवाओं (33 प्रमुख दवाओं) को कर से बाहर कर दिया गया है, बल्कि दूध, पनीर, खाखरा (चपाती) जैसे खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि हर परिवार के पास ज्यादा खर्च करने लायक आमदनी बचेगी और वे अन्य वस्तुओं व सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। सीमेंट (इसमें जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है) और गाड़ियों के कल-पुर्जे जैसे क्षेत्रों में लागत अब घटेगी, जिससे निर्माण, गाड़ियों की मांग और लघु व मध्यम उद्योगों के कामकाज में इजाफा होगा।

इन सुधारों से जुड़े प्रमुख अनुमानों के मुताबिक, 0.7 की एमपीसी (उपभोग-प्रवृत्ति) के साथ, प्रत्यक्ष उपभोग में प्रारंभिक वृद्धि 70,000 करोड़ रुपये की होगी, जबकि इससे 85,000 करोड़ रुपये का राजस्व-नुकसान होगा। जैसे-जैसे नए खर्च अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे, मांग में 1.98 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकेगी। आयकर के हालिया बदलावों को भी यदि इसमें जोड़ दें, तो करीब 5.31 लाख करोड़ रुपये की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का करीब 1.6 प्रतिशत हिस्सा होगा। इन दो सुधारों के बाद जीडीपी में 100 से 120 आधार अंकों में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में सात प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

एफएमसीजी, ऑटो, सीमेंट, रिटेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे तमाम क्षेत्रों में अब तेजी आएगी। सरल अनुपालन, इनपुट क्रेडिट में सुधार और कम कागजी कार्रवाइयों से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के विस्तार में मदद मिलेगी, नकदी प्रवाह में सुधार होगा और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। जीएसटी 2.0 सुधारों से कर अनुपालन आसान होगा और कर गणना व उसकी फाइलिंग की जटिलताएं कम होंगी। इससे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। इस कटौती से दिन-प्रतिदिन के कामों के लिए जरूरी पूंजी का बोझ कम होगा और 'प्रोविजनल रिफंड' व स्वतः पंजीकरण जैसी सुविधाओं के कारण तरलता बढ़ेगी, जिससे जल्द पैसे पाए जा सकेंगे। दरों में कटौती के अलावा, इन सुधारों द्वारा स्वतः ऑनलाइन पंजीकरण, त्वरित रिफंड और उल्टे शुल्क ढांचे (आउटपुट की तुलना में इनपुट पर अधिक कर) से जुड़े मसलों के समाधान जैसे ढांचागत सुधार किए गए हैं, जिससे कपड़ा, उर्वरक और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा।

इन बदलावों से वर्गीकरण संबंधी विवादों का भी निपटारा होगा और आत्मनिर्भर भारत के नजरिये के अनुरूप एक अधिक प्रतिस्पर्द्धी, बेहतर व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकेगा, जिससे अंततः व्यापार में सुगमता बढ़ेगी, उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी और त्योहारी व सालाना खरीदारी में भी इजाफा होगा। इन तमाम उपायों से नकदी के प्रवाह में सुधार होगा, अनुपालन संबंधी चुनौतियां कम होंगी और जीएसटी के तहत आर्थिक विकास व व्यावसायिक क्षमता के लिए अधिक अनुकूल माहौल बन सकेगा।

यह जीएसटी सुधार रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी राहत लेकर आया है। बर्तन, दूध की बोतलें, दुग्ध उत्पाद, सिलाई मशीन व उसके पुर्जों जैसी जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है, जिससे परिवारों को किराने के मासिक खर्च में 10 से 15 प्रतिशत की बचत हो सकेगी। मुख्य भोजन और पदार्थ जैसे दूध व पनीर पर अब जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे पोषण सुरक्षा में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ मिला है और 33 से अधिक जीवनरक्षक दवाएं अब जीएसटी-मुक्त कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी, थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर पर कर घटाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा सुलभ व सस्ती हो जाएगी। कॉपी, पेंसिल, रबड़ और क्रेयॉन पर जीएसटी छूट से शिक्षा क्षेत्र को राहत मिली है और इससे छात्रों व परिवारों का खर्च कम हो सकेगा।

कृषि उपकरणों व मशीनरी पर दरों में कमी (12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी) करके किसानों को भी लाभ दिया गया है, जिससे ग्रामीण आय बढ़ सकेगी। छोटी कारों (1200 सीसी पेट्रोल व 1500 सीसी डीजल गाड़ियों तक) और मोटरसाइकिलों (350 सीसी तक) पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ सकेगी। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी लाभ मिला है, क्योंकि एसी, टीवी और रेफ्रिजरेटर पर अब 28 के बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

जाहिर है, 'जीएसटी 2.0' देश में सरल, अधिक न्यायसंगत और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कर-दरों को न्यायसंगत बनाकर और व्यापक ढांचागत व प्रक्रिया संबंधी सुधारों के जरिये घरेलू क्रय शक्ति बढ़ाकर जीएसटी 2.0 अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा और मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में जीवन को सुगम बनाने व सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा विकसित भारत का सपना

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

यहां स्कैन करें

जब 1962 में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने खुद यह सुझाव दिया कि उनका जन्मदिन देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हर साल 5 सितंबर को देश के लाखों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मगर यह भी सोचिए कि क्या हम डॉ राधाकृष्णन की कल्पना के अनुरूप शिक्षकों और उनके पेशे को वह सम्मान दे पाए हैं, जो उन्हें दिया जाना चाहिए था?

जब भी हम अपने किसी पुराने शिक्षक से मिलते हैं, तो क्या उनसे मिलकर वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा कि किसी नेता, उद्योगपति, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर या किसी साधु-संत से मिलने पर अनुभव करते हैं? क्या आज शिक्षक के पेशे के प्रति नौजवान उतने ही आकर्षित होते हैं, जितना आईएएस, आईपीएस, सीए, एमबीए की नौकरियों से होते हैं? अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में पूरे देश के सभी स्कूली शिक्षकों की पदोन्नति और नई भर्तियों के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ साल 2009 से पहले भर्ती किए गए और अगले पांच वर्षों में रिटायर होने वाले शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह जाहिर है कि शिक्षकों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है।

एआई युग में शिक्षकों का काम विद्यार्थियों को एक कोच, मेंटर या पथ-प्रदर्शक मित्र के रूप में भविष्य का रास्ता दिखाने का होगा।

पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे युगांतरकारी परिवर्तन आए हैं कि विश्व स्तर पर उद्योगों, व्यवसायों, बाजारों, समाज, शिक्षा, मीडिया व राजनीति में सब कुछ उलट-पलट रहा है। यह 'सब कुछ' इतनी तेजी से घटित हो रहा है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम जॉर्ज ओरवेल के *1984* जैसा कोई वैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहे हैं या हॉलीवुड की *एवेंजर* जैसी कोई फिल्म देख रहे हैं। सूचना-क्रांति ने दुनिया को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी, अब एआई-क्रांति ऐसे परिवर्तनों को ला रही है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।

दरअसल, आज विश्व स्तर पर पांचवीं औद्योगिक क्रांति के अनुरूप 'शिक्षा 5.0' की बहुत चर्चा हो रही है, जिसे मोटे तौर पर पांचवीं शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। यह सत्य है कि 2035 तक पहुंचते-पहुंचते दुनिया में शिक्षकों का पेशा खत्म नहीं होने जा रहा, किंतु एक बात तय है कि उनकी महत्ता व भूमिका में बड़े बदलाव आएंगे। शिक्षक का काम अब सिर्फ व्याख्यान देकर ज्ञान बांटना न होकर, विद्यार्थियों को एक कोच, मेंटर या पथ-प्रदर्शक मित्र के रूप में भविष्य का रास्ता दिखाने का होगा।

वैसे, शिक्षकों के बारे में समाज की धारणा आजादी के बाद के वर्षों में कैसे बदल गई, यह हमारे साहित्य और फिल्मों के शिक्षक पात्रों के चरित्र-चित्रण में देखा जा सकता है। प्रेमचंद, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर जैसे 20वीं सदी के लेखकों ने अपनी रचनाओं में शिक्षकों को बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया था। पिछले दशकों की फिल्मों में शिक्षकों को एक हास्यास्पद चरित्र के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इनमें शिक्षक की भूमिका हास्य पैदा करने के लिए हैं, क्योंकि वे सनकी, जिद्दी और तानाशाह के रूप में कहानी में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थी वर्ग की मानसिकता से बिल्कुल कटे हुए हैं।

देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की तादाद अभी 4.5 करोड़ बताई जाती है। इनको पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधनों की लगातार कमी देखी गई है। कल्पना करिए, वर्ष 2035 तक जब उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आठ करोड़ हो जाएगी, तब कैसा परिदृश्य होगा? मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, देश में करीब 16 लाख शिक्षक कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। वहीं एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार, राज्यों के विश्वविद्यालयों में करीब 40 फीसदी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20 प्रतिशत शिक्षकों की जगहें खाली हैं।

भारतीय समाज और सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों को भी आत्मालोचना करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कहा गया है कि शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, इसलिए वे राष्ट्र-निर्माता हैं। उन्हें उच्चस्तरीय सम्मान और जीवन-स्तर दिया जाना चाहिए, जिससे सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं को शिक्षक बनने को प्रेरित किया जा सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

भगवान लीला क्यों करते हैं

भूलिए नहीं, सद्कर्म के लिए जीवन मिला है। मोक्ष के लिए जीवन मिला है। व्यास जी ने कहा है कि हमें मोक्ष देने के लिए ही अव्यक्त ईश्वर व्यक्त हो गया। जैसे सरसों में अव्यक्त था तेल, लेकिन तेल के रूप में व्यक्त हो गया। मिट्टी में घड़ा अव्यक्त था, चाक पर चढ़ा, तो व्यक्त हो गया। हमें मोक्ष देने के लिए ही व्यक्त या अवतरित हो गए ईश्वर। व्यास जी ने कहा है-

नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः॥

शुकदेव जी कह रहे हैं कि मोक्ष देने के लिए ईश्वर प्रकट होता है। पूछा गया कि फिर करता क्या है ईश्वर व्यक्त, प्रगट या अवतरित होने के बाद? भगवान हमारे मोक्ष के लिए करते क्या हैं? उत्तर मिला, लीला करते हैं। बहुत से लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। रंग भी उनका लाल होगा, गाड़ी भी बड़ी होगी, पर उनके मुख से सरस, मांगलिक और हृदयस्पर्शी एक शब्द नहीं निकल पाएगा।

भगवान क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। पूछा गया कि लीला करने से क्या होगा? उत्तर मिला, उसे सुनेंगे कल्याणकामी लोग, तो तत्पर हो जाएंगे। तत्पर का अर्थ सजग होना होता है। तत्परता का अर्थ केवल ध्यान देना नहीं है, तत्परता का अर्थ है- ईश्वर के लिए समर्पित हो जाना। *श्रीमद्भागवत* में लिखा है-

अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमस्थितः।
भजते तादृशीः क्रीड़ा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्॥

जब भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं, तो वह ऐसी लीलाएं करते हैं, जिनको सुनने वाले उनकी ओर आकर्षित होकर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं।

मायके में कन्या अलग तरह की मर्यादा में रहती है, किंतु जब वह ससुराल में आ गई, तो उसकी मर्यादाएं अलग हो जाती हैं। वह ससुराल में मायके की तरह रहेगी, तो उसका सुखी जीवन नष्ट होने लगेगा। अतः तत्परता जरूरी है। जहां पर हम अभी हैं, वहीं पर सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा समर्पण होना चाहिए। भगवान यही संदेश देने के लिए इहलौकिक संसार में अवतार लेते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि रामजी लीला पुरुषोत्तम हैं, प्रेमी नहीं हैं। कृष्ण भक्ति करने वाले अनेक लोगों को मालूम नहीं है कि मर्यादा में भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। कोई जरूरी नहीं है कि गोपियों के साथ भगवान ने जो लीला की, केवल वही प्रेम का प्रदर्शन है। मर्यादित व्यक्ति भी प्रेमी हो सकता है।

हमें मोक्ष देने के लिए ईश्वर प्रकट होते हैं। पूछा गया कि फिर करते क्या हैं ईश्वर व्यक्त, प्रगट या अवतरित होने के बाद? भगवान हमारे मोक्ष के लिए क्या करते हैं? उत्तर मिला, लीला करते हैं।

लीला की परिभाषा जो सनातन धर्म में बताई जाती है, शास्त्रों में बताई जाती है, उस कर्म को लीला कहते हैं, जिस कर्म में कर्म करने वाले को कर्तृत्व का अभिमान न हो। ऐसे ही कर्म का नाम लीला है, लीला करने वाले को किसी फल की आकांक्षा नहीं होती है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

पोप लियो XIV | ईसाई धर्मगुरु

बिना संकोच मांगने और बिना निहित स्वार्थ के देने की कला में जो आनंद है, वह सबसे अनूठा है। यह आनंद हमें अपने जीवन के परम सत्य में स्थापित करता है। दरअसल, हम प्रेम बांटने और प्रेम पाने के लिए ही बने हैं।

एक शिल्पकार की भूमिका निभा रहे शिक्षक

भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महज औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के दाता, मानवता के सच्चे पथ-प्रदर्शक शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन का चयन भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और अद्वितीय शिक्षक डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर किया गया। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा का सर्वोच्च माध्यम माना। उनकी सोच थी कि यदि शिक्षक को सम्मान मिलेगा, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और समाज में नैतिक मूल्यों की नींव मजबूत होगी। यही कारण है कि इस दिन देश भर में विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है, जो अच्छे-बुरे में अंतर करना सिखाता है।

कहा जाता है कि आज शिक्षकों की गुणवत्ता में ह्रास हो गया है। उनके आचरण के आधार पर भी उनको घेरने का प्रयास किया जाता है। निस्संदेह, सभी पीली वस्तुएं सोना नहीं होतीं, लेकिन एकाध अपवाद के आधार पर पूरे शिक्षक समाज को कठघरे में भी नहीं खड़ा किया जा सकता। सच यही है कि आज भी तमाम शिक्षक दिन-रात मेहनत करते हैं, ताकि अपने विद्यार्थियों में जीवन-मूल्यों का बीजारोपण कर सकें, उन्हें एक बेहतर इंसान बना सकें और समाज के लिए एक उत्पादक के तौर पर पेश कर सकें। आज भी ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं, जो इस सोच के साथ जीते हैं कि शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम की सीमाओं में बंधा नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पहलुओं को समझाने का माध्यम होता है। यही कारण है कि वे अपने आचरण से भी विद्यार्थियों के सामने उदाहरण पेश करते हैं।

साफ है, शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह वह शक्ति है, जो आने वाले कल की नींव तैयार करती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को केवल अंकों की दौड़ में धकेल देगा, तो आने वाला समाज प्रतिस्पर्द्धा में उलझा हुआ और तनावग्रस्त रहेगा। यही कारण है कि शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों में मूल्यों, सहयोग और रचनात्मकता का भाव जगाएं, ताकि हम एक प्रगतिशील, संवेदनशील और नवाचार उन्मुख समाज गढ़ सकें। सुखद है कि शिक्षक इस दिशा में सक्रिय हैं। उनकी सोच और कोशिशों पर ही विकसित भारत का सपना टिका है। यही कारण है कि उनको समाज का ऐसा दीपक कहा जाता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं।

ममता कुशवाहा, शिक्षक

अनुलोम-विलोम
शिक्षक दिवस

शिक्षकों में गुणवत्ता की कमी बड़ी चुनौती

एक मशहूर कहावत है, शिक्षा देना ही एकमात्र ऐसा काम है, जो बाकी सभी तरह के पेशों को जन्म देता है। शिक्षक के बिना किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मगर आज हालात प्रतिकूल जान पड़ते हैं। एक वक्त था, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यानी शिक्षा की जो किरण भारत से निकलती थी, वह पूरी दुनिया को रोशन करती थी। पांचवीं सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए सिद्धार्थ ने अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान की तलाश शुरू की और बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। चाणक्य एक ऐसे शिक्षक थे, जिन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के मायने बदल दिए। उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और विचार को व्यवहार में बदलने की शिक्षा दी। तीसरी सदी में विष्णु शर्मा ने 'पंचतंत्र' की रचना की और शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया। 14वीं सदी में पैदा हुए कबीर भी एक ऐसे ही शिक्षक थे, जिन्होंने सरल दोहों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर कटाक्ष किया और लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी। ये वे गुरु हैं, जिन्होंने भारत वर्ष का निर्माण किया। मगर आज ऐसे शिक्षकों का अभाव दिखता है।

ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के मुताबिक, शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में चीन सबसे आगे है। चीन में 75 प्रतिशत छात्र अपने शिक्षकों की इज्जत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। चीन में अध्यापक की नौकरी को डॉक्टर की नौकरी जैसा दर्जा हासिल है। चीन, तुर्किये, दक्षिण कोरिया और मिस्र में सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर शिक्षक बनें। इस सर्वे में भारत को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए हमें लगता है कि भारत में शिक्षकों को वह सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके वे हकदार हैं। यह उस देश की दशा है, जहां गुरु-शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई है, और जहां एकलव्य जैसे छात्र ने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया था।

आज जब शिक्षकों को गढ़ने के पाठ्यक्रम पर विमर्श चलता है, तो किसी भी संस्थान के लिए ऐसे शिक्षक तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है, जो अपने विधार्थियों को निर्भीक और बेहतर इंसान बनने, सत्य के पक्ष में खड़े होने और समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान अर्जित करने को प्रेरित करें। जिस समाज में शिक्षक सच्चे अर्थों में समाज के पथ प्रदर्शक होंगे, वहीं सम्मानित होंगे, छात्र उन्हें ही याद करेंगे। मगर इसके लिए शिक्षकों को अपने अंतस में झांकना होगा।

जयप्रकाश नवीन, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शिक्षक राष्ट्र को आकार देने वाले शिल्पकार होते हैं

उपहार जैसा सुधार

अंततः वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की प्रतीक्षा पूरी हुई। यह एक बड़ा सुधार है और चूंकि इसका लाभ आम लोगों के साथ कारोबार जगत को भी मिलेगा, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और वह भी ऐसे समय जब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति की चुनौतियों से दो-चार होना पड़ रहा है। आठ वर्ष बाद जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने के फैसले के साथ ही यह देखा जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ मिले। उन आशंकाओं का निवारण किया जाना चाहिए, जिनके तहत यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कुछ उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में वास्तव में कमी आएगी या नहीं? इन आशंकाओं का निवारण करके ही 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार को देश को दीवाली के उपहार की संज्ञा दी जा सकेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सुधार के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन की जटिलताएं सचमुच खत्म हों और छोटे कारोबारियों को बेवजह की कागजी कार्यवाही पूरी न करनी पड़े। जीएसटी में बड़े सुधार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है, वह इसलिए औचित्यहीन और व्यर्थ है, क्योंकि जीएसटी परिषद ने आम सहमति से यह फैसला लिया कि अब इस टैक्स की दो ही श्रेणियां-5 और 18 प्रतिशत होंगी। यह ठीक है कि आम सहमति से लिए गए इस फैसले को लेकर कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है, लेकिन एक तो यह नुकसान बहुत अधिक नहीं और दूसरे, वह तात्कालिक रूप से ही होगा। जीएसटी की दो श्रेणियां किया जाना समय की मांग थी। ऐसा करने से केवल रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं सस्ती ही नहीं होंगी, बल्कि उनकी खपत भी बढ़ेगी। इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी के उन अन्य आर्थिक सुधारों को भी गति देनी होगी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के मामले में भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत को विकसित देश बनने के लिए तेजी से प्रगति करना आवश्यक है। इसके लिए केवल सभी अपेक्षित सुधार ही नहीं किए जाएं, बल्कि उन पर अमल की ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि आर्थिक सुधारों के मामले में दलगत हितों की संकीर्ण राजनीति को तिलांजलि दी जाए। यह अपेक्षा सबसे अधिक कांग्रेस से है, क्योंकि उसने हर मामले में सस्ती राजनीति करना अपना एजेंडा बना लिया है।

कठोरतम सजा मिले

यह वाकई चिंताजनक है कि राजधानी पटना में नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है। गंभीर बीमारियों के उपचार से संबंधित कई दवाएं भी जांच में मानक के अनुरुप नहीं मिली हैं। इस संबंध में दोषी पाए गए दवा दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं तथा कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी की गई है। चिंता की बात है कि नकली रैपर लगाकर नामी ब्रांड की दवाओं को बाजार में बेचा जा रहा। ये दवाएं उत्तराखंड से मंगाने की बात सामने आई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। शासन के स्तर से कार्रवाई भी की जाती रही है, फिर भी यह क्रम बदस्तूर जारी है। अच्छी बात है कि औषधि नियंत्रण विभाग समय-समय पर छापेमारी करता है तथा जब्त दवाओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है। किंतु, शायद यह नाकाफी है। जरूरत है, पूरे रैकेट को ध्वस्त करने की तथा दोषी धंधेबाजों के लिए ऐसी सजा के प्रविधान की, जिससे किसी भी हाल में वे दोबारा दवा का कारोबार नहीं कर सकें। विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए भी कड़ी नीति आवश्यक है। यह भी देखा जाना चाहिए कि पूर्व में दोषी पाए गए लोगों को क्या सजा मिली। वे फिर कहीं नकली दवाओं की खरीद-बिक्री तो नहीं कर रहे। पुलिस-प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राजव्यापी अभियान के तहत कठोरतम कार्रवाई के प्रयास किए जाने चाहिए।

आमजन को दवा खरीदते वक्त काफी सजग रहने की जरूरत है। उन्हें लेबल और बिल की जांच अवश्य करनी चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राज्यपालों-राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए किसी समय सीमा में बांधा जाना चाहिए?

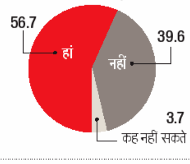

आज का सवाल
क्या जीएसटी सुधार से टैरिफ की चुनौती का भी सामना करना आसान होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

समय के अनुरूप सुधार

आदित्य सिन्हा

2017 में शुरुआत के साथ जीएसटी ने जहां देश के बाजार को एकीकृत किया, वहीं 2025 के सुधार से यह विकास को गति देने वाली परिपक्व प्रणाली बनेगी

सुधारों को अक्सर इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो इनसे हर किसी को लाभ पहुंचता है। वास्तविकता में सुधारों के भी दो पहलू होते हैं। इसमें भी किसी को लाभ होता और किसी को नहीं। सुधार इतना जरूर करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और लोगों पर बोझ की दिशा बदल देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधारों के नाम पर की जाने वाली पहल अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, अधिक टिकाऊ विकास पथ पर ले जाती है। हाल में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर किए गए सुधार इसी गतिशीलता को दर्शाते हैं। इसके जरिये कर संरचना को सरल बनाकर, लोगों पर बोझ घटाकर, उत्पादकों के लिए विसंगतियों को दुरुस्त कर और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर परिषद ने जीएसटी को भ्रम और अनुपालन की जटिलता के जाले से बाहर निकालकर विकासोन्मुख ढांचे की ओर नए सिरे से उन्मुख किया है। इन सुधारों का सशक्त पहलू यह है कि इसमें मध्यमवर्गीय उपभोक्ता विजेता के रूप में उभरता दिखता है।

सबसे स्पष्ट परिवर्तन चार स्तरों वाले जीएसटी ढांचे से एक सरल और नागरिक हितैषी प्रणाली की ओर बढ़ना है, जिसमें केवल दो मुख्य स्लैब हैं। मेरिट वस्तुओं के लिए पांच प्रतिशत और मानक स्लैब के रूप में 18 प्रतिशत। जबकि 40 प्रतिशत की विशेष स्लैब केवल विलासिता और हानिकारक वस्तुओं जैसे कि सट्टेबाजी और कैसिनो, बड़े वाहनों और कुछ गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों के लिए नियत की गई है। पुराने सिस्टम के तहत शब्दों में छोटा सा अंतर बड़ी विसंगति की वजह बनता रहा है। जैसे क्या पराठा रोटी के समान था? पनीर को छूट और चीज पर टैक्स? ये अस्पष्टताएं वर्गीकरण विवाद, मुकदमेबाजी और प्रशासनिक बैकलाग की स्थिति को निर्मित करती रहीं। इसके चलते तमाम छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन के मोर्चे पर अधिक समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करने पड़ते। स्वाभाविक रूप से इसका उत्पादन पर असर पड़ता। अब चार स्लैब वाली व्यवस्था को दो श्रेणियों में सिमेटकर परिषद ने विवादों की गुंजाइश को घटाते हुए कर प्रणाली में अनिश्चितताओं को दूर करते हुए उसे अधिक पूर्वानुमानित बना दिया है।

इस सुधार से लोगों को सीधी राहत भी मिलने वाली है। दूध, पनीर और ब्रेड अब जीएसटी से मुक्त हो गए हैं। जबकि साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल और रोजमर्रा उपभोग में आने वाली कई वस्तुएं जो पहले 12 या 18 प्रतिशत की श्रेणी में आती थीं, उन पर दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे घरेलू बजट का संतुलन और बेहतर होगा।

अवधेश राजपूत

एसी, टीवी, बाइक से लेकर छोटी कारों समेत कई वस्तुओं पर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना भी लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध होगा।

जीएसटी सुधार के पीछे मंशा एकदम स्पष्ट है कि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा रहे, जो खर्च होकर आर्थिकी को गति प्रदान करे। जहां निजी उपभोग की जीडीपी में करीब 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, वहां यह पहल मांग को तात्कालिक रूप से बढ़ाने का काम करेगी। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी इस सुधार से घटेगा। पहली बार जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को कर मुक्त कर दिया गया है। कई जीवनरक्षक दवाएं भी कर मुक्त हो गई हैं, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े उपकरणों पर भी टैक्स घटा दिया गया है। यहां मुद्दा केवल कल्याण का नहीं, बल्कि विकास का भी है। किफायती स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक बीमा कवरेज लोगों को चिकित्सा खर्च के झटकों से बचाने का काम करते हैं। इससे अन्य खर्चों के लिए संसाधन बचेंगे। साथ ही, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित कार्यबल बनाकर उत्पादकता में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जरिये भी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यह स्थिति तब बनती है जब इनपुट पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक कर लगता है। यह उद्यमों के लिए अनुपयोगी क्रेडिट जमा करने, तरलता पर दबाव डालने और प्रतिस्पर्धा गंवाने का कारण बनता है। कपड़ा क्षेत्र इस समस्या से बहुत प्रभावित था, जहां मानव निर्मित फाइबर पर 18 प्रतिशत, यार्न पर 12 प्रतिशत और तैयार कपड़े पर पांच प्रतिशत कर था। उर्वरकों को भी ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कच्चे माल पर 18 प्रतिशत, लेकिन अंतिम उत्पादों पर पांच प्रतिशत कर लागू था। अब इन विसंगतियों को सुधारा गया है। ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर कर की दर को 12 से पांच प्रतिशत तक कम किया गया है, जिससे किसानों के लिए लागत घटेगी। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पांच प्रतिशत कर लगने से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदमों को और मजबूती मिलेगी।

एक महत्वपूर्ण सुधार संस्थागत स्तर पर भी है। जीएसटी प्रणाली की लंबे समय तक इसलिए आलोचना की गई कि उसमें राष्ट्रीय स्तर के उचित अपीलीय तंत्र का अभाव है। उद्यमों को अक्सर राज्यों के बीच असंगत निर्णयों का सामना करना पड़ा, जिसने अनिश्चितता को बढ़ाया। इस कड़ी में 2025 के अंत तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटैट को अमल में लाने का निर्णय महत्वपूर्ण है। न्यायाधिकरण सितंबर से अपीलें स्वीकार करेगा और दिसंबर तक सुनवाई शुरू करेगा। जबकि बैकलाग यानी लंबित अपीलों के लिए जून 2026 की समयसीमा होगी। प्रिंसिपल बेंच भी अग्रिम निर्णयों के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी, जिससे न्यायालयों के बीच स्थिरता बनेगी। यह संस्थागत सुधार विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वानुमानित विवाद समाधान निवेश जोखिम घटाता है। कंपनियां अधिक निवेश और विस्तार करने के लिए तभी तैयार होती हैं, जब उन्हें पता होता है कि असहमतियों एवं विसंगतियों का तत्परता के साथ निरंतर समाधान संभव होगा।

जीएसटी को तार्किक बनाना समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इसकी जटिलताएं विवादों को बढ़ाकर विकृतियों को जन्म दे रही थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी। इसके समग्र परिणाम उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढ़ा रहे थे। वास्तव में 2017 में अपनी शुरुआत के साथ जीएसटी ने जहां पूरे देश के बाजार को एकीकृत करने का काम किया तो 2025 का सुधार इसे विकास की गति बढ़ाने वाली परिपक्व प्रणाली के रूप में स्थापित करता है।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

शिक्षकों की साख संभाली जाए

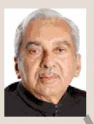

जगमोहन सिंह राजपूत

समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्वीकार्यता अध्यापकों के अनुकरणीय आचरण से ही आएगी

आज देश शिक्षक दिवस मना रहा है। प्राचीन भारतीय परंपरा में गुरु समाज में ही नहीं, सत्ता द्वारा भी सम्मानित किया जाता था। गुरुकुल के अधिष्ठाता से मिलने जब राजा-महाराजा भी जाते थे, तो वे परिसर के बाहर ही अपना सारा ताम-झाम और सुरक्षा छोड़ देते थे, अंदर जाकर आचार्य की चरणधूलि लेकर अपने को धन्य समझते थे, लेकिन आज स्थिति अलग है? एक बार मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था, तो मेरे बगल में एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोफेसर साहब, कोई ऐसा उपाय बताइए, जिसमें शैक्षिक सुधार लोगों को दिखाई देने लगे, मगर अधिक धन लगाने की आवश्यकता न पड़े। बिना किसी देरी के मैंने कहा कि ऐसा उपाय है। अगर आप इसे लागू कर सकें तो छात्रों का नामांकन बढ़ जाएगा, अध्यापकों की स्कूल उपस्थिति में भारी सुधार होगा, कर्मठता बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की साख भी लौटने लगेगी। आपको केवल एक आदेश जारी करना होगा कि कोई भी अध्यापक-प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जब किसी अधिकारी से मिलने जाए, तो वह कुर्सी से उठकर उसका स्वागत करे, कुर्सी पर बैठाए, उसके बाद अपना आसन ग्रहण करे। उसके अनुरोध को प्राथमिकता से सुने और निपटाए, अधिकारी उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए और उसके मातहत कर्मचारी इसे देखें। मुख्यमंत्री बोले कि यह लगता तो सरल है, किंतु इसके त्वरित प्रभाव व्यवस्था यानी नौकरशाही पर ठीक नहीं पड़ेंगे। उन्होंने इसे प्रभावशाली कदम बताया, मगर लागू करने का साहस नहीं किया।

यह सही है कि सरकारी स्कूल बड़ी संख्या में अध्यापकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे अत्यंत निंदनीय चलन के लिए अध्यापक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था ही जिम्मेदार हैं। यह 'चलन' केवल अध्यापकों तक ही फैली नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित अनेक सरकारी अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी से 'मोलभाव' कर लेते हैं। हफ्ते में एक-दो दिन अपने कार्यस्थल पर जाकर सारे सप्ताह की उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। इस सबका समाधान क्या है? इसे ढूंढ़ने के पहले यह जानना होगा कि ऐसी अवस्था पनपी कैसे? यह अनैतिक स्थिति मुख्य रूप से शिक्षकों के प्रति समाज की बेरुखी और व्यवस्था के अपमानजनक व्यवहार से ही उपजी है। समाज की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की साख में भारी गिरावट की स्थिति के प्रति उदासीनता ने इसे अत्यंत अशोभनीय स्तर तक गिरा दिया है। 2012 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि देश के दस हजार शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 'डिग्री बेच रहे हैं।' उनकी गुणवत्ता में कोई रुचि है ही नहीं। आठ साल बाद इस कथन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में पुनः दोहराया गया। यह कितनी शर्मनाक स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार एक अन्य पक्ष को भी ठीक से समझने की आवश्यकता है।

छात्रों के प्रति दायित्वों का निर्वहन करें शिक्षक ● फाइल

राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों में 1955-60 के दौरान यदि किसी स्कूल का दरवाजा टूट जाता था, तो ग्रामीण उसे अपना स्कूल मानते हुए नया लगा देते थे। अब इतना सरकारीकरण हो चुका है कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है, तो लोग कहते हैं कि स्कूल की खिड़की उखाड़कर जलाएं, सरकार खुद लगाएगी। दरअसल समाज का स्कूल से जो परंपरागत संबंध था, अध्यापक का जो सम्मान था, उसके तिरोहित होने में सरकारी अधिकारियों की असंवेदनशीलता और अहंकार मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे हैं। देश के 56 प्रतिशत बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय जैसे केंद्र संचालित स्कूलों की साख पूरे देश में है, लेकिन सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ा प्रतिशत उन बच्चों का है, जिनके पालकों ने उन्हें यहां प्रवेश केवल इसलिए दिलाया है, क्योंकि वे किसी निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिला सके। सरकारी स्कूलों की साख के लगातार गिरने का एक कारण यह है कि व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक जिन-जिन पर इसका उत्तरदायित्व है, उनके अपने बच्चे भी निजी स्कूलों में ही पढ़ते हैं।

अध्यापकों का सम्मान उनके अपने प्रयासों का योगदान भी मांगता है। क्या वे एक अनुकरणीय कार्यसंस्कृति का उदाहरण पेश कर रहे हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के पुनर्निर्माण में वहां के शिक्षकों की बड़ी भूमिका थी। समय-प्रतिबद्धता, कार्यसंस्कृति, आत्मसम्मान, उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता और व्यवस्था द्वारा हर पग पर उनको यह आभास दिलाया गया कि वे ही राष्ट्र निर्माता हैं, वे भविष्य के कर्णधार तैयार कर रहे हैं। उनसे व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण के जो तत्व बच्चे सीख कर जाएंगे, वे बड़ी-बड़ी शोधशालाओं, अस्पतालों, प्रशासनिक कार्यालयों में भी कुछ वर्ष बाद दिखाई देंगे। आज जापान में कोई भी अपने कार्यस्थल पर देर से नहीं पहुंचता है। भारत के अध्यापक यदि चाहें तो कुछ वर्षों के अंतराल में यहां भी यह स्थिति आ सकती है। राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निर्वाह अध्यापकों को ही करना है। समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्वीकार्यता भी अध्यापकों के अनुकरणीय आचरण से ही आएगी।

(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक सामंजस्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

चिंता

जीवन में समय-समय पर चिंता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चिंता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। प्रायः नकारात्मक प्रभावों पर अधिक चर्चा होती है। इस संदर्भ में चिंता को चिता समान कहा जाता है। यह सत्य है कि चिंता का अतिरेक व्यक्ति को आशंका, भय, घबराहट या अनिद्रा से ग्रस्त कर सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हो सकता है।

यह मान लेना उचित नहीं कि जीवन में चिंता होना बिल्कुल गलत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति में अपनी परिस्थितियों और उत्तरदायित्यों के अनुरूप सम्यक स्तर की चिंता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थी की अगले दिन परीक्षा है, तो उसे इसकी चिंता होनी चाहिए। अन्यथा वह परीक्षा की तैयारी में ध्यान नहीं दे पाएगा और उसका परीक्षा-फल प्रभावित हो सकता है। उपयुक्त स्तर की चिंता हमें अपने उद्देश्यों के प्रति प्रेरित करती है और सतर्क रखती है, जिससे हम त्रुटियों से बचते हैं।

इसलिए चिंता के दुष्प्रभावों से सावधान रहने के साथ ही हमें इसकी सकारात्मक भूमिकाओं के महत्व को भी समझना चाहिए। सामान्यतः जो चिंता होती है, उसके स्पष्ट कारण होते हैं और यह अस्थायी होती है। जब कारण समाप्त हो जाते हैं, तो चिंता भी समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कभी-कभी व्यक्ति में ऐसी चिंता देखी जाती है, जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होता और जो निरंतर बनी रहती है। ऐसी असामान्य चिंता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, जिसके लिए उचित उपचार आवश्यक होता है। इस प्रकार चिंता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें जिम्मेदार बनाती है और हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

डा. अरुण कुमार तिवारी

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अवैध मतांतरण घातक

'रोका जाए धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग' शीर्षक से लिखे आलेख में सीबीपी श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि यदि देश में धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं रोका गया, तो यह अवैध मतांतरण के मामलों में वृद्धि का कारण बनेगा, जो देश के लिए उचित नहीं है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर नागरिक को अपने पंथ को चुनने की स्वतंत्रता है। यदि अवैध मतांतरण को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में हालात फिर से भारत-पाकिस्तान के बंटवारे जैसे हो सकते हैं। अवैध मत परिवर्तन से किसी विशेष पंथ-मजहब की संख्या बढ़ने पर वे अलग देश की मांग कर सकते हैं। अवैध मतांतरण के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, अंधविश्वास और आस्था की कमी। देश की खुफिया एजेंसियों को इस मुद्दे पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देश विरोधी ताकतें मतांतरण के नाम पर देश के खिलाफ काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मतांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह अत्यंत गलत है कि कुछ पंथ विशेष के लोग भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश का गलत फायदा उठाकर अवैध मतांतरण करवा रहे हैं। यदि वे सच में गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो मत परिवर्तन की शर्त क्यों रखते हैं? जो लोग धन के लालच में मत परिवर्तन करते हैं, वे भौतिकतावाद को प्राथमिकता देते हैं। हिंदुओं में मत परिवर्तन का एक कारण जात-पात की समस्या भी हो सकती है। जब किसी को अपने पंथ में सम्मान नहीं मिलता, तो वह उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा होता कि लेखक उन उपायों का भी जिक्र करते, जिन्हें अपनाकर देश अवैध मतांतरण की समस्या से छुटकारा पा सके।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग

प्रकृति का रौद्र रूप बहुत ही खतरनाक है। पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। चारों ओर तबाही मंजर है। हाहाकार मचा हुआ है। प्रकृति संकेत देना चाह रही है कि अभी से भी चेत जाओ, नहीं तो आगे मंजर और भयावह होगा। जिस तरीके से मानव समाज प्रकृति के तत्वों व संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, वही काफी चिंताजनक है। वृक्ष एवं नदियों का कटाव, पौधारोपण नहीं करना, नदी-नालों में कचरा फेंकना एवं जमा करना दिनचर्या बन गई है। हम अपनी पुरानी पद्धति एवं संस्कृति से विमुख हो गए हैं। हमारे पूर्वज जल, जंगल, ज़मीन की पूजा करते थे, आज सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का कर रहे हैं। जल के दुरुपयोग में हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता समाप्त हो रही है। टेक्नोलाजी के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति को जोड़ने की आवश्यकता है। नदियों से बालू निकालने के चक्कर में अवैध खनन व कटाव थम नहीं रहा। इससे सतह की संरचना बिगड़ रही है।

रजनीश तिवारी, पटना

व्यापक हुई शिक्षकों की भूमिका

प्रतिवर्ष पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। गुरु-शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता-पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। अब शिक्षक केवल पुस्तकों के अध्यापन तक सीमित नहीं है, बल्कि आनलाइन प्लेटफार्म, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर हमें जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन सही और गलत में फर्क करना, नैतिक मूल्यों को समझाना और मानवता की राह पर चलना केवल एक शिक्षक ही सिखा सकते हैं। शिक्षकों के लिए यह अति महत्त्वपूर्ण है कि वे युवाओं में सत्य, सहृदयता और मानवता जैसे मूल्यों एवं आदर्शों का समावेश करें।

कुमार गौरव, मधुबनी

X पोस्ट

गुटखा, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी और जीवन बीमा एवं मेडिक्लेम को कर मुक्त होते देखना सुखद एवं संतोषजनक है।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

एक ही कैलेंडर वर्ष में पहले 12 लाख रुपये की सालाना आय को आयकर मुक्त करना और कुछ ही महीनों बाद जीएसटी में बड़े सुधारों का सूत्रपात करके निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्री के रूप में विरासत खासी समृद्ध हो गई है।
तुषार गुप्ता@Tushar15_

ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका के साथ नहीं रहने वाला खत्म हो जाएगा। उन्हें याद रहे कि अमेरिका के बिना भी हजारों साल से भारत का अस्तित्व कायम रहा है और आगे भी रहेगा। कंवल सिब्बल@KanwalSibal

पीएम मोदी के चीन दौरे की तो खूब चर्चा हुई, पर हाल में फिलीपींस के राष्ट्रपति, सिंगापुर, फिजी के पीएम और दक्षिण कोरिया, जर्मनी के वरिष्ठ मंत्रियों के भारत दौरे पर उतना ध्यान नहीं गया। स्वदेशीकरण, विविधीकरण और संतुलन की दृष्टि से इनका भी अपना महत्व है।
तन्वी मदान@tanvi_madan

जनपथ

करें बखेड़ा बेवजह बोल-बोल कर झूठ,
ऊंगली औरों पर उठे स्वयं चाहते छूट।
स्वयं चाहते छूट सही यदि 'राहुल थ्योरी',
फिर तो समझो आप किये वोटों की चोरी।
'मालिक' की हर बात सिर्फ दोहराएं खेड़ा,
सच्चाई झुठलाय बेवजह करें बखेड़ा!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 145

https://t.me/AllNewsPaperPaid

****

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 5 सितम्बर 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

जीएसटी सुधार या भूल सुधार

30 जून और 1 जुलाई 2017 की आधी रात को संसद भवन को बिजली की लड़ियों और फूलों से सजाया गया था। जगमगाती संसद में नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक आजादी की घोषणा की और वो भी आधी रात को। मीडिया ने इसे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक पल बताया था। मकसद साफ था कि नेहरूजी ने आधी रात को ही दुनिया के सामने देश की आजादी का ऐलान किया था, तो किसी भी तरह उनके समकक्ष आने के लिए नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन का ही इस्तेमाल किया और वह भी आधी रात को। दरअसल 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू हुई और इसमें वैट, सेवा टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष टैक्स को एक साथ किया गया। लेकिन जिस तरह नोटबंदी की असफलता देश के सामने आने में देर नहीं हुई। वैसे ही जीएसटी की कमियां भी व्यापारियों को परेशान करने लगीं और आम आदमी के लिए भी कई तरह से यह व्यवस्था मारक साबित हुई।

अब इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव के वादे किए थे। उनके हिसाब से यह जनता के लिए दीवाली का तोहफा होगा। लेकिन शायद बिहार चुनाव के कारण दीवाली से पहले ही जीएसटी में दरों में बदलाव किया गया है, जो इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को इसकी मंजूरी दे दी है। अब 12फीसदी और 28 फीसदी की कर स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। केवल दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगे साथ ही सिगरेट, शराब, निजी नौका, हेलीकॉप्टर जैसे खास सामानों पर 40फीसदी की विशेष कर दर लागू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, 'यह सुधार आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, और एमएसएमई के लिए लाभकारी होंगे।'

मीडिया एक बार फिर चरणवंदन में लग चुका है। इसे मोदी का मास्टरस्ट्रोक जैसे शीर्षकों से पेश किया जा रहा है, जबकि असल में यह कांग्रेस की सलाह पर अमल है और अपनी गलती का सुधार है। 2017 से आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर जीवनरक्षक दवाओं तक सब पर जीएसटी का भार सहना पड़ता था। अब सरकार इसे आम आदमी के लिए राहत बता रही है। राहुल गांधी 2017 से लेकर अब तक कई बार यह मांग कर चुके थे कि गरीबों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई आदि को ध्यान में रखकर कर की दरें लागू हों, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। दरअसल जीएसटी के कारण खाद, किताब, ट्रैक्टर, दवाई, पढ़ाई दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेन्सिल-किताबें, ऑक्सीजन, इंश्योरेंस और अस्पताल के खर्च जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो गई थीं। देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा, सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा था।

अब राहत देकर इसे जनता के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर पेश किया जा रहा है। नए जीएसटी स्लैब के बाद अब कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं पर अब शून्य दर से कर लगेगा। दूध, पनीर, स्नैक्स और ब्रेड सहित आम उपभोग की 175 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पनीर, छेना और पराठे सहित सभी प्रकार की भारतीय रोटियों पर कर 5 प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा। बालों का तेल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, रसोई के सामान अब 5 प्रतिशत कर के दायरे में आएंगे। 33 जीवन रक्षक दवाइयां 12 प्रतिशत से शून्य कर के दायरे में आ जाएंगी। मानव निर्मित रेशे पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा फिलहाल बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि बीमा कंपनियों से आप उपभोक्ता को कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि अपने नुकसान की भरपाई भी आखिर में कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलेंगी। यही बात बाकी उत्पादों पर भी लागू होती है। एक बार कोई सामान महंगा बिकने लगे तो शायद ही कभी दाम कम होते हैं। इसलिए दीवाली से पहले जिन लोगों को यह लग रहा है कि सरकार से उनको वाकई तोहफा मिल गया तो वे अपनी खुशियां थाम कर रखें। नई दरें लागू होने के बाद देखें कि सामान सस्ता होता है या किसी और तरीके से कीमत बढ़ाई जाती है।

वैसे भी इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड उद्योगपतियों के साथ खड़े होने का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64फीसदी हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, और अरबपतियों से केवल 3फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स की दर 30फीसदी से घटाकर 22फीसदी कर दी गई है। दरअसल एक देश एक टैक्स की बात करते हुए मोदी सरकार ने 0फीसदी, 5फीसदी, 12फीसदी, 18फीसदी, 28 फीसदी की दरों के साथ 0.25फीसदी, 1.5फीसदी, 3फीसदी और 6फीसदी की विशेष दरों वाली एक देश 9 टैक्स प्रणाली को लागू किया था। इस वजह से व्यापारियों को तकलीफ हो रही थी, उसके कुछ उदाहरण भी सामने आए थे। तमिलनाडु में एक व्यापारी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो उसे निर्मला सीतारमण के सामने बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। सरकार की जिद और मनमानेपन का यह एक सबूत था। हालांकि जीएसटी को श्री मोदी अपने बड़ी सफलता की तरह पेश करते रहे, लेकिन उसमें बार-बार बदलाव से यह जाहिर था कि 140 करोड़ की आबादी को प्रभावित करने वाले इस फैसले पर ठीक से सोच-विचार भाजपा ने नहीं किया। इससे पहले 28 फ़रवरी 2005 को यूपीए सरकार ने लोक सभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। फिर 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए तब भाजपा के साथ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही जीएसटी का घोर विरोध किया था। अब इसी जीएसटी को वे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि यह कांग्रेस के फैसले को दोहराने से ज्यादा कुछ नहीं है।

लगातार अनिश्चित हो रही विधेयकों के अनुमोदन की समय-सीमाएं

■ के रवींद्रन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा राज्यपालों और राष्ट्रपति को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित तीन महीने की समय-सीमा, जिसकी अब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा पुनर्परीक्षा की जा रही है, लगातार अनिश्चित होती जा रही है।

यह मामला, जो मूल निर्णय के समय सुलझा हुआ प्रतीत हो सकता था, अब नाजुक होता जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के माध्यम से व्यापक संवैधानिक सिद्धांत सामने आ रहे हैं। दो-न्यायाधीशों के निर्णय की स्थिरता अनिश्चित प्रतीत होती है, न केवल बड़ी पीठ के संदेह के कारण, बल्कि अप्रैल के निर्णय में निहित अस्पष्टताओं के कारण भी, जो अनपेक्षित परिणामों के द्वार खुले छोड़ देती हैं। दांव पर केवल विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता ही नहीं, बल्कि संवैधानिक पाठ, न्यायिक रचनात्मकता और अनजाने में नए संवैधानिक मानदंडों के निर्माण के जोखिमों के बीच संतुलन भी है।

शुरू से ही, 8 अप्रैल के इस फैसले की कुछ हलकों में राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की लगातार शिकायतों के समाधान के रूप में सराहना की गई। राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य करने वाले इस आदेश को जवाबदेही बढ़ाने और कार्यपालिका की मनमानी को रोकने के रूप में देखा गया। हालांकि, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होता था, लेकिन इसमें अपनाई गई विधि, जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं, एक कठोर समय-सीमा लागू करना—समस्याओं से भरी थी।

अब राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार कर रही बड़ी पीठ ने पहले ही इस तनाव को चिह्नित कर दिया है और आगाह किया है कि समय-सीमा अनिवार्य करना वास्तव में संविधान में संशोधन के समान हो सकता है। यह तर्क इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि दस्तावेज़ के निर्माताओं ने, व्यापक बहस के बाद, संबंधित कार्यकारी प्राधिकारियों पर ऐसी सख्तियां लागू करने से जानबूझ कर परहेज़ किया था। इसके बजाय, उन्होंने दुरुपयोग को रोकने के लिए असाधारण मामलों में परंपराओं, राजनीतिक ज़िम्मेदारी और न्यायिक निगरानी पर भरोसा किया। एक निश्चित अवधि को संवैधानिक मौन मानने का प्रयास करके, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने शायद एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे नेकनीयत न्यायिक नवाचार भी उचित नहीं ठहरा सकते।

बड़ी पीठ ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त किया है। यह असाधारण विलंब के मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप की वैधता को स्वीकार करता है, जहां सहमति न देना या निष्क्रियता स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति को नष्ट करती है। ऐसा हस्तक्षेप उपचारात्मक है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक विघटन के विशिष्ट उदाहरणों को संबोधित करना है। हालांकि, इस मामले में विशिष्ट उपाय को हर स्थिति में लागू होने वाले एक सार्वभौमिक नियम में परिवर्तित करने से वैचारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इससे न्यायपालिका के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से पुनर्लेखन करके एक विधायी कार्य संभालने का जोखिम पैदा होता है। पीठ की आशंका है कि ऐसा दृष्टिकोण संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह भविष्य में न्यायिक रूप से निर्धारित समय-सीमाओं को चुनौती देने वाले मुकदमों की संभावना को खुला छोड़ देता है, जिससे समाधान के बजाय अधिक अस्थिरता पैदा होती है।

> इस अनिश्चितता के व्यावहारिक परिणाम दूरगामी हैं। यदि 8 अप्रैल का फैसला बरकरार रहता है, तो राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे पूर्वानुमानितता पैदा होगी और विधायी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। फिर भी, ऐसा करने से, यह उस विचार-विमर्श की गुंजाइश को भी कम कर देता है।

8 अप्रैल के फैसले में न्यायिक समीक्षा के अपने व्यवहार में भी अस्पष्टताएं हैं। इसने सही ही पुष्टि की कि विधेयकों को लंबित रखने में राज्यपाल का आचरण न्यायिक जांच से परे नहीं है। यह कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जवाबदेही से मुक्त नहीं है, खासकर जब निष्क्रियता प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करती है। फिर भी, यह निर्णय ऐसी समीक्षा के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहा।

विशेष रूप से, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या जांच केवल आचरण तक ही सीमित है—अर्थात विलंब तक—या क्या यह विधेयकों के सार को भी शामिल कर सकती है। निर्णय यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि एक बार जब किसी विधेयक को निर्धारित अवधि बीत जाने के कारण स्वत: स्वीकृति मिल जाती है, तो राज्यपाल की पूर्व निष्क्रियता को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन क्या इससे संबंधित विधेयकों की विषयवस्तु, आशय और संवैधानिक वैधता की भी जांच करने का रास्ता खुलता है? यदि बिना किसी ठोस समीक्षा के स्वत: स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो संभावना है कि संदिग्ध संवैधानिक योग्यता वाले विधेयक बिना किसी जांच के पारित हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि न्यायालय स्वयं विषयवस्तु की जांच में शामिल होते हैं, तो यह न्यायिक वीटो के समान हो सकता है, जो शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।

इन विवादों को सुलझाने के लिए स्पष्ट संस्थागत रास्तों के अभाव से दुविधा और भी जटिल हो जाती है। संविधान में नियंत्रण और संतुलन की एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जहां राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के विधानों में संवैधानिक औचित्य की रक्षा में एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, विधेयकों पर अनिश्चित काल तक रोक लगाकर इस पद का दुरुपयोग करने से यह सुरक्षा अवरोध का साधन बन गया है। इस असंतुलन को दूर करने की न्यायपालिका की प्रवृत्ति समझ में आती है, लेकिन एक कठोर ढांचा लागू करके, अप्रैल के फैसले ने एक और संतुलन- न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक संशोधन के बीच की रेखा- को बिगाड़ने का प्रयास किया। वृहद पीठ की चिंता, सुविधावाद की आड़ में न्यायिक अतिक्रमण के खतरे को उजागर करती है।

इस अनिश्चितता के व्यावहारिक परिणाम दूरगामी हैं। यदि 8 अप्रैल का फैसला बरकरार रहता है, तो राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे पूर्वानुमानितता पैदा होगी और विधायी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। फिर भी, ऐसा करने से, यह उस विचार-विमर्श की गुंजाइश को भी कम कर देता है जिसका संविधान निर्माताओं ने इरादा किया होगा, खासकर उन मामलों में जहां विधेयक जटिल संवैधानिक या नीतिगत प्रश्न उठाते हैं। दूसरी ओर, यदि वृहद पीठ द्वारा फैसले को खारिज कर दिया जाता है, तो अनिश्चितकालीन विलंब की यथास्थिति वापस आ जाएगी, जब तक कि संसद स्वयं समय-सीमा तय करने के लिए हस्तक्षेप न करे, जो एक राजनीतिक रूप से जटिल प्रस्ताव है। किसी भी स्थिति में, गहरा सवाल अनसुलझा रहता है: जब विधेयकों में देरी हो रही हो, तो न्यायिक समीक्षा का वैध दायरा क्या होना चाहिए? क्या न्यायपालिका केवल यह आकलन करने तक सीमित है कि क्या देरी अनुचित है, या क्या वह आगे बढ़कर विधेयकों की प्रकृति की जांच कर सकती है, जब तक कि स्वीकृति न मिल जाए?

अप्रैल के फैसले में स्पष्टता की कमी से मुक़दमों की बाढ़ आने का ख़तरा है। उदाहरण के लिए, तीन महीने की राज्यपालीय चुप्पी के बाद स्वत: कानून बन जाने वाले किसी विधेयक को बाद में संवैधानिक कमज़ोरियों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तब अदालतों को न केवल स्वत: स्वीकृति तंत्र की वैधता पर, बल्कि स्वयं कानून की मूल संवैधानिकता पर भी निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। यह दो-स्तरीय मुक़दमेबाज़ी उस निश्चितता को प्रदान करने के बजाय जटिलता की परतें बढ़ाएगी जिसका दावा इस फैसले में किया गया था। यह राज्यपालों को रणनीतिक रूप से पीछे हटने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, यह जानते हुए कि विवादास्पद विधेयक, एक बार स्वत: स्वीकृति मिलने के बाद, वैसे भी न्यायिक बाधाओं का सामना करेंगे। ऐसा परिणाम विरोधाभासी रूप से उसी समस्या को और मज़बूत कर सकता है जिसका समाधान अप्रैल के फैसले में किया गया था।

बड़ी पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई इन तनावों को दूर करने की कठिनाई को रेखांकित करती है। न्यायिक रचनात्मकता लंबे समय से भारतीय संवैधानिक कानून की एक पहचान रही है, मूल संरचना सिद्धांत से लेकर मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्याओं तक। फिर भी, व्याख्या और संशोधन के बीच एक रेखा, चाहे कितनी भी धुंधली क्यों न हो, रही है। 8 अप्रैल के फैसले पर बहस उस सीमा की नाज़ुकता को उजागर करती है। समय-सीमाएं निर्धारित करके, दो न्यायाधीशों की पीठ ने भले ही नेकनीयती से प्रयास किया हो, शायद हद पार कर दी हो। बड़ी पीठ का सतर्क दृष्टिकोण इस जागरूकता को दर्शाता है कि संवैधानिक मौन का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वे कभी-कभी कार्यपालिका के अवरोधों की अनुमति देते हों। न्यायिक आदेश के माध्यम से हर कमी को पूरा करने का जोखिम यह है कि संविधान धीरे-धीरे आधारभूत पाठ नहीं रह जाता और न्यायिक रूप से जोड़े गए खंडों का एक ढेर बन जाता है।

सपनों को संवारने वाला शिल्पकार: शिक्षक

■ डॉ. सूर्यकांत मिश्रा

प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर विचारों की छलछलाती सोच कुछ नया लिखने की प्रेरणा प्रदान करती महसूस की जाती है। मैं अपने शिक्षकीय अनुभव पर कुछ लिखूं या फिर मेरे अपने गुरुओं की महिमा का गान करूं, समझ पाने में असमर्थ हूं। कभी यह विचार भी मन में उठने लगते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते आज के कुछ शिक्षक इस महान पेशे को कलंकित कर जाते हैं, क्या आज की सम्मानजनक वेतन प्रणाली ने ऐसे शिक्षकों के जीवन में अमर्यादित आचरण का बीजारोपण किया है? आर्थिक संपन्नता के चलते ही कहीं शिक्षकीय पेशा अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहा है? ऐसे सवाल अंतर्मन में इसलिए हिलोरे मार रहे हैं कि आज से लगभग आधी शताब्दी पूर्व इस महत्वपूर्ण पेशे में संलग्न लोगों को मिलने वाला वेतन पारिवारिक जरूरतों के लिए अपर्याप्त था, किंतु शिक्षकों का आचरण वास्तव में गुरुओं की श्रेणी का हुआ करता था। वर्तमान समय में कुछ लोगों के कारण इस पेशे में आई सामाजिक गिरावट ने यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या आज भी शालाओं को गुरुकुल का पर्याय माना जा सकता है? मेरी आत्मा से निकला उत्तर नकारात्मक जान पड़ता है! शिक्षक दिवस के दिन इन बदली हुई परिस्थितियों में बहुत कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जो भारतीय संस्कृति को नागवार गुजरता हो।

> एक सच्चा शिक्षक अपनी महानता से आपको प्रभावित नहीं करना चाहता बल्कि वह आपको यह एहसास कराना चाहता है कि आपके पास स्वयं को खोजने का कौशल है। हमारे राष्ट्रनिर्माता को यह याद रखना होगा कि एक प्रतिभाशाली शिक्षक न केवल आज के बच्चे की जरूरतों को पूरा करने वाला माध्यम है बल्कि हर बच्चे के भविष्य में आशाओं और सपनों को संवारने वाला बड़ा शिल्पकार भी है।

एक शिक्षक के रूप में इस सेवा को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को एक नहीं अनेक पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। अपनी छवि गुरु के रूप में स्थापित करने का सपना उसी दशा में पूरा हो सकता है, जब एक शिक्षक सबसे पहले अपने रहने और कपड़े पहनने के तरीकों का भलीभांति ध्यान रखें। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रवेश करे, वह खुद को पूरे अनुशासन की परिधि में तौल ले। कारण यह कि हर विद्यार्थी अपने शिक्षक को अपना आदर्श मानतस्र हैं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय सामग्री बच्चों के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव छोड़ती है। आगे चलकर यही शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में महती भूमिका निभाती है। इसी कारण कहा जाता है- ०२१०शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है।' जब हम शिक्षक के रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अपने जीवनकाल के सबसे अच्छे शिक्षक की तस्वीर घूमने लगती है। यह तस्वीर इसलिए हमारे सामने आती है, क्योंकि हमने उस शिक्षक से वह सब कुछ सीखा है जिसके चलते आज सम्मानजनक स्थान पर खड़े हैं। वही एक अच्छा शिक्षक माना जा सकता है, जो खुद को कुछ बोलने से पहले तौलता हो कि उसकी वाणी का प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक? एक शिक्षक का बेहतरीन व्यक्तित्व उसके बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। एक शिक्षक का बेहतरीन वक्ता होना ही वह गुण है जिसके चलते उसके विद्यार्थी उसे पसंद करने लगते हैं। प्रत्येक शिक्षक को यह स्मरण रखना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों से बेसिर पैर की बात न करे। ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों के प्रेरणा स्त्रोत नहीं हो सकते।

वर्तमान समय तेजी के साथ परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर है। आज के बच्चों का जीवन जीने का तरीका पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका है। खास कर आज की किशोरवय और युवा पीढ़ी की सोच का अध्ययन कर उन्हें शिक्षित करना बड़ी चुनौती है। वर्तमान पीढ़ी जिसमें युवक-युवती दोनों ही शामिल हैं, उन्हें किसी काम में किसी अन्य का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं। फिर वह उनके माता-पिता सहित शिक्षक ही क्यों न हों? ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों का कर्तव्य और अधिक बढ़ जाता है कि उनके विचारों में घुलमिल चुकी विषमता को कैसे बाहर निकालें? यदि एक शिक्षक ही व्यसन के कुचक्र में पड़कर अपनी कक्षाओं में प्रवेश करेगा तो क्या वह आग में घी डालने जैसा नहीं होगा? तब हमें विचार करना होगा कि हम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उच्च विचारों को अपने हृदय में कैसे स्थान प्रदान करें? एक अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि एक अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। प्रत्येक शिक्षक इस बात को जानता है कि उसका काम न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार भी करना है। तब वर्तमान का शिक्षक खुद को एक ऐसा उपकरण क्यों नहीं मान रहा है, जो उच्च स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में सक्षम रहता है। आज एक शिक्षक की चुनौती पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। कारण यह कि अब जमाना 'गूगल' का है! हर छात्र गूगल और किताबों के माध्यम से अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता है। तब एक शिक्षक को हर परिस्थिति में अपने विद्यार्थियों के सवालों का सटीक जवाब देने खुद को अपडेट रखना होगा।

'शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था का हृदय है।' उसके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से ही जीवन प्रकाशवान हो सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अब शिक्षक का कार्य बोर्ड पर दो चॉक लेकर खड़ा होना ही नहीं रह गया है बल्कि अपने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से वह सब कुछ प्रदान करना है जिसकी उम्मीद एक शिक्षक के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी चाहती है। समाज निर्माण की भूमिका में आज तैनात समस्त शिक्षकों को यह समझ लेना चाहिए कि 'एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक' पूरी दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में कहा जाए तो आज जरूरत इस बात की है कि एक अध्यापक खुद को केवल शिक्षक नहीं बल्कि यह मानकर काम करे कि वह जागरूकता पैदा करने की बड़ी मशीन है। शिक्षकों का प्रभाव केवल कक्षा की चहार दीवारी तक ही नहीं उससे भी आगे भविष्य निर्माण तक विस्तृत है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम कहा करते थे- 'शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। यदि लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।'

एक सच्चा शिक्षक अपनी महानता से आपको प्रभावित नहीं करना चाहता बल्कि वह आपको यह एहसास कराना चाहता है कि आपके पास स्वयं को खोजने का कौशल है। हमारे राष्ट्र निर्माता को यह याद रखना होगा कि एक प्रतिभाशाली शिक्षक न केवल आज के बच्चे की जरूरतों को पूरा करने वाला माध्यम है बल्कि हर बच्चे के भविष्य में आशाओं और सपनों को संवारने वाला बड़ा शिल्पकार भी है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अच्छा शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों में आशा का बीज बो सकता है। उनके अंदर अंकुरित हो रही कल्पना को प्रस्फुटित कर सकता है। एक शिक्षक ही विद्यार्थियों में सीखने के प्रति जीवटता और जुनून पैदा कर सकता है। इसी कारण शिक्षा को संजीवनी और शिक्षक को हनुमान कहा जाता है।

ललित सुरजन की कलम से

जीएसटी : परेशानियों का अंबार

द इकॉनामिस्ट के इस अंक में भारत के वर्तमान परिदृश्य पर तीन लेख हैं। एक लेख में कहा गया है कि जीएसटी का स्वागत है, किन्तु यह अनावश्यक रूप से जटिल और लालफीताशाही से ग्रस्त है जिसके कारण इसकी उपादेयता बहुत घट गई है। पत्रिका यह भी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही जोरदार प्रचार के साथ बहुत सी योजनाएं प्रारंभ कर दी हों, लेकिन इनमें से अनेक तो पहले से चली आ रही थीं। जीएसटी का प्रस्ताव भी पुराना था। पत्रिका नोट करती है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिस व्यवस्थित रूप में कार्य होना चाहिए उसे नरेन्द्र मोदी करने में समर्थ प्रतीत नहीं होते। जीएसटी की चर्चा करते हुए द इकानॉमिस्ट का कहना है कि अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा फार्म भरना पड़ेंगे। इसके अलावा जीएसटी वाले अन्य देशों में जहां टैक्स की सिर्फ एक दर है वहां भारत में शून्य से लेकर अट्ठाइस तक दरें तय की गई हैं। इसके चलते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जो दो प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई थी वह अब शायद एक प्रतिशत भी न बढ़ पाए।

(देशबन्धु में 13 जुलाई 2017 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2017/07/blog-post_12.html

मिलाद-उन-दबी आज

पैग़म्बर मुहम्मद अमर चरित्र और मानवता के लिए आदर्श

इस्लाम का संदेश कोई नया धर्म नहीं है। प्रथम मानव और प्रथम पैग़म्बर हज़रत आदम से लेकर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा (अलैहिमुस्सलाम) तक सभी दूतों ने एक ही शिक्षा दी—एक ईश्वर की उपासना और मानवता की सेवा। पैग़म्बर मुहम्मद उसी परम्परा के अंतिम दूत हैं, जिन्होंने इस सत्य को पुन: स्थापित किया और पूर्णता प्रदान की।

पैग़म्बर मुहम्मद का जीवन चरित्र विश्व-इतिहास में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला जीवन है। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श है, जो न केवल अपने समय में, बल्कि पिछले 14 सौ वर्षों से निरन्तर पढ़ा, समझा और अपनाया जा रहा है। उनकी सैरत (जीवनी) पर असंख्य भाषाओं में ग्रन्थ लिखे गए हैं। उनकी शिक्षा यह है कि श्रेष्ठता का आधार न जाति है, न वर्ण, न सम्पत्ति, अपितु केवल धर्मनिष्ठ आचरण और उत्तम चरित्र है।

ईश्वर ने अपने अंतिम दूत, पैग़म्बर मुहम्मद को समस्त संसार के लिए दया और करुणा का स्रोत बनाकर भेजा। क़ुरआन में कहा गया है-

और हमने तुम्हें केवल जगतों के लिए दया स्वरूप भेजा है। (सूरा अंबिया: 107)

पैग़म्बर ने सदैव न्याय को सर्वोपरि रखा। एक प्रसंग में एक यहूदी व्यक्ति मुक़दमे में विजयी हुआ क्योंकि सत्य उसी के पक्ष में था, जबकि विरोधी एक मुसलमान था। उन्होंने घोषणा की:

यदि मेरी पुत्री फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। (बुख़ारी)

यह शिक्षा देती है कि न्याय के सामने रिश्ते, जाति या धर्म का कोई मूल्य नहीं।

जब ताइफ़ नगर के लोगों ने पैग़म्बर को पत्थरों से घायल कर दिया, तो स्वर्गदूत ने उन्हें दण्ड देने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया:

मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनकी संतति से सदाचारी लोग उत्पन्न हों।

इस घटना से स्पष्ट होता है कि पैग़म्बर दया और क्षमा के प्रतीक थे।

हज के अंतिम उपदेश में पैग़म्बर ने मानव समानता की घोषणा की-

किसी अरब को अजमी पर, किसी गोर वर्ण को श्याम वर्ण पर कोई श्रेष्ठता नहीं, केवल धर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठता का आधार है।

यह संदेश विश्व-मानवता के लिए भाईचारे और समानता का शाश्वत सिद्धान्त है।

पैग़म्बर ने सदैव अनाथ, विधवा और निर्धन की सहायता पर बल दिया। उन्होंने कहा-सबसे उत्तम मनुष्य वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। (मुस्नद अहमद)

पैग़म्बर ने पड़ोसी के अधिकार को आस्था का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा-

जिब्रील मुझे निरन्तर पड़ोसी के अधिकार की शिक्षा देते रहे, यहां तक कि मैंने सोचा वे पड़ोसी को वारिस बना देंगे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

वह व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं जो स्वयं तो तृप्त हो और उसका पड़ोसी भूखा रहे। (मुस्नद अहमद)

पैग़म्बर ने नारी को ईश्वर की अमानत बताया। अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा-

हे लोगो! स्त्रियों के विषय में ईश्वर से डरते रहो, क्योंकि तुमने उन्हें ईश्वर की अमानत स्वरूप ग्रहण किया है। उन्होंने यह भी कहा-

तुममें सबसे श्रेष्ठ वही है जो अपने परिवार के साथ श्रेष्ठ आचरण रखे, और मैं अपने परिवार के साथ सबसे श्रेष्ठ हूं। (तिर्मिज़ी)

पैग़म्बर ने अत्याचार को सबसे बड़ा पाप बताया-अत्याचार से बचो, क्योंकि अन्याय प्रलय के दिन अंधकार बनेगा।

अत्याचारित की प्रार्थना से बचो, क्योंकि उसके और ईश्वर के बीच कोई परदा नहीं। (बुख़ारी, मुस्लिम) उन्होंने घोषणा की-

हे लोगो! तुम्हारा रक्त, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मर्यादा- सब एक-दूसरे पर उसी प्रकार पवित्र है जैसे यह दिन, यह महीना और यह नगर पवित्र है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

आज आवश्यकता है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि वे वास्तव में समस्त मानवता के लिए करुणा मूर्ति हैं।

-नुज़हत सुहैल पाशा

आपके पत्र

खतरनाक मौसम में भी स्कूल खुले क्यों?

दुनिया भर में आपदा और संकट के समय शिक्षा व्यवस्था पर अस्थायी रोक लगाना कोई नई बात नहीं है। कोरोना काल में महीनों तक स्कूल बंद रहे और वैकल्पिक माध्यमों से शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। जब महामारी के दौर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई, तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वही संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जाती?

यहां तर्क दिया जा सकता है कि पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए स्कूल बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन क्या पढ़ाई का महत्व बच्चों और शिक्षकों की जान से बड़ा है? शिक्षा तभी सार्थक है जब छात्र और शिक्षक सुरक्षित हों। गीली और टूटती छतों के नीचे, पानी से भरे आंगनों में और बीमारी के खौफ में पढ़ाई कराने का निर्णय शिक्षा नहीं, बल्कि मजबूरी और लापरवाही कहलाएगी।

दरअसल, असली समस्या हमारी नीति और नीयत दोनों की है। जिन अधिकारियों को स्थानीय हालात देखकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, वे केवल ऊपर से आए आदेशों का इंतज़ार करते रहते हैं। और ऊपर बैठे नीति-निर्माता आमतौर पर कागज़ी रिपोर्टों और फाइलों के आधार पर निर्णय लेते हैं। नतीजा यह होता है कि जमीनी हालात और सरकारी आदेशों के बीच बड़ा अंतर रह जाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर एक स्पष्ट नीति बनाएं। इसमें यह तय हो कि किन परिस्थितियों में स्वत: स्कूल बंद माने जाएंगे। जैसे- जब किसी जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी हो, जब लगातार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो जाए, या जब भवनों की सुरक्षा संदिग्ध हो। इससे निचले स्तर के अधिकारी समय रहते फैसला ले सकेंगे और बच्चों को जोखिम से बचाया जा सकेगा।

इसके साथ-साथ स्कूल भवनों की नियमित मरम्मत और रखरखाव पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए। हर बरसात में छत टपकना और दीवारें गिरना हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल देता है। यदि बच्चों के लिए सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं करा सकते तो फिर शिक्षा के अधिकार की बातें खोखली साबित होती हैं।

एक और पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब सरकारें 'स्मार्ट क्लास', 'डिजिटल एजुकेशन' और 'न्यू एजुकेशन पॉलिसी' की बात करती हैं, तो क्यों न आपदा के समय ऑनलाइन या वैकल्पिक शिक्षा का सहारा लिया जाए? बच्चों की पढ़ाई बिना उनकी सुरक्षा से समझौता किए जारी रखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे दूरदर्शी कदमों की जगह केवल आदेश जारी करने की औपचारिकता निभाई जाती है।

बच्चे देश का भविष्य हैं—यह वाक्य हम बार-बार सुनते हैं। लेकिन जब इस भविष्य को सुरक्षित रखने का समय आता है, तो हमारी व्यवस्था सबसे ज्यादा असफल साबित होती है। बारिश और बाढ़ जैसे हालात में स्कूलों को खुला रखना बच्चों और शिक्षकों दोनों की जान को खतरे में डालने जैसा है। यह केवल संवेदनहीनता ही नहीं, बल्कि लापरवाही की पराकाष्ठा है।

संवेदनशील शासन वही है जो संकट की घड़ी में अपने नागरिकों—खासकर बच्चों—की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यदि इस बुनियादी दायित्व में भी हम असफल रहते हैं, तो विकास, शिक्षा और प्रगति के सारे दावे केवल खोखले नारे भर रह जाएंगे।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

जीएसटी सुधार से देश के विकास को मिलेगी गति

बुधवार को जीएसटी काउंसिल ने वो फैसला ले ही लिया, जिसका 15 अगस्त के बाद से देश को बेसब्री से इंजतार था। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधार का ऐलान करते हुए आम देशवासी को राहत देने का वादा किया था। जीएसटी काउंसिल ने इस पर अमल करते हुए वस्तु कर के दो स्लैब 12 और 28 प्रतिशत को खत्म कर दिया। इनकम टैक्स में राहत के बाद यह केंद्र सरकार का आम आदमी को दूसरा बड़ा तोहफा है। इससे किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं न केवल सस्ती होंगी बल्कि उनकी खपत भी बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। वैसे तो जीएसटी में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब इसकी पृष्ठभूमि में एक ओर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल को माना जा रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि आज की आर्थिक दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत होनी चाहिए। कअमेरिका जैसा विकसित देश भी टैरिफ को हथियार बनाकर अपने हित में ट्रेड डील की कोशिश कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अमेरिका के समक्ष झुकने की बजाए इसके विकल्प को अपनाने का रास्ता चुना है। अमेरिका से समझौता हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में देश के सामने टैरिफ को लेकर उपजी चुनौतियों का समाधान यही है कि हम घरेलू स्तर पर खपत, मांग और निवेश को बढ़ाकर विकास को गति दें। इससे न केवल हमारी विकास वृद्धि दर बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ती मांग से निवेश और रोजगार का चक्र भी जारी रहेगा। यह स्थिरता हमें दुनिया में वैकल्पिक बाजारों की ओर बढ़ने का भी अवसर देगी। इसलिए जीएसटी सुधारों को केवल बदलाव नहीं, बल्कि नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के रूप में देखना चाहिए। वैसे भी जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दुधारू गाय सबित हुआ है। एक जुलाई 2017 को लागू होने के बाद से हर साल इससे सरकार की आय में इजाफा हुआ है। इस साल 2025 में तो जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। शुरुआती साल में इसके जरिए सरकारी खजाने में 7.41 लाख करोड़ रुपये आए थे, वहीं अगले साल 2018–19 में जीएसटी से कमाई का आंकड़ा 11.77 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। अब तक कलेक्शन में तीन गुना से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया जा चुका है। 2021-22 से लेकर 2024-25 तक सिर्फ पांच साल में ही जीएसटी से सरकार की कमाई दोगुनी हो गई और ये 11.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22.08 लाख लाख करोड़ रुपये पहुंच गई, लेकिन अब बात अमेरिकी टैरिफ से निपटने और देश के विकास को नई रफ्तार देने की है। विकास दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली, लोगों की आय लगातार बढ़े और दूसरी महंगाई नियंत्रण में रहे। आय तभी बढ़ेगी जब देश में निवेश और उत्पादन को गति मिले और रोजगार के नए अवसर बनें। वहीं महंगाई पर काबू पाने के लिए अप्रत्यक्ष करों में कटौती सबसे प्रभावी उपायों में से मानी जाती है। इसी आर्थिक सोच के तहत सरकार ने इस साल डिरेगुलेशन की दिशा में दो बड़े सुधार किए हैं जिसका असर अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। विदेशी कंपनियां निवेश की ओर आकर्षित होंगी और भारतीय कंपनिया और स्टार्टअप्स अनुपालन के बोझ से मुक्त होकर नवाचार में छलांग लगाएंगे। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा।

दिवस विशेष

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

हर प्रश्न में छिपा हुआ है शिक्षक, हर उत्तर में सीख

शिक्षक दिवस, जिसे भारत में हर साल 5 सितंबर को उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है, केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और जीवन मूल्यों का एक जीवंत महोत्सव है। यह दिन हमें डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षाविद् की याद दिलाता है, जिन्होंने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। आज यह दिन न केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित है, बल्कि यह हमें हर उस व्यक्ति को सम्मानित करने का अवसर देता है जो हमारे जीवन को नए अर्थ, दिशा और संभावनाओं से समृद्ध करता है। परंपरागत रूप से, शिक्षक वह गुरु था जो ज्ञान का दीप जलाता था, और शिष्य उसकी रोशनी में जीवन पथ पर आगे बढ़ता था। लेकिन आधुनिक युग में शिक्षक की परिभाषा और अधिक व्यापक हो गई है। आज शिक्षक वह नहीं जो केवल किताबी ज्ञान दे, बल्कि वह है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने, चुनौतियों का सामना करने और मूल्यों को अपनाने की कला सिखाता है। यह माता-पिता हो सकते हैं जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, दोस्त जो कठिन समय में हौसला देते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति जिसकी सलाह हमारे जीवन को नया मोड़ देती है। शिक्षक दिवस को नए दृष्टिकोण से देखना यही है कि हम इसे केवल एक व्यक्ति या पेशे तक सीमित न करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज का हर वह व्यक्ति है जो हमें कुछ सिखाता है। एक बच्चा अपनी मासूम जिज्ञासा से नया दृष्टिकोण देता है, एक सहकर्मी सहयोग और नेतृत्व की कला सिखाता है, और हमारी असफलताएं भी हमें धैर्य व दृढ़ता का पाठ पढ़ाती हैं। इस तरह शिक्षक दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि उस निरंतर सीखने की प्रक्रिया का सम्मान है जो हमें हर पल बेहतर बनाती है। यह हमें यह अहसास कराता है कि ज्ञान का कोई एक स्रोत नहीं, यह जीवन के हर अनुभव, हर रिश्ते और हर क्षण में बिखरा हुआ है। शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान बांटने तक सीमित नहीं, बल्कि वह एक मूर्तिकार है जो संवेदनशीलता, मानवीयता और नैतिकता को आकार देता है। आज के युग में, जब तकनीकी प्रगति दुनिया को तेजी से बदल रही है, शिक्षक हमें यह सिखाता है कि असली प्रगति मशीनों या व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सामूहिक कल्याण में निहित है। वह हमें यह समझाता है कि सफलता का अर्थ केवल अपनी जीत नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का साझा प्रयास है। एक शिक्षक का प्रभाव उसके शब्दों से कहीं अधिक उसके चरित्र, सोच और जीवनशैली में झलकता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, सादगी और समर्पण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। शिक्षक दिवस को नए अर्थ देने का मतलब है इसे केवल अतीत के सम्मान तक सीमित न रखकर भविष्य की नींव बनाने का उत्सव बनाना। शिक्षक का दायित्व महज पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के लिए तैयार करना है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है, शिक्षक वह आधार प्रदान करता है जो हमें हर बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाने की शक्ति देता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई में अवसर छिपा है और हर सवाल में एक नया जवाब। शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों, व्यवहार और जीवनशैली से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें। चाहे वह कक्षा में बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक हो, नैतिकता का पाठ सिखाने वाले माता-पिता हों, या समाज में बदलाव लाने वाला कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति अपने स्तर पर शिक्षक की भूमिका निभाता है। शिक्षक दिवस को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक दिन या व्यक्ति का उत्सव नहीं, बल्कि वह अनंत शृंखला है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। शिक्षक दिवस को नए अर्थ देना यही है कि इसे औपचारिकता से परे ले जाकर जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर अनुभव, हर रिश्ते और हर क्षण में बिखरी हुई है। शिक्षक दिवस का असली उत्सव तब है जब हम अपनी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और हर अनुभव से सीख लेते हैं। यह दिन केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अनंत यात्रा का उत्सव है जिसमें हम सभी सहयात्री हैं, कभी शिक्षक, कभी शिष्य, और हमेशा एक सीखने वाले। यही शिक्षक दिवस का सच्चा अर्थ है, जो इसे आज के युग में सही मायनों में जीवंत और प्रासंगिक बनाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

बाढ़ से बेहाल सरहद के आर-पार के पंजाब

आपदा

विवेक शुक्ला

आजकल सरहद के आर-पार का पंजाब फिर से शोकाकुल है। दोनो पंजाब बाढ़ के कारण हुई अपनी बर्बादी पर रो रहे हैं। भयानक बाढ़ ने लाखों लोगों को तबाह कर दिया है। इस कष्ट और बेबसी ने मुल्कों और सरहदों की दूरियां मिटा दी हैं। दरअसल दोनों पंजाब अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। भारी मानसूनी बारिश, नदियों का उफान, और बांधों से पानी का अनियंत्रित रिसाव ने दोनों देशों के पंजाब प्रांतों में भयावह बाढ़ ला दी है। बेशक, जलवायु परिवर्तन इस बाढ़ का एक दीर्घकालिक कारण है। इस तरफ दोनों देशों को पर्याप्त ध्यान देना होगा। पाकिस्तान को विशेष रूप से अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। उसे अपने डिफेंस बजट को कम करके जनता के हितों में फैसले लेने होंगे।

अमृता प्रीतम ने देश के बंटवारे के कारण पंजाब में हुए कत्लेआम पर एक कालजयी रचना लिखी थी- 'अज्ज आखाँ वारिस शाह नूं, कितों कबरां विच्चों बोल...'। ये नज़्म 1947 में हुए बंटवारे की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। इसमें बंटवारे के दर्द को बेहद मार्मिक तरीके से व्यक्त किया गया है। आजकल सरहद के आर-पार का पंजाब फिर से शोकाकुल है। दोनो पंजाब बाढ़ के कारण हुई अपनी बर्बादी पर रो रहे हैं। भयानक बाढ़ ने लाखों लोगों को तबाह कर दिया है। इस कष्ट और बेबसी ने मुल्कों और सरहदों की दूरियां मिटा दी हैं। दरअसल दोनों पंजाब अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। भारी मानसूनी बारिश, नदियों का उफान, और बांधों से पानी का अनियंत्रित रिसाव ने दोनों देशों के पंजाब प्रांतों में भयावह बाढ़ ला दी है।

सोशल मीडिया पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाता है। सब तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। पंजाब क्षेत्र में इस साल मानसून असामान्य रूप से तीव्र रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों में मौसम विभागों के अनुसार, 1 जुलाई से 27 अगस्त 2025 के बीच पंजाब में पिछले साल की तुलना में 26.5% अधिक बारिश दर्ज की गई। यह अत्यधिक वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून का परिणाम है, जो दोनों देशों में भारी बारिश का प्रमुख स्रोत है। जलवायु परिवर्तन ने इस मानसून को और उग्र बना दिया है, क्योंकि गर्म हवा अधिक नमी को समाहित करती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी और अनियंत्रित बारिश होती है। पंजाब की प्रमुख नदियां-रावी, सतलज, ब्यास, और चिनाब—इस साल असामान्य रूप से उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने इन नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत के पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर, और फिरोजपुर जैसे जिलों में बाढ़ आई। पाकिस्तान में भी, इन नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसने लाहौर, कसूर, और बहावलनगर जैसे क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। लाहौर के पॉश इलाकों में रावी का पानी घुसने से हजारों घर प्रभावित हुए हैं।

हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना भी इस बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, देश के 7,500 ग्लेशियरों में से लगभग 45% तेजी से पिघल रहे हैं। यह पिघलता पानी रावी, सतलुज, और चिनाब जैसी नदियों में प्रवेश करता है, जिससे उनका जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हमजा हबीब कहते हैं कि उनके देश के पंजाब में खराब जल निकासी प्रणाली ने बाढ़ के प्रभाव को और बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए, वाघा बॉर्डर पर जलभराव की स्थिति भारत की तुलना में अधिक गंभीर थी, क्योंकि भारत ने बेहतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेनेज सिस्टम लागू किया है। इसके विपरीत, पाकिस्तान में अपर्याप्त ड्रेनेज ने पानी को जमा होने दिया, जिससे सड़कें, घर, और खेत जलमग्न हो गए।

भारत में भी, कुछ क्षेत्रों में पुराने बुनियादी ढांचे और अतिक्रमण ने जल निकासी को बाधित किया, जिससे

बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। सब जानते हैं कि पंजाब दोनों देशों का 'अन्न भंडार' है। इस बाढ़ ने इसे बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत में 61 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि डूब गई, जबकि पाकिस्तान में हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गईं। यह न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि लाखों किसानों की आजीविका को भी नष्ट कर रहा है। 2022 की बाढ़ की तरह, इस बार भी पाकिस्तान में खाद्य संकट की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और यह बाढ़ उसकी चुनौतियों को और बढ़ा रही है। हजारों घर, सड़कें, और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। पाकिस्तान में इससे पहले 2022 में भी भयानक बाढ़ से हाहाकार मच गया था। तब भी पड़ोसी मुल्क का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था।

हजारों लोगों की जानें गई थीं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पाकिस्तान ने भारत से आलू, टमाटर,प्याज और खाद्य तेलों का आयात करने की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा था कि सरकार बाढ़ के बाद देश भर में फसल बर्बाद होने के बाद लोगों की सुविधा के लिए भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। तब पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जताई थी। उन्होंने कहा था, "पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं।" पर भारत-पाकिस्तान के रिश्ते पहलगाम की घटना के कारण बहुत खराब हो चुके हैं। इस बीच, भारत में भी, पंजाब के प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रभावित लोग सरकार से मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। इस बाढ़ ने दोनों देशों में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। पाकिस्तान के पंजाब में लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि भारत में 1,000 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग अपने घर, खेत, और आजीविका खो चुके हैं। सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान करतारपुर कॉरिडोर भी पानी से लबालब है। भारत ने भारी मानसूनी बारिश के कारण अपने डैमों से पानी छोड़ने की सूचना पाकिस्तान को बीते महीने दे दी थी। यह सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि डैम भर जाने पर अतिरिक्त पानी नदियों में बहता है, जो पाकिस्तान की ओर जाता है। भारत ने मानवीय आधार पर 24-26 अगस्त को कई चेतावनियां जारी कीं, भले ही सिंधु जल संधि अप्रैल 2025 में निलंबित हो गई थी। पर पाकिस्तान के कुछ यू ट्यूबर्स आरोप लगा रहे हैं कि भारत के इस कदम से न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बाढ़ आई। उनका दावा है कि भारत ने डैमों को पाकिस्तान के पानी से भरकर अचानक फाटक खोले, जिससे पाकिस्तानी पंजाब में विनाशकारी बाढ़ आई। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन आरोपों को नकार दिया है। बेशक, जलवायु परिवर्तन इस बाढ़ का एक दीर्घकालिक कारण है। इस तरफ दोनों देशों को पर्याप्त ध्यान देना होगा। पाकिस्तान को विशेष रूप से अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। उसे अपने डिफेंस बजट को कम करके जनता के हितों में फैसले लेने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

करेंगे दान तो बनेंगे समृद्ध और खुशहाल

संकलित

दर्शन

एक विवेकशील प्राणी होने के नाते मनुष्य से त्याग की अपेक्षा स्वाभाविक है। वास्तव में मानव का पूर्ण विकास ही त्याग द्वारा संभव है। जो दूसरे के लिए जितना अधिक त्याग कर सकता है, वह उतना ही महान समझा जाता है राजा हरिश्चंद्र को हम आज भी उनके त्याग के लिए ही तो स्मरण करते हैं। महर्षि दधीचि ने तो एक विराट लक्ष्य के लिए अपनी देह का ही त्याग कर दिया था। वास्तव में हमारे समृद्ध इतिहास में कई विभूतियां तो केवल अपनी त्याग भावना के लिए ही विख्यात हुई हैं। त्याग की भावना का विकास करने के लिए सभी धर्मों में दान की महिमा बताई गई है। कहा जाता है धन का दान करने से धन शुद्ध होता है। आवश्यक नहीं है कि मात्र धनी व्यक्ति ही दान करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। दान की भावना जाग्रत होने पर आप पाएंगे कि आपके पास भी एक अक्षय भंडार है। मात्र धनदान या अन्नदान ही दान नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति धनहीन हो, परंतु उसके पास एक स्वस्थ एवं निरोग शरीर हो। क्या ऐसे लोगों के लिए श्रमदान विकल्प नहीं है? उनके आसपास कितने अशक्त लोग मिल जाएंगे, जिनकी वे अपनी शारीरिक ऊर्जा से सेवा कर सकते हैं। किसी के कार्य में हाथ बंटा लेना भी श्रमदान है। विद्यादान या ज्ञानदान को तो उत्तम में सवरेत्तम माना गया है। किसी निर्धन बच्चे को निःशुल्क पढ़ा देना भी तो दान ही है। आप किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त की सहायता कर सकते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, धन और भाव सब उपकरण हैं।

नई बातें सीख पाएंगे तो व्यक्तित्व में निखार आएगा

संकलित

प्रेरणा

एक गरीब व्यक्ति अर्जुन के पास पहुंचा और बोला कि कोई चोर उसकी गाय चुराकर ले गया है। मेरी मदद करें। अर्जुन उस व्यक्ति की मदद के लिए अपने धनुष-बाण लेने युधिष्ठिर-द्रौपदी के कमरे में चले गए। अर्जुन ने उस गरीब की मदद तो कर दी, लेकिन पांडवों का बनाया हुआ नियम तोड़ दिया। ये नियम तोड़ने के लिए अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। अर्जुन 12 वर्षों के लिए अकेले ही वनवास के लिए निकल पड़े थे। वे वन-वन घूम रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि मुझे इस वनवास में तपस्या करके अपने व्यक्तित्व को और निखारना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुझे वन में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि नए लोगों से मिलकर कुछ नया सीखना चाहिए। वनवास के समय में श्रीकृष्ण और अर्जुन की मुलाकात हुई। अर्जुन ने पूरी बात श्रीकृष्ण को बता दी। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम मेरे साथ द्वारका चलो। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो वनवास में ही रहना है। मैं वन से बाहर नहीं जा सकता। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वन में घूमो और नए-नए स्थानों का, नई-नई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करो। जब हम यात्रा में होते हैं, तब हमें लगातार नया सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। तभी यात्रा का लाभ मिल सकता है। वन तो तुम देख चुके हों, अब मैं तुम्हें द्वारका इसीलिए ले जा रहा हूं, ताकि तुम एक ऐसी नगरी देख सको, जहां तुम्हें और नई बातें सीखने को मिलेगी। द्वारका में योग में भोग और भोग में योग देखने को मिलेगा। तुम्हें द्वारका में बहुत बड़ा संदेश मिलेगा।

अंतर्मन

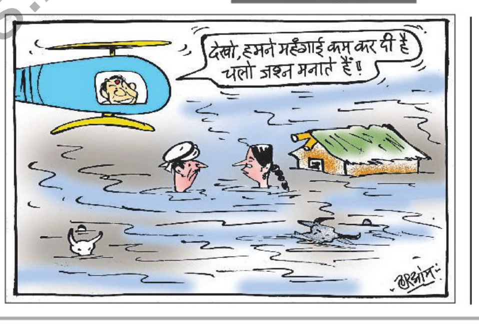

आज की पाती

नए मीटर हटाए सरकार

इलेक्ट्रानिक मीटर क्या लगे, जी का जंजाल बन गए हैं। पुराने मीटर उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त थे और किसी को शिकायत नहीं थी। जैसे हो बिजली के नए मीटर लगे उपभोक्ताओं के दोगुने बिल आने लगे हैं। चारों तरफ त्राहि-त्राहि है। आर्थिक तंगी में बढ़े हुए बिल जैसे गरीबी में आटा गीला हो गया है। उपभोक्ता चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटा कर पुराने मीटर ही लगाए जाएं और नए मीटर हटा कर विभाग जनहित का कार्य करे। इन नए मीटरों की न तो जनता ने मांग की थी और न इन्हें कोई चाहता है। इस कवायद से भले ही विद्युत विभाग की आय बढ़ी है, पर उपभोक्ता इस ट्रंप के से टैरिफ को नहीं सह पा रहे हैं। आशा है जनहित में विभाग और सरकार इस योजना को बंद कर अवश्य अनुगृहीत करेंगे।

- दिलीप तिवारी, दुर्ग

ट्रेंड

सिंगापुर मूल्यवान साझेदार

विकसित भारत के निर्माण की हमारी यात्रा में सिंगापुर एक मूल्यवान साझेदार है। हम उन्नत विनिर्माण, कौशल विकास और डिजिटल ढांचों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सबका मंगल एवं कल्याण हो

सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पंचम अवतार भगवान वामन की जयंती पर समस्त देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सबके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और आनंद बढ़े, सबका मंगल एवं कल्याण हो।

- अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री

प्रगतिशील कदम

आवश्यक वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि के लिए संशोधित जीएसटी स्लैब समावेशी विकास की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। सिक्किम के लोगों की ओर से, मैं इस परिवर्तनकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं।

- प्रेम सिंह तमांग, सीएम, सिक्किम

तकनीक की दुनिया

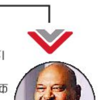

वैश्विक राजनीति में काफी अनिश्चितता है। लेकिन वैश्विक बाजारों ने सकारात्मकता दिखाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तकनीक की दुनिया में अद्भुत प्रगति हो रही है जो समृद्धि की ओर ले जा रही है।

- अनिल अग्रवाल, उद्यमी

करंट अफेयर

एनआरआई अमित नासा का सह-प्रशासक नियुक्त

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यहां घोषणा की कि भारतीय-अमेरिकी अमित क्षत्रिय को नासा का 'अन्वेषण-केंद्रित' नया सह-प्रशासक नियुक्त किया गया है। नासा में 20 साल सेवा दे चुके क्षत्रिय हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय (ईएसडीएमडी) में चंद्रमा और मंगल से जुड़े अभियान कार्यक्रमों के उप-प्रभारी थे। नासा के एक बयान में कहा कि कार्यवाहक नासा प्रशासक सीन पी डफी ने बुधवार को अमित क्षत्रिय को नासा का अन्वेषण केंद्रित नया सह-प्रशासक नियुक्त किया। विस्कॉन्सिन में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे एवं कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा ऑस्टिन स्थित टेक्सास विवि से शिक्षा प्राप्त क्षत्रिय इतिहास में मिशन नियंत्रण उड़ान निदेशक के रूप में सेवा करने वाले लगभग 100 लोगों में से एक हैं। नासा की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल के अनुसार, वह 2003 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े थे। क्षत्रिय को अंतरिक्ष स्टेशन के 50वें अभियान के वास्ते प्रमुख उड़ान निदेशक के रूप में उनके कार्यों के लिए नासा उत्कृष्ट नेतृत्व पदक से सम्मानित किया गया था। नासा ने कहा कि अपनी नयी भूमिका में वह एजेंसी में सर्वोच्च रैंक वाले सिविल सेवक के रूप में तथा डफी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करेंगे।

ऑफ बीट

सिर्फ कैलोरी पर नजर रखना जरूरी नहीं

वजन-समावेशी स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ है बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें वजन घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कैलोरी की संख्या के बजाय समग्र कल्याण के लिए भोजन करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इसमें तनाव कम करने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता देना, धूम्रपान से बचना, कम शराब पीना और आनंददायक तरीकों से शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का प्रयास करना भी शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति वजन-समावेशी दृष्टिकोण वजन बढ़ने से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करता है। अधिक वजन वाले लोग अक्सर दूसरों से - जिनमें उनके अपने डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता भी शामिल हैं - भेदभाव, पूर्वाग्रह, नकारात्मक रूढ़िवादिता और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करते हैं विभिन्न आकारों के 40% से अधिक अमेरिकी वयस्कों ने अपने दैनिक जीवन में वजन संबंधी अपमान का अनुभव किया है। अमेरिका में लोग वजन कम करने के लिए जिस हद तक जाते हैं, उसके पीछे संभवतः इस अपमान से बचना एक प्रमुख कारण है। बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकियों ने 2021 में वजन घटाने के उत्पादों और कार्यक्रमों पर लगभग 72.6 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

कल्पमेधा

काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना बेवकूफी है।
- स्वामी दयानंद सरस्वती

राहत की दर

पिछले कई वर्षों से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली और इसकी दरों को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस मसले पर सरकार के भीतर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा था। नतीजतन, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं पर भी कर के रूप में लोगों को नाहक ही ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही थी, जिन्हें अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। अब आखिरकार सरकार ने जीएसटी की दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की है और इसे आम जनता के लिए भारी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि कई वस्तुओं और सेवाओं पर अब तक लागू कर की दरों में जिस तरह कमी की गई है, उससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके तर्कसंगत होने को लेकर जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं, उसमें यह निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे बहुत देर से उठाया गया कदम बताया है।

गौरतलब है कि बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक में जिन नई दरों को मंजूरी दी गई, उसके तहत बारह फीसद और अट्ठाईस फीसद के स्तर को खत्म कर दिया गया है और अब सिर्फ पांच और अठारह फीसद की दर लागू रहेगी। मगर कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी को चालीस फीसद तक बढ़ा दिया गया है। इसी महीने की बाईस तारीख से लागू होने वाले करों के नए ढांचे में जो बदलाव किए गए हैं, उसके तहत लोगों के लिए आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं और सामान्य सेवाओं के मामले में काफी राहत दी गई है। मसलन, खाद्य और डेयरी उत्पाद, दवाएं, तेल, घी, सूखे मेवे, चपाती आदि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई उपयोगी चीजों को पांच फीसद के कर-ढांचे में डाला गया है। जबकि जीवन-बीमा सहित कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। वहीं, वातानुकूलन यंत्र, टीवी, प्रोजेक्टर सहित कई इलेक्ट्रोनिक चीजों को अठारह फीसद के स्तर में लाया गया है। इससे इतर, बड़े आकार वाली महंगी कारों के साथ-साथ पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और कैफीनयुक्त पेय जैसी कुछ चीजों पर अब चालीस फीसद जीएसटी तय की गई है।

जाहिर है, नए ढांचे का मकसद आबादी के एक बड़े हिस्से के खर्च और उपभोग को राहत के दायरे में लाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। यह एक आम हकीकत है कि अगर कोई वस्तु लोगों की आय के मुताबिक क्रयशक्ति की सीमा में होती है, तभी वे उसे खरीदने या उसके उपयोग को लेकर सहज होते हैं। कर की दरों में कमी के बाद वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में जो अंतर आएगा, आम इस्तेमाल में आने वाली चीजों की महंगाई में गिरावट आएगी, उससे बड़ी संख्या में लोग उसके उपभोग के दायरे में आ जाएंगे। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और इस तरह आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी शुल्कों से जो चुनौती पैदा हुई है, उसका सामना करने की दिशा में विकल्प भी तैयार होंगे। यों करीब आठ वर्ष पहले जब जीएसटी को लागू किया गया था, तभी से समय-समय पर अनेक उत्पादों पर कर की दरों में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन कई अन्य उत्पादों पर कटौती की मांग होती रही। अब जीएसटी में बदलाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन राज्यों की ओर से जिस तरह राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए समय देने की मांग उठी है, उसके मद्देनजर यह देखने की बात होगी कि सरकार इस संबंध में कौन-सा रास्ता निकालती है!

लापरवाही की हद

बड़े अस्पताल आमतौर पर उपचार के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। मगर इनके सघन चिकित्सा कक्ष में अव्यवस्था की वजह से नवजात बच्चे चूहों के शिकार बनने लगें, तो यह घोर लापरवाही और संवेदनहीनता का ही सबूत है। यह दुखद ही है कि आए दिन सरकारी अस्पतालों में आज भी अराजकता दिखाई पड़ती रहती है और लापरवाही के कारण कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बच्चों के सघन चिकित्सा कक्ष में चूहों के कुतरने से दो नवजात शिशुओं की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय में बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन कठघरे में हैं, लेकिन इस घटना से जहां साफ-सफाई से लेकर कर्मियों की घोर लापरवाही उजागर हुई है, वहीं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लग गया है। लोग अपने बच्चों को अस्पताल में लेकर इस उम्मीद से जाते हैं कि उनका ठीक से उपचार होगा। जब सघन चिकित्सा कक्ष में उन्हें रखा जाता है, तो इस विश्वास के साथ अभिभावक इंतजार करते हैं कि बच्चा स्वस्थ होकर सुरक्षित बाहर आ आएगा। मगर उस कक्ष में भी चूहों के कुतरने से नवजात की मौत हो जाए, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या यह समूचे अस्पताल प्रबंधन की नाकामी और लापरवाही का सबूत नहीं है?

राज्य के इस सबसे बड़े अस्पताल में चूहों की समस्या काफी समय से है। फिर भी इसकी अनदेखी की गई। समय-समय पर चूहों के सफाए के लिए अभियान भी चलाए गए, लेकिन समस्या अगर ज्यों की त्यों है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर साफ-सफाई ठीक से की गई होती, प्रबंधन के स्तर पर हर वक्त चौकसी बरती गई होती, तो अस्पताल परिसर में चूहे नहीं पाए जाते। इससे साबित होता है कि अस्पताल परिसर में चूहों के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। इस घटना की वजह से बस व्यवस्था की पोल-पट्टी खुली है। नवजात बच्चियों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद साफ-सफाई करने वाली एजंसी का ठेका जरूर खत्म कर दिया गया है, लेकिन पूछा जाना चाहिए कि हर वक्त चौकसी बरतने की जिम्मेदारी किसकी है?

वैश्विक संतुलन के ध्रुव और भारत

भारत की विदेश नीति की असल चुनौती यही है कि उसे अमेरिका की एकपक्षीय व्यापारिक नीतियों से पैदा हुए अविश्वास और वैश्विक अस्थिरता का सामना करते हुए भी रणनीतिक तथा आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है।

ब्रह्मदीप अलूने

कूटनीति का एक प्रमुख दायित्व यह होता है कि वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए शक्ति-संतुलन का मूल्यांकन करे और ऐसी रणनीति अपनाए, जिससे किसी भी क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति-प्रतिस्पर्धा में राष्ट्र के हित प्रभावित न हों। भारत की विदेश नीति की असल चुनौती यही है कि उसे अमेरिका की एकपक्षीय व्यापारिक नीतियों से पैदा हुए अविश्वास और वैश्विक अस्थिरता का सामना करते हुए भी रणनीतिक तथा आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक और विचारधारा के स्तर पर देश के दीर्घकालीन हितों की दृष्टि से इस पर समग्रता की जरूरत महसूस की जा रही है। देश की आर्थिक प्रगति निर्बाध चलती रहे, इसलिए निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था कायम रखनी होगी। अमेरिका-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा के भू-राजनीतिक प्रभावों को समझते हुए रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना होगा। बहुपक्षीय मंचों का कूटनीतिक उपयोग करते हुए भी महाशक्तियों की मोर्चाबंदी की कोशिशों से अलग रहना होगा और भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान बनाए रखने के लिए साझेदारी का चुनाव भी समझदारी से करना होगा।

शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने के संदेश के बीच दुनिया के शांतिपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की संभावनाएं पुतिन और शी जिनपिंग के नेतृत्व में खोजना राजनीतिक जटिलताओं को बढ़ा सकता है। इससे दुनिया की व्यवस्थागत समस्याएं भी बढ़ सकती हैं और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। दरअसल, भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकांक्षाएं और सुरक्षा चुनौतियां इतनी जटिल हैं कि वह केवल एक शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए उसकी भू-राजनीतिक जरूरतें उसे अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ अलग-अलग स्तरों पर सहयोग और संतुलन साधने के लिए प्रेरित करती हैं।

तीव्र आर्थिक विकास की भारत की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत न केवल अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, बल्कि अमेरिकी निवेश और पूंजी प्रवाह ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान की है। लाखों भारतीय पेशेवर अमेरिका में कार्यरत हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयों का नेतृत्व इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सिलिकान वैली और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंध पारस्परिक निर्भरता बढ़ाते हैं। हाल के वर्षों में रक्षा तकनीकी साझेदारी ने भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ाया है, जिससे वह क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में अधिक सक्षम बन सका है। रणनीतिक दृष्टि से भी अमेरिका भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चीन की विस्तारवादी नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान को मिलने वाला उसका समर्थन भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ भारत का सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली और बेजिंग के बीच संबंध सुधरते दिखाई दिए। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सहयोग की गुंजाइश दोनों देशों के बीच बनी रहती

है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद ऐसे मंचों पर संवाद भारत को तनाव कम करने और टकराव को नियंत्रित करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से यह उम्मीद बढ़ी है कि व्यापारिक असंतुलन, सीमा पर स्थिरता और

> प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दोनों पड़ोसी देश डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने शुल्क के दबाव में, अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई भू-राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। भारत के लिए चीन सीमा विवाद, पाकिस्तान गठजोड़, आर्थिक निर्भरता, समुद्री विस्तारवाद और वैश्विक मंचों पर विरोध बड़ी चुनौती है। भारत की विदेश नीति चीन को संतुलित करने के लिए कृतसंकल्प रही है और इस वास्तविकता को नजरअंदाज करने का जोखिम भी नहीं लिया जा सकता।

ब्रिक्स जैसे मंचों में सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इससे यह संदेश जाता है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत संवाद का रास्ता बंद नहीं करता।

प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दोनों पड़ोसी देश डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने शुल्क के दबाव में अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई भू-राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। भारत के लिए चीन सीमा विवाद, पाकिस्तान गठजोड़, आर्थिक निर्भरता, समुद्री विस्तारवाद और वैश्विक मंचों पर विरोध बड़ी चुनौती है। भारत की विदेश नीति चीन को संतुलित करने के लिए कृतसंकल्प रही है और इस वास्तविकता को नजरअंदाज करने का जोखिम भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी सहयोग आवश्यक है।

भारत हमेशा सामरिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है। यह नीति कहती है कि वह किसी एक शक्ति पर निर्भर न होकर दूसरी शक्तियों के साथ भी संतुलन बनाए। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच रूस भारत के लिए एक संतुलनकारी ध्रुव है। भारत की रक्षा संरचना का बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक और हथियारों पर आधारित है। लड़ाकू विमानों से लेकर टैंकों और पनडुब्बियों तक, भारत की सैन्य क्षमता की रीढ़ रूसी सहयोग से बनी है। आज भी ब्रह्मोस मिसाइल, एस-400 रक्षा प्रणाली और टी-90 टैंक भारत की सामरिक शक्ति को परिभाषित करते हैं। पश्चिमी देश अक्सर संवेदनशील तकनीक साझा करने से हिचकते हैं, जबकि रूस ने लंबे समय से भारत को ऐसी रक्षा तकनीक उपलब्ध कराई है जो उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत के लिए रूस केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि रक्षा सहयोग का स्थायी साझेदार है।

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पश्चिम से बहुत दूर हो गया है और चीन पर उसकी निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। भारत के लिए यह स्थिति सामरिक रूप से अनुकूल नहीं है। रूस की चीन पर निर्भरता से पाकिस्तान और रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती चीन है और अगर रूस उस पर अधिक निर्भर होता है, तो भारत के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ता है। रूस भारत का पारंपरिक रक्षा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन चीन के साथ रूस की तकनीकी साझेदारी भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करती है। रूस को पूरी तरह चीन के पाले में जाने से रोकने के लिए भारत को ऊर्जा, रक्षा और निवेश में रूस से रिश्ते बनाए रखने होंगे। वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को अमेरिका, जापान, फ्रांस और यूरोपीय देशों से सहयोग बढ़ाना होगा। रूस-चीन मित्रता कुछ मामलों में भारत को राहत दे सकती है। जैसे ट्रंप की नीतियों से निपटने के फिलहाल दबाव बनाया गया है, लेकिन दीर्घकाल में अगर रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, तो यह भारत की सामरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए समस्या भी बन सकता है।

रूस और चीन की तुलना में भारत निश्चित रूप से एक उभरती हुई शक्ति है। यह एक युवा, बड़ी आबादी, तेज आर्थिक विकास, मजबूत लोकतंत्र और हिंद-प्रशांत में रणनीतिक स्थिति से लाभान्वित हो रहा है। जबकि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के अभाव, चीन की तुलना में कम वैश्विक पहुंच और मध्यम स्तर की सैन्य-तकनीकी आत्मनिर्भरता भारत की प्रमुख समस्याएं हैं। रूस और चीन के मजबूत रिश्ते भारत के लिए दोधारी तलवार की तरह हैं। एक ओर यह बहुध्रुवीयता और वैश्विक संतुलन को बढ़ावा देकर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हैं, तो दूसरी ओर यह चीन-पाकिस्तान धुरी को और मजबूत बना कर भारत की सुरक्षा और सामरिक स्वतंत्रता के लिए नई चुनौतियां पैदा करते हैं। भारत का हित इसी में हैं कि वह सभी से मित्रता रखे, पर निर्भरता किसी पर न बनाए।

दुनिया मेरे आगे

निर्भयता की राह

अनिल त्रिवेदी

आजादी और मुक्ति का सच्चा अर्थ आज हमारे कहे-लिखे हुए केवल बोलचाल के शब्द ही हैं या वास्तविक स्वरूप में हमारे जन जीवन और अंतर्मन में जीवंत रूप से रचे-बसे सहज आपसी व्यवहार हैं? आजादी का मूल अर्थ भयमुक्त होना ही हो सकता है। जब तक मन निर्भय न हो, स्वाधीनता से सहज साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जो भयभीत होता है, वह स्वाधीनता के दर्शन के बारे कभी भी गहराई से सोच समझ ही नहीं पाता है। स्वाधीनता और स्वावलंबन एक तरह से आपस में इस तरह घुले मिले हैं कि दोनों को समझे बिना या आत्मसात किए बिना इनकी जीवनी शक्ति को जाना नहीं जा सकता है। इस जगत में मनुष्य के अलावा बाकी सब स्वावलंबी है। इसीलिए मानवेतर सारे जीव-जंतुओं के सामने स्वाधीनता का सवाल कभी आया ही नहीं। मनुष्य ने अन्य मनुष्यों को पराधीन बनाया, परावलंबी और यंत्रवत भी बनाया। साथ ही साथ खुद भी परावलंबी बना और यंत्रवत बनने या यंत्र का आदी बनने की राह पर चल पड़ा है। आधुनिक मनुष्य ने ही अपने मन में बसे लालच, लाचारी या भय के कारण स्वाधीनता की जगह पराधीनता का विस्तार करने वालों की गुलामी को भयभीत और मन से लाचार होकर अपनी स्वाधीनता को अपने ही हाथों खोकर पराधीनता को अपनाया। इस दृष्टि से समझें तो जो मनुष्य आत्मविश्वास से भरा है, वह स्वाधीन है और जो खुद पर भी विश्वास नहीं करता और भयग्रस्त रहता है, वह स्वाधीनता का अर्थ और मर्म नहीं जान सकता है।

स्वाधीनता को समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य पराधीनता को क्यों और कैसे स्वीकार या आत्मसात कर लेता है। इतनी लंबी मानव सभ्यता के इतिहास में स्वाधीनता के लिए तरह-तरह के संघर्ष हुए, कुर्बानियां दी गईं, जो आज भी कई रूप में जारी हैं। मानव मन में परावलंबन और मानसिक गुलामी की जड़ें भी शायद इतनी गहरी रची-बसी हैं कि मानव समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की आजादी के लिए आज भी कहीं कोई मनुष्य या उसका समूह संघर्ष करता रहता है। स्वाधीनता इतनी व्यापक और सहज अवधारणा है जो समझ तो जल्दी आ जाती है और अपने लिए हम चाहते भी हैं, पर अन्य के साथ व्यवहार करते समय हम कई किंतु-परंतु लगा लेते हैं। यहां आकर हम सिद्धांत और व्यवहार में उलझ जाते हैं। शायद यह हम सबके आपसी विश्वास और आत्मविश्वास में कमी के कारण या सही आकलन न कर पाने का दोष भी हो सकता है।

> स्वाधीनता जीने का एक ढंग है, जिसमें आचरणगत मर्यादा और उत्तरदायित्व अंतर्निहित है। इसकी संकल्पना के मूल में हवा और प्रकाश की तरह सहज, सरल स्वाधीनता की उपलब्धता है। पर ऐसा हम आज तक सुनिश्चित कर नहीं पाए और नतीजतन हम सबने स्वाधीनता में कई किंतु-परंतु लगाकर इसे व्यवस्थागत अवधारणा में बदल डाला है।

दरअसल, स्वाधीनता जीने का एक ढंग है, जिसमें आचरणगत मर्यादा और उत्तरदायित्व अंतर्निहित है। इसकी मौलिक संकल्पना के मूल में हवा और प्रकाश की तरह सहज, सरल स्वाधीनता की उपलब्धता है। पर ऐसा हम आज तक सुनिश्चित कर नहीं पाए और नतीजतन हम सबने स्वाधीनता में कई किंतु-परंतु लगाकर इसे व्यवस्थागत अवधारणा में बदल डाला है। अब दुनियाभर की व्यवस्थाओं की अपनी-अपनी स्वाधीनता को लेकर व्याख्याएं हैं, जो स्वाधीनता की लक्ष्मणरेखा खींच कर इसकी मूल अवधारणा को ही बदल देती है। खुला मन, खुली सोच और समझ एक तरह से स्वाधीनता के लिए प्राणवायु की तरह हैं। लोकतांत्रिक समाज और व्यवस्था की आधारभूमि पर स्वाधीनता का स्वरूप निखरता है। यह कोई दिखावटी गहना नहीं है, बल्कि जीवन की जीवनी शक्ति या प्राणवायु है।

भयग्रस्त मन स्वाधीनता की राह नहीं बनाता। मन का भय पराधीनता को ही लाचार भाव से जीवन की नियति बना बैठता है। हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता भय के खिलाफ खुला विद्रोह है। मानव इतिहास गवाह है कि गुलामी का प्रतिरोध बहुत धीरे-धीरे होता है। इस धीमी गति का कारण असुरक्षित मनःस्थिति है। हमारा स्वानुशासन स्वाधीनता का विस्तार करता है। स्वाधीनता अपने आप में सीमातीत और बंधनमुक्त अवधारणा है। फिर भी व्यक्ति, समाज और व्यवस्था के आचरण में अनुशासन की मर्यादा का बिंदु आ जाता है। स्वानुशासन स्वयंस्फूर्त होता है, जबकि अनुशासन व्यवस्थागत संकल्पना है।

स्वाधीनता का अर्थ मनमर्जी और मनमानी से एकदम भिन्न है। स्वाधीनता मूल रूप से स्वाभिमान से जुड़ा विचार है जो व्यक्ति और समाज को निर्भय जीवन और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने की आधारभूमि प्रदान करता है। एक सवाल यह भी उठता है कि ऐसा कैसे होता है कि मनुष्य ही मनुष्यों को पराधीन करने की योजना या रणनीति बनाकर मनुष्यों में भय फैलाता है और लोग लाचार या भयग्रस्त हो पराधीन हो जाते हैं। पराधीनता के खिलाफ अलख जगाने का काम भी मनुष्य समूह ही करते हुए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करते हैं। पराधीनता की अति स्वाधीनता की भूख जगाती है और स्वाधीनता में अनमनापन, उदासी, लापरवाही पराधीनता को जन्म देती है। इस तरह स्वाधीनता यानी सदैव चौकस और संवेदनशील रहते हुए भयमुक्त जीवन है। यह मनुष्य की सभ्यता का मूल है और पराधीनता मानवीय असमर्थता की पराकाष्ठा। स्वाधीनता मानव मन की पूर्णता की प्रखर अभिव्यक्ति है। इससे परिपूर्ण मानव सभ्यता मानव-ऊर्जा का वैसा ही सकारात्मक स्वरूप है, जैसा प्राणवायु और सूर्यप्रकाश का प्राकृत स्वरूप होता है।

निर्भयता मन की स्वाधीन और प्राकृत स्थिति है। निर्भय मन ही निर्भय समाज और सभ्यता को आगे बढ़ाता है। भयभीत मनुष्य या समाज स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते, पर स्वाधीनता का विचार मनुष्य मन के सारे भयों को दूर करने का द्वार खोलते हैं। स्वावलंबन हमें न केवल व्यक्ति के रूप में, बल्कि सामूहिक रूप से भी स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ जीते रहने की निरंतर ऊर्जा देता है। स्वाधीनता हमारी मूल प्रवृत्ति है और निर्भयता स्वाधीनता का मूल है।

चौपाल

कूटनीति और सावधानी

'कूटनीतिक जीत' (संपादकीय 2 सितंबर) पढ़ा। शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और आर्थिक सहयोग को मजबूती देने के उद्देश्य से ही हुई थी। चीन के तियानजिन में हाल ही में संपन्न हुए एससीओ सम्मेलन के घोषणापत्र में जिस तरह साफ शब्दों में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की बात शामिल की गई है, वह भारत की कूटनीतिक सफलता है। हालांकि यह अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है कि भारत-चीन संबंधों में कोई विशेष परिवर्तन होगा या एससीओ के जरिए वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जबकि मोदी-जिनपिंग में आपसी संबंध सुधारने की दिशा में ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही। इस सम्मेलन से कुछ उल्लेखनीय हासिल हुआ, तो वह यह कि दोनों देशों के बीच टूटा संवाद-संपर्क फिर से कायम हुआ। इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पहलगाम हमले की निंदा की गई। यह भारत की कूटनीतिक जीत है।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम

आत्मनिर्भरता का दम

हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को प्रस्तुत भारत का पहला स्वदेशी बिट प्रोसेसर विक्रम-32 देश के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक ठोस कदम है। वर्षों तक हम विदेशी तकनीक पर निर्भर रहे, लेकिन अब अंतरिक्ष मिशनों जैसे कठिन क्षेत्रों में उपयोग होने वाली इस चिप का स्वदेशी निर्माण हमारी वैज्ञानिक क्षमता और युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का प्रमाण है। यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर पहचान दिलाने में सहायक होगी। आने वाले समय में यदि सरकार इसी तरह अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत चिप निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा और दुनिया को यह तकनीक निर्यात करेगा। यह उपलब्धि हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि हम 'मेड इन इंडिया' को केवल नारा नहीं, बल्कि सच्चाई बना सकते हैं।

- आराध्या सिंह, आजमगढ़

परीक्षा की जटिलता

शिक्षक बनने की प्रक्रिया आज परीक्षाओं के मकड़जाल में फंस गई हैं। बीएड, बीटीसी, टीईटी, सुपर टीईटी जैसी कई परीक्षाओं की श्रृंखला ने शिक्षक अभ्यर्थियों को उलझा दिया है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए टीईटी अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवा छोड़नी पड़ेगी या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेनी होगी। सच तो यह है कि बीएड और बीटीसी जैसे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारना ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। यदि प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर पढ़ाई हो, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाए और नियमित मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी हो, तो अलग से परीक्षाओं की जरूरत ही नहीं पड़े। दूसरी ओर, इन परीक्षाओं के नाम पर मोटी फीस लेकर बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को वर्षों तक तैयारी और परीक्षा की दौड़ में उलझाए रखना शिक्षा सुधार का उपाय नहीं, बल्कि उनकी मानसिक थकान का कारण बन गया है।

- आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी

बदलते रिश्ते

आज की दुनिया में रिश्ते लगातार बदल रहे हैं। तकनीक और सुविधाओं ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी, लेकिन इसके साथ ही इंसानों के बीच नजदीकियां कम कर दी हैं। पहले लोग एक-दूसरे से सहज बात करते थे। उदाहरण के लिए, किसी दुकान से कोई सामान खरीदने जाते वक्त हम दुकानदार से बातें करते। उससे जान-पहचान बढ़ाते थे। अब हर सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध है। जीवन की ऐसी छोटी-छोटी बातें धीरे-धीरे गायब हो रही हैं। लोग भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। रिश्तों का महत्त्व कम हो रहा है और पैसे पर लोगों का ध्यान अधिक बढ़ गया है। इसका प्रभाव लोगों की सोच पर दिखाई दे रहा है। रिश्ते अब पहले की तरह गहरे नहीं रहे, सिर्फ चंद दोस्तों, परिवार और सहपाठियों तक सीमित रह गए हैं। तकनीक लोगों को जोड़ तो रही है, लेकिन दूसरी ओर वास्तविक जीवन में लोगों को एक-दूसरे से दूर भी कर रही है।

- दिव्यांशु खनाल, नोएडा

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com